WHITE BOOK

COACH UP IAS

YOUR SELECTION Is OUR BUSINESS

भारतीय अर्थव्यवस्था

(NCERT)

सिविल सेवा परीक्षा के लिए

IAS COACH ASHUTOSH SRIVASTAVA

IAS COACH MANISH SHUKLA

8009803231/92365 69979

WALL OF FAME

UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18

SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55

SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163

SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3

DEEPAK SINGH
SDM RANK-20

ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11

SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)

SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)

KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)

SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)

ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)

AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)

SANDEEP K. SATYARTHI
CTD (PCS-2018)

MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)

AFTAB ALAM
PCS OFFICER

ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)

CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349

YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

D 22&23, PURNIYA CHAURAHA, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

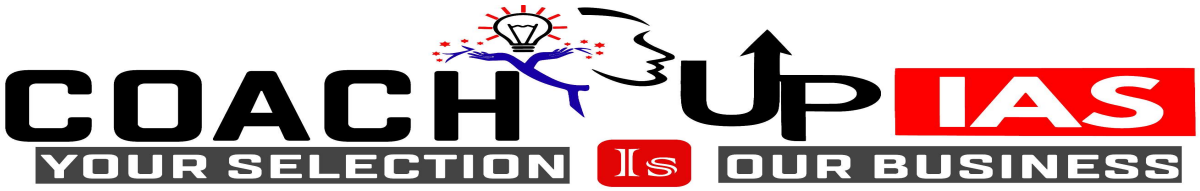

COACH UP IAS
YOUR SELECTION Is OUR BUSINESS

CSAT
LIVE CLASSES
FOUNDATION COURSE

KEY FEATURES
- 60 Interactive Teaching Hours
- Comprehensive coverage of entire Syllabus
- Well-structured and planned topic sequence.
- Personalized Mentorship
- Regular Quizzes and practice sets
- Well-designed Study Material

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

SAMARPAN
LIVE CLASSES
12 MONTHS WEEKEND BATCH FOR PRELIMS & MAINS

KEY FEATURES
- NCERT + Complete GS (Pre + Mains)
- CSAT
- Test Series

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

AARAMBH
LIVE CLASSES
3 YEARS INTEGRATED IAS/PCS FOUNDATION COURSE

KEY FEATURES
- NCERT + Complete GS (Pre + Mains)
- Optional
- CSAT
- Test Series + Mock Interview

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

AAVEG
LIVE CLASSES
14 MONTHS REGULAR FOUNDATION COURSE FOR IAS/PCS

KEY FEATURES
- Complete G S (Pre + Mains)
- Optional
- Essay Writing
- Interview

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

AAROHAN
LIVE CLASSES
20 MONTHS REGULAR FOUNDATION COURSE FOR IAS/PCS

KEY FEATURES
- NCERT + Complete GS (Pre + Mains)
- Optional
- CSAT
- Test Series + Mock Interview

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

PCS-J FOUNDATION
LIVE CLASSES
FOR 15 MONTHS (PCS-J, HJS, APO)

KEY FEATURES
- LAW
- G K

COACH UP IAS - YOUR SELECTION IS OUR BUSINESS

Saarthi
THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E. , MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.

TABLE OF CONTENT

CLASS 9		
1.	अध्याय 1	पालमपुर गांव की कहानी
2.	अध्याय 2	लोग एक संसाधन के रूप में
3.	अध्याय 3	गरीबी एक चुनौती के रूप में
4.	अध्याय 4	भारत में खाद्य सुरक्षा
CLASS 10		
1.	अध्याय 1	विकास
2.	अध्याय 2	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
3.	अध्याय 3	धन और ऋण
4.	अध्याय 4	वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
5.	अध्याय 5	उपभोक्ता अधिकार
CLASS 11		
1.	अध्याय 1	स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
2.	अध्याय 2	भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
3.	अध्याय 3	उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
4.	अध्याय 4	गरीबी
5.	अध्याय 5	भारत में मानव पूंजी निर्माण
6.	अध्याय 6	ग्रामीण विकास
7.	अध्याय 7	रोजगार: विकास, अनौपचारिकीकरण और अन्य मुद्दे
8.	अध्याय 8	अवसंरचना
9.	अध्याय 9	पर्यावरण और सतत विकास
10.	अध्याय 10	भारत और उसके पड़ोसियों का तुलनात्मक विकास और अनुभव
CLASS 12		
1.	अध्याय 1	परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र
2.	अध्याय 2	राष्ट्रीय आय लेखांकन
3.	अध्याय 3	धन और बैंकिंग
4.	अध्याय 4 & 5	सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था
5.	अध्याय 6	खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र

CLASS 9

CHAPTER 1

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ उत्पादन का कारक
- ✓ भूमि वितरण
- ✓ खेती और गैर-कृषि गतिविधियाँ
- ✓ पूंजी आवश्यकताएँ

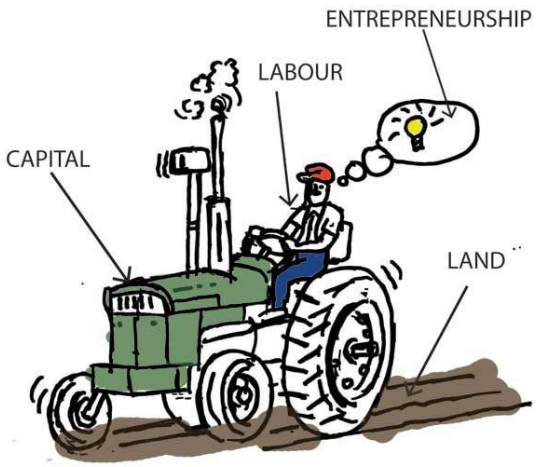

- यहां हम पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव के माध्यम से कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझेंगे जैसे- उत्पादन का कारक, भूमि वितरण, खेती और गैर-कृषि गतिविधियां, पूंजी आवश्यकताएं।
- पालमपुर सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के साथ आसपास के गांवों से काफी जुड़ा हुआ है। पालमपुर की कहानी हमें गाँव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन गतिविधियों से परिचित कराती है। भारत में, गाँवों में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है।

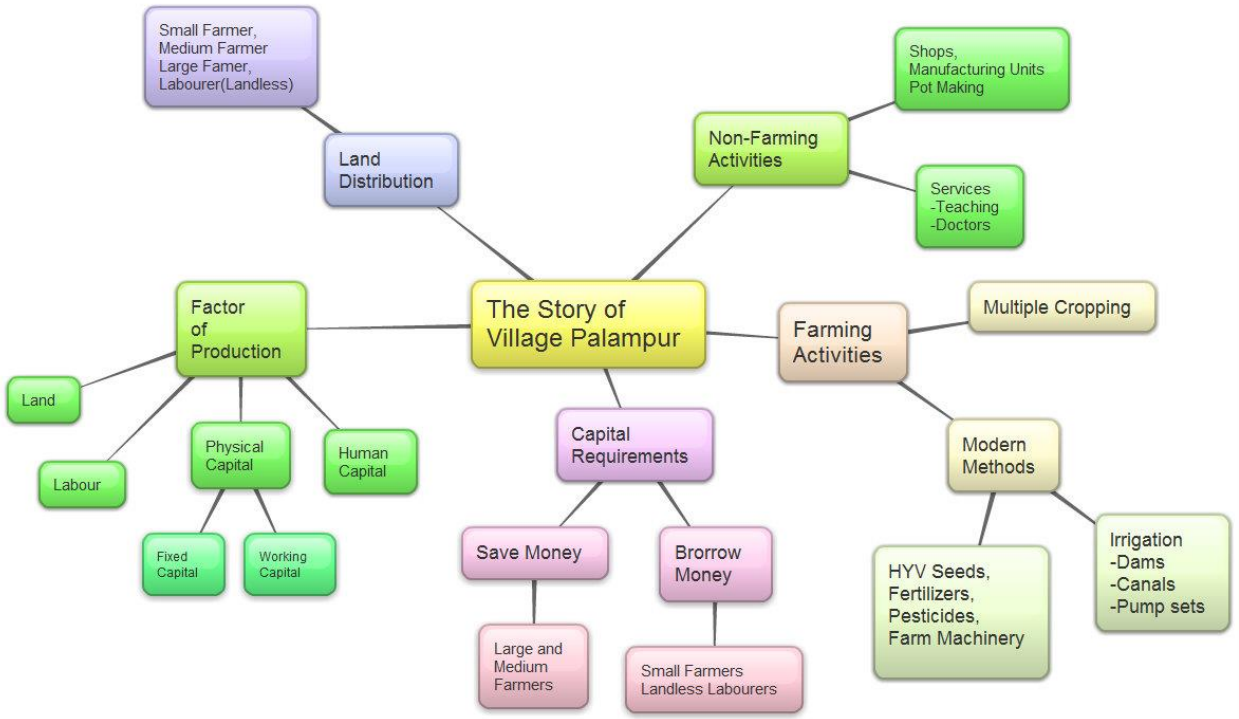

अब हम पालमपुर में उत्पादन गतिविधियों से संबंधित अवधारणाओं को समझेंगे।

उत्पादन का संगठन:

➢ उत्पादन का उद्देश्य ⟶ उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो हम चाहते हैं।

- पहली आवश्यकता है भूमि, और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, खनिज
- दूसरी आवश्यकता है श्रम, यानि काम करने वाले लोग ⟶ (मानसिक श्रम) शिक्षित और शारीरिक श्रमिक
- तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, यानी उत्पादन के दौरान हर चरण में आवश्यक इनपुट की विविधता [भौतिक पूंजी: उपकरण, मशीनें, भवन, कच्चा माल और हाथ में पैसा]
- चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी (उद्यमिता) [मानव पूंजी: यह किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और दक्षताओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है]

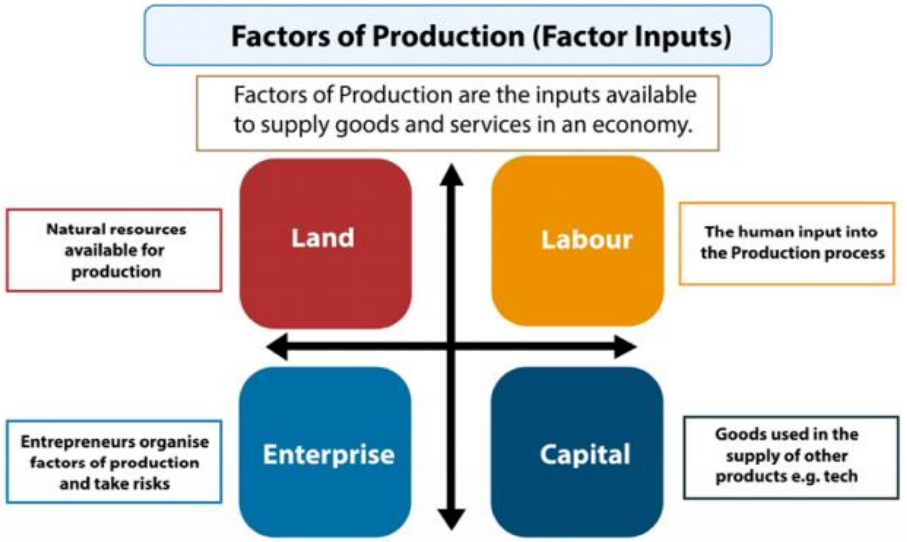

आइए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को समझें:

Factor	Characteristics	Examples	Rewards
Land	Land + Extracted Resources	Farm + Crops	Rent
Labour	Physical + Mental Input	Workforce	Wages
Capital	Fixed + Working Capital	Machinery	Interest
Entrepreneurship	Organisation of Factors	Manager	Profit

गतिविधि के आधार पर:

प्राइमरी सेक्टर:

- प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध देश के प्राकृतिक संसाधनों से है।
- आर्थिक विवरण: इसका संबंध कच्चे माल के निष्कर्षण से है।
- इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और खनन शामिल हैं।
- प्राथमिक क्षेत्र में कृषि प्रमुख व्यवसाय है।
- प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कच्चे माल और बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग उद्योगों या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।
- यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले बुनियादी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

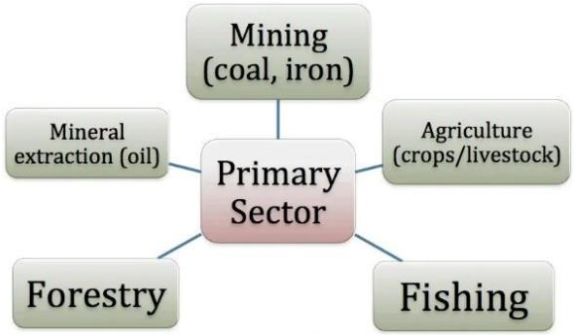

द्वितीयक क्षेत्र:

- द्वितीयक क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। यह प्राइमरी के बाद अगला चरण है। उत्पाद प्रकृति द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है बल्कि उसे बनाना पड़ता है और इसलिए विनिर्माण की कुछ प्रक्रिया आवश्यक है।
- इसलिए द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र शामिल है, जो निर्माण गतिविधियों और तैयार माल के विनिर्माण में लगा हुआ है।

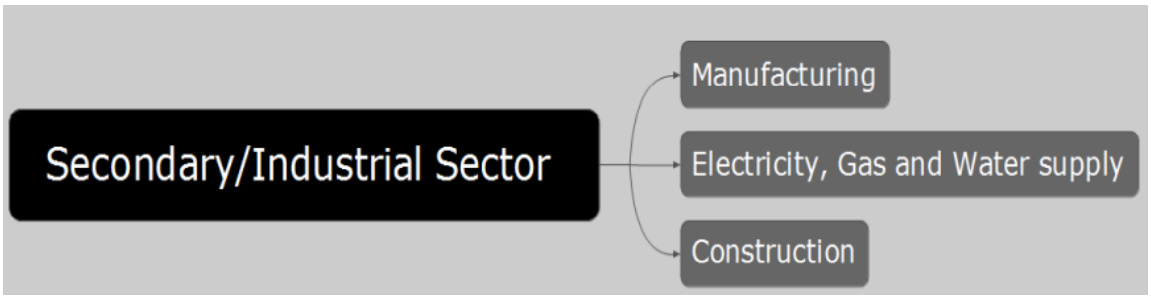

तृतीय श्रेणी का उद्योग:

- अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को आम तौर पर सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
- इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, होटल, परिवहन, वित्त, उत्पादक से उपभोक्ता तक माल का वितरण और बिक्री जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है, जैसा कि थोक और खुदरा बिक्री, कीट नियंत्रण या मनोरंजन में हो सकता है।

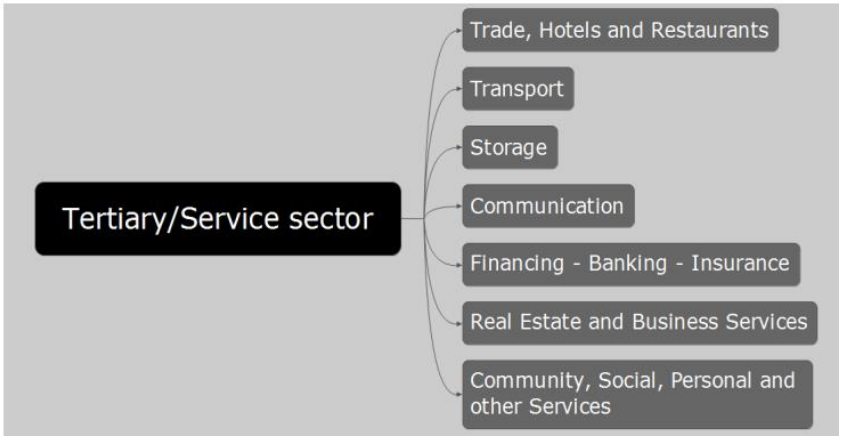

चतुर्धातुक गतिविधियाँ:

- इसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद तैयार करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास शामिल है।

- ये 'ज्ञान क्षेत्र' में विशिष्ट तृतीयक गतिविधियाँ हैं जो एक अलग वर्गीकरण की मांग करती हैं
- चतुर्धातुक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पहलू है।
- यह वह प्रक्रिया है जो उद्यमियों को अर्थव्यवस्था में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में नवाचार करने और सुधार करने में सक्षम बनाती है।
- प्राथमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय कक्षाएँ, अस्पताल और डॉक्टरों के कार्यालय, थिएटर, लेखा और ब्रोकरेज फर्म सभी इस श्रेणी की सेवाओं से संबंधित हैं

पंचम गतिविधियाँ:

- क्विनरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जहां शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं।
- इसमें वह सरकार भी शामिल है जो कानून पारित करती है।
- इसमें उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा क्षेत्र के शीर्ष निर्णयकर्ता भी शामिल हैं।
- अक्सर 'गोल्ड कॉलर' व्यवसायों के रूप में जाना जाता है, वे तृतीयक क्षेत्र के एक अन्य उपखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय और कानूनी सलाहकारों आदि के विशेष और उच्च भुगतान वाले कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उच्चतम स्तर के निर्णय-निर्माता या नीति-निर्माता पंचम गतिविधियाँ करते हैं।
- क्विनरी = गोल्ड कॉलर प्रोफेशन।

कार्य शर्तों के आधार पर:
संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र

- संगठित क्षेत्र में कुछ कंपनियां या कार्यस्थल शामिल होते हैं जिनमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी भी होती है। वे सरकार द्वारा अधिकृत हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम आदि सहित विभिन्न कानूनों में निर्धारित कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा।
- असंगठित क्षेत्र में छोटी व्यावसायिक इकाइयों और इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, जो अक्सर नियमितता के किसी आश्वासन के बिना होते हैं। यदि आप किसान हैं, घरेलू नौकर हैं, किराने की दुकान पर सेल्समैन हैं, तो आपको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला माना जा सकता है।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर
संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर नीचे सारणीबद्ध है।

संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम मिलता है।	असंगठित क्षेत्र की विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं।
नौकरी नियमित है और काम के घंटे निश्चित हैं। यदि लोग अधिक काम करते हैं, तो उन्हें नियोक्ता द्वारा ओवरटाइम के लिए भुगतान मिलता है।	नौकरियाँ कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होतीं।
श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं।	रोजगार सुरक्षित नहीं है. लोगों को बिना किसी कारण के बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है.
कर्मचारियों को मेडिकल और कई अन्य लाभ मिलेंगे.	श्रमिकों के लिए कोई लाभ उपलब्ध नहीं है।

उदाहरण: सरकारी कर्मचारी, पंजीकृत औद्योगिक श्रमिक, आदि। उदाहरण: दुकानदारी, खेती, घरेलू काम, आदि।
संपत्ति स्वामित्व के आधार पर:
प्राइवेट सेक्टर

- निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा लाभ के लिए चलाया जाता है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।
- मुक्त बाज़ार, पूंजीवादी-आधारित समाजों में निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनता है।
- निजी क्षेत्र के व्यवसाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी नामक व्यवस्था में सरकार द्वारा संचालित एजेंसियों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र:

- सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे व्यवसाय शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण किसी देश की सरकार के पास होता है।
- इन संगठनों में केंद्र या राज्य सरकारों का स्वामित्व और नियंत्रण या तो पूर्ण या आंशिक होता है। लेकिन सरकार के पास बहुमत हिस्सेदारी है और इकाई को चलाने के संबंध में हर एक निर्णय वह लेती है।
- इन संगठनों में सरकारी एजेंसियां, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, नगर पालिकाएं, स्थानीय सरकारी प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक सेवा संस्थान शामिल हैं।
- उनमें से कुछ गैर-लाभकारी संगठन हो सकते हैं जबकि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं।
- यह आम तौर पर निजी कंपनियों की तुलना में आम जनता को अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर सामान और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य किसी देश के भीतर आम जनता का कल्याण सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच अंतर

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:

सार्वजनिक क्षेत्र	**प्राइवेट सेक्टर**
परिभाषा: सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन सरकार या अन्य राज्य-संचालित निकायों द्वारा किया जाता है।	निजी क्षेत्र के संगठनों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन व्यक्तियों, समूहों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
स्वामित्व: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का स्वामित्व केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारी निकायों के पास हो सकता है और यह स्वामित्व पूर्ण या आंशिक होता है।	निजी क्षेत्र की इकाइयों का स्वामित्व व्यक्तियों या संस्थाओं के पास होता है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
उद्देश्य: सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का मुख्य उद्देश्य आम जनता की सेवा करने वाली गतिविधियों में संलग्न होना है।	निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय संचालन से लाभ कमाना है।
पूंजी का स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पूंजी कर संग्रह, उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क, बांड, ट्रेजरी बिल आदि से आती है।	निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए पूंजी या तो उसके मालिकों से या ऋण, शेयर और डिबेंचर जारी करने आदि के माध्यम से आती है।
रोजगार लाभ : सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ नौकरी की सुरक्षा, आवास सुविधाएँ, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कई रोजगार लाभ प्रदान करती हैं।	निजी क्षेत्र की इकाइयाँ उच्च वेतन पैकेज, पदोन्नति और मान्यता की बेहतर संभावना, प्रतिस्पर्धी माहौल और बोनस और अन्य लाभों के संदर्भ में अधिक प्रोत्साहन जैसे लाभ प्रदान करती हैं।
स्थिरता: सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियाँ बहुत स्थिर होती हैं क्योंकि गैर-प्रदर्शन के कारण बर्खास्त होने की संभावना बहुत कम होती है।	निजी क्षेत्र में नौकरियाँ बहुत सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि प्रदर्शन न करने पर बर्खास्तगी तक हो सकती है। लागत में कटौती या परिचालन कम करने की स्थिति में कंपनियां लोगों को नौकरी से भी निकाल सकती हैं।
नौकरी में पदोन्नति: सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पदोन्नति का मानदंड आम तौर पर कर्मचारी की वरिष्ठता पर आधारित होता है।	निजी क्षेत्र की इकाइयों में पदोन्नति का मानदंड आम तौर पर कर्मचारी की योग्यता और कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है।
क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य क्षेत्र हैं पुलिस, सेना, खनन, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग, आदि।	निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ मुख्य क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, तेज गति से चलने वाली उपभोक्ता वस्तुएं, निर्माण, आतिथ्य, फार्मास्यूटिकल्स आदि हैं।

आइए पालमपुर गांव के संदर्भ में कुछ अन्य शब्दों को समझें:

एकाधिक फसलें:

- वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहुफसली खेती कहलाती है।
- यह किसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है

उपज:

- उपज को एक ही मौसम के दौरान भूमि के किसी दिए गए टुकड़े पर उत्पादित फसल के रूप में मापा जाता है

अधिक उपज देने वाली किस्में (HYVs):

- 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) के बीजों का उपयोग करके गेहूं और चावल की खेती से परिचित कराया।
- पारंपरिक बीजों की तुलना में, HYV बीजों ने एक ही पौधे पर बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा करने का वादा किया।
- परिणामस्वरूप, ज़मीन का वही टुकड़ा अब पहले की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करेगा।
- सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए HYV बीजों को भरपूर पानी और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की भी आवश्यकता होती है।
- उच्च पैदावार केवल HYV बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी।

आधुनिक कृषि पद्धति:

- पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति को आजमाने वाले पहले व्यक्ति थे।
- इन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल स्थापित किए, और खेती में HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया।
- उन्हें गेहूं की उच्च पैदावार से पुरस्कृत किया गया।
- वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आधुनिक खेती के तरीकों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अत्यधिक उपयोग किया है।
- हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता के नुकसान से जुड़ी है।
- ट्यूबवेल सिंचाई के लिए भूजल के निरंतर उपयोग से जमीन के नीचे जल-स्तर कम हो गया है।

रासायनिक खाद:

- रासायनिक उर्वरक खनिज प्रदान करते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं।
- रासायनिक उर्वरक मिट्टी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को भी मार सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके उपयोग के कुछ समय बाद, मिट्टी पहले से कम उपजाऊ हो जाएगी।
- रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है।
- किसान अब समान उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आदानों का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। इसका मतलब है कि खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है।

अधिशेष का अभाव

- किसान उपज का एक हिस्सा स्वयं उपभोग के लिए रखते हैं और अधिशेष को पास के बाजार में बेचते हैं। कृषि उपज का वह भाग जो बाज़ार में बेचा जाता है, विपणन योग्य अधिशेष कहलाता है।
- छोटे किसानों के पास बहुत कम अतिरिक्त उत्पादन होता है। केवल मध्यम और बड़े किसानों के पास ही बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त अधिशेष उपज होती है।
- अधिशेष की कमी का मतलब है कि किसान अपनी बचत से पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ हैं, और उन्हें उधार लेना पड़ता है।

CLASS 9

CHAPTER 2

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ मानव पूंजी
- ✓ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की भूमिका
- ✓ भारत में बेरोजगारी के स्वरूप.
- ✓ आर्थिक और गैर-आर्थिक गतिविधियाँ
- ✓ बाजार और गैर-बाजार गतिविधियाँ

जनसंख्या → दायित्व के बजाय अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति

मानव पूंजी:

→ मानव पूंजी उनमें निहित कौशल और उत्पादक ज्ञान का भंडार है।

→ जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखभाल के रूप में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है

मानव एक संसाधन के रूप में

- यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि जनसंख्या कैसे एक संपत्ति हो सकती है न कि देनदारी। यह समाज के श्रमिक वर्ग को उनके मौजूदा उत्पादक कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में संदर्भित करने का एक तरीका है। जब शिक्षा और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी मनुष्य को अर्थव्यवस्था की संपत्ति बनने में मदद करते हैं। इस प्रकार, एक संसाधन के रूप में लोग कार्यशील जनसंख्या को संदर्भित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप समाज का विकास होता है।

मानव संसाधन और भौतिक संसाधन के बीच अंतर

- मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न हैं क्योंकि मनुष्य उत्पादक उत्पादन देने के लिए अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकता है। हालाँकि, भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधन अपने उपयोग के लिए मानव संसाधन पर निर्भर हैं और अकेले कोई उत्पादक उत्पादन नहीं दे सकते हैं।

मानव पूंजी निर्माण

- जब मौजूदा मानव संसाधन को कार्यबल को अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाने पर खर्च करके और विकसित किया जाता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है।

मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका-

शिक्षा निम्नलिखित कारणों से मानव पूंजी निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

1. एक शिक्षित मनुष्य को अर्थव्यवस्था के लिए एक संपत्ति माना जा सकता है, दायित्व नहीं।
2. शिक्षा किसी व्यक्ति को आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकती है। यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है और सरकार की दक्षता बढ़ाता है।
3. यह गुणवत्ता और मात्रा के मामले में व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाता है।
4. क्योंकि शिक्षित होने से जहां व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वहीं समाज के प्रति चेतना भी विकसित होती है।
5. एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भी जागरूक होता है और इससे अंततः देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका-

मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य निम्नलिखित तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

1. यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो बीमारी से लड़ने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है।
2. स्वस्थ रहने से व्यक्ति के समग्र परिणाम में भी वृद्धि होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की कार्यक्षमता एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है।

3. किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे तौर पर उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में काम करने में अधिक समय व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार बेहतर स्वास्थ्य से कार्यक्षमता बढ़ेगी।

उपर्युक्त बिंदु साबित करते हैं कि यदि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के उपाय किए जाएं जिससे देश में एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो मानव पूंजी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

नोट: मनुष्य कई गतिविधियाँ करता है जिन्हें आर्थिक और गैर-आर्थिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।

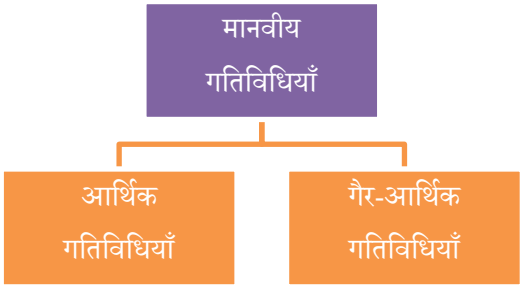

आर्थिक गतिविधियाँ: आर्थिक गतिविधियाँ मानव की उन गतिविधियों को संदर्भित करती हैं जो मौद्रिक लाभ के लिए या उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। श्रमिकों, किसानों, दुकानदारों, निर्माताओं, डॉक्टरों, वकीलों, टैक्सी चालकों आदि की गतिविधियाँ इस श्रेणी में आती हैं।

गैर-आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं जो किसी मौद्रिक लाभ के लिए नहीं की जाती हैं। इन्हें अवैतनिक गतिविधियाँ भी कहा जाता है। गृहिणियों द्वारा किये जाने वाले घरेलू कार्य गैर-आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं।

आर्थिक गतिविधियों के दो भाग होते हैं: बाज़ार गतिविधियाँ और गैर-बाज़ार गतिविधियाँ

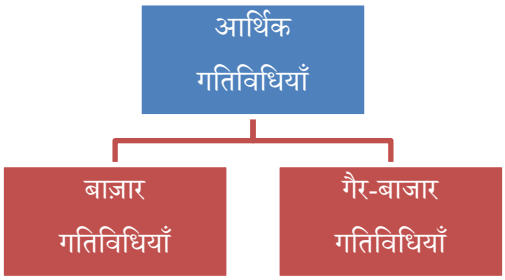

बाज़ार गतिविधियाँ: बाज़ार गतिविधियों में प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पारिश्रमिक शामिल होता है यानी, वेतन या लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधि। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है।

गैर-बाजार गतिविधियाँ: गैर-बाज़ार गतिविधियाँ स्व-उपभोग के लिए उत्पादन हैं

बाज़ार की गतिविधियाँ	**गैर-बाजार गतिविधियाँ**
बाज़ार गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं जो कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए की जाती हैं।	**गैर-बाजार गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं जो स्व-उपभोग के लिए की जाती हैं।**
ये गतिविधियाँ कुछ लाभ प्रदान करती हैं।	**ये गतिविधियाँ कोई लाभ नहीं देतीं।**
इन गतिविधियों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल है जो पैसे के लिए बाजार में बेचे जाते हैं	**इन गतिविधियों में उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल है जिनका उपभोग निर्माता या उसके परिवार द्वारा किया जाता है।**
उदाहरण के लिए, एक उद्योगपति जो स्टील का कारखाना चलाता है और उसे बाजार में बेचकर कुछ लाभ कमाता है।	**उदाहरण के लिए, एक छोटा किसान जो स्वयं उपभोग के लिए बगीचे जैसे छोटे भूखंड में विभिन्न सब्जियों की खेती करता है।**

किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक:

- शिक्षा और कौशल बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक हैं।
- अधिकांश महिलाओं के पास अल्प शिक्षा और कम कौशल निर्माण है।
- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।

जनसंख्या की गुणवत्ता:

- जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा द्वारा इंगित व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण पर निर्भर करती है।
- जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की विकास दर तय करती है।

- अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व है।
- साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या एक संपत्ति है

बेरोजगारी:

- बेरोजगारी तब कही जाती है जब जो लोग निर्धारित वेतन पर काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है।
- बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति हैं वे देनदारी में बदल जाते हैं।
- जब हम बेरोजगार लोगों की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों से होता है। बेरोजगारों की संख्या की गणना करते समय 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों पर विचार नहीं किया जाता है
- बेरोजगारी से आर्थिक अधिभार बढ़ता है। बेरोजगारों की कार्यशील जनसंख्या पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है।
- ग्रामीण क्षेत्र: मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी
- शहरी क्षेत्र: शिक्षित बेरोजगारी।

नोट: कार्यबल जनसंख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग शामिल हैं।

प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के बीच अंतर

- ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी दोनों के मामले हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी पाने में असमर्थ होता है। यह ज्यादातर उन किसानों के लिए होता है जो वर्ष के कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं जब कोई फसल नहीं उगाई जाती है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। जब कृषि भूमि पर काम करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में काम करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या से अधिक होती है, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण माना जाता है। यदि भूमि के एक टुकड़े पर काम करने के लिए केवल तीन लोगों की आवश्यकता है, बल्कि पांच लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो दो अतिरिक्त लोग छिपी हुई बेरोजगारी का एक उदाहरण हैं।

शिक्षित बेरोजगारी

- भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक आम घटना बन गयी है। भारत में मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम करने के योग्य मानती है। इससे युवा अकुशल और अंततः बेरोजगार हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के पास न केवल डिग्री हो बल्कि वह नौकरी पाने के लिए पर्याप्त कुशल भी हो।

बेरोजगारी के परिणाम:

- बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है।
- बेरोज़गारी आर्थिक अधिभार को बढ़ाती है यानी कामकाजी आबादी पर बेरोज़गारों की निर्भरता।
- बेरोजगारी के कारण सामाजिक अशांति और तनाव बढ़ सकता है।

CLASS 9

CHAPTER 3

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ गरीबी को समझना
- ✓ गरीबी रेखा
- ✓ गरीबी विश्लेषण
- ✓ सामाजिक बहिष्कार
- ✓ भेद्यता
- ✓ गरीबी के कारण
- ✓ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

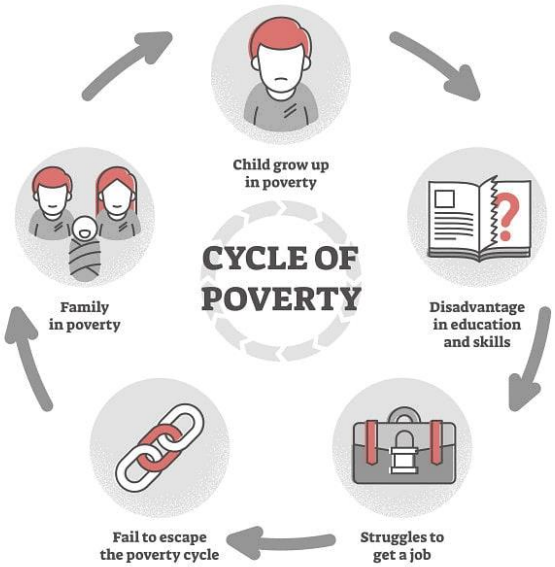

- स्वतंत्र भारत के सामने गरीबी सबसे कठिन चुनौती है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन के न्यूनतम मानकों का आनंद लेने के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों का अभाव होता है।
- गरीब लोग गांवों में भूमिहीन मजदूर, शहरों और कस्बों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर, बच्चे, ढाबों में काम करने वाले या भिखारी भी हो सकते हैं।
- तथ्यों के अनुसार भारत में हर चौथा व्यक्ति गरीब है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे।

गरीबी रेखा

- गरीबी रेखा आय या उपभोग स्तर के आधार पर गरीबी को मापने की एक विधि है। गरीबी रेखा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है।
- गरीबी रेखा उस रेखा को संदर्भित करती है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है जो लोगों को उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- एक व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक "न्यूनतम स्तर" से नीचे आता है।
- भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम स्तर की भोजन आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि के माध्यम से किया जाता है।
- इन भौतिक मात्राओं को रुपये में उनकी कीमतों से गुणा किया जाता है। भारत में गरीबी की गणना वांछित कैलोरी आवश्यकता के आधार पर की जाती है।
- भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 कैलोरी है।
- इन गणनाओं के आधार पर, वर्ष 2011-12 के लिए, एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित की गई थी।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों का संचालन करके गरीबी रेखा का अनुमान समय-समय पर (सामान्य रूप से हर पांच साल में) लगाया जाता है। यह भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है।

गरीबी विश्लेषण

- आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संकेतक आय और उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। लेकिन अब गरीबी को सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित अन्य सामाजिक संकेतकों के माध्यम से देखा जाता है।
- सामाजिक वैज्ञानिक अतीत की घटनाओं और उपलब्धियों से लेकर मानव व्यवहार और समूहों के बीच संबंधों तक समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं।
- सामाजिक वैज्ञानिक आय और उपभोग के स्तर के अलावा कई पहलुओं से गरीबी का विश्लेषण करते हैं।
- ये पहलू हैं -

– साक्षरता का ख़राब स्तर

– कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है

– स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव

– नौकरी के अवसरों की कमी

– स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव इत्यादि

सामाजिक बहिष्कार

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या समूहों को उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका आनंद अन्य (उनके "बेहतर") लेते हैं।
- इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यप्रणाली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से बाहर रखा जाता है। इससे कम आय की तुलना में अधिक गरीबी पैदा हुई।

भेद्यता

- गरीबी के प्रति संवेदनशीलता एक माप है, जो कुछ समुदायों (जैसे, पिछड़ी जाति या आदिवासी के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के गरीब बनने या बने रहने की अधिक संभावना का वर्णन करता है। आने वाले वर्षों में।
- संपत्ति, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में विभिन्न समुदायों के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों द्वारा भेद्यता का निर्धारण किया जाता है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय जिस समूह को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है उसे सुभेद्य समूह कहा जाता है।

कमजोर वर्ग

- सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं।
- आर्थिक समूहों में सबसे कमजोर समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार हैं।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आबादी के सामाजिक रूप से वंचित सामाजिक समूहों में भूमिहीन कैजुअल मजदूरी श्रमिक परिवार होने का दोहरा नुकसान, समस्या की गंभीरता को उजागर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा

- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा एक मौद्रिक सीमा है जिसके तहत किसी व्यक्ति को गरीबी में जीवन यापन करने वाला माना जाता है।
- इसकी गणना प्रत्येक देश से गरीबी सीमा को लेकर - एक वयस्क के भरण-पोषण के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को देखते हुए - और इसे डॉलर में परिवर्तित करके की जाती है।
- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $1.90 प्रति दिन है।

भारत में गरीबी के कारण

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर: औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया और कपड़ा जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया।

2. 1980 के दशक तक विकास की निम्न दर:

- इसके परिणामस्वरूप नौकरी के अवसर कम हुए और आय की वृद्धि दर कम हुई।

- इसके साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर भी थी।
- दोनों ने मिलकर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया।
- दोनों मोर्चों पर विफलता: आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या नियंत्रण ने गरीबी के चक्र को कायम रखा

3. सिंचाई एवं हरित क्रांति:

- सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति के साथ, कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा हुए।
- लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था

4. उद्योग:

- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने कुछ नौकरियाँ प्रदान कीं। लेकिन ये सभी नौकरी चाहने वालों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- शहरों में उचित नौकरियाँ न मिलने पर कई लोगों ने रिक्शा चालक, विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
- अनियमित छोटी आय के कारण, ये लोग महंगे आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।
- उन्होंने शहरों के बाहरी इलाकों में झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया और गरीबी की समस्या, जो काफी हद तक एक ग्रामीण घटना थी, शहरी क्षेत्र की विशेषता भी बन गई।

5. आय असमानताएँ:

- उच्च गरीबी दर की एक अन्य विशेषता भारी आय असमानताएं रही हैं।
- इसका एक प्रमुख कारण भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण है।
- भूमि सुधारों को ठीक से लागू नहीं किया गया है और पर्याप्त भूमि संसाधनों की कमी भी कई लोगों के गरीब होने का एक कारण है।
- छोटे किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि के लिए पैसे उधार लेते हैं और बाद में भुगतान करने में असफल हो जाते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऋणग्रस्तता का यह उच्च स्तर गरीबी का कारण और प्रभाव दोनों है।
- चूंकि भूमि संसाधनों की कमी भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण रही है, इसलिए नीति के उचित कार्यान्वयन से लाखों ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार हो सकता है।

गरीबी निवारण उपाय

गरीबी हटाना भारतीय विकासात्मक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान गरीबी-विरोधी रणनीति निम्नलिखित दो उद्देश्यों पर आधारित है

(i) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:

- सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। 1980 के दशक तक आर्थिक विकास कम था लेकिन तब से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है।
- उच्च आर्थिक विकास गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करता है। आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच मजबूत संबंध है।
- आर्थिक विकास अवसरों को बढ़ाता है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
- उच्च आर्थिक विकास लोगों को शिक्षा में निवेश से बेहतर आर्थिक रिटर्न की उम्मीद के साथ अपने बच्चों (लड़कियों सहित) को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- लेकिन फिर भी, ग्रामीण गरीब आर्थिक विकास का सीधा लाभ नहीं उठा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग गरीब बने हुए हैं

(ii) लक्षित गरीबी-विरोधी कार्यक्रम:

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)-**

  यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। प्रस्तावित नौकरियों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी।

  इसी प्रकार, राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के तहत, यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)**

  (पीडीएस) जो भोजन और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई, गरीबी उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह कार्यक्रम भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल और चीनी जैसी वस्तुओं का आवंटन।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए राशन कार्ड जारी करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान।
- भोजन की कमी का प्रबंधन और खाद्यान्न का वितरण।

  पीडीएस को बाद में जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लॉन्च किया गया था और इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीपीडीएस खाद्यान्न की उचित व्यवस्था और वितरण के लिए गरीबों की पहचान और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए, भारत सरकार के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) पीडीएस के समान ही भूमिका निभाती है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)**

- इसे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त शुरू किया गया था। एनआरएलएम का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रणाली बनाना है।
- जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।
- उस उद्देश्य के लिए, गरीबों को अपनी घरेलू आय बढ़ाने के लिए सशक्त और सक्षम बनाकर स्थायी अवसर पैदा करना है। गरीबों को आय-सृजित संपत्ति के अलावा - उन्हें अधिकारों, हकदारियों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- मिशन का उद्देश्य गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करना और उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना है। 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) कर दिया गया।

- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन**

- इसे 2013 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह स्वयं सहायता समूहों में शहरी गरीबों को संगठित करने, बाजार-आधारित रोजगार के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करने और ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके उन्हें स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित है।

- **प्रधानमंत्री जनधन योजना**

- इसे 2014 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना था और 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया। यह योजना विशेष रूप से बैंक रहित गरीबों को लक्षित करती है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना

- इसे 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था
- सभी के लिए आवास योजना झुग्गीवासियों के लिए आवास सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी। इसे भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
- इसका उद्देश्य शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पीने के पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ठोस और स्थायी आवास प्रदान करना है।

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)**
  - इसे 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने की परिकल्पना की गई है
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम), पोषण अभियान**
  - इसे 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - अल्प-पोषण के स्तर को कम करना और देश में बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाना। साथ ही, किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
  - इसे 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था
  - यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है।
- **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि**
  - इसे 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म-ऋण सुविधाएं प्रदान करना है

CLASS 9

CHAPTER 4

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ खाद्य सुरक्षा
- ✓ भूख
- ✓ बफर स्टॉक
- ✓ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
- ✓ राशन कार्ड
- ✓ गरीबी उन्मूलन योजनाएं
- ✓ एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

खाद्य सुरक्षा क्या है?

- खाद्य सुरक्षा का अर्थ है हर समय सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। गरीब लोग खाद्य असुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- खाद्य सुरक्षा कभी-कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सरकारी सतर्कता और कार्रवाई पर निर्भर करती है, जब इस सुरक्षा को खतरा होता है।

खाद्य सुरक्षा के आयाम

- भोजन की उपलब्धता: इसका अर्थ है देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अन्न भंडार में संग्रहीत पिछले वर्ष का स्टॉक।
- अभिगम्यता: इसका मतलब है कि भोजन सभी के लिए सुलभ है।
- सामर्थ्य: इसका मतलब है कि भोजन सभी के लिए किफायती है और एक व्यक्ति अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन खरीद सकता है।

किसी देश में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?

किसी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है:

- सभी के लिए भोजन की पर्याप्त उपलब्धता।
- भोजन स्वीकार्य गुणवत्ता का होना चाहिए और सभी व्यक्तियों के पास इसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए।
- भोजन की पहुंच पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है?

- प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए सूखा, के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन कम हो जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है।
- भोजन की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं।
- ऊंची कीमतों पर, कुछ लोग भोजन खरीदने में असमर्थ हैं।
- यदि ऐसी आपदा बहुत व्यापक क्षेत्र में घटित होती है या अधिक समय तक खिंचती है तो इससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- बड़े पैमाने पर भुखमरी अकाल में तब्दील हो सकती है

अकाल क्या है?

- अकाल भोजन की व्यापक कमी है, जो युद्ध, मुद्रास्फीति, फसल की विफलता, जनसंख्या असंतुलन या सरकारी नीतियों सहित कई कारकों के कारण होता है। यह घटना आमतौर पर क्षेत्रीय कुपोषण, भुखमरी, महामारी और बढ़ी हुई मृत्यु दर के साथ या उसके बाद आती है।

- बंगाल में 1943 का अकाल भारत का सबसे विनाशकारी अकाल था।
- मौतों की संख्या: बंगाल प्रांत में 30 लाख

'खाद्य-असुरक्षित' कौन हैं?

- भारत में बड़ी संख्या में लोग खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं, सबसे बुरी तरह प्रभावित समूह भूमिहीन लोग हैं जिनके पास निर्भर रहने के लिए बहुत कम या कोई जमीन नहीं है, पारंपरिक कारीगर और पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले, छोटे स्व-रोज़गार श्रमिक और भिखारी हैं।
- शहरी क्षेत्रों में प्रभावित श्रमिक वे हैं जो कम वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं।
- भोजन खरीदने में असमर्थता के साथ-साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य असुरक्षा में भूमिका निभाती है।
- एससी, एसटी और ओबीसी के कुछ वर्ग (उनमें से निचली जातियां) जिनके पास या तो खराब भूमि-आधार है या बहुत कम भूमि उत्पादकता है, वे खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं।
- महिलाओं में कुपोषण की घटना अधिक है। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चे को भी कुपोषण का खतरा रहता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा

- हरित क्रांति के बाद देश प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी अकाल से बचा है।
- पूरे देश में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है।
- उचित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

भूख:

- भूख खाद्य असुरक्षा का संकेत देने वाला एक और पहलू है।
- इसलिए खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में वर्तमान भूख को खत्म करना और भविष्य की भूख के जोखिमों को कम करना शामिल है।
- भूख के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं।

चिरकालिक भूख

- दीर्घकालिक भूख मात्रा और/या गुणवत्ता के मामले में लगातार अपर्याप्त आहार का परिणाम है।
- गरीब लोग अपनी बहुत कम आय के कारण दीर्घकालिक भूख से पीड़ित होते हैं और परिणामस्वरूप जीवित रहने के लिए भी भोजन खरीदने में असमर्थ होते हैं।

मौसमी भूख

- मौसमी भूख भोजन उगाने और कटाई के चक्र से संबंधित है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक श्रम के कारण प्रचलित है, उदाहरण के लिए, बरसात के मौसम में आकस्मिक निर्माण श्रमिकों के लिए कम काम होता है।
- इस प्रकार की भूख तब होती है जब किसी व्यक्ति को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है।

बफर स्टॉक-

- यह भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न का भंडार है।
- एफसीआई उन किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है और वे पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान करते हैं।
- इस पूर्व घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है।
- इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हर साल बुवाई के मौसम से पहले एमएसपी घोषित की जाती है।

सरकार द्वारा यह बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है?

- यह घाटे वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए किया जाता है जिसे निर्गम मूल्य भी कहा जाता है।
- इससे प्रतिकूल मौसम की स्थिति या आपदा की अवधि के दौरान भोजन की कमी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलती है।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम

- 1970 के दशक के मध्य में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने गरीबी स्तर की उच्च घटनाओं की सूचना दी। इसके कारण, तीन महत्वपूर्ण खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। वे हैं

– खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)।

– एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली-

- एफसीआई द्वारा खरीदा गया भोजन समाज के गरीब वर्ग के बीच सरकारी विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कहा जाता है।
- राशन की दुकानें अब अधिकांश इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में मौजूद हैं। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानों के नाम से भी जाना जाता है। इन दुकानों पर अनाज, चीनी, खाना पकाने के लिए तेल बाजार से सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार ये जरूरी सामान खरीद सकता है

– नोडल मंत्रालय - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

– पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है।

– केंद्र सरकार. एफसीआई के माध्यम से = खरीद + भंडारण + परिवहन + राज्य सरकारों को खाद्यान्न का आवंटन

– राज्य सरकारें = परिचालन जिम्मेदारियां + राज्य आवंटन + पात्र परिवारों की पहचान + राशन कार्ड जारी करना + उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी

- कवर की गई वस्तुएं (राज्य दर राज्य अलग-अलग) - गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल, दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले, आदि।

पीडीएस की कार्यप्रणाली

- चिन्हित लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदारियां साझा करती हैं।
- केंद्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदता है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचता है। यह प्रत्येक राज्य में अनाज को गोदामों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है।
- राज्य इन गोदामों से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जहां लाभार्थी कम केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है। कई राज्य लाभार्थियों को अनाज बेचने से पहले इसकी कीमत पर सब्सिडी देते हैं।

पीडीएस का महत्व

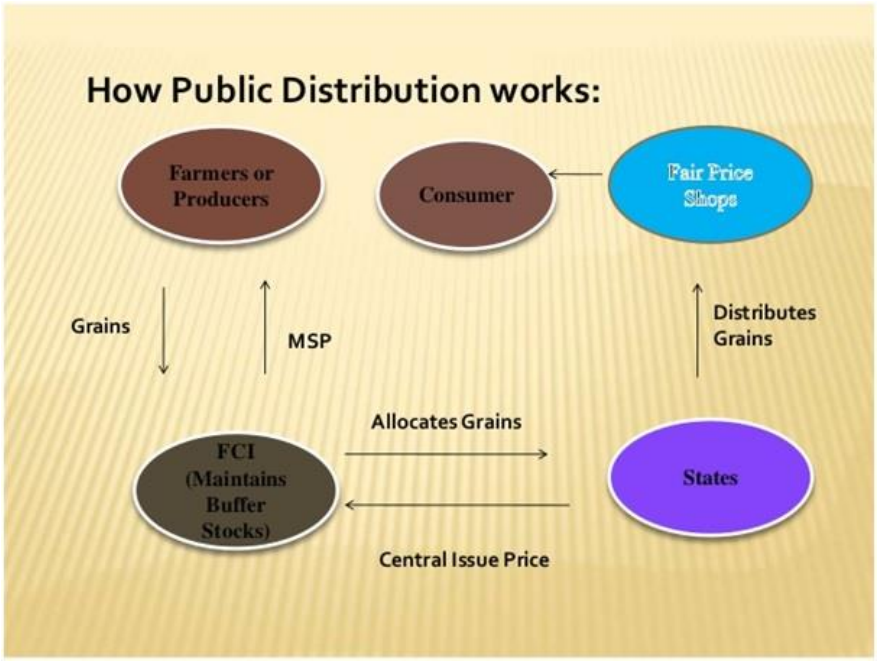

- खाद्य सुरक्षा के स्तंभों को मजबूत करके राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना
- खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करना
- भोजन का बफर स्टॉक बनाए रखें
- अनाज का पुनर्वितरण- देश के अधिशेष क्षेत्रों को अभावग्रस्त क्षेत्रों में।
- किसानों की आय को स्थिर करना

भारत में पीडीएस प्रणाली से जुड़े मुद्दे

- लाभार्थियों की पहचान: अध्ययनों से पता चला है कि टीपीडीएस जैसे लक्ष्यीकरण तंत्र में बड़े पैमाने पर समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, 2009 में गठित एक विशेषज्ञ समूह के अनुमान के अनुसार, पीडीएस लगभग 61% बहिष्करण और 25% लाभार्थियों को शामिल करने की त्रुटि से ग्रस्त है, यानी गरीबों का गैर-गरीब के रूप में गलत वर्गीकरण और इसके विपरीत।
- खाद्यान्न का रिसाव: (परिवहन रिसाव + एफपीएस मालिकों द्वारा कालाबाजारी) टीपीडीएस राशन की दुकानों से खुले बाजार में परिवहन के दौरान खाद्यान्न के बड़े रिसाव से पीड़ित है। टीपीडीएस के मूल्यांकन में, तत्कालीन योजना आयोग ने अखिल भारतीय स्तर पर पीडीएस चावल और गेहूं का 36% रिसाव पाया।
- सार्वजनिक सेवाओं तक ख़राब पहुँच -अक्षमता
- उदासीनता - गैर-जिम्मेदारी
- बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, 'एजेंटों और बिचौलियों' द्वारा जबरन वसूली - कमजोर जवाबदेही
- ढीली प्रणालियाँ और कमजोर सत्यनिष्ठा - विवेक का दुरुपयोग
- कमजोर नागरिक समाज - सुशासन की कम मांग
- खरीद से जुड़ा मुद्दा: ओपन-एंडेड खरीद यानी, बफर स्टॉक भरा होने पर भी आने वाले सभी अनाज को स्वीकार करना, खुले बाजार में कमी पैदा करता है।
- भंडारण से जुड़े मुद्दे: सीएजी के एक प्रदर्शन ऑडिट से सरकार की भंडारण क्षमता में गंभीर कमी का पता चला है। बढ़ती खरीद और अनाज सड़ने की घटनाओं को देखते हुए, पर्याप्त ढंके हुए भंडारण की कमी चिंता का विषय होना स्वाभाविक है।
- खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रावधान ने किसानों को गरीबों द्वारा खाए जाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन से भूमि को चावल और गेहूं की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और इस प्रकार, फसल विविधीकरण को हतोत्साहित किया है।
- पर्यावरणीय मुद्दे: खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता और अधिशेष प्राप्त करने पर अत्यधिक जोर, जो जल-गहन हैं, पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर पाया गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे खरीद राज्य पर्यावरणीय तनाव में हैं, जिसमें तेजी से भूजल की कमी, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और पानी की स्थिति खराब होना शामिल है।

राशन कार्ड के प्रकार

राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं:

1. सबसे गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड

2. गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बीपीएल कार्ड

3. अन्य सभी के लिए एपीएल कार्ड।

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)

- AAY दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किए गए बीपीएल परिवारों में से एक करोड़ सबसे गरीब लोगों की पहचान की गई थी। संबंधित राज्य ग्रामीण विकास विभागों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सर्वेक्षण के माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान की गई थी।
- प्रत्येक पात्र परिवार को 35 किलोग्राम मात्रा के साथ पच्चीस किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में अतिरिक्त 50 लाख बीपीएल परिवारों द्वारा इस योजना का दो बार विस्तार किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) 2007-08 में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था (i) क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि, (ii) मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना, (iii) रोजगार के अवसर पैदा करना और (iv) कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। एनएफएसएम के तहत 2014-15 से मोटे अनाज को भी मिशन में शामिल किया गया। एनएफएसएम के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में प्रथाओं के बेहतर पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों का बीज वितरण, कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मिट्टी सुधारक शामिल हैं। किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013

सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी तक कवरेज के उद्देश्य से जुलाई 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) लागू किया। अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक इसका जीवन चक्र दृष्टिकोण है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण के विशेष प्रावधान किए गए हैं।

- प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली मां स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद मुफ्त भोजन की हकदार हैं।
- छह महीने से छह साल की उम्र का प्रत्येक बच्चा स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से उम्र के अनुरूप निःशुल्क भोजन पाने का हकदार है।
- आठवीं कक्षा तक या छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में, जो भी लागू हो, स्थानीय द्वारा संचालित सभी स्कूलों में स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन एक मध्याह्न भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। निकाय, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय।
- राज्य सरकार स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से भी कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है।

आंगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1975 में बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का हिंदी में अर्थ है "आंगन आश्रय"।

वर्तमान में, राशन कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ केवल संबंधित राज्य के भीतर निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से ही उठा सकते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दूर करने और भूख की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना शुरू की है।

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

आईसीडीएस भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए आईसीडीएस को आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ा गया है।

खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका:

- भारत की खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में महत्वपूर्ण है।
- सहकारी समितियाँ गरीब लोगों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानें स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में चल रही सभी उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 94% दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं।
- नीचे दिखाए गए उदाहरण भारत की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए सहकारी समितियों की सफलता की कहानियां हैं। दिल्ली में, मदर डेयरी दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दर पर उपभोक्ताओं को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में प्रगति कर रही है।
- अमूल गुजरात में दूध और दूध उत्पादों में सहकारी समितियों की एक और सफलता की कहानी है। इससे देश में श्वेत क्रांति आई है।

याद रखने योग्य बातें

- सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है।
- जब खाद्य उत्पादन या वितरण में समस्या आती है तो गरीब परिवार को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।
- भारत में भोजन, सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सरकार की सतर्क और समय पर कार्रवाई पर निर्भर करती है।
- मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन एक आवश्यक वस्तु है। किसी राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है यदि उसके सभी नागरिकों के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध (उपलब्धता) हो, सभी व्यक्तियों के पास भोजन खरीदने की क्षमता हो और भोजन तक पहुंच (पहुंच) में कोई बाधा न हो।
- समाज का सबसे गरीब तबका ज्यादातर खाद्य असुरक्षित है और बेहतर स्थिति वाले लोगों को राष्ट्रीय आपदा और आपदा के दौरान खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे खाद्यान्न की कमी हो जाती है। बढ़ी हुई कीमत अंततः भुखमरी और अकाल की ओर ले जाती है।
- अकाल के दौरान महामारी दूषित पानी के जबरन उपयोग या सड़ने वाले भोजन और भूख से कमजोर होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण होती है।
- भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर, छोटे स्व-रोज़गार श्रमिक और भिखारियों सहित निराश्रित समूह भोजन और पोषण असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित समूह हैं।
- कम वेतन वाले व्यवसायों के श्रमिक और आकस्मिक मजदूर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित लोग हैं।
- कृषि मौसमी और कम भुगतान वाली गतिविधि है। भोजन खरीदने में असमर्थता के अलावा, सामाजिक संरचना (जैसे एससी, एसटीसी, ओबीसी आदि) की भी खाद्य असुरक्षा में भूमिका है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों, गरीबी की अधिकता वाले राज्यों, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे अधिक है।
- गरीबी और भुखमरी खाद्य असुरक्षा के आयाम हैं।
- भूख पुरानी या मौसमी हो सकती है। दीर्घकालिक भूख आय की कमी के कारण नियमित रूप से मात्रा और गुणवत्ता में कमी वाले आहार का परिणाम है।

- मौसमी भूख खाद्य उत्पादन और कटाई की मौसमी प्रकृति का परिणाम है जो भूमिहीन कृषि मजदूरों को सबसे अधिक प्रभावित करती है।
- हरित क्रांति के माध्यम से भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की।
- सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घटक शामिल हैं।
- बफर स्टॉक अधिशेष उत्पादक राज्य से घाटे वाले राज्यों और समाज के सबसे गरीब वर्ग को वितरण (पीडीएस के माध्यम से) के लिए सरकार द्वारा (एफसीआई के माध्यम से) खरीदा गया खाद्यान्न (गेहूं और चावल) का स्टॉक है।
- सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली पूर्व-घोषित कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कहा जाता है।
- जिस कीमत पर गरीब वर्ग के लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है उसे निर्गम मूल्य कहा जाता है।
- यह बाजार मूल्य से कम है। एफसीआई द्वारा समाज के गरीब वर्ग के बीच खरीदे गए भोजन के वितरण की प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कहा जाता है।
- राशन की दुकानें (जिन्हें उचित मूल्य की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है), लोगों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने के लिए खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का भंडार रखती हैं।
- पीडीएस के अलावा, खाद्य सुरक्षा के घटक वाले अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं:
- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस); काम के बदले भोजन (एफएफडब्ल्यू), मध्याह्न भोजन, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) आदि। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ-साथ विभिन्न सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन भी गहनता से काम कर रहे हैं। मदर डेयरी, अमूल, अनाज बैंकों को सफल और नवीन खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप माना जाता है

CLASS 10

CHAPTER 1

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ विकास को समझना
- ✓ विकास तुलना
- ✓ प्रति व्यक्ति आय
- ✓ मानव विकास
- ✓ सतत विकास

विकासात्मक अर्थशास्त्र

- विकासात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो लोगों, क्षेत्रों और देशों की आर्थिक, सामाजिक और मौद्रिक स्थितियों में सुधार से संबंधित है।
- यह गरीब देशों के अमीर और समृद्ध देशों में परिवर्तन का अध्ययन करता है।
- विकास के इस स्तर का अध्ययन और माप करते समय यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में स्थितियों में सुधार पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य, साक्षरता, कामकाजी परिस्थितियों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और बाजार स्थितियों जैसे कारकों का उपयोग करता है।
- विकास अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग जटिल और विविध है क्योंकि हर देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा अलग-अलग होती है।

विकास का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें हैं

- अलग-अलग लोगों की विकास के बारे में अलग-अलग धारणाएँ होती हैं क्योंकि व्यक्तियों की जीवन स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं और इसलिए उनकी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ और लक्ष्य अलग-अलग होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति का विकास शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के विकास से भिन्न होगा। हालाँकि ये इच्छाएँ, आवश्यकताएँ परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं।
- यानी एक व्यक्ति के विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में दूसरे की इच्छाओं से समझौता करना पड़ सकता है।
- बांध का विकास बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन यह उन आदिवासियों के लिए विनाशकारी होगा जिनके गांव डूब जाएंगे।

जो एक के लिए विकास हो सकता है, वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता।

विकास के लक्ष्य

विकास का उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है और इसे केवल मौद्रिक (आय) लक्ष्यों से अधिक भी पूरा करना होता है। इसे मापने के लिए हमें कुछ संकेतकों की आवश्यकता है जो हमें मापने में मदद करें:

- आय
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- समानता
- सुरक्षा
- आदर

- इनमें से कुछ कारकों को मापा जा सकता है, जबकि अन्य को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे विकास के महत्वपूर्ण संकेतक नहीं हैं। जैसे कि आप सुरक्षा की अवधारणा को कैसे मापेंगे? यह अलग-अलग ताकत वाले लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है!!
- निर्णय लेते समय आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने सभी विकल्पों पर विचार करें।
- उदाहरण के लिए, स्कूल बदलते समय आप न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बल्कि पर्यावरण और अन्य सुविधाएं जैसे खेल, पाठ्येतर गतिविधियाँ, अनुशासन आदि भी देखेंगे।
- इसी प्रकार, विकास को मापते समय हमें सभी लक्ष्यों के उचित मिश्रण पर विचार करके ऐसा करना होगा।
- जब एक महिला नौकरी करती है तो वह अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बन जाती है और इस प्रकार परिवार में उसका रुतबा और सम्मान भी बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपनी खर्च करने योग्य आय में वृद्धि चाहता है, बल्कि इसके साथ मिलने वाले अन्य लाभ जैसे गुणवत्तापूर्ण जीवन भी चाहता है।

भारत के लिए विकास लक्ष्य क्या होने चाहिए?

- क्या भारत में गरीब लोग हैं? - आय समानता (क्रय शक्ति)
- क्या भारत में सभी लोग शिक्षित हैं? - साक्षरता
- क्या भारत में सभी लोग स्वस्थ हैं? - जीवन प्रत्याशा
- क्या पर्यावरण प्रदूषण मुक्त है? - स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
- क्या सभी सामाजिक समूहों के साथ समान व्यवहार किया जाता है? - एससी, एसटी, महिलाओं और विकलांगों के लिए आरक्षण
- क्या भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है? - लैंगिक समानता

कई अन्य लक्ष्य भी हो सकते हैं और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारणाएँ होंगी और इन लक्ष्यों के प्रति उनकी प्राथमिकता भी अलग-अलग हो सकती है।

विकास तुलना-

- यदि विभिन्न देशों/क्षेत्रों/लोगों के अलग-अलग विकास लक्ष्य और परिभाषाएँ हैं, तो हम उनकी तुलना कैसे करते हैं?

- जब हम कहते हैं कि कोई देश विकसित, विकासशील या अविकसित है तो इसका क्या मतलब है?
- हम इन देशों को किसके दृष्टिकोण से वर्गीकृत करते हैं?

- उदाहरण के लिए, एक कक्षा में, एक छात्र जो पढ़ाई में अच्छा है, वह खेल में अच्छा नहीं हो सकता है, या जो बहुत सामाजिक है वह पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है। अलग-अलग छात्रों में अलग-अलग गुण और प्रतिभाएं होंगी, लेकिन ऐसे छात्र भी होते हैं जो अपने सभी लक्ष्यों को संतुलित करने में सक्षम होते हैं और कहा जाता है कि उनका समग्र विकास होता है।
- कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और हम इन विशेषताओं के आधार पर अपनी तुलना करते हैं। यह बात विकास के मापन पर भी लागू होती है।

विकास को मापने के लिए हम किन कारकों पर विचार करते हैं और उन्हें मापने के लिए किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है?

- आय - औसत आय, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति समता
- स्वास्थ्य - शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)
- शिक्षा - साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात

क्या हमें आय के संकेतक के रूप में कुल राष्ट्रीय आय या औसत आय का उपयोग करना चाहिए?

- आय के स्तर को मापने के लिए, सकल आय की तुलना में किसी क्षेत्र की औसत आय लेना वांछनीय है क्योंकि यह एक औसत व्यक्ति की क्रय शक्ति का पता लगाने में मदद करता है।
- उदाहरण के लिए; छोटा देश होने के कारण सिंगापुर की जीडीपी 350 अरब डॉलर है और भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। पूर्ण रूप से भारत की जीडीपी सिंगापुर की जीडीपी से अधिक है, लेकिन सिंगापुर की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है और इसलिए सिंगापुर में औसत आय बहुत अधिक है।
- इसलिए, देशों के बीच तुलना के लिए, कुल आय इतना उपयोगी उपाय नहीं है। चूंकि, देशों की आबादी अलग-अलग है, कुल आय की तुलना करने से हमें यह नहीं पता चलेगा कि एक औसत व्यक्ति कितना कमा सकता है।
- इसलिए, हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है
- विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट में, इस मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है।

2022 के अनुसार-

- कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को उन अर्थव्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी प्रति व्यक्ति आय (यहां- प्रति व्यक्ति जीएनआई) 2020 में $1,045 या उससे कम है;
- निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति जीएनआई $1,046 और $4,095 के बीच है; <भारत वर्तमान में इस श्रेणी में है>
- उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति जीएनआई $4,096 और $12,695 के बीच है;
- उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति GNI $12,696 या अधिक है।

मानव विकास से जुड़े कुछ प्रमुख शब्दों को समझना

औसत आय या प्रति व्यक्ति आय

⟶ यह देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि होती है।

⟶ औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है।

⟶ सभी देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना डॉलर में की जाती है ताकि इसकी तुलना की जा सके।

शिशु मृत्यु दर

⟶ शिशु मृत्यु दर (या आईएमआर) उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है।

साक्षरता दर

⟶ साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है।

शुद्ध उपस्थिति अनुपात

⟶ शुद्ध उपस्थिति अनुपात स्कूल जाने वाले 6-10 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है, जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या का प्रतिशत है।

मानव विकास रिपोर्ट

⟶ यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है

सकल नामांकन अनुपात

⟶ तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का अर्थ प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से परे उच्च शिक्षा के लिए नामांकन अनुपात है।

बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई)

- किसी के बॉडी मास इंडेक्स की गणना यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि कोई वयस्क कुपोषित है या नहीं।
- इसकी गणना किसी व्यक्ति के वजन (किलोग्राम में) को उसकी ऊंचाई (मीटर में) के वर्ग से जोड़कर की जाती है, जिसे किलोग्राम/वर्ग मीटर की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप द्रव्यमान किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर में होती है।
- यदि यह संख्या 18.5 से कम है तो व्यक्ति को कुपोषित माना जाता है। यदि यह बीएमआई 25 से अधिक है, तो व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है।

मानव विकास रिपोर्ट

मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला एचडीआर 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था।

प्रत्येक रिपोर्ट सूचकांकों का एक अद्यतन सेट भी प्रस्तुत करती है जैसे-

1. मानव विकास सूचकांक
2. असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक
3. लिंग विकास सूचकांक
4. लैंगिक असमानता सूचकांक
5. बहुआयामी गरीबी सूचकांक

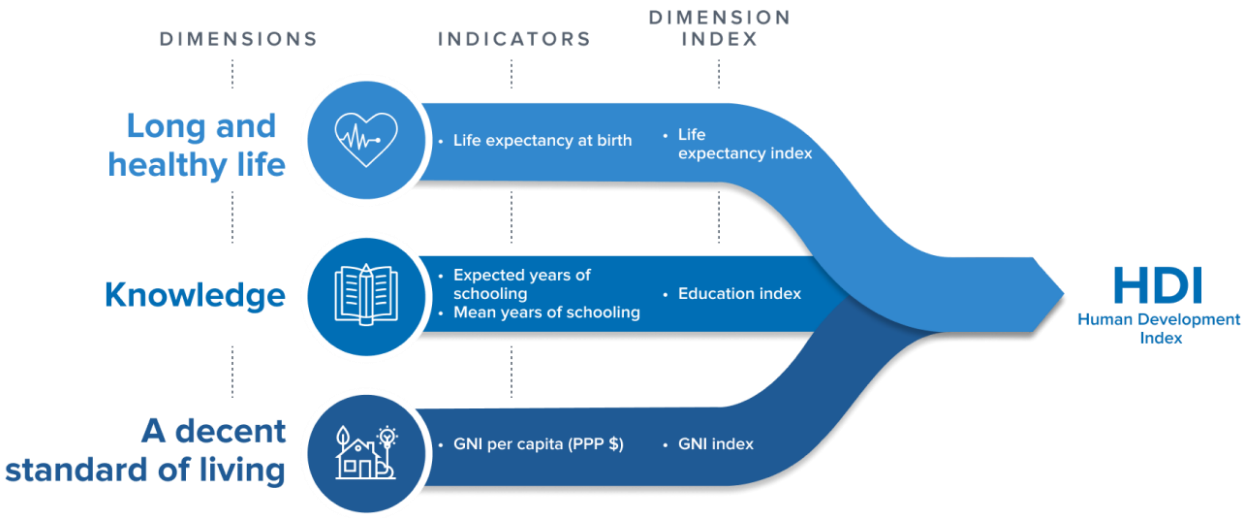

- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का एक सारांश माप है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन, जानकार होना और एक सभ्य जीवन स्तर होना। एचडीआई तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है।
- स्वास्थ्य आयाम का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है, शिक्षा आयाम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के आधार पर मापा जाता है। जीवन स्तर का आयाम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है।

सतत विकास

- इसका मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास है। यह विकास की प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करती है।

पर्यावरणीय स्थिरता:

- यह प्रकृति को संसाधनों के एक अटूट स्रोत के रूप में उपयोग करने से रोकता है और इसकी सुरक्षा और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करता है।
- पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, पानी की बचत, टिकाऊ गतिशीलता का समर्थन, और टिकाऊ निर्माण और वास्तुकला में नवाचार जैसे पहलू, कई मोर्चों पर पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में योगदान करते हैं।

सामाजिक स्थिरता:

- यह दुनिया भर में जीवन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उचित और उचित रूप से वितरित गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करने के लिए लैंगिक समानता, लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

आर्थिक स्थिरता:

- समान आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी के लिए धन पैदा करता है।
- निवेश और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण।
- गरीबी को उसके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करना।

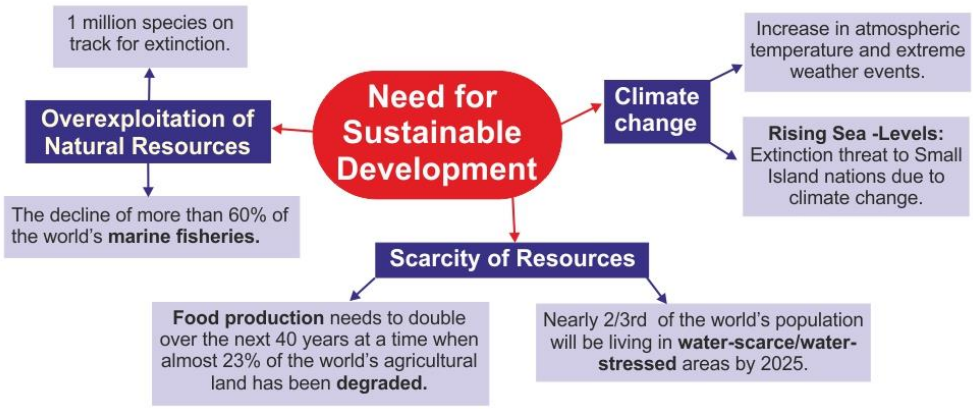

CLASS 10

CHAPTER 3

अध्याय 2 के विषय पहले से ही पिछले अध्यायों में शामिल हैं

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ पैसा और क्रेडिट
- ✓ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग
- ✓ वस्तु विनिमय प्रणाली
- ✓ बैंकों की ऋण गतिविधियाँ
- ✓ ऋण का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र
- ✓ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

पैसा क्या है?

- पैसा विनिमय का एक माध्यम है. कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है वह इसका उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए कर सकता है जिनकी उन्हें आवश्यकता या इच्छा हो सकती है।

वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है?

- जब पैसा अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था तब लोग एक-दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। खरीदार और विक्रेता को उन दोनों के पास मौजूद सामान का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होना होगा। इससे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न होती है।

- एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है वही दूसरा खरीदना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का सीधे आदान-प्रदान किया जाता है, जरूरतों का दोहरा संयोग एक आवश्यक विशेषता है

मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है?

- पैसा विनिमय का एक समान माध्यम प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है जो सभी के लिए स्वीकार्य है। यह विनिमय की प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है और इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है।

धन के प्रकार एवं रूप

- पहले मवेशी और अनाज का उपयोग धन के माध्यम के रूप में किया जाता था। जैसे-जैसे मनुष्यों ने धातुओं की खोज की और धातुओं को निकालने और संसाधित करने के बेहतर साधन पाए, हमने उन्हें धन के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। 100 साल पहले तक चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के जैसे धातु के सिक्कों का उपयोग माध्यम के रूप में किया जाता था।
- हाल ही में हमने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण आदि के माध्यम से डिजिटल लेनदेन पर हावी होने वाली नकदी रहित अर्थव्यवस्था के उद्भव को देखा है, जहां किसी भी मूर्त संपत्ति का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है।
- सरकारी तंत्र में विश्वास की कमी के साथ, हम बिटकॉइन, रिपल, एथेरियम आदि जैसी क्रिप्टो मुद्राओं को भी अपनाते हुए देख रहे हैं।

मुद्रा क्या है?

- मुद्रा - आधुनिक मुद्रा कीमती धातुओं से नहीं बनी है। मवेशियों और अनाज की तरह इसका अपना कोई उपयोग नहीं है।
- इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि यह सरकार द्वारा अधिकृत है। कानून के मुताबिक इसे भुगतान का माध्यम मानने से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसी मुद्रा को लीगल टेंडर या फिएट मनी कहा जाता है।
- भारत में करेंसी नोट RBI जारी करता है और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। आप एक रुपये को छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का चिन्ह देख सकते हैं। 1 नोट जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं.
- दूसरी ओर सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं

लोग बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं?

- हमें हर वक्त पैसों की जरूरत नहीं होती और हम इसे हर वक्त अपने साथ नहीं रख सकते। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हम अतिरिक्त पैसे बचा लेते हैं। यह पैसा हम अपने घर में या बैंक में बचाकर रख सकते हैं।
- बैंक बचत पर ब्याज प्रदान करता है और साथ ही जमा राशि को डकैती आदि से सुरक्षा भी प्रदान करता है।
- चूंकि बैंक खातों में जमा राशि को मांग पर निकाला जा सकता है, इसलिए इन जमाओं को मांग जमा कहा जाता है

बैंकों की ऋण गतिविधियाँ:

- बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं।
- बैंक जमा राशि के बड़े हिस्से का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं।

- विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग है।
- बैंक लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा राशि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, बैंक उन लोगों (जमाकर्ताओं) और जिन्हें इन निधियों की आवश्यकता है (उधारकर्ता) के बीच मध्यस्थता करते हैं।
- बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलते हैं।
- उधारकर्ताओं से जो शुल्क लिया जाता है और जमाकर्ताओं को जो भुगतान किया जाता है, उसके बीच का अंतर उनकी आय का मुख्य स्रोत है

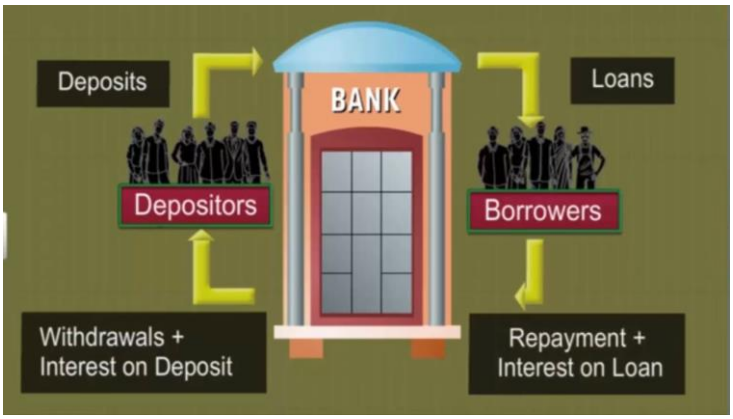

चेक

- चेक एक कागज है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक बनाया गया है।
- यह नकदी के उपयोग के बिना लेनदेन को निपटाने में मदद करता है।

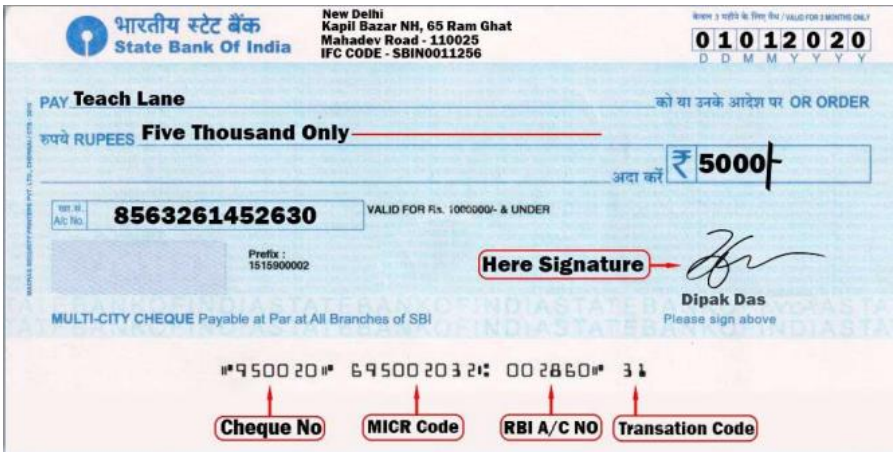

सावधि जमा क्या हैं?

- कुछ पैसे लोग भविष्य निधि, बीमा, आवर्ती जमा जैसी योजनाओं में बचाते हैं और निर्दिष्ट समय से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है। इन्हें टाइम डिपॉजिट कहा जाता है.
- हमें पता होना चाहिए कि सावधि जमा पर ब्याज > मांग जमा पर ब्याज।

क्रेडिट क्या है?

- जब ऋणदाता द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को एक समझौते के तहत धन/वस्तु/सेवाएं उधार दी जाती हैं तो उसे ऋण कहा जाता है।
- समझौते में आम तौर पर ऋण की शर्तें होती हैं जिसमें यह सूचीबद्ध होता है कि कितना पैसा उधार दिया जा रहा है, किस समय के लिए, ब्याज क्या होगा और भुगतान न करने की स्थिति में प्रावधान क्या होगा।

क्रेडिट की शर्तें क्या हैं?

- ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता, और पुनर्भुगतान का तरीका एक साथ मिलकर क्रेडिट की शर्तें कहलाती हैं। ऋण की शर्तें ऋणदाता या उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।
- क्रेडिट अपने उपयोग और क्रेडिट की शर्तों के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

ऋण की सकारात्मक भूमिका

- जब कोई उद्यमी या व्यवसायी क्रेडिट पर पैसा उधार लेता है, तो वह इसका उपयोग नई मशीनरी, कच्चे माल या सामान खरीदने के लिए पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है जो उसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- वह अपने मुनाफ़े से मिले पैसे का इस्तेमाल कर्ज़ चुकाने में कर सकता है. ऐसे में ऋण विकास में सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ऋण की नकारात्मक भूमिका

- जब कोई किसान बीज, सिंचाई और फसल के लिए पैसा उधार लेता है और खेती से आवश्यक उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह ऋण चुकाने में विफल रहता है और उसे ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ सकती है।
- इस मामले में, किसान की मदद करने के बजाय, ऋण ने नकारात्मक भूमिका निभाई और उसे उस स्थिति में धकेल दिया जहां से उबरना मुश्किल है।

संपार्श्विक

- संपार्श्विक एक संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास होती है (जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों के पास जमा राशि) और इसका उपयोग ऋण चुकाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में किया जाता है।
- यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति या संपार्श्विक बेचने का अधिकार है।
- संपत्ति जैसे भूमि का स्वामित्व, बैंकों के पास जमा राशि, लिव

क्रेडिट की शर्तें:

- ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता, और पुनर्भुगतान का तरीका एक साथ मिलकर क्रेडिट की शर्तें कहलाती हैं।
- क्रेडिट की शर्तें एक क्रेडिट व्यवस्था से दूसरी क्रेडिट व्यवस्था में काफी भिन्न होती हैं।
- वे ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं

ऋण का औपचारिक क्षेत्र

- बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण लिया जाता है
- क्रेडिट गतिविधि की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाती है
- ऋण के पुनर्भुगतान का कोई अनुचित साधन नहीं
- ब्याज दर कम है - जिससे उधार लेना सस्ता हो गया है
- परिणामस्वरूप, ब्याज की अदायगी के बाद उधारकर्ताओं के पास अधिक आय बच जाती है
- उधारकर्ता आसानी से कर्ज चुका सकते हैं

ऋण का अनौपचारिक क्षेत्र

- ऋण साहूकारों, रिश्तेदारों, व्यापारियों, दोस्तों आदि के माध्यम से लिया जाता है
- क्रेडिट गतिविधि की निगरानी आरबीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा नहीं की जाती है
- ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऋण शार्क जैसे अनुचित तरीके अपनाए जा सकते हैं
- ब्याज दर ऊंची है - जिससे उधार लेना महंगा हो गया है
- परिणामस्वरूप, ब्याज की अदायगी के बाद उधारकर्ताओं के पास कम या कोई आय नहीं बचती है
- उधारकर्ता कर्ज के जाल में फंस सकते हैं
- इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक और सहकारी समितियाँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ऋण बढ़ाएँ, ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो।
- औपचारिक क्षेत्र के लाभों के कारण, हमें बैंकों और सहकारी समितियों की अधिक आवश्यकता है। वे सस्ता ऋण प्रदान करते हैं जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है

स्वयं सहायता समूह क्या हैं?

- नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) स्व-सहायता समूहों को 'ग्रामीण गरीबों का एक समरूप समूह के रूप में परिभाषित करता है जो स्वेच्छा से अपनी कमाई से जो भी राशि बचा सकते हैं उसे बचाने के लिए बनाया जाता है और पारस्परिक रूप से योगदान और आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं के लिए सहमत होता है।'
- एक स्व-सहायता समूह को "समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और सामूहिक रूप से सामान्य उद्देश्य पूरा करने की इच्छा रखने वाले लोगों का स्व-शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समूह" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- एसएचजी सूक्ष्म स्तर पर स्वयं सहायता के लिए एक लघु स्वैच्छिक एजेंसी है, जिसका ध्यान कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाओं पर उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्रित किया गया है। इसलिए मूल रूप से, एसएचजी की अवधारणा "महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए" सिद्धांत पर आधारित है।
- स्व-सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो अपने रहने की स्थिति में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चुनते हैं। वे गरीबों, विशेषकर महिलाओं के बीच सामाजिक पूंजी बनाने में मदद करते हैं।

स्वयं सहायता समूहों के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं:

- अपने सदस्यों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना,
- उन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए एक सामूहिक योजना बनाने के लिए राजी करना, और
- औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को उन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करना।

- ऐसे समूह उन सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में काम करते हैं जो संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखते हैं। नतीजतन, स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म-वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। वित्तीय सेवाओं की श्रेणी में जमा, ऋण, धन हस्तांतरण और बीमा जैसे उत्पाद शामिल हो सकते हैं।
- एसएचजी में बहुत गरीब लोग शामिल हैं जिनकी औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच नहीं है। वे सदस्यों को एक-दूसरे को स्थान और समर्थन प्रदान करने के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। यह सदस्यों को समूह वातावरण में सहयोग करना और काम करना सीखने में भी सक्षम बनाता है।
- एसएचजी एक बचत तंत्र प्रदान करते हैं, जो सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। यह अपने सदस्यों को छोटे ऋण के लिए एक लागत प्रभावी वितरण तंत्र भी प्रदान करता है।
- एसएचजी गरीब महिलाओं को कुछ उत्पादक गतिविधियों में शामिल करके उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे बदले में उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ मिलेगा।

एसएचजी के उद्देश्य

- एसएचजी का मुख्य उद्देश्य बचत की आदत, बैंकिंग संस्कृति, यानी ऋण प्राप्त करना और एक निश्चित अवधि में उसे चुकाना और इस प्रक्रिया में, ऋण के माध्यम से फिर से आर्थिक समृद्धि पैदा करना है। एसएचजी ज्यादातर अनौपचारिक समूह होते हैं जिनके सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं और समूह के भीतर बारी-बारी से या आवश्यकता के आधार पर भरोसा करते हैं।

एसएचजी की उत्पत्ति और विकास:

- एसएचजी की शुरुआत वर्ष 1975 में बांग्लादेश में चटगांव विश्वविद्यालय के मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी। यह सामान्य रूप से गरीबी उन्मूलन, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम है।

- भारत में 1986-87 में इसकी शुरूआत का श्रेय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को जाता है। लेकिन असली प्रयास 1991-92 के बाद एसएचजी को बैंकों के साथ जोड़ने से हुआ।
- इस दिशा में पहली संगठित पहल 1954 में गुजरात में की गई थी जब अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टीएलए) ने मिल श्रमिकों के घरों की महिलाओं को सिलाई, बुनाई जैसे प्राथमिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए संगठित करने के लिए अपनी महिला विंग का गठन किया था। कढ़ाई, टाइपसेटिंग और आशुलिपि आदि।
- 1972 में, इसे और अधिक व्यवस्थित संरचना दी गई जब इला भट्ट के नेतृत्व में एक ट्रेड यूनियन के रूप में स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) का गठन किया गया। उन्होंने फेरीवालों, विक्रेताओं, बुनकरों, कुम्हारों, पापड़/अगरबत्ती बनाने वालों, मैनुअल मजदूरों, सेवा प्रदाताओं और पशुपालकों, नमक श्रमिकों, गोंद संग्राहकों, रसोइयों और विक्रेताओं जैसे छोटे उत्पादकों जैसे महिला श्रमिकों को संगठित किया, जिनका प्राथमिक उद्देश्य था:

– उनकी आय और संपत्ति में वृद्धि;

– उनके भोजन और पोषण मानकों को बढ़ाना; और

– उनकी संगठनात्मक और नेतृत्व शक्ति बढ़ाना।

– समग्र उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण रोजगार के लिए संगठित करना था।

- 1980 के दशक में, MYRADA - एक कर्नाटक स्थित गैर-सरकारी संगठन, ने कई स्थानीय रूप से गठित समूहों को बढ़ावा दिया ताकि सदस्यों को सामूहिक रूप से ऋण सुरक्षित करने और गतिविधियों के लिए अपनी बचत के साथ इसका उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके जो उन्हें आर्थिक रूप से लाभकारी रोजगार प्रदान कर सके।
- आज, देश के कुल बैंक-लिंक्ड एसएचजी का लगभग 44% चार दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हैं।
- नाबार्ड-बैंक लिंकेज कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40.95 मिलियन परिवारों और 204.75 मिलियन लोगों को शामिल किया गया है और 31-03-2007 तक संचयी ऋण का आंकड़ा 18040 करोड़ था।

एक एसएचजी के प्रमुख कार्य

- शोषणकारी ऋण से मुक्ति - ग्रामीण भारत में लोग अभी भी अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भर हैं। ये साहूकार झूठे समझौते करके, कागजों पर गलत रकम लिखकर, अत्यधिक ब्याज दरें वसूलकर और ऋण न चुकाने पर संपत्ति जब्त करके इन गरीब लोगों का शोषण करते हैं। स्वयं सहायता समूह इन लोगों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराते हैं।
- सामूहिक गारंटी प्रणाली - उन सदस्यों के लिए जो संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखते हैं। गरीब अपनी बचत इकट्ठा करके बैंकों में जमा करते हैं। बदले में उन्हें अपना सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त होती है।
- नेतृत्व विकास: एसएचजी ग्रामीण लोगों को उनकी संबंधित गतिविधियों के लिए नेता के रूप में कार्य करने के लिए संगठनात्मक मंच प्रदान करते हैं। एसएचजी गतिशील नेतृत्व प्रदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कौशल सेट के अनुसार नेतृत्व करने का मौका मिलता है। उदाहरण: अकेले आंध्र प्रदेश में 1,40,000 महिला नेता तैयार हुईं।
- सामाजिक अखंडता-एसएचजी दहेज, शराब आदि जैसी प्रथाओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- लिंग समानता-एसएचजी महिलाओं को सशक्त बनाता है और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करता है। सशक्त महिलाएँ ग्राम सभा और चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।
- दबाव समूह - शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें दहेज, शराब, खुले में शौच के खतरे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे मुद्दों को उजागर करने और नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।
- हाशिये पर पड़े वर्ग के लिए आवाज- सरकारी योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से हैं और इसलिए एसएचजी के माध्यम से उनकी भागीदारी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है
- बचत - सभी एसएचजी सदस्य नियमित रूप से एक छोटी राशि बचाते हैं। राशि छोटी हो सकती है, लेकिन बचत सभी सदस्यों की नियमित और निरंतर आदत होनी चाहिए।
- "पहले बचत - बाद में ऋण" प्रत्येक एसएचजी सदस्य का आदर्श वाक्य होना चाहिए।

- आंतरिक उधार - एसएचजी को सदस्यों को ऋण देने के लिए बचत राशि का उपयोग करना चाहिए। उद्देश्य, राशि, ब्याज दर, पुनर्भुगतान की अनुसूची आदि समूह द्वारा ही तय की जानी है।
- वित्तीय समावेशन - एसएचजी ने देश भर में लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं को संगठित किया है। 40.95 मिलियन परिवारों और 204.75 मिलियन लोगों को नाबार्ड-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है और 31-03-2007 तक संचयी ऋण का आंकड़ा 18040 करोड़ है।
- आवास और स्वास्थ्य पर प्रभाव - एसएचजी के माध्यम से प्राप्त वित्तीय समावेशन से बाल मृत्यु दर में कमी आई है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और गरीबों में बेहतर पोषण, आवास और स्वास्थ्य के माध्यम से बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ी है - खासकर महिलाओं और बच्चों में।
- बैंकिंग साक्षरता - यह अपने सदस्यों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती है और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को उन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है।

CLASS 10

CHAPTER 4

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ विदेश व्यापार
- ✓ संयुक्त उद्यम
- ✓ बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी)
- ✓ वैश्वीकरण
- ✓ वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान

विदेश व्यापार

- विदेशी व्यापार देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम रहा है। रेशम मार्ग जैसे व्यापार मार्ग भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम दोनों बाजारों से जोड़ते थे।
- व्यापारिक हितों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया।
- विदेशी व्यापार उत्पादकों के लिए घरेलू बाज़ारों से आगे तक पहुँचने का अवसर पैदा करता है
- खरीदारों के लिए, दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं का आयात घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं से परे वस्तुओं की पसंद का विस्तार करने का एक तरीका है।
- व्यापार खुलने से माल एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक जा सकता है।
- बाज़ारों में वस्तुओं की पसंद बढ़ती है। दोनों बाजारों में समान वस्तुओं की कीमतें बराबर हो जाती हैं।
- इस प्रकार विदेशी व्यापार के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ा जाता है या बाजारों का एकीकरण किया जाता है।
- देशों के बीच अधिक से अधिक सामान और सेवाएँ, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है।
- बेहतर आय, बेहतर नौकरी या बेहतर शिक्षा की तलाश में लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना-जाना होता है।

बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs):

- MNC एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकें।
- ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उत्पादन लागत कम हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक मुनाफा कमा सकें।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादन का विकेंद्रीकरण क्यों करती हैं?

- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उत्पादन लागत कम हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक मुनाफा कमा सकें।
- उत्पादन को अधिकाधिक जटिल तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ न केवल विश्व स्तर पर तैयार उत्पाद बेचती हैं, बल्कि विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं।
- उत्पादन प्रक्रिया को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया गया है और दुनिया भर में फैलाया गया है।
- कंपनियाँ विशेष राष्ट्रों की ताकत के आधार पर विभिन्न देशों में इकाइयाँ स्थापित करती हैं।
- उदाहरण के लिए, चीन और वियतनाम उत्पादन के लिए सस्ते श्रम बाजार होने का लाभ प्रदान करते हैं जबकि भारत को शिक्षित और कुशल अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं का लाभ मिलता है।
- सामान्य तौर पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां उत्पादन स्थापित करती हैं जहां यह बाजारों के करीब होता है; जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो; और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ऐसी सरकारी नीतियों की तलाश कर सकती हैं जो उनके हितों का ध्यान रखती हों।
- विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों को उत्पादन के ऑर्डर देती हैं। उत्पादों की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को की जाती है, जो बाद में इन्हें अपने ब्रांड नाम के तहत ग्राहकों को बेचती हैं।
- भूमि, भवन, मशीनें और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। कई शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विकासशील देश की सरकारों के पूरे बजट से अधिक संपत्ति है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना उत्पादन निम्नलिखित तरीकों से फैला सकती हैं: स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करके, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का उपयोग करके, स्थानीय कंपनियों के साथ निकटता से प्रतिस्पर्धा करके या उन्हें खरीदकर, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन दूर स्थित स्थानों पर उत्पादन पर एक मजबूत प्रभाव डाल रही हैं। .
- परिणामस्वरूप, इन व्यापक रूप से फैले हुए स्थानों में उत्पादन आपस में जुड़ रहा है।

संयुक्त उद्यम

- कभी-कभी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन देशों की कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं।

स्थानीय कंपनी को लाभ:

- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अतिरिक्त निवेश के लिए धन उपलब्ध करा सकती हैं, जैसे तेज़ उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदना।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने साथ उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक ला सकती हैं।

विदेशी कंपनी को लाभ:

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और फिर उत्पादन का विस्तार करना है।
- उदाहरण: वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया जा रहा है

वैश्वीकरण:

- वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर्संबंध की यह प्रक्रिया है। यह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के एकीकरण को संदर्भित करता है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।
- देशों के बीच अधिक से अधिक सामान और सेवाएँ, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमारी दुनिया काफी बदल गई है। प्रौद्योगिकी में बदलाव ने परिवहन और संचार को और अधिक कुशल बना दिया है, जिससे हम कहीं भी किसी से भी जुड़ सकते हैं।
- बीसवीं सदी के मध्य तक, उत्पादन बड़े पैमाने पर देशों के भीतर ही आयोजित किया जाता था।
- भारत जैसे उपनिवेश कच्चे माल और खाद्य सामग्री का निर्यात करते थे और तैयार माल का आयात करते थे। व्यापार दूर देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम था।

भारत ने शुरू में विदेशी व्यापार पर बाधाएँ क्यों लगाईं?

1. आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और निवेश पर रुकावटें डाल दी थीं। ऐसा देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था। उद्योग 1950 और 1960 के दशक में ही आ रहे थे और उस स्तर पर आयात से प्रतिस्पर्धा ने इन उद्योगों को विकसित होने और विकसित होने की अनुमति नहीं दी होगी। केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के आयात की अनुमति थी।
2. योजनानुसार देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले उद्योगों में विदेशी घुसपैठ से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। भारत विश्व बाजार में मुख्य उद्योगों के बराबर पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहता था और इसलिए उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी प्रगति पर अतिरिक्त नजर रखनी थी और अधिक तेजी से बढ़ते उद्योगों को राजकोषीय टैरिफ और अन्य माध्यमों से प्रोत्साहन देना था। 1991 के आसपास, भारत सरकार द्वारा नीति में कुछ बदलाव किए गए क्योंकि यह निर्णय लिया गया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है।

वे कारक जिन्होंने वैश्वीकरण को सक्षम बनाया

1. प्रौद्योगिकी

- पिछले पचास वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में कई सुधार हुए हैं। इससे कम लागत पर लंबी दूरी तक माल की अधिक तेजी से डिलीवरी संभव हो गई है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में विकास ने लोगों को दुनिया भर में एक-दूसरे से संपर्क करने, तुरंत जानकारी तक पहुंचने और दूरदराज के क्षेत्रों से संचार करने की अनुमति दी है।
- उपग्रह संचार उपकरणों द्वारा इसे सुगम बनाया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी ने सेवाओं के उत्पादन को विभिन्न देशों में फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीकांफ्रेंस दुनिया भर में लगातार लंबी यात्राओं को बचाने में मदद करती हैं। ऑर्डर दिए जाते हैं और भुगतान इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

2. विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण

- सरकारें विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने (विनियमित) करने और यह तय करने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग कर सकती हैं कि किस प्रकार का सामान और प्रत्येक का कितना हिस्सा देश में आना चाहिए।
- आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर बाधाएँ डाल दी थीं।
- देश के भीतर के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए इसे आवश्यक माना गया।
- उस स्तर पर आयात से प्रतिस्पर्धा ने इन उद्योगों को उभरने की अनुमति नहीं दी होगी।
- भारत ने केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि के आयात की अनुमति दी।
- 1991 में आर्थिक संकट के बाद विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर लगी बाधाएँ काफी हद तक दूर हो गईं।

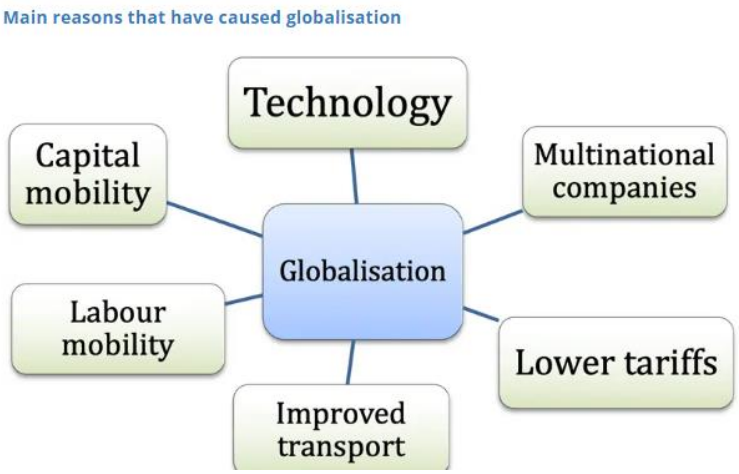

- इसका मतलब था कि वस्तुओं का आयात और निर्यात आसानी से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थीं।
- सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है।
- सरकार अब पहले की तुलना में बहुत कम प्रतिबंध लगाती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है।

वैश्वीकरण के लाभ

1. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

- दुनिया भर में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हमारे लिए अच्छा है। समझौते के माध्यम से कोई भी देश प्रौद्योगिकी उधार ले सकता है और अपने समग्र विकास के लिए इसे अपने देश में लागू कर सकता है। हम न्यूनतम लागत, समय और प्रयास पर उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दुनिया के किसी भी हिस्से से एक-दूसरे से आसानी से संवाद कर सकते हैं।

2. बेहतर सेवाएँ

- वैश्वीकरण हमें सदैव बेहतर सेवाएँ प्रदान करता है। तकनीकी प्रगति के माध्यम से हमारी सेवाएँ जैसे जल आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्किंग, इंटरनेट, बिजली आपूर्ति और अन्य सेवाएँ पहले की तुलना में आसान और बेहतर हो गई हैं। वैसे, दुनिया भर में इंटरनेट की आसान पहुंच भी वैश्वीकरण का ही परिणाम है।

3. जीवनयापन का मानकीकरण

- वैश्वीकरण की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण देशों को गरीबी से लड़ने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाता है।
- कई शोधकर्ताओं ने कहा है कि जब कोई देश अपने व्यापार को दुनिया के लिए खोलता है, तो उनकी आर्थिक विकास दर तेज होती है और जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

4. बुनियादी ढांचे का विकास

- तकनीकी प्रगति और दुनिया भर में इसके स्थानांतरण के कारण देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। देश लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में अधिक सक्षम हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास का मतलब संबंधित देशों का समग्र विकास है। यहां यह कहना जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे का विकास एक-दूसरे के अनुकूल हैं।

5. विदेशी मुद्रा भंडार

- वैश्वीकरण के माध्यम से देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण कर सकते हैं।

6. आर्थिक विकास

- वैश्वीकरण में संसाधनों का अधिकतम उपयोग शामिल है जिसमें घाटे वाले संसाधनों की खरीद की जाती है और अधिशेष संसाधनों को अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। यह समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है।

7. किफायती उत्पाद

- नवीनतम तकनीक तक पहुंच के साथ, देश अपने देशवासियों को किफायती कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और प्रतिस्पर्धा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के उनके प्रयास को बढ़ावा देता है, कंपनियां उत्पाद की कीमत कम करती हैं या प्रवेश मूल्य निर्धारण रणनीति का पालन करती हैं।

8. विश्व जीडीपी विकास दर में योगदान

- वैश्वीकरण विश्व सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रत्येक देश का योगदान सुनिश्चित करता है।

9. बाज़ार का विस्तार

- सबसे बढ़कर, वैश्वीकरण बाज़ार के विस्तार को बढ़ावा देता है। यह घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर जाने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, घरेलू स्तर पर कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं की मांग में संतृप्ति देख सकती हैं लेकिन वैश्वीकरण के माध्यम से घरेलू कंपनियां विदेशी ग्राहकों की बढ़ती मांगों को बनाए रख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं।

वैश्वीकरण के नुकसान:

1. बेरोजगारी दर का बढ़ना

- इससे दूसरे देश में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण मूल देश से नौकरियों की आउटसोर्सिंग हो सकती है। वैश्वीकरण सस्ती कीमत पर उच्च-कुशल कार्य की मांग करता है। लेकिन जिन देशों में संस्थाएं अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं, वे उच्च कुशल श्रमिक पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप उन देशों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है।

2. व्यापार असंतुलन

- व्यापार संतुलन का तात्पर्य किसी देश के निर्यात और आयात की वस्तुओं और सेवाओं के बीच मूल्यों के संतुलन से है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, कोई भी देश विश्व के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकता है। इसीलिए, कुछ मामलों में विकासशील देश आयातित वस्तुओं के मामले में विकसित देशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन उनकी निर्यात क्षमताएँ आयात की तुलना में कम हैं।

3. बढ़ती असमानता

- वैश्वीकरण विशेषज्ञता और व्यापार को बढ़ाकर दुनिया भर में असमानता बढ़ा सकता है। यद्यपि विशेषज्ञता और व्यापार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यह सापेक्ष गरीबी का कारण बन सकते हैं।
- इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। दुनिया में सभी प्रभुत्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ये सभी कंपनियां अपने उत्पाद निर्माण या असेंबलिंग के लिए विकासशील या अविकसित देशों से सस्ता श्रम खरीद रही हैं। चीन, भारत और अफ्रीका इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इससे ऐसे देशों में रोज़गार तो बढ़ता है लेकिन वे अपेक्षाकृत विकसित देशों से पीछे रह जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा।

4. पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औद्योगीकरण की गति बढ़ रही है। औद्योगीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है लेकिन यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है। वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान बुनियादी ढांचे के विकास के कारण होता है माल के बढ़ते परिवहन के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और अन्य प्रकार का प्रदूषण
- आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं. कोका-कोला विश्व की अग्रणी शीतल पेय कंपनी है। यह कंपनी शीतल पेय बनाने में भारी मात्रा में पानी की खपत करती है। उत्तरी भारत के एक राज्य, उत्तर प्रदेश में, स्थानीय किसानों द्वारा दावा किए गए पानी के बहुत अधिक उपयोग के कारण सरकारी आदेश द्वारा कोका-कोला बोतल संयंत्र को बंद कर दिया गया था।

CLASS 10

CHAPTER 5

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ उपभोक्ता अधिकार
- ✓ कंज्यूमर इंटरनेशनल (सी आई)
- ✓ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
- ✓ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो भुगतान करने के बाद बाजार से कोई वस्तु या सेवा खरीदता है और उसका उपयोग करता है।

कुछ सामान्य तरीके जिनसे निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा सकता है:

- कम वजन और कम माप: बाजार में बेचे जाने वाले सामान को कभी-कभी सही ढंग से मापा या तौला नहीं जाता है।
- ऊँची कीमतें: अक्सर व्यापारी निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलते हैं।
- निम्न-मानक गुणवत्ता: बेचे गए सामान कभी-कभी निम्न-मानक गुणवत्ता के होते हैं, उदाहरण के लिए, समाप्ति तिथि से अधिक समय पर दवाएं बेचना, ख़राब या दोषपूर्ण घरेलू उपकरण बेचना।
- डुप्लीकेट वस्तुएं: असली पार्ट्स या सामान के नाम पर नकली या डुप्लीकेट वस्तुएं बेची जाती हैं।
- मिलावट और अशुद्धता: अधिक मुनाफा कमाने के लिए तेल, घी और मसालों जैसी महंगी खाद्य वस्तुओं में मिलावट आम बात है। इससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होता है.
- सुरक्षा उपकरणों की कमी: स्थानीय स्तर पर उत्पादित नकली या घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत उपकरण या अन्य उपकरणों में आवश्यक अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इससे दुर्घटना हो सकती है.
- कृत्रिम अभाव: कुछ बेईमान व्यवसायी जमाखोरी करके कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। वे उपभोक्ताओं के बीच घबराहट पैदा करके अपना सामान अधिक कीमत पर बेचते हैं।
- विक्रेताओं द्वारा गलत और अधूरी जानकारी प्रदान की जाती है जो उपभोक्ताओं को आसानी से गुमराह कर सकती है।
- असंतोषजनक बिक्री के बाद सेवा: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इत्यादि जैसी वस्तुओं पर आवश्यक भुगतान के बावजूद आपूर्तिकर्ता संतोषजनक बिक्री के बाद सेवा प्रदान नहीं करते हैं।
- कंज्यूमर्स इंटरनेशनल: यह उपभोक्ता वकालत समूहों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1960 को हुई थी और वर्तमान में 220 से अधिक देशों के 240 से अधिक सदस्य संगठन (विभिन्न एजेंसियां और गैर सरकारी संगठन) हैं।

सीआई 8 बुनियादी उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है:

1. असुरक्षित उत्पादों से सुरक्षा का अधिकार
2. उत्पाद जानकारी का अधिकार
3. उत्पाद विकल्पों की एक श्रृंखला का अधिकार
4. सरकारी नीति में प्रतिनिधित्व का अधिकार
5. बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों का अधिकार
6. असंतोषजनक उत्पादों से संबंधित शिकायतों के निवारण का अधिकार

7. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और
8. ऐसे पर्यावरण का अधिकार जो मानव कल्याण के लिए खतरा न हो।

- सीआई अपने सदस्य संगठनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्य करता है, और यह कॉर्पोरेट जवाबदेही को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के लिए अभियान चलाता है।
- उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए, समूह उत्पाद-सुरक्षा मुद्दों और बाज़ार में दुरुपयोग पर शोध भी प्रकाशित करता है।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जॉन एफ कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए उपभोक्ता अधिकारों पर दिए गए भाषण से प्रेरित था। वह उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले पहले विश्व नेता थे।
- कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के कार्यकर्ता अनवर फज़ल ने बाद में इस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रस्तावित किया। हालाँकि, भारत हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। यह उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA), 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और यह प्रभाव में आया था।
- 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को बदलने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अगस्त 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

नये अधिनियम की आवश्यकता:

- डिजिटल युग ने वाणिज्य और डिजिटल ब्रांडिंग के एक नए युग के साथ-साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं के एक नए समूह की शुरुआत की है। डिजिटलीकरण ने आसान पहुंच, विकल्पों की एक विशाल विविधता, सुविधाजनक भुगतान तंत्र, बेहतर सेवाएं और सुविधा के अनुसार खरीदारी प्रदान की है। हालाँकि, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं।
- डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली नई चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए, भारतीय संसद ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पारित किया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का समय पर और प्रभावी प्रशासन और निपटान प्रदान करना है।

2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुख्य प्रावधान

उपभोक्ता की नई परिभाषा:

- नए अधिनियम ने 'उपभोक्ता' की परिभाषा को व्यापक बना दिया है।

उपभोक्ता की परिभाषा:

- अधिनियम के अनुसार, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो सेवाओं का लाभ उठाता है और स्वयं के उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लेता है, तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता है। यह परिभाषा टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से सभी प्रकार के लेनदेन यानी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन को कवर करती है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

- अधिनियम एक नियामक प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और कार्यान्वयन करेगा और अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा।
- CCPA को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं:
    - सीसीपीए को स्वत: कार्रवाई करने, उत्पादों को वापस लेने, वस्तुओं/सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश देने, लाइसेंस रद्द करने, जुर्माना लगाने और क्लास-एक्शन सूट दायर करने का अधिकार होगा।
    - सीसीपीए के पास उपभोक्ता कानून के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच या जांच करने के लिए एक जांच विंग होगा।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:

- अधिनियम में उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) या फोरम की स्थापना का प्रावधान है।
- अधिसूचित नियमों के अनुसार, राज्य आयोग रिक्तियों, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मामलों पर तिमाही आधार पर केंद्र सरकार को जानकारी प्रदान करेंगे।

सीडीआरसी निम्नलिखित से संबंधित शिकायतों पर विचार करेंगे:

- ओवरचार्जिंग या भ्रामक चार्जिंग
- अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ
- खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है।
- दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री

शिकायतों की ई-फाइलिंग:

- नया अधिनियम उपभोक्ता को उपभोक्ता के निवास स्थान या कार्यस्थल पर स्थित क्षेत्राधिकार वाले उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल स्थापित किया है।
- यह पहले की स्थिति के विपरीत है जहां उपभोक्ता को खरीद के स्थान पर या जहां विक्रेता का पंजीकृत कार्यालय का पता है, शिकायत दर्ज करनी होती थी।
- नए अधिनियम में उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों की सुनवाई और/या जांच करने के लिए सक्षम प्रावधान भी शामिल हैं।
- उपभोक्ताओं को अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

उत्पाद दायित्व और दंडात्मक परिणाम:

- अधिनियम ने उत्पाद दायित्व की अवधारणा पेश की है।
  - एक निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता अब दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं में कमी के कारण होने वाली चोट या क्षति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा।
- यह प्रावधान मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को अपने दायरे में लाता है। 'उत्पाद विक्रेता' शब्द में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल होंगे।

भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड:

- सीसीपीए झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या समर्थनकर्ता पर जुर्माना लगा सकता है। सीसीपीए उन्हें कारावास की सजा भी दे सकता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान का प्रावधान:

- नया अधिनियम वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान करता है। मध्यस्थता के लिए नियमों में सख्त समयसीमा तय की जाएगी.
- हाल ही में अधिसूचित नियमों के अनुसार, एक शिकायत को उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जहां भी शीघ्र निपटान की गुंजाइश मौजूद है और पक्ष इसके लिए सहमत हैं। मध्यस्थता उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में स्थापित की जाने वाली मध्यस्थता कोशिकाओं में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के जरिए समझौते के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी.
- इससे न केवल विवाद को निपटाने में शामिल पक्षों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि मामलों की कुल लंबितता को कम करने में भी मदद मिलेगी।

अनुचित व्यापार आचरण:

- नए अधिनियम ने अधिकारियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी सशक्त बनाया है।

- अधिनियम अनुचित व्यापार प्रथाओं की एक व्यापक परिभाषा पेश करता है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा विश्वास में दी गई व्यक्तिगत जानकारी को साझा करना भी शामिल है, जब तक कि ऐसा खुलासा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता है।

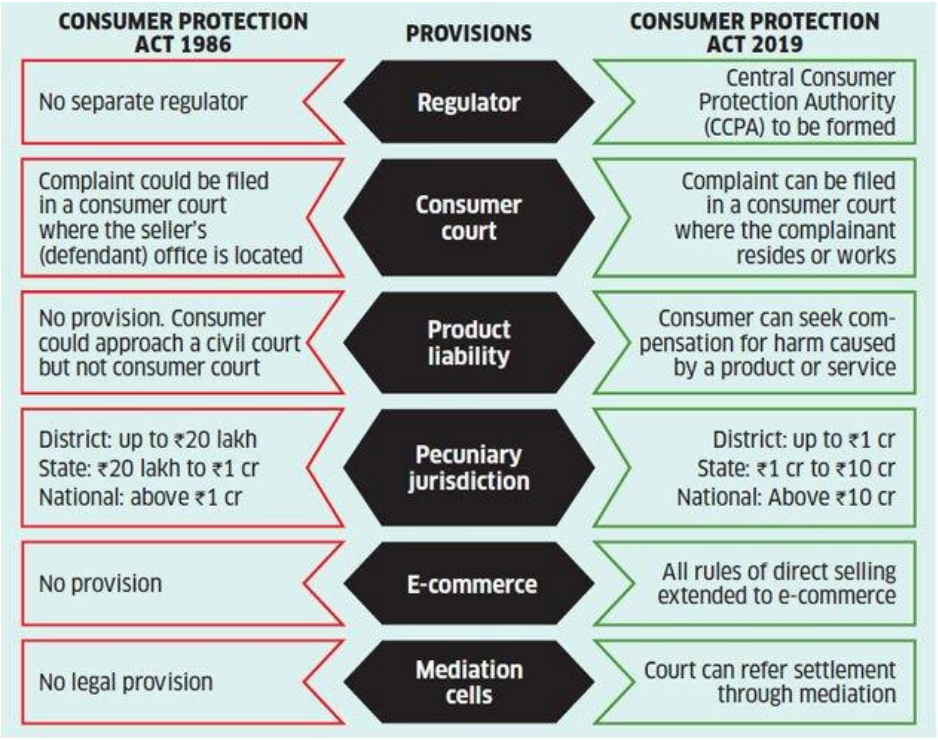

समयबद्ध निवारण:

- देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायतों का लंबित होना आम बात है। नया अधिनियम समाधान प्रक्रिया को सरल बनाकर उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने में मदद कर सकता है।
- इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत मामलों का निर्णय सीमित समयावधि में किया जाता है।

आईएसआई मार्क (भारतीय मानक संस्थान)

- यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक औद्योगिक सामान प्रमाणन चिह्न है। यह उत्पादों के लिए अच्छी गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के रूप में कार्य करता है

एगमार्क

- यह भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमाणन चिह्न है। एगमार्क भारत में उत्पादित और उपभोग किये जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए गारंटी के रूप में कार्य करता है।

बानगी:

- सोना, चाँदी, प्लैटिनम आदि कीमती धातुओं से बनी वस्तुओं की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उन पर एक आधिकारिक चिह्न अंकित किया जाता था।

खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं के कर्तव्य

- उपभोक्ता को आईएसआई मार्क, एगमार्क या हॉलमार्क जैसे गुणवत्ता प्रमाणन की जांच करनी चाहिए।
- उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें विशेष रूप से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद पर वैध बिल या कैश मेमो और वारंटी प्राप्त हो।
- उपभोक्ता को किसी सेल्समैन को किसी विशेष ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए
- यदि कोई दुकानदार ख़राब सामान बेच रहा है तो उपभोक्ता को संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए

CLASS 11

CHAPTER- 1

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना
- ✓ आजादी से पहले कृषि क्षेत्र
- ✓ आजादी से पहले का बुनियादी ढांचा
- ✓ आजादी से पहले का औद्योगिक क्षेत्र

- ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी।
- भारत विशेष रूप से सूती और रेशम वस्त्र, धातु और कीमती पत्थर के काम आदि के क्षेत्र में अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था।
- भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य - भारत को ब्रिटेन के तेजी से बढ़ते आधुनिक औद्योगीकरण के लिए एक फीडर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।

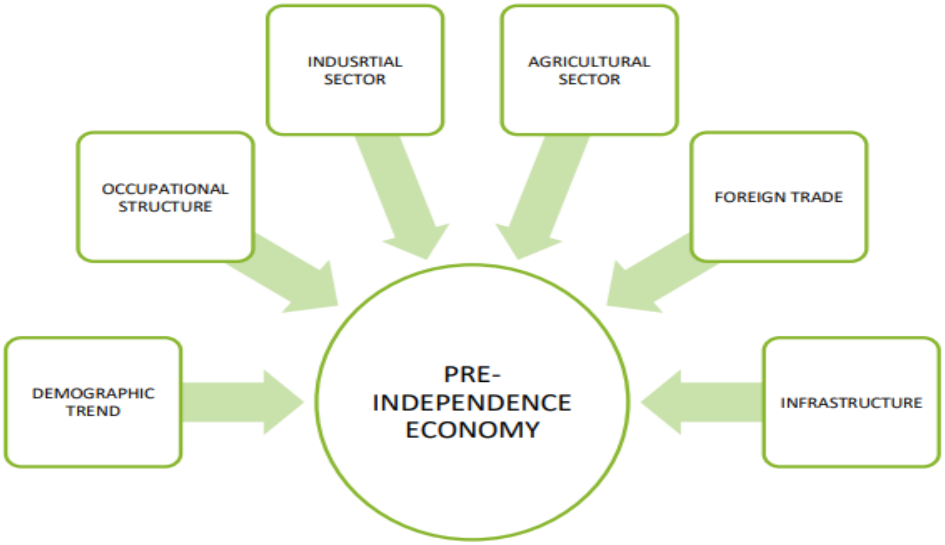

- ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में ब्रिटेन के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संवर्धन से अधिक चिंतित थीं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में एक मूलभूत परिवर्तन - भारत ब्रिटेन से कच्चे माल के शुद्ध आपूर्तिकर्ता और तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता में बदल गया।
- औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया।

कृषि क्षेत्र

- कृषि अर्थव्यवस्था - ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान थी। देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी ज्यादातर गांवों में रहती थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी।
- स्थिर कृषि क्षेत्र - अधिकतम आबादी की भागीदारी के कारण अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण कृषि उत्पादकता बहुत कम हो गई है।
- भूमि बंदोबस्त की प्रणालियों के कारण, कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ कृषकों के बजाय जमींदारों के पास चला गया। किसी भी जमींदार ने कृषि के विकास के लिए प्रयास करने की पहल नहीं की।
- कृषि आदानों की कमी - प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं की कमी और उर्वरकों के नगण्य उपयोग के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता और दक्षता का निराशाजनक स्तर हुआ।
- भारत की कृषि में सीढ़ीदार निर्माण, बाढ़-नियंत्रण, जल निकासी और मिट्टी के अलवणीकरण में निवेश की कमी थी।

- कृषि का व्यावसायीकरण - किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में शायद ही मदद कर सके क्योंकि वे नकदी फसलें पैदा कर रहे थे जिनका उपयोग अंततः ब्रिटिश उद्योगों द्वारा अपने देश में किया जाना था। इससे आगे खाद्य फसलों की कमी हो गई।
- देश का विभाजन: अविभाजित देश की अत्यधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र, विशेषकर जूट उद्योग के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा (पूरा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया (वर्तमान) बांग्लादेश)

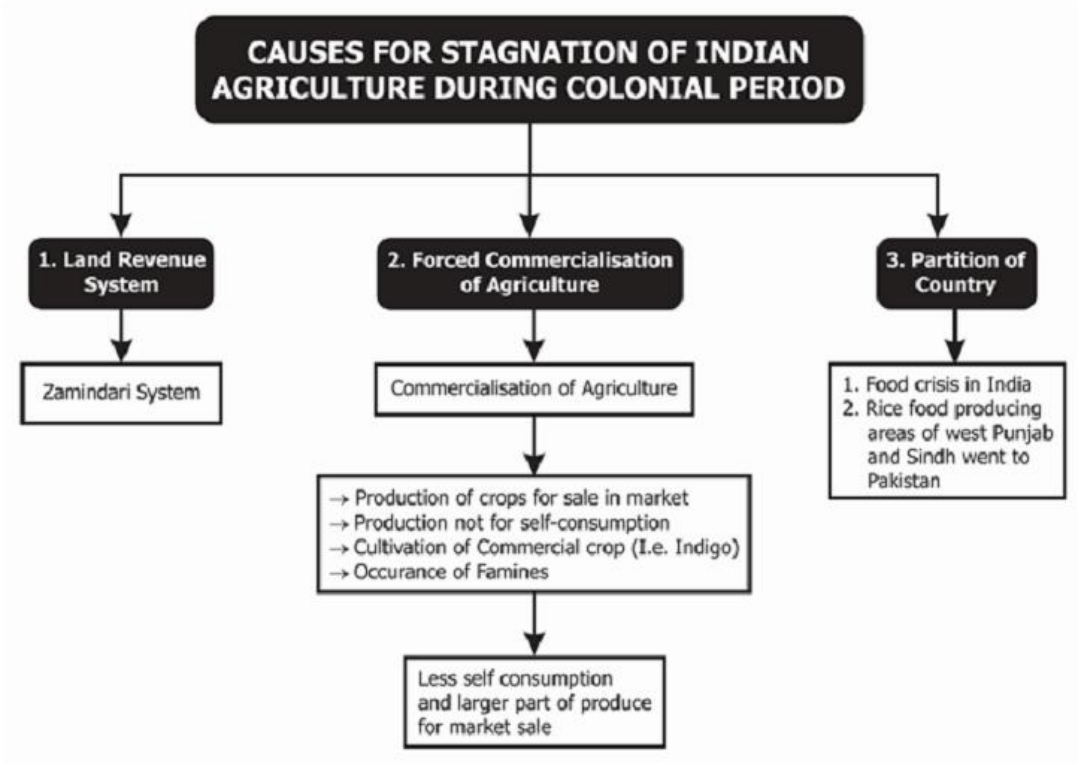

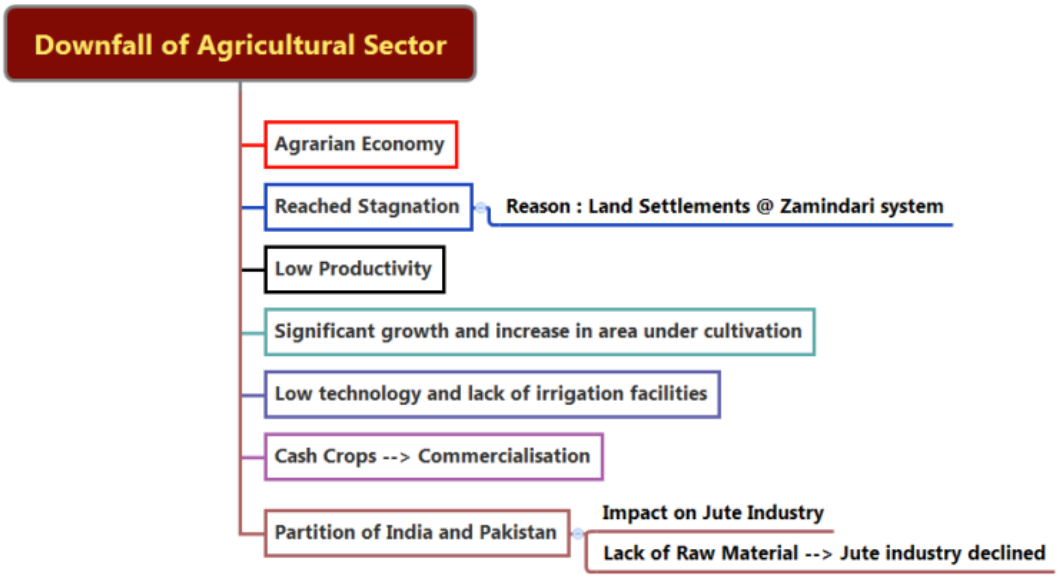

औद्योगिक क्षेत्र

- दुनिया में सर्वोत्तम हस्तशिल्प सामग्री के उत्पादन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भी भारत एक कुशल औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर सका। भारतीय उद्योग में तेजी से गिरावट आई और किसी भी आधुनिक औद्योगिक आधार को उसकी जगह लेने की अनुमति नहीं दी गई।
- व्यवस्थित विऔद्योगीकरण की ब्रिटिश नीति - ब्रिटेन में आगामी आधुनिक उद्योगों के लिए भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल (फीडर इकोनॉमी) के निर्यातक मात्र की स्थिति में लाना।
- भारत को ब्रिटेन के उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए बाज़ार बनाना ताकि उनका निरंतर विस्तार सुनिश्चित किया जा सके।
- भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने भारत में भारी बेरोजगारी और ग्रामीण संकट पैदा कर दिया।
- सूती और जूट कपड़ा मिलें मुख्य रूप से देश के पश्चिमी हिस्सों - महाराष्ट्र और गुजरात (भारत) में केंद्रित थीं।
- उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमानी शुरू कर दीं लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी और स्थिर रही।
- लोहा और इस्पात उद्योग बढ़ने लगे - टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) की स्थापना 1907 में हुई। चीनी, सीमेंट, कागज आदि जैसे अन्य उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आए।
- पूंजीगत सामान उद्योग - हालांकि आगे औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यह आवश्यक था, लेकिन यह उद्योग फल-फूल नहीं सका। नोट: पूंजीगत सामान उद्योग - इसका मतलब ऐसे उद्योग हैं जो मशीन टूल्स का उत्पादन कर सकते हैं जो बदले में उपभोग के लिए उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- नए औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान निराशाजनक और टुकड़ों में (अव्यवस्थित) रहा।
- इस प्रकार, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र आधुनिकीकरण, विविधीकरण, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक निवेश से वंचित था।

विदेश व्यापार

- भारत प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है।
- माल उत्पादन, व्यापार और टैरिफ की ब्रिटिश प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत को प्राथमिक उत्पादों (कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट आदि) का निर्यातक और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं (कपास, रेशम और ऊनी कपड़े और पूंजी) का आयातक बना दिया। ब्रिटेन की फ़ैक्टरियों में उत्पादित हल्की मशीनरी जैसे

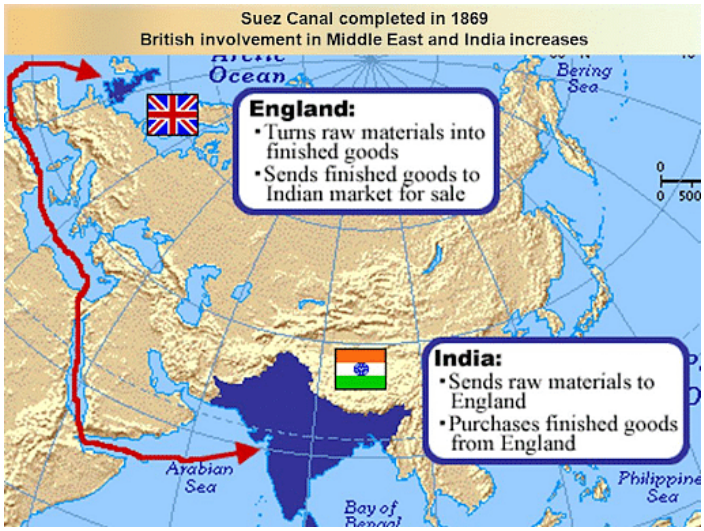

सामान)।

- ब्रिटेन ने भारत के निर्यात और आयात पर एकाधिकार नियंत्रण बनाए रखा, जिसके कारण भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित रहा, जबकि बाकी को चीन, सीलोन (श्रीलंका) और फारस (ईरान) जैसे कुछ अन्य देशों के साथ अनुमति दी गई।
- स्वेज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया।
- ब्रिटेन में औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यालय (भारत कार्यालय) द्वारा किए गए खर्च और ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध पर खर्च का उपयोग भारत से उत्पन्न राजस्व से किया गया था।

नोट: इंडिया ऑफिस ब्रिटिश भारत के प्रांतों के वायसराय और अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन की देखरेख के लिए 1858 में लंदन में स्थापित एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था।

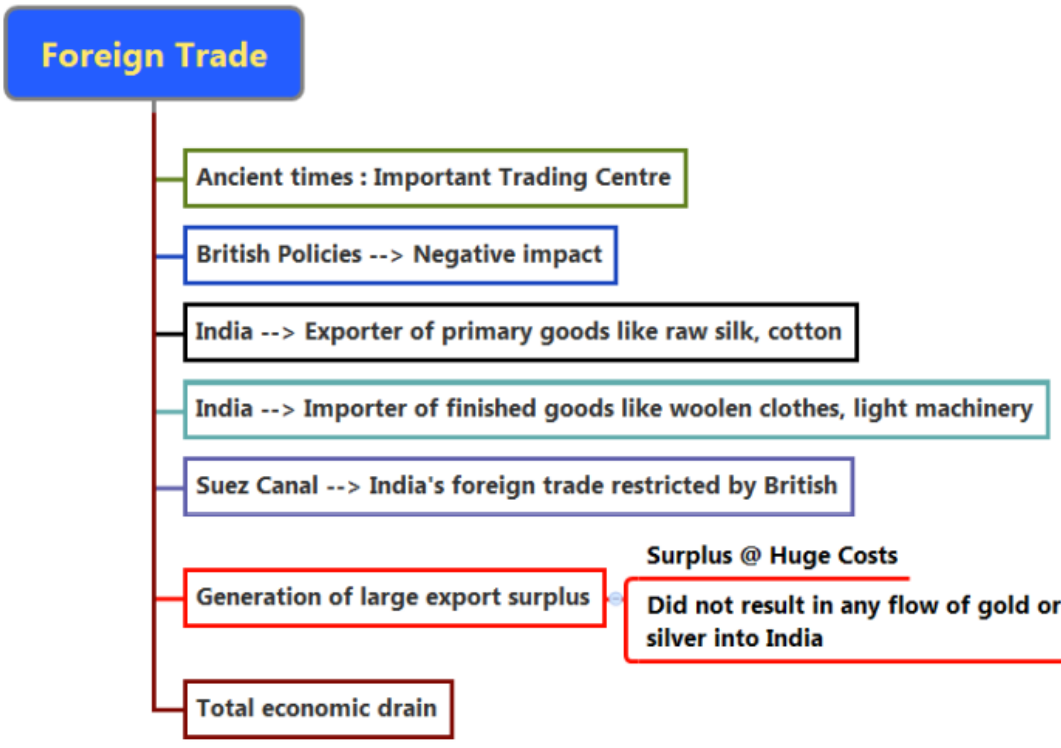

जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति

जनसांख्यिकी-मानव जनसंख्या की सांख्यिकीय विशेषताएं जैसे आयु, जातीयता, लिंग, रोजगार, शिक्षा, आय, विवाह दर, जन्म और मृत्यु दर आदि।

- ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का पहला दस्तावेजीकरण 1881 (दशवार्षिक) जनगणना के माध्यम से किया गया था। इस जनगणना से भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता का पता चला।
- समग्र साक्षरता स्तर: 16 प्रतिशत से कम; (महिला साक्षरता स्तर लगभग सात प्रतिशत था)
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं: या तो बड़ी आबादी के लिए अनुपलब्ध थीं या, जब उपलब्ध थीं, बेहद अपर्याप्त थीं।
- जल और वायु जनित बीमारियों का बड़े पैमाने पर बढ़ना, जिससे जीवन पर भारी असर पड़ रहा है
- समग्र मृत्यु दर बहुत अधिक थी और शिशु मृत्यु दर काफी चिंताजनक थी - लगभग 218:1000
- जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम थी - 32 वर्ष
- औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में व्यापक गरीबी व्याप्त थी, जिसने उस समय भारत की जनसंख्या की बिगड़ती स्थिति में योगदान दिया।

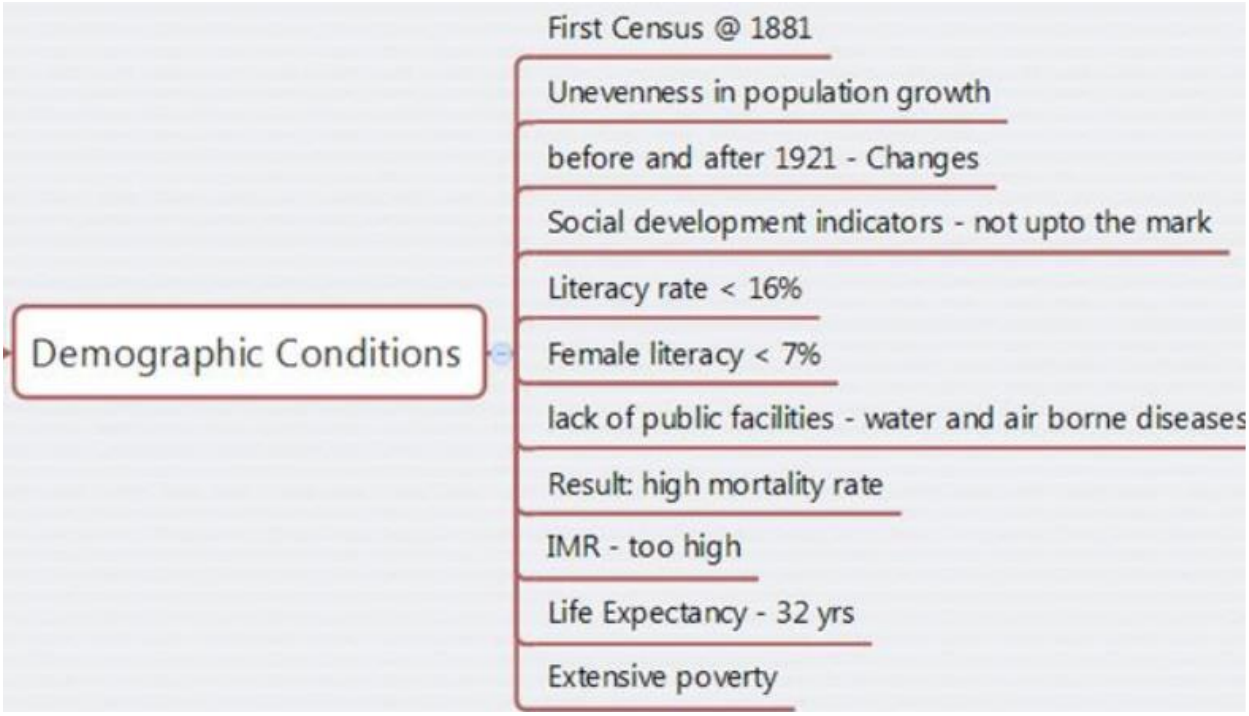

व्यावसायिक संरचना

- व्यावसायिक संरचना विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में कामकाजी व्यक्तियों के वितरण को दर्शाती है
- औपनिवेशिक काल के दौरान व्यावसायिक संरचना में बदलाव के बहुत कम संकेत देखे गए।
- कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 70-75%) कृषि में देखा गया।
- क्षेत्रीय भिन्नता में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः केवल 10 और 15-20% की वृद्धि हुई।
- तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में कुछ वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र पर कार्यबल की निर्भरता में गिरावट देखी गई।
- इसी समय के दौरान उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी में वृद्धि का अनुभव हुआ।

आधारभूत संरचना

- विभिन्न औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए (लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नहीं), भारत में बुनियादी ढांचे (रेलवे, बंदरगाह, जल परिवहन, डाक और तार) का विकास हुआ।

सड़कें-

- भारत के अंदर सेना को संगठित करना
- कच्चे माल को ग्रामीण इलाकों से निकालकर निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाहों तक दूर इंग्लैंड भेजना
- बरसात के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचना।

रेलवे-

- 1850 के दशक में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया
- लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया गया जिससे भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएं टूट गईं
- भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला जिससे भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा
- भारत के निर्यात व्यापार की मात्रा में विस्तार हुआ और इसका लाभ भारतीय लोगों को शायद ही कभी मिला
- सामाजिक लाभ ने देश के भारी आर्थिक नुकसान को कम कर दिया है, रेलवे को और अधिक उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता है।

→ विद्युत टेलीग्राफ ने दूरदराज के हिस्सों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा किया।

→ डाक सेवाएँ उपयोगी तो थीं लेकिन अपर्याप्त रहीं।

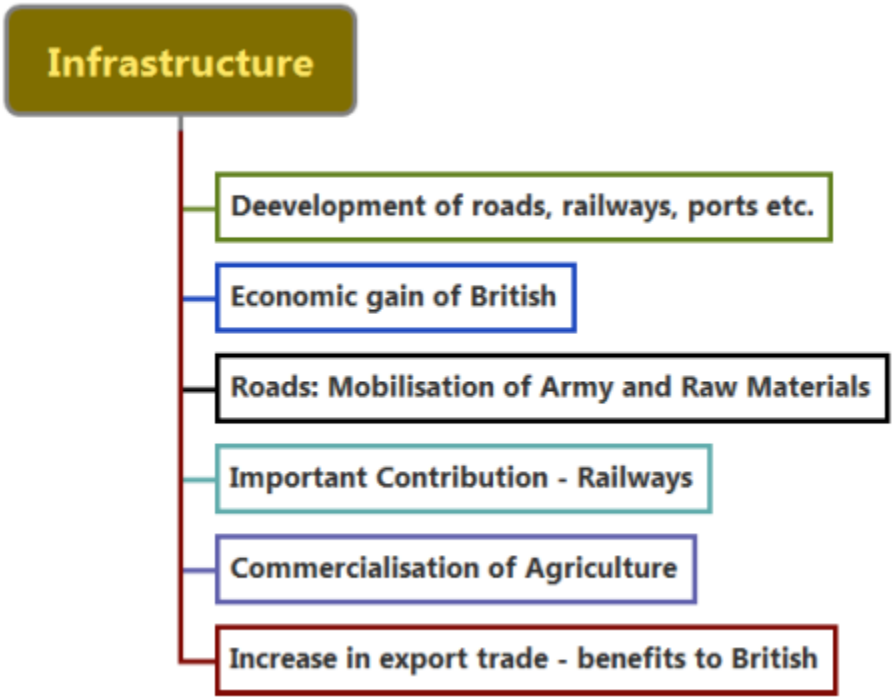

CLASS 11

CHAPTER-2

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ- पूँजीवादी, समाजवादी, मिश्रित
- ✓ स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था (1950 - 1990)
- ✓ भूमि सुधार
- ✓ सब्सिडी
- ✓ उद्योग और व्यापार नीतियां
- ✓ नेहरू- विकास का महालनोबिस मॉडल
- ✓ विकास का राव-मनमोहन मॉडल

आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है:

1. क्या उत्पादन करना है?
2. उत्पादन किसके लिए करें?
3. उत्पादन कैसे करें?

क्या उत्पादन करना है इसका संबंध है-

- उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का चयन
- बाज़ार विश्लेषण के अनुसार
- उपभोक्ता की मांग के अनुसार

किसके लिए उत्पादन करना है इसका संबंध है- समाज का वह भाग जिसके लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है:

- आय के वितरण के अनुसार
- संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार

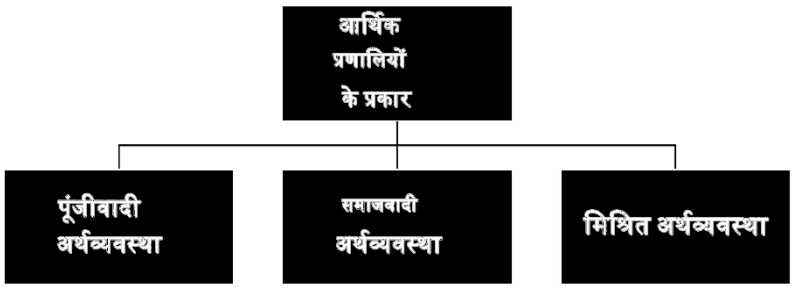

उत्पादन कैसे करें से संबंधित है - उत्पादन की तकनीक का चयन:

1. श्रम गहन तकनीक

- पूंजी की तुलना में अधिक श्रम का उपयोग
- श्रम > पूंजी

2. पूंजी गहन तकनीक

- श्रम से अधिक पूंजी का उपयोग
- पूंजी>श्रम

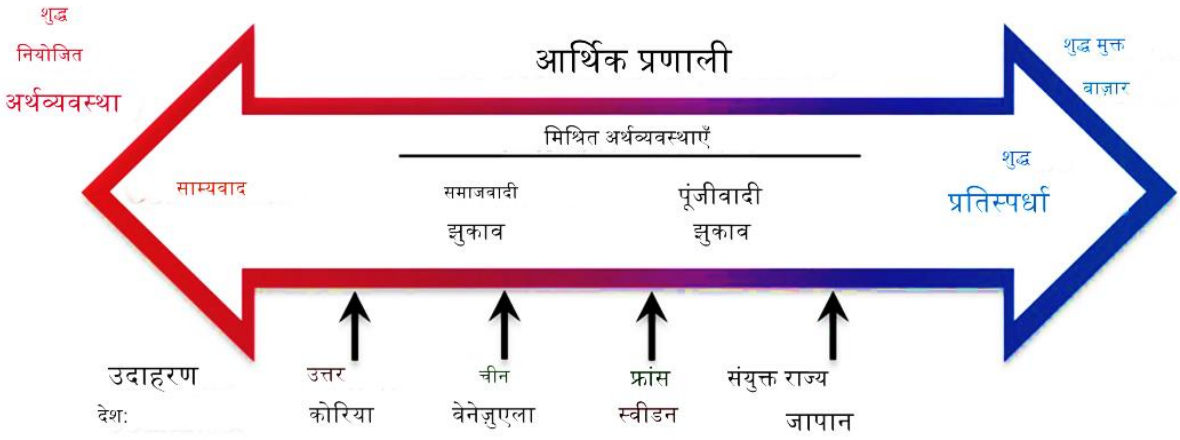

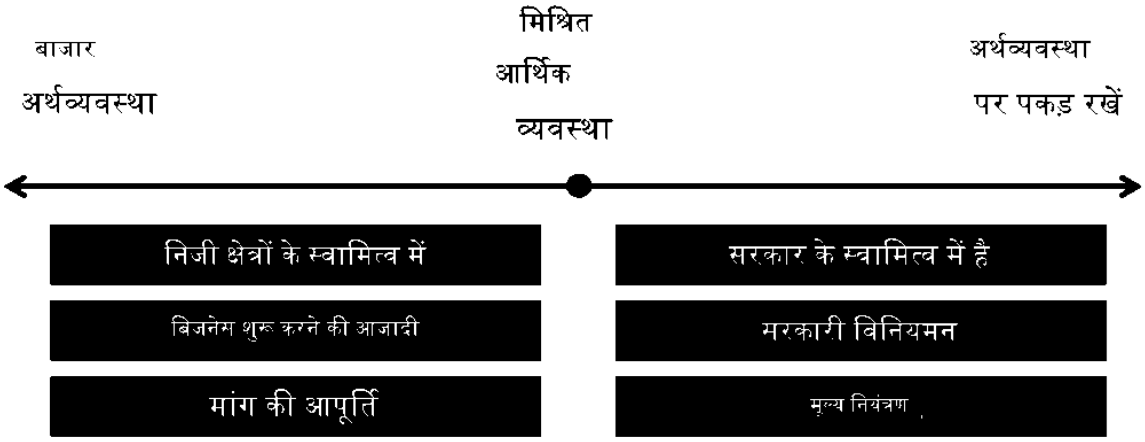

पूंजीवादी (बाज़ार) अर्थव्यवस्था प्रणाली

- पूंजीवादी व्यवस्था में, निर्मित उत्पादों को लोगों के बीच इस आधार पर विभाजित नहीं किया जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, बल्कि क्रय शक्ति (पीपी) के आधार पर विभाजित किया जाता है - जो उत्पादों और सेवाओं को खरीदने की क्षमता है।
- जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को सामान और सेवाएँ खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए।
- उदाहरण - वंचितों के लिए किफायती आवास की बहुत आवश्यकता है लेकिन इसमें बाजार की मांग शामिल नहीं होगी क्योंकि जरूरतमंदों के पास मांग को पूरा करने के लिए क्रय शक्ति नहीं है।
- इसलिए, बाजार की शक्तियों के अनुसार वस्तु का निर्माण और आपूर्ति नहीं की जाएगी।

विशेषताएँ	**गुण**	**अवगुण**
उद्यम की स्वतंत्रता- प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आर्थिक विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है	उत्पादन में वृद्धि	एकाधिकार की ओर ले जाता है
निजी संपत्ति का अधिकार - प्रत्येक व्यक्ति कितनी भी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर सकता है	लचीली व्यवस्था	असमानता
उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता	संसाधनों का इष्टतम उपयोग	मंदी और बेरोजगारी
उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा	प्रगति और समृद्धि	अपर्याप्त उत्पादन
नवप्रवर्तन की अधिक गुंजाइश	कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद	वर्ग संघर्ष

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था

- समाजवादी समाज में, सरकार यह निर्धारित करती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किन उत्पादों का निर्माण किया जाना है।
- ऐसा माना जाता है कि सरकार समझती है कि देश के नागरिकों के लिए क्या उचित है, इसलिए व्यक्तिगत खरीदारों की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।
- सरकार यह निष्कर्ष निकालती है कि उत्पाद कैसे बनाए जाएं और उत्पाद का निपटान कैसे किया जाए।
- सिद्धांत रूप में, समाजवाद के तहत साझाकरण इस पर आधारित माना जाता है कि किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, न कि वह क्या खरीद सकता है।
- संसाधनों का बेहतर आवंटन और धन और सामाजिक न्याय का समान वितरण।
- आर्थिक नियोजन का अस्तित्व
- सरकार की योजनाबद्ध और निश्चित आर्थिक भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों के पास न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के साधन हों।
- उपभोक्ताओं को पसंद की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है।
- अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और पक्षपात के लिए प्रजनन भूमि। समाजवाद अपने नागरिकों में कड़ी मेहनत या किसी रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता है।

नोट: लालफीताशाही आधिकारिक कार्रवाई पर विचार करने या पूरा करने से पहले अत्यधिक कागजी कार्रवाई और कठिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता की प्रथा को दर्शाती है

मिश्रित आर्थिक प्रणाली

- यह एक कमांड (समाजवादी) अर्थव्यवस्था और एक बाजार (पूंजीवादी) अर्थव्यवस्था का एक सुनहरा संयोजन है।
- इस प्रयोजन के लिए मिश्रित आर्थिक प्रणालियों को दोहरी आर्थिक प्रणालियाँ भी कहा जाता है।
- हालाँकि, मिश्रित प्रणाली को निर्धारित करने के लिए कोई ईमानदार तरीका नहीं है, कभी-कभी यह शब्द अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों में सख्त प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक बाजार प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।

मिश्रित आर्थिक प्रणाली के लक्ष्य और नीतियाँ

विशेषताएँ	**गुण**	**अवगुण**
एक नियोजित अर्थव्यवस्था और एक बाजार अर्थव्यवस्था का संयोजन।	बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा.	सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिलता है जबकि निजी क्षेत्र नियंत्रित रहता है।
सभी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व- मिश्रित अर्थव्यवस्था में सभी तीन क्षेत्र सामंजस्य के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं	केंद्रीय आर्थिक नियोजन का लाभ उठाता है	अकुशल योजना - अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर रहते हैं।
समाज कल्याण- का उद्देश्य देश में धन के अंतर को कम करना और असमानताओं से लड़ना है।	संपत्ति के स्वामित्व और वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की आर्थिक स्वतंत्रता।	क्षेत्रों की अप्रभावीता- निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती, इसलिए वह अप्रभावी हो जाता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में अप्रभावीता आती है।
आर्थिक नियोजन - राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के लिए सामान्य दिशानिर्देश।	मूल्य तंत्र का अस्तित्व. इसलिए संसाधनों का आवंटन अधिक वैज्ञानिक और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।	निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का लगातार डर.

सैद्धांतिक, समाजवादी और मिश्रित आर्थिक मॉडल के बीच अंतर

पैरामीटर	पूंजीवादी	समाजवादी	मिश्रित
संपत्ति का स्वामित्व	निजी	जनता	सार्वजनिक और निजी दोनों
मूल्य निर्धारण	मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित	केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित.	केंद्रीय योजना प्राधिकरण और मांग एवं आपूर्ति द्वारा निर्धारित।
उत्पादन का उद्देश्य	लाभ का उद्देश्य	समाज कल्याण	निजी क्षेत्र में लाभ का उद्देश्य और सार्वजनिक क्षेत्र में कल्याण का उद्देश्य
सरकार की भूमिका	कोई भूमिका नहीं	पूरी भूमिका	सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण भूमिका और निजी क्षेत्र में सीमित भूमिका
प्रतियोगिता	मौजूद	कोई प्रतिस्पर्धा नहीं	केवल निजी क्षेत्र में मौजूद हैं
आय का वितरण	बहुत असमान	बिल्कुल बराबर	काफ़ी असमानताएँ मौजूद हैं।

भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है?

- भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारत की लगभग आधी कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई है, जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक है।
- इसके एक-तिहाई कर्मचारी सेवा उद्योग में कार्यरत हैं, जो भारत के उत्पादन में दो-तिहाई योगदान देता है।
- इस खंड की उत्पादकता भारत के बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से संभव हुई है।

- 1990 के दशक से, भारत ने कई उद्योगों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। इसने कई राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण कर दिया है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना। यह उनके बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है जो उच्च विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है।
- अपने मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ-साथ उत्पादन, उपभोग, व्यवसाय की स्वतंत्रता और लाभ के उद्देश्य की उपस्थिति के माध्यम से, यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल आवंटन हो।
- आय, संपत्ति आदि की असमानताओं को कम करने की दिशा में काम करके।
- बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य की सभी मुख्य विशेषताएं मौजूद हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990

भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद का युग

योजना का अर्थ

- एक योजना बताती है कि किसी राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इसमें कुछ सामान्य लक्ष्यों के साथ-साथ विशिष्ट उद्देश्य भी होने चाहिए जिन्हें एक निश्चित समय के भीतर हासिल किया जाना चाहिए;
- भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की अवधि की होती हैं और इन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता है (हमने इसे पूर्व सोवियत संघ से उधार लिया था)।
- हमारे योजना दस्तावेज़ किसी योजना के पांच वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और बीस वर्षों की अवधि में क्या हासिल करना है (जिसे परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है) निर्दिष्ट करते हैं।
- 1950 में, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और पंचवर्षीय योजनाओं का युग शुरू हुआ।

स्वतंत्रता के बाद की योजना

- आर्थिक कार्यक्रम समिति (ईपीसी) - अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) द्वारा गठित, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। इस समिति का उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना था जो निजी और सार्वजनिक भागीदारी और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित कर सके। ईपीसी ने 1948 में भारत में एक स्थायी योजना आयोग बनाने की सिफारिश की।
- मार्च 1950 में सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुसरण में, एक प्रस्ताव (इसलिए कार्यकारी निकाय जो न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक है) द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे।
- योजना आयोग को देश के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, कमी वाले संसाधनों को बढ़ाने, संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएँ तैयार करने और प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
- लोकतांत्रिक समाजवाद: नेहरू सोवियत योजना की उपलब्धियों से बहुत प्रभावित थे; दर्शन न केवल निजी क्षेत्र की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के विकास को रोकना था, बल्कि निजी क्षेत्र को आर्थिक लाभ के बजाय सामाजिक लाभ के मुख्य उद्देश्य के लिए खेलने की स्वतंत्रता भी प्रदान करना था।

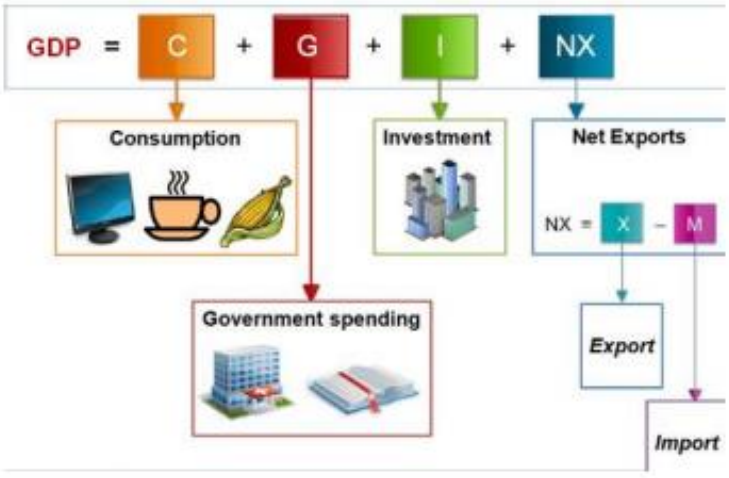

- केंद्रीय योजना आम वस्तुओं को वितरित करती है, जैसे बड़े पैमाने पर पारगमन, आवास और ऊर्जा, जबकि मुक्त बाजार को उपभोक्ता वस्तुओं को वितरित करने की अनुमति है।

पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य

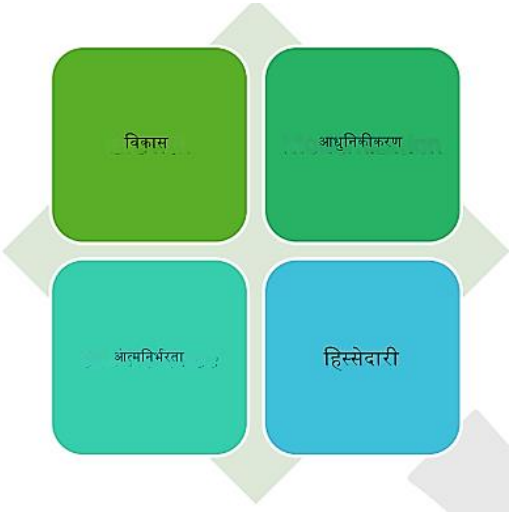

विकास

- विकास का तात्पर्य देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की देश की क्षमता में वृद्धि से है।
- आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगातार वृद्धि है - एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य।
- किसी देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक) से प्राप्त होती है - इनमें से प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किया गया योगदान अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना बनाता है।

आधुनिकीकरण

- किसी कारखाने द्वारा नई प्रकार की मशीन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम को आधुनिकीकरण कहा जाता है।
- आधुनिकीकरण से सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है जैसे कि यह मान्यता कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए।

आत्मनिर्भरता

- एक राष्ट्र अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके या अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- पहली सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया जिसका अर्थ है उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता है, ताकि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो सके, खासकर भोजन के लिए।
- ऐसी आशंका थी कि आयातित खाद्य आपूर्ति, विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी पर निर्भरता भारत की संप्रभुता को हमारी नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बना सकती है।
- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 प्रकोप की पृष्ठभूमि में आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) पर जोर दिया।

हिस्सेदारी

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल अमीरों तक पहुंचने के बजाय गरीब वर्गों तक भी पहुंचे - प्रत्येक भारतीय को भोजन, एक सभ्य घर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए; और धन के वितरण में असमानता को कम करना।

कृषि आवश्यकताओं को संबोधित करना

- कृषि से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जो फसलों के उत्पादन के लिए भूमि की खेती से संबंधित हैं; खाद्य फसलें और गैर-खाद्य फसलें।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व:

- जीडीपी में योगदान
- उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति

- रोज़गार
- औद्योगिक कच्चा माल
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान
- घरेलू व्यापार में योगदान
- राष्ट्र का धन

भारतीय कृषि की समस्याएँ:

- सिंचाई के स्थाई साधनों का अभाव
- वित्त की कमी
- पारंपरिक तकनीकें
- छोटी एवं बिखरी हुई जोत

भारतीय कृषि में सुधार:

- तकनीकी सुधार
- HYV बीजों का उपयोग
- रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
- वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन पद्धतियाँ
- खेती के यंत्रीकृत साधन

भूमि सुधार

- 'भूमि सुधार' शब्द विशेष रूप से भूमि स्वामित्व सुधारों को संदर्भित करता है। टेन्योर शब्द, लैटिन शब्द "टेनियो" से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'पकड़ना'। इसलिए, भूमि स्वामित्व का उपयोग उन शर्तों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनके तहत भूमि रखी जाती है।
- भूमि सुधारों को सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे अमीर जमींदारों और गरीब किसानों के बीच तीव्र असमानताओं वाले शोषणकारी संबंधों को दूर करना चाहते हैं, जिनके पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है।
- यह जोत के आकार पर सीमा लगाने के माध्यम से कुछ अनुपस्थित/गैर-खेती मालिकों के हाथों में भूमि जोत की एकाग्रता के खिलाफ एक कदम है, जिसका स्वामित्व एक परिवार के पास हो सकता है।
- जमींदारी उन्मूलन: राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत ग्रामीण जन सामाजिक आधार के कारण यह पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सफल रहा; लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, नौकरशाही की उदासीनता, भ्रष्टाचार और जमींदारों के प्रभाव के कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्य राज्यों में विफल रही।

किरायेदारी अधिकार:

- बाद के भूमि सुधारों ने किरायेदारों के अधिकारों को मान्यता दी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, मध्यस्थ काश्तकारों को समाप्त करने और काश्तकारों को राज्य के साथ सीधे संबंधों में लाने से मिट्टी जोतने वालों को कृषि प्रणाली में उनका उचित स्थान मिलेगा और उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा।

भूमि सीमा:

- 'भूमि जोत पर सीमा' शब्द का तात्पर्य कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार से है जिसके आगे कोई भी व्यक्तिगत किसान या कृषक परिवार कोई भूमि नहीं रख सकता है। अन्य सभी भूमि सुधार उपायों की तरह, ऐसी सीमा का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

भूदान और ग्रामदान आंदोलन

- भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किसान विद्रोह के तुरंत बाद शुरू किया गया था, और कुछ वर्षों के बाद, 1957 में ग्रामदान के नाम से जाना जाने वाला एक और आंदोलन अस्तित्व में आया।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक संबंधित गांव में भूमि मालिकों और पट्टाधारकों को अपने भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी करना था, जिसके बाद सभी भूमि समतावादी पुनर्वितरण और संयुक्त खेती के उद्देश्य के लिए एक ग्राम संघ की संपत्ति बन जाएंगी।
- विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान के माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को खत्म करने की आशा की और कहा कि यह आंदोलन भूमि के उचित पुनर्वितरण, जोत के समेकन और उनकी संयुक्त खेती को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- हालाँकि, आंदोलन अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा और भूमि अधिग्रहण और भूमि वितरण दोनों के संबंध में सफलता की डिग्री बहुत सीमित थी।
- ज्यादातर मामलों में, गाँव के जमींदारों ने जमीन के केवल वे टुकड़े ही दान में दिए जो या तो खेती के लिए अयोग्य थे या किरायेदारों या सरकार के साथ विवाद में थे।

लेकिन फिर भी ऐसे मामले थे जिनमें:

- जमींदारों के पास भूमि के बड़े क्षेत्र बने रहे (कानून में खामियों का उपयोग) किरायेदारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने स्व-खेतीकर्ता (वास्तविक जोतने वाले) होने का दावा किया
- भूमि हदबंदी कानून में आने वाली बाधाएँ
- बड़े जमींदारों ने इस कानून को अदालतों में चुनौती दी जिससे इसके कार्यान्वयन में देरी हुई
- कानून से बचने के लिए इस देरी का उपयोग अपनी जमीनों को करीबी रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत करने में किया भूमि सुधारों की सफलता देखी गई: केरल और पश्चिम बंगाल में सरकारें किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं

हरित क्रांति

स्वतंत्रता के दौरान:

- देश की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है
- कम उत्पादकता का सामना करना पड़ा ➔ पुरानी तकनीक का उपयोग + आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव
- भारत की कृषि ➔ मानसून पर निर्भर; और यदि मानसून कम हुआ तो किसानों को परेशानी होगी (यदि सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं होगी)

हरित क्रांति का पहला चरण (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक)

- HYV बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था।
- HYV बीजों का उपयोग केवल गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हुआ

हरित क्रांति का दूसरा चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक):

- HYV प्रौद्योगिकी का बड़ी संख्या में राज्यों में प्रसार और इससे फसलों की अधिक विविधता को लाभ हुआ, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम हुआ।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए - कृषि उपज की पर्याप्त मात्रा को बाजार में बेचने के लिए रखना महत्वपूर्ण है (और किसानों द्वारा स्वयं उपभोग नहीं किया जाना चाहिए)
- कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, विपणन अधिशेष कहलाता है

विपणन योग्य अधिशेष:

- इसका तात्पर्य किसान के अपने कृषि उपभोग से अधिक उत्पादन के अधिशेष से है। इस प्रकार, गेहूं का विपणन योग्य अधिशेष = गेहूं का उत्पादन - गेहूं की खेत में खपत।

- हरित क्रांति अवधि के दौरान उत्पादित चावल और गेहूं का एक अच्छा हिस्सा (विपणन अधिशेष के रूप में उपलब्ध) किसानों द्वारा बाजार में बेच दिया गया जिससे खाद्यान्न की कीमत में गिरावट आई।
- निम्न-आय समूह - सापेक्ष कीमतों में इस गिरावट से लाभान्वित (अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत भोजन पर खर्च करें)

प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम:

- छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना - क्योंकि केवल बड़े किसान ही आवश्यक लागत वहन कर सकते थे, जिससे हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हुआ।
- HYV फसलों पर कीटों के हमले का खतरा अधिक था

डर 'डर' ही रह गया- सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण:

- छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया
- सब्सिडी वाले उर्वरक ताकि छोटे किसानों को भी आवश्यक इनपुट तक पहुंच मिल सके; चूंकि छोटे किसान आवश्यक इनपुट प्राप्त कर सकते थे, समय के साथ छोटे खेतों का उत्पादन बड़े खेतों के उत्पादन के बराबर हो गया, जिससे छोटे और अमीर किसानों को लाभ हुआ।
- सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से कीटों के हमले के कारण होने वाले जोखिमों को कम किया गया

सब्सिडी

सब्सिडी की जरूरत

- विशेष रूप से छोटे किसानों द्वारा नई HYV तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सब्सिडी का उपयोग करना आवश्यक है - किसानों को नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए

सब्सिडी जारी रखने के ख़िलाफ़ मामला-

- एक बार जब प्रौद्योगिकी लाभदायक पाई जाती है और व्यापक रूप से अपनाई जाती है, तो सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है - जिसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सब्सिडी से उर्वरक उद्योग को भी लाभ होता है; और किसानों के बीच, सब्सिडी बड़े पैमाने पर अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करती है
- अंततः लक्ष्य समूह को लाभ नहीं मिलता है और यह सरकार के वित्त पर एक बड़ा बोझ है

कृषि सब्सिडी जारी रखने की जरूरत-

- भारत में खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय बनी हुई है क्योंकि अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और वे सब्सिडी के बिना आवश्यक इनपुट वहन करने में सक्षम नहीं होंगे, इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानता बढ़ेगी और समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा।

आगे बढ़ने का सही तरीका:

- सुनिश्चित करें कि केवल गरीब किसानों को ही लाभ मिले
- अवलोकन: जैसे-जैसे कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान और साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या का अनुपात काफी कम हो जाता है।
- 1950 और 1990 के बीच: कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इस पर निर्भर जनसंख्या में गिरावट नहीं आई (1950 में 67.5 प्रतिशत से 1990 तक 64.9 प्रतिशत) - औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ने काम करने वाले लोगों को अवशोषित नहीं किया कृषि क्षेत्र।

उद्योग एवं व्यापार

- गरीब राष्ट्र तभी प्रगति कर सकते हैं जब उनके पास एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो क्योंकि उद्योग रोजगार प्रदान करता है जो कृषि में रोजगार की तुलना में अधिक स्थिर होता है
- औद्योगिक क्षेत्र आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देता है ➔ इसलिए, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया।

- स्वतंत्रता के बाद: यदि अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास में बाजार और राज्य की भूमिका:

- स्वतंत्रता के समय- हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक औद्योगिक उद्यमों में निवेश करने के लिए पूंजी की कमी; छोटे बाज़ार उद्योगपतियों को बड़ी परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने में असमर्थ हैं ➔ राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में व्यापक भूमिका निभानी होगी
- समाजवादी तर्ज पर अर्थव्यवस्था का विकास: अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाली राज्य की नीति - राज्य का उन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण होगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे।
- निजी क्षेत्र की नीतियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी हो

औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (आईपीआर 1956):

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया - समाज के समाजवादी पैटर्न के लिए आधार तैयार करने के लिए उद्योगों का वर्गीकरण - तीन श्रेणियां:
2. पहला: उद्योग जिनका स्वामित्व विशेष रूप से राज्य के पास होगा
3. दूसरा: ऐसे उद्योग जिनमें निजी क्षेत्र राज्य क्षेत्र के प्रयासों को पूरक कर सकता है, जिसमें राज्य नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी लेता है
4. तीसरा: बचे हुए उद्योग जो निजी क्षेत्र में होने थे; लाइसेंस की एक प्रणाली के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था

- केवल लाइसेंस जारी होने से ही कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता था - पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ➔ आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर लाइसेंस प्राप्त करना आसान होता था
- उद्योगों को कर लाभ और कम टैरिफ पर बिजली जैसी कुछ रियायतें दी गईं ➔ क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए
- यहां तक कि मौजूदा उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या उत्पादन में विविधता लाने (नई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करने) के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था ➔यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से अधिक न हो
- उत्पादन का विस्तार करने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार आश्वस्त थी कि अर्थव्यवस्था को बड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता है।

व्यापार नीति-आयात प्रतिस्थापन

हमने जो औद्योगिक नीति अपनाई उसका व्यापार नीति से गहरा संबंध था

पहले सात FYPs: व्यापार की विशेषता एक अंतर्मुखी व्यापार रणनीति थी ➔ आयात प्रतिस्थापन; आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य

आयात से सुरक्षा के दो रूप थे: टैरिफ और कोटा

टैरिफ: आयातित वस्तुओं पर कर; वे आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाते हैं और उनके उपयोग को हतोत्साहित करते हैं।

कोटा: उन वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट करें जिन्हें आयात किया जा सकता है, दोनों आयात को प्रतिबंधित करते हैं और इसलिए, घरेलू फर्मों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं।

संरक्षण की नीति

- इस धारणा के आधार पर कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं - यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों को संरक्षित किया जाता है, तो वे समय के साथ प्रतिस्पर्धा करना सीखेंगे

- आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने पर विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की आशंका थी

योजना के उद्देश्य

- आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन एवं 'कल्याणकारी राज्य' का पैटर्न सुनिश्चित करना।
- सतत आर्थिक विकास।
- गरीबी निर्मूलन
- रोजगार सृजन एवं स्व-रोजगार
- पारंपरिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की योजना का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया था
- प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की सभी आकांक्षाओं को उचित स्थान और महत्व दें - आजीविका के पर्याप्त साधन, रोजगार के अवसर और न्याय और समानता पर आधारित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था।
- आत्मनिर्भरता - विश्व अर्थव्यवस्था में अधीनस्थ स्थिति पर प्रहार करने का एक प्रयास।
- आर्थिक समानता सुनिश्चित करना
- योजना के लिए वित्तीय संसाधन
- केंद्रीय बजट और राज्य बजट - राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति पक्ष
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई)
- घरेलू निजी क्षेत्र
- सकल बजटीय सहायता - यह केंद्रीय बजट से एक राशि है जो योजना अवधि के दौरान नियोजित निवेश को निधि देने के लिए जाती है।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)।

प्राइम मूविंग फोर्स - कृषि बनाम। उद्योग

- उस समय की सरकार ने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना।
- उपलब्ध संसाधन आधार को देखते हुए यह एक अतार्किक निर्णय लगता है क्योंकि भारत में उन सभी पूर्वापेक्षाओं का अभाव है जो उद्योग को इसके प्रमुख प्रस्तावक के रूप में घोषित करने का सुझाव दे सकते हैं -
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगभग कोई उपस्थिति नहीं.
- मजबूत बुनियादी ढांचे उद्योगों, यानी लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चे तेल, तेल शोधन और बिजली की कमी।
- निवेश योग्य पूंजी की उपलब्धता का अभाव - चाहे सरकार द्वारा या निजी क्षेत्र द्वारा।
- औद्योगीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का अभाव और अनुसंधान एवं विकास की कमी।
- कुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति की कमी।
- लोगों में उद्यमिता की भावना का अभाव।
- औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार का अभाव।
- कई अन्य सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारक जिन्होंने अर्थव्यवस्था के उचित औद्योगीकरण के लिए नकारात्मक शक्तियों के रूप में कार्य किया।

अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में भारत की स्पष्ट पसंद कृषि क्षेत्र रही होगी क्योंकि:

- देश के पास उपजाऊ भूमि का प्राकृतिक संसाधन था जो खेती के लिए उपयुक्त था।
- मानव पूंजी को किसी भी प्रकार के उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।
- कृषि में संलग्नता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या
- केवल अपनी भूमि के स्वामित्व, सिंचाई और कृषि के अन्य आदानों को व्यवस्थित करके, भारत विकास की बेहतर संभावनाओं की ओर बढ़ सकता था।
- एक बार जब जनता कृषि से लाभकारी आय के माध्यम से क्रय क्षमता का एक स्तर हासिल करने में सक्षम हो गई, तो भारत उद्योगों के विस्तार के लिए आगे बढ़ सकता था।

निम्नलिखित विकास औद्योगीकरण के पक्ष में थे -

- उद्योग को प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुनकर, भारत ने अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण के साथ-साथ खेती के पारंपरिक तरीके को आधुनिक बनाने का विकल्प चुना।
- दुनिया भर में और साथ ही डब्ल्यूबी (विश्व बैंक) और आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) में प्रमुख विचारधारा तेजी से वृद्धि और विकास के साधन के रूप में औद्योगीकरण के पक्ष में थी।
- द्वितीय विश्व युद्ध ने रक्षा शक्ति की सर्वोच्चता साबित कर दी थी - जिसे न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समर्थन की आवश्यकता है, बल्कि एक मजबूत औद्योगिक आधार की भी आवश्यकता है।
- भारत को भी निवारक शक्ति के रूप में अपने लिए एक शक्तिशाली रक्षा अड्डे की आवश्यकता थी।
- स्वतंत्रता के समय तक, औद्योगीकरण की ताकत पहले ही साबित हो चुकी थी और इसकी प्रभावशीलता के बारे में कोई संदेह नहीं था।
- भारतीय आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया, जब 2002 में सरकार ने घोषणा की कि अब से, उद्योग के स्थान पर, कृषि अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति होगी।
- योजना आयोग के अनुसार इस तरह के नीतिगत बदलाव से अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का समाधान होगा:
- कृषि उत्पादन में वृद्धि से अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षा हासिल कर सकेगी.
- कृषि अधिशेष वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) शासन से लाभान्वित होकर निर्यात उत्पन्न करेगा।
- गरीबी उन्मूलन की चुनौती को काफी हद तक हल किया जाएगा क्योंकि जोर कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाएगा और अधिक लाभकारी रोजगार पैदा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास को प्रेरित करेगा।

भारत के लिए योजनाबद्ध और मिश्रित अर्थव्यवस्था

- स्वतंत्रता के बाद, भारत को एक योजनाबद्ध और मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया।
- भारत न केवल संसाधनों के स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं का सामना कर रहा था, बल्कि अंतर-क्षेत्रीय असमानताएँ भी सदियों से प्रचलित थीं।
- गहराई तक व्याप्त व्यापक गरीबी का समाधान केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेगी।
- जनता की घोर गरीबी ने सरकार को योजना बनाने के लिए मजबूर किया ताकि वह संसाधनों के आवंटन में सक्रिय भूमिका निभा सके और उन्हें समान वृद्धि और विकास के लिए जुटा सके।
- हालाँकि, भारत को एक अर्ध-संघीय देश घोषित किया गया था, लेकिन योजना की प्रक्रिया में, आर्थिक गतिविधियों के विनियमन, निर्देशन और संचालन का अधिकार केंद्र सरकार में अधिक से अधिक केंद्रीकृत हो गया।

नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनने के लिए निम्नलिखित कारकों ने दबाव डाला -

- महामंदी (1929) और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण चुनौतियों ने अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया
- 1950 और 1960 के दशक में, दुनिया भर के नीति निर्माताओं के बीच प्रमुख दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में था - सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देश इसके उल्लेखनीय उदाहरण थे।
- बाजार की विफलता की स्थितियों को बेअसर करने के लिए अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख भूमिका
- भारत में योजना बनाने के पीछे प्रमुख शक्ति स्वयं नेहरू थे जिनका मजबूत समाजवादी झुकाव था।

सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर क्यों?

- राज्य को अर्थव्यवस्था में सक्रिय और प्रमुख भूमिका दी जानी है, यह बात भारत के स्वतंत्र होने के समय तक ही तय हो चुकी थी।
- स्वाभाविक रूप से, सरकार-नियंत्रित उद्यमों की एक विशाल संरचना बनने जा रही थी जिसे पीएसयू के रूप में जाना जाएगा।

पीएसयू के महत्वाकांक्षी विस्तार के पीछे का कारण निम्नलिखित प्रमुख आवश्यकताएं थीं:

- ढांचागत आवश्यकताएँ
- औद्योगिक आवश्यकताएँ

- रोजगार सृजन
- सामाजिक क्षेत्र का विकास
- निजी क्षेत्र का उद्भव

नेहरू - विकास का महालनोबिस मॉडल

- भारत की नियोजन रणनीति में निर्णायक मोड़ दूसरी पंचवर्षीय (1956- 61) योजना के साथ आया।
- योजना के लिए अपनाए गए मॉडल को विकास की नेहरू-महालनोबिस रणनीति के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण और पी.सी. द्वारा व्यक्त किया गया था। महलनोबिस इसके मुख्य वास्तुकार थे।
- पी सी महलनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद् हैं। वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे
- विकास का महालनोबिस मॉडल बुनियादी वस्तुओं (पूंजीगत सामान या निवेश सामान जो आगे सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है) की प्रबलता पर आधारित था।
- इसका विषय यह था कि- यदि औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ाना है, तो देश को बुनियादी उद्योगों और उद्योगों को विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो आगे के विकास के लिए आवश्यक मशीनें बनाते हैं।
- यह इस आधार पर था कि यह सर्वांगीण निवेश को आकर्षित करेगा और परिणामस्वरूप उत्पादन की उच्च दर में वृद्धि होगी।
- इससे रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए लघु और सहायक उद्योग विकसित किया जाएगा।

मॉडल के अन्य तत्व थे -

- आयात प्रतिस्थापन - भारतीय कंपनियों को आयातित वस्तुओं के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित विकल्प विकसित करने और विदेशी पूंजी पर भारत की निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ सुरक्षात्मक बाधाएं।
- सार्वजनिक क्षेत्र परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय है।
- एक जीवंत लघु-स्तरीय निजी क्षेत्र, जो बिखरे हुए और न्यायसंगत विकास और उत्पादक उद्यमियों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को संचालित करता है।

मॉडल के परिणाम -

- औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को ऊपर उठाने के मूल उद्देश्य की दृष्टि से यह रणनीति सफल रही।
- समग्र औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में तेजी आई।
- इस रणनीति ने काफी कम समय में एक अच्छी तरह से विविधीकृत औद्योगिक संरचना की नींव रखी और यह एक बड़ी उपलब्धि थी।
- इसने आत्मनिर्भरता को आधार दिया।

आलोचना -

- भारी उद्योग क्षेत्र और कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं आदि जैसे अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के बीच दृश्यमान असंतुलन।
- यह काफी हद तक ट्रिकल-डाउन प्रभाव पर निर्भर करता है कि विकास का लाभ समय के साथ सभी वर्गों तक पहुंचेगा।
- गरीबी उन्मूलन धीमा और क्रमिक था।

राव-मनमोहन सिंह विकास मॉडल

- 1991 से आर्थिक सुधार राव-मनमोहन मॉडल (नरसिम्हा राव - प्रधान मंत्री और मनमोहन सिंह - वित्त मंत्री) पर आधारित हैं।

मॉडल की विशेषताएं

- निजी क्षेत्र को उदारतापूर्वक निवेश करने की अनुमति देने के लिए चुनिंदा नियंत्रणों और परमिटों को समाप्त करें।
- आर्थिक प्रबंधन में राज्य की भूमिका को पुनर्निर्देशित करना। राज्य को सामाजिक और ढांचागत विकास पर दोबारा ध्यान देना चाहिए।
- संसाधन प्रवाह और प्रतिस्पर्धा से लाभ पाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए बाहरी क्षेत्र का उदारीकरण।
- अर्थव्यवस्था को खोलें और पीएसई के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करें - बेहतर लाभप्रदता, उत्पादकता और दक्षता के लिए।

- विदेशी मुद्रा भंडार संचय से भुगतान संतुलन का दबाव कम हुआ और विदेशी प्रवाह - एफडीआई और एफआईआई में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी बन गई।
- इसकी सफलता 8वीं योजना (1992-1997) के दौरान अर्थव्यवस्था की 6.5% से अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर में देखी गई है। इतिहास में बीओपी संकट छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार जमा हुआ।

CLASS 11

CHAPTER-3

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ आर्थिक संकट
- ✓ आर्थिक सुधार
- ✓ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
- ✓ लाइसेंस राज
- ✓ नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न

- 1991 में, भारत को अपने विदेशी ऋण से संबंधित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा - सरकार विदेशों से लिए गए अपने उधार का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी।
- जब व्यय आय से अधिक होता है, तो सरकार घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों के साथ-साथ देश के लोगों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेती है।
- विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम आम तौर पर पेट्रोल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर पहुंच गया जो एक पखवाड़े के लिए भी पर्याप्त नहीं था।
- जब हम पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं का आयात करते हैं, तो हम डॉलर में भुगतान करते हैं जो हम अपने निर्यात से कमाते हैं।
- आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से संकट और बढ़ गया।
- वित्तीय संकट की उत्पत्ति का पता 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन से लगाया जा सकता है। सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक था।

विकास नीतियां

- विकास नीतियों के लिए आवश्यक था कि भले ही राजस्व बहुत कम था, फिर भी सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अपने राजस्व को बढ़ाना होगा।
- सरकार के विकास कार्यक्रमों पर निरंतर खर्च से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ।
- सरकार. कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं था।

- बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से होने वाली आय भी बहुत अधिक नहीं थी।

1980 के दशक का आर्थिक संकट

- सरकारी व्यय उसके राजस्व से इतने बड़े अंतर से बढ़ने लगा कि उधार के माध्यम से व्यय को पूरा करना अस्थिर हो गया।
- कई जरूरी सामानों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई.
- निर्यात की वृद्धि के अनुरूप हुए बिना आयात बहुत ऊंची दर से बढ़ा।
- विदेशी मुद्रा भंडार उस स्तर तक गिर गया जो दो सप्ताह से अधिक समय तक आयात के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त नहीं था।
- अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं।

आईबीआरडी और आईएमएफ से समर्थन

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नाम से जाना जाता है, से संपर्क किया और संकट के प्रबंधन के लिए ऋण के रूप में 7 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।
- ऋण प्राप्त करने के लिए, इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत से अपेक्षा की कि वह निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाए और खोले, कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका कम करे और व्यापार प्रतिबंध हटाए।
- भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तों पर सहमति व्यक्त की और नई आर्थिक नीति (एनईपी) की घोषणा की।
- संकट को टालने और कम करने के लिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) (विश्व बैंक) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से संपर्क किया और संकट के प्रबंधन के लिए ऋण के रूप में 7 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।

आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के उपाय

1. उदारीकरण - निजी क्षेत्र पर से प्रतिबंध हटाना
2. निजीकरण - कई क्षेत्रों में सरकार की भूमिका कम करना
3. वैश्वीकरण- व्यापार प्रतिबंधों को हटाना

भारत के लिए आईएमएफ की शर्तें

- रुपये का अवमूल्यन 22 प्रतिशत।
- सर्वोच्च आयात शुल्क में 130 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से 30 प्रतिशत की भारी कमी।
- सीमा शुल्क कटौती के कारण राजस्व की कमी को बेअसर करने के लिए उत्पाद शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
- सभी सरकारी खर्चों में सालाना 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
- भारत विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तों पर सहमत हुआ - नई आर्थिक नीति (एनईपी) की घोषणा की - जिसमें निम्नलिखित आर्थिक सुधार शामिल थे:

1. फर्मों के प्रवेश और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करके अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना;
2. भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से उदारीकरण की शुरुआत की गई;
3. एफडीआई पर प्रतिबंध हटाने के साथ-साथ घरेलू उद्यमियों को एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रतिबंधों से मुक्त करना;
4. भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण के जाल से मुक्त कराना;
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भार कम करना, जिन्होंने रिटर्न की दर बहुत कम दिखाई है या जो वर्षों से घाटे में चल रहे थे।

आर्थिक सुधार के फ़ायदे-

- कीमतों में वृद्धि - मुद्रास्फीति 7% से बढ़कर 16.7% हो गई
- राजकोषीय घाटे में वृद्धि - गैर-विकास व्यय में वृद्धि के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण और परिणामी ब्याज में वृद्धि हुई।
- प्रतिकूल भुगतान संतुलन: जब भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा कम पड़ जाती है या कुल आयात कुल निर्यात से अधिक हो जाता है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है।
- इराक-कुवैत युद्ध 1990-91 - इससे पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई। खाड़ी देशों से धन का प्रवाह रुक गया।
- सार्वजनिक उपक्रमों का निराशाजनक प्रदर्शन - राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और सरकार के लिए एक बड़ी देनदारी बन गए थे।
- विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट - भारतीयों का विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में सबसे निचले स्तर पर गिर गया और यह 2 सप्ताह के आयात बिल का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त था।

⟶ किसी देश का भुगतान संतुलन एक विशेष अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड है।

⟶ आयात कवर - देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) के साथ कवर किए जा सकने वाले आयात के महीनों की संख्या को मापता है।

सुधार के उपाय

1. व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय

- इनमें वे सभी आर्थिक नीतियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ावा देना है - चाहे वह घरेलू हो या बाहरी।
- घरेलू मांग बढ़ाने के लिए, जनता की क्रय शक्ति बढ़ाना आवश्यक है, जो लाभकारी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के सृजन पर जोर देता है।

2. संरचनात्मक सुधार के उपाय

- ऐसे उपाय जिनमें वे सभी नीतिगत सुधार शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं।
- इसमें स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था को बंधन मुक्त करना शामिल है ताकि वह बढ़ी हुई उत्पादकता की अपनी क्षमता की खोज कर सके।
- लोगों की क्रय क्षमता बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ी हुई आय की आवश्यकता होती है, जो गतिविधियों के बढ़े हुए स्तर से आती है।
- इस प्रकार बढ़ी हुई आय बाद में उन लोगों के बीच वितरित की जाती है जिनकी क्रय शक्ति बढ़ानी होती है।
- यह व्यापक आर्थिक नीतियों के एक उपयुक्त सेट को उचित रूप से शुरू करने से होगा।

सुधारों का एलपीजी ढांचा

⟶ भारत में सुधारों की प्रक्रिया को तीन प्रक्रियाओं - उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के रोडमैप के माध्यम से पूरा किया जाना था।

उदारीकरण

- इस संदर्भ में "उदारीकरण" शब्द का तात्पर्य आर्थिक उदारीकरण से है।
- यह नीति दर्शाती है कि किसी भी उद्योग, व्यापार या व्यवसाय के उद्यमी को अधिक स्वतंत्रता दी जानी है और उस पर सरकारी नियंत्रण को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

- नियमों और प्रतिबंधों को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए उदारीकरण की शुरुआत की गई थी।
- केवल कल्याण और अन्य नियामक तंत्र के प्रमुख मुद्दे ही राज्य के पास बचे हैं।

लाइसेंस राज

- लाइसेंस राज उन नियमों और नौकरशाही को संदर्भित करता है जो 1951 और 1991 के बीच भारत में भारतीय व्यवसायों को स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक थे। सरकार ने लाइसेंसिंग प्रणाली का सहारा लिया ताकि वह उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अनुसार उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रख सके।

लाइसेंस क्या है?

- लाइसेंस से तात्पर्य सरकार द्वारा एक फर्म को दी गई लिखित अनुमति से है जिसमें उल्लेख होता है कि फर्म द्वारा किस उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, लाइसेंस में कई अन्य विवरण भी शामिल होते हैं जैसे वह स्थान जहां फैक्ट्री स्थित होनी है; किन उत्पादों का उत्पादन किया जाना है; उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा क्या है; उत्पादन के विस्तार आदि को लेकर क्या स्थितियाँ हैं?

उदाहरण: लाइसेंस राज के सुनहरे दिनों को याद करने के लिए भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे उपयुक्त है। उन दिनों, केवल कुछ ब्रांड जैसे बजाज, राजदूत (एस्कॉर्ट्स के), वेस्पा (बाद में बजाज के), चेतक (बाजा के), लैंब्रेटा आदि मौजूद थे। बजाज मार्केट लीडर था और इसका चेतक ब्रांड इतना लोकप्रिय था कि लोग इसे बुक करते थे और इसकी डिलीवरी के लिए महीनों तक इंतजार करते थे। कारण यह था कि औद्योगिक लाइसेंस में यह निर्धारित था कि वे कितनी मात्रा में स्कूटर का उत्पादन कर सकते हैं और यह भी कि वे अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से केवल 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यदि वे इससे आगे विस्तार करना चाहते थे, तो उन्हें पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी।

लाइसेंस के लिए क्या थी बाध्यता?

लाइसेंसिंग नीति ने निम्नलिखित शर्तों में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बना दिया:

- मौजूदा औद्योगिक इकाइयों (आईडीआर अधिनियम 1951 के पूर्व अधिनियमन) को अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता थी।
- लाइसेंस प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में स्थापित की जाने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिए। यदि उद्योग अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन निवेश रुपये से ऊपर था। 10 करोड़; फर्म को उद्योग विभाग के साथ सूचना का एक ज्ञापन दाखिल करना आवश्यक था।
- यदि कोई वस्तु लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है और कोई फर्म इन वस्तुओं का निर्माण करना चाहती है, तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- यदि कोई फर्म अपनी उत्पादन क्षमता 25% से अधिक बढ़ाना चाहती है, तो उसे पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- मेट्रो शहर में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। विनिर्माण इकाई का स्थान बदलने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी।

→ लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्यमी को सरकार के पास आवेदन दाखिल करना पड़ता था। आवेदन मिलने के बाद सरकार जरूरी जांच करेगी और अगर सरकार को पता चला कि औद्योगिक इकाई जनहित के खिलाफ नहीं है तो वह लाइसेंस दे देगी. यदि औद्योगिक इकाई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

→ नौकरशाही लालफीताशाही ने पर्याप्त प्रशासनिक बोझ डाला और इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि लाइसेंस के लिए आवेदन को किस समय सीमा के भीतर या किस समय सीमा में मंजूरी दी जाएगी। एक तिहाई से अधिक आवेदन खारिज कर दिए गए जिसका मतलब था निवेश का नुकसान। तीव्र औद्योगीकरण में यह एक बड़ी बाधा थी। लाइसेंस राज द्वारा निर्मित मुद्दे हैं:

- उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों और अधिकारियों से निपटना पड़ता था; और अपनी फ़ैक्टरियों से ज़्यादा समय दिल्ली में बिताया।
- लाइसेंसिंग नीति उद्देश्यों का टकराव थी। घोषित उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसने विस्तार, नई वस्तुओं के उत्पादन आदि को प्रतिबंधित कर दिया। इसी तरह, घोषित उद्देश्य आर्थिक शक्ति को कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकना था, लेकिन वास्तव में इसने वैसा ही किया। व्यापक भ्रष्टाचार के कारण बड़े घरानों को नए लाइसेंस दिए गए। उन्हें नए खिलाड़ियों की कीमत पर आगे बढ़ने की भी अनुमति दी गई। लाइसेंस राज में रिश्वतखोरी एक संस्कृति थी

उदारीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपाय

1. औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाना:

- सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं, सामाजिक कारणों, खतरनाक रसायनों और प्रमुख पर्यावरणीय कारणों से संबंधित 18 उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया।
- इसके बाद, पांच उद्योगों (शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स) के एक छोटे समूह को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।
- रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण।
- कीमतें निर्धारित करने के लिए बाजार तंत्र। कई उद्योगों में, बाजार को कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है

2. वित्तीय क्षेत्र में सुधार:

- वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के कारण भारतीय और विदेशी दोनों तरह के निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना हुई।
- वित्तीय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
- भारत में वित्तीय क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- भारत में सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को आरबीआई के विभिन्न मानदंडों और विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
- आरबीआई यह तय करता है कि बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकते हैं, ब्याज दरें तय करता है, विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने की प्रकृति आदि तय करता है।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य आरबीआई की भूमिका को वित्तीय क्षेत्र के नियामक से घटाकर सुविधाप्रदाता बनाना है।
- इसका मतलब यह है कि वित्तीय क्षेत्र को कई मामलों पर आरबीआई से परामर्श किए बिना निर्णय लेने की अनुमति दी जा सकती है।

3. विदेशी निवेश का उदारीकरण:

- पहले विदेशी कंपनियों को पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती थी, अब देश में एफडीआई के प्रवाह के लिए स्वचालित मंजूरी दी गई।
- उच्च प्राथमिकता वाले और निवेश-गहन उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया और अब वे होटल और पर्यटन, बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर विकास आदि जैसे क्षेत्रों सहित 100% एफडीआई को आमंत्रित कर सकते हैं।
- माल की बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नाम या ट्रेडमार्क के उपयोग की अनुमति दी गई।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार:

- सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करने और उनके प्रबंधन को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई।

5. एमआरटीपी अधिनियम:

- औद्योगिक नीति 1991 ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया। (अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा प्रतिस्थापित)
- प्रतिस्पर्धा की वर्तमान दुनिया में यह अधिनियम अप्रचलित हो गया। MRTP एक्ट उन कंपनियों के विस्तार को रोकता है जिनकी संपत्ति 100 करोड़ थी, क्योंकि इन कंपनियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी
- आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण, नए उद्यमों की स्थापना के लिए प्रवेश-पूर्व प्रतिबंध, मौजूदा व्यवसायों के विस्तार, विलय और अधिग्रहण आदि से संबंधित नियमों को समाप्त कर दिया गया है।

6. कर सुधार:

- कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से इसकी राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है।
- कर दो प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
- प्रत्यक्ष करों में व्यक्तियों की आय के साथ-साथ व्यावसायिक उद्यमों के मुनाफे पर कर शामिल होते हैं।

- 1991 के बाद से, व्यक्तिगत आय पर करों में लगातार कमी आई है क्योंकि यह महसूस किया गया था कि आयकर की उच्च दरें कर चोरी का एक महत्वपूर्ण कारण थीं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि आयकर की मध्यम दरें बचत और आय के स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
- निगम कर की दर, जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है। वस्तुओं और वस्तुओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, अप्रत्यक्ष करों, वस्तुओं पर लगाए गए करों में सुधार के प्रयास भी किए गए हैं।

निजीकरण

- जिन नीतियों के माध्यम से राज्य का 'रोल बैक' किया गया उनमें विनियमन, निजीकरण और सार्वजनिक सेवाओं में बाजार सुधारों की शुरूआत शामिल थी।
- उस समय निजीकरण का उपयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जाता था जिसके तहत राज्य की संपत्तियों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता था।
- सरकारी कंपनियों को दो तरीकों से निजी कंपनियों में बदला जा सकता है

I. सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार की वापसी

II. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की एकमुश्त बिक्री द्वारा

- निजीकरण का दूसरा प्रकार विनिवेश है।
- विनिवेश राज्य से निजी क्षेत्र में 100 प्रतिशत से कम स्वामित्व हस्तांतरण का विराष्ट्रीयकरण है।
- सामान्य अर्थ में वे सभी आर्थिक नीतियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र या बाजार (अर्थव्यवस्था) के विस्तार को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं, उन्हें निजीकरण की प्रक्रिया कहा गया है।

विनिवेश

- पीएसयू की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण विनिवेश के रूप में जाना जाता है।
- सरकार के अनुसार, बिक्री का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करना था।
- सरकार ने परिकल्पना की कि निजीकरण एफडीआई के प्रवाह को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
- सरकार हर साल पीएसयू के विनिवेश का लक्ष्य तय करती है. उदाहरण के लिए, 1991-92 में विनिवेश के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।
- आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों का कम मूल्यांकन किया गया है और उन्हें निजी क्षेत्र को बेच दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार को काफी नुकसान हुआ है.
- विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों के विकास और देश में सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के बजाय सरकारी राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था।

नवरत्न, महारत्न और मिनीरत्न

- 1996 में, दक्षता में सुधार करने, व्यावसायिकता लाने और उन्हें उदार वैश्विक वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने नौ सार्वजनिक उपक्रमों को चुना और उन्हें नवरत्न घोषित किया।
- कंपनी को कुशलतापूर्वक चलाने और इस प्रकार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णय लेने के लिए उन्हें अधिक प्रबंधकीय और परिचालन स्वायत्तता दी गई
- नवरत्न मूल रूप से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को दिया गया शीर्षक था, जिन्हें 1997 में भारत सरकार द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में पहचाना गया था, जिनके पास तुलनात्मक लाभ हैं", उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि "उनका समर्थन किया जा सके।" उनका लक्ष्य वैश्विक दिग्गज बनना है"।

पीएसयू कंपनियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

- महारत्न

- नवरत्न
- मिनीरत्न

- मूल रूप से, नवरत्न शब्द का अर्थ नौ बहुमूल्य रत्नों से बना एक ताबीज या आभूषण था। बाद में, इस प्रतीकवाद को सम्राट विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अपनाया गया, जहां नवरत्न अपने-अपने दरबार में नौ असाधारण पुरुषों का एक समूह थे।
- महारत्न श्रेणी 2009 से सबसे नवीनतम है, अन्य दो 1997 से कार्य कर रही हैं।
- 2022 तक, 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 मिनीरत्न हैं
- सरकार इन सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न, मिनीरत्न और महारत्न का दर्जा देती है।
- 2009 में, सरकार ने महारत्न का दर्जा स्थापित किया, जिसने कंपनी की निवेश सीमा को रु. से बढ़ा दिया। 1,000 करोड़ से रु. 5,000 करोड़. महारत्न कंपनियाँ अब किसी परियोजना में अपनी कुल संपत्ति का 15 प्रतिशत तक निवेश करने का निर्णय ले सकती हैं; नवरत्न कंपनियां स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती हैं।

मिनीरत्नों के प्रकार

- मिनीरत्नों को दो श्रेणियों I और II में विभाजित किया जा सकता है।
- श्रेणी I से संबंधित मिनीरत्न के लिए रुपये तक की वित्तीय स्वायत्तता। 500 करोड़ या उनकी कुल संपत्ति के बराबर, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।
- रुपये तक की श्रेणी II मिनीरत्न वित्तीय स्वायत्तता। 300 करोड़ या उनकी निवल संपत्ति का 50% तक, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

कुछ महारत्न कंपनियों के उदाहरण-

I. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
II. कोल इंडिया लिमिटेड
III. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल)
IV. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
V. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड)
VI. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)
VII. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
VIII. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कुछ नवरत्न कंपनियों के उदाहरण

I. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)
II. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
III. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
IV. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
V. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
VI. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
VII. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

भूमंडलीकरण

- वैश्वीकरण को 'राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण में वृद्धि' कहा जाता है।
- डब्ल्यूटीओ के लिए, वैश्वीकरण का आधिकारिक अर्थ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का "वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही" की ओर बढ़ना है।

- वैश्वीकरण निम्नलिखित की राष्ट्रीय सीमाओं के पार मुक्त आवागमन के माध्यम से विश्व आर्थिक एकीकरण है:
- वित्तीय पूंजी का प्रतिनिधित्व पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में निवेश द्वारा किया जाता है,
    - संयंत्र और मशीनरी द्वारा प्रदर्शित भौतिक पूंजी
    - तकनीकी

वैश्वीकरण के मुख्य तत्व

- घरेलू बाजारों को विदेशी वस्तुओं के प्रवाह के लिए खोलने के लिए, भारत ने आयात पर सीमा शुल्क घटाकर केवल 10% कर दिया।
- आयात लाइसेंसिंग लगभग ख़त्म कर दी गयी है.
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए टैरिफ बाधाओं को भी महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है।
- भारत सरकार की एफडीआई नीति ने स्वचालित मार्ग के तहत कुछ परियोजनाओं में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति देकर ताजा विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया।

सुधार के बाद के लाभ

- विकास दर में वृद्धि - अर्थव्यवस्था सुधार पूर्व युग की तुलना में तेज़ गति से बढ़ी।
- निर्यात में वृद्धि - निर्यात में काफी वृद्धि हुई। भारत सॉफ्टवेयर निर्यात में वैश्विक नेता है।
- विदेशी निवेश के प्रवाह में वृद्धि
- निजी क्षेत्र का विकास - निजी क्षेत्र ने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया और उत्पादन तथा रोजगार का विस्तार किया
- सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन - सुधारों की शुरुआत के साथ, कुल सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत हो गई।
- विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण 25 जून, 2021 तक $608.99 बिलियन मुद्रा भंडार के साथ, भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है (वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार)

CLASS 11

CHAPTER 4

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ गरीबी
- ✓ गरीबी के प्रकार
- ✓ गरीबी रेखा
- ✓ गरीबी मूल्यांकन से संबंधित समितियाँ
- ✓ गरीबी के कारण
- ✓ सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन के न्यूनतम मानकों का आनंद लेने के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीजों की कमी होती है।
- सापेक्ष गरीबी और पूर्ण गरीबी गरीबी के दो प्रकार हैं।
- सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों या देशों में अन्य लोगों की तुलना में लोगों की गरीबी से है।
- पूर्ण गरीबी का तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या से है।

- गरीबी रेखा उस रेखा को संदर्भित करती है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है जो लोगों को उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
- किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक "न्यूनतम स्तर" से नीचे आता है।
- भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 कैलोरी है।
- तेंदुलकर समिति के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान मासिक आधार पर रु. ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रु. शहरी क्षेत्रों में 1000. जो लोग एक महीने में इतनी रकम भी नहीं कमा पाते, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।
- एक व्यक्ति जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम है उसे गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) माना जाता है, जबकि जो ऐसा करने में असमर्थ हैं उसे इसके नीचे (बीपीएल) कहा जाता है।

स्वतंत्र भारत में गरीबी का आकलन

- दादाभाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- दादाभाई नौरोजी के प्रयासों और सावधानीपूर्वक शोध ने उन्हें निर्वाह-आधारित गरीबी स्तर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया (हालांकि उन्होंने कभी भी "गरीबी रेखा" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया)
- इसकी गणना चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जियां, घी, वनस्पति तेल और नमक के निर्वाह आहार की लागत का उपयोग करके की गई थी।

स्वतंत्र भारत में गरीबी का आकलन

- स्वतंत्र भारत में, देश में गरीबों की संख्या की पहचान करने के लिए एक तंत्र बनाने के कई प्रयास किए गए हैं।
- उदाहरण के लिए, 1962 में योजना आयोग ने एक अध्ययन समूह का गठन किया।
- 1979 में, 'न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स' नामक एक अन्य निकाय का गठन किया गया था। लोकप्रिय रूप से "वाई के अलघ समिति" के नाम से जाना जाता है
- 1979 में वाईके अलघ समिति का सुझाव, जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम या ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम उपभोग करते हैं, वे गरीब हैं, इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव इस तथ्य पर आधारित था कि ग्रामीण लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं।
- परिणामस्वरूप, वाईके अलघ ने भारत की पहली गरीबी रेखा की स्थापना की।
- योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की।
- तेंदुलकर समिति ने गरीबी के मूल्यांकन के लिए जीवन यापन की लागत को एक विधि के रूप में उपयोग किया।
- तेंदुलकर समिति के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान मासिक आधार पर रु. ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रु. शहरी क्षेत्रों में 1000. जो लोग एक महीने में इतनी रकम भी नहीं कमा पाते, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है।
- 2014 में, रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई जिसने ग्रामीण भारत में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को बढ़ाकर 972 रुपये और शहरी भारत में 1,407 रुपये कर दिया।
- रंगराजन समिति की सिफारिशों पर फैसला होना बाकी है।
- इसलिए, तेंदुलकर गरीबी रेखा आधिकारिक गरीबी रेखा बनी हुई है और वर्तमान आधिकारिक गरीबी अनुमान का आधार है

नोट: तेंदुलकर के अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 21.9% है। हालाँकि, रंगराजन के अनुमान के अनुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 29.5% है।

गरीबी का वर्गीकरण:

⟶ दीर्घकालिक गरीब- वे लोग जो हमेशा गरीब रहते हैं और जो आमतौर पर गरीब होते हैं लेकिन जिनके पास कभी-कभी थोड़ा अधिक पैसा हो सकता है (उदाहरण: आकस्मिक श्रमिक) को दीर्घकालिक गरीबों के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

⟶ क्षणिक गरीब- वे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के अंदर और बाहर आते-जाते रहते हैं (उदाहरण: छोटे किसान और मौसमी श्रमिक) और कभी-कभार गरीब जो ज्यादातर समय अमीर रहते हैं लेकिन कभी-कभी दुर्भाग्य का सामना कर सकते हैं। उन्हें क्षणिक गरीब कहा जाता है।

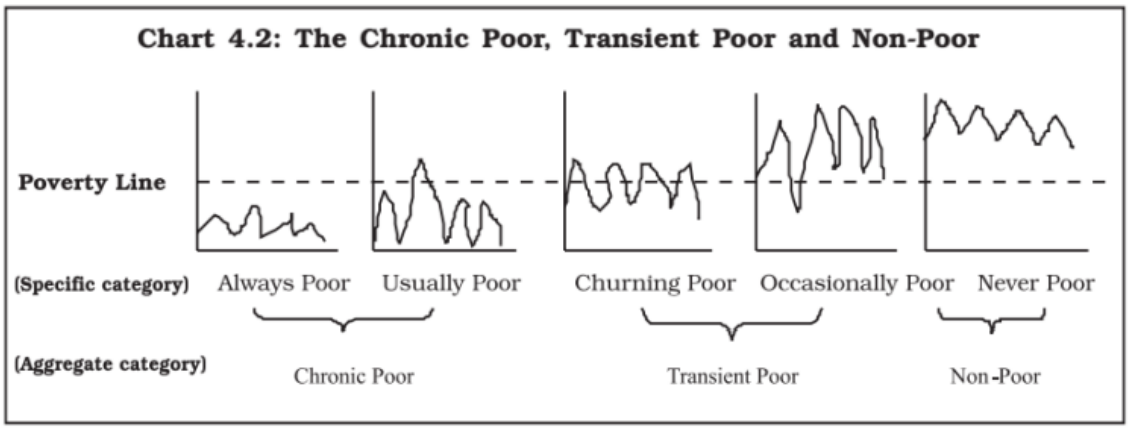

भारत में गरीबी के कारण

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर: औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया और कपड़ा जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया।

2. 1980 के दशक तक विकास की निम्न दर:

- इसके परिणामस्वरूप नौकरी के अवसर कम हुए और आय की वृद्धि दर कम हुई।
- इसके साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर भी थी।
- दोनों ने मिलकर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया।
- दोनों मोर्चों पर विफलता: आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जनसंख्या नियंत्रण ने गरीबी के चक्र को कायम रखा

3. सिंचाई और हरित क्रांति:

- सिंचाई के प्रसार और हरित क्रांति के साथ, कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर पैदा हुए।
- लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था

4. उद्योग:

- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने कुछ नौकरियाँ प्रदान कीं। लेकिन ये सभी नौकरी चाहने वालों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- शहरों में उचित नौकरियाँ न मिलने पर कई लोगों ने रिक्शा चालक, विक्रेता, निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
- अनियमित छोटी आय के कारण, ये लोग महंगे आवास का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।
- उन्होंने शहरों के बाहरी इलाकों में झुग्गियों में रहना शुरू कर दिया और गरीबी की समस्या, जो काफी हद तक एक ग्रामीण घटना थी, शहरी क्षेत्र की विशेषता भी बन गई।

5. आय असमानताएँ:

- उच्च गरीबी दर की एक अन्य विशेषता भारी आय असमानताएं रही हैं।
- इसका एक प्रमुख कारण भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण है।
- भूमि सुधारों को ठीक से लागू नहीं किया गया है और पर्याप्त भूमि संसाधनों की कमी भी कई लोगों के गरीब होने का एक कारण है।
- छोटे किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि के लिए पैसे उधार लेते हैं और बाद में भुगतान करने में असफल हो जाते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऋणग्रस्तता का यह उच्च स्तर गरीबी का कारण और प्रभाव दोनों है।
- चूंकि भूमि संसाधनों की कमी भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण रही है, इसलिए नीति के उचित कार्यान्वयन से लाखों ग्रामीण गरीबों के जीवन में सुधार हो सकता है।

गरीबी निवारण उपाय

- गरीबी हटाना भारतीय विकासात्मक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान गरीबी-विरोधी रणनीति निम्नलिखित दो उद्देश्यों पर आधारित है -

(iii) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:

- सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। 1980 के दशक तक आर्थिक विकास कम था लेकिन तब से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है।
- उच्च आर्थिक विकास गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करता है। आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच मजबूत संबंध है।
- आर्थिक विकास अवसरों को बढ़ाता है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
- उच्च आर्थिक विकास लोगों को शिक्षा में निवेश से बेहतर आर्थिक रिटर्न की उम्मीद के साथ अपने बच्चों (लड़कियों सहित) को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- लेकिन फिर भी, ग्रामीण गरीब आर्थिक विकास का सीधा लाभ नहीं उठा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग गरीब बने हुए हैं

(iv) लक्षित गरीबी-विरोधी कार्यक्रम-

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)-
- यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। प्रस्तावित नौकरियों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी।
- इसी प्रकार, राज्य सरकारें योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के तहत, यदि किसी आवेदक को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

- (पीडीएस) जो भोजन और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई, गरीबी उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह कार्यक्रम भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल और चीनी जैसी वस्तुओं का आवंटन।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए राशन कार्ड जारी करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान।
- भोजन की कमी का प्रबंधन और खाद्यान्न का वितरण।

- पीडीएस को बाद में जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के रूप में लॉन्च किया गया था और इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीपीडीएस खाद्यान्न की उचित व्यवस्था और वितरण के लिए गरीबों की पहचान और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए, भारत सरकार के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) पीडीएस के समान ही भूमिका निभाती है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

- इसे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त शुरू किया गया था। एनआरएलएम का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के लिए एक कुशल और प्रभावी प्रणाली बनाना है।
- जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।
- उस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य गरीबों को अपनी घरेलू आय बढ़ाने के लिए सशक्त और सक्षम बनाकर स्थायी अवसर पैदा करना है। गरीबों को आय-सृजित संपत्ति के अलावा - उन्हें अधिकारों, हकदारियों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- मिशन का उद्देश्य गरीबों की जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करना और उन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना है। 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) कर दिया गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- इसे 2013 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह स्वयं सहायता समूहों में शहरी गरीबों को संगठित करने, बाजार-आधारित रोजगार के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करने और ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके उन्हें स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने में मदद करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- इसे 2014 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना था और 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया। यह योजना विशेष रूप से बैंक रहित गरीबों को लक्षित करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- इसे 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था
- सभी के लिए आवास योजना झुग्गीवासियों के लिए आवास सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी। इसे भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
- इसका उद्देश्य शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पीने के पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ठोस और स्थायी आवास प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

- इसे 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- इसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने की परिकल्पना की गई है

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम), पोषण अभियान

- इसे 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- अल्प-पोषण के स्तर को कम करना और देश में बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाना। साथ ही, किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)

- इसे 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था
- यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि

- इसे 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म-ऋण सुविधाएं प्रदान करना है

CLASS 11
CHAPTER 5

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ मानव पूंजी
- ✓ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण की भूमिका
- ✓ भारत शिक्षा पर कितना खर्च करता है

मानव पूंजी निर्माण

- मानव पूंजी निर्माण किसी देश में लोगों को ऐसे श्रमिकों में बदलने की प्रक्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम हैं।
- इस प्रक्रिया के दौरान, अपेक्षाकृत अकुशल व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल दिए जाते हैं।
- मानव पूंजी का तात्पर्य एक समय में किसी राष्ट्र के 'कौशल और विशेषज्ञता' के भंडार से है। यह कौशल और विशेषज्ञता का कुल योग है।
- मानव पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में वृद्धि की प्रक्रिया है।
- मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है।
- मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए अभिन्न अंग हैं क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने की क्षमता होगी और लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता होगी, तभी वे योगदान देने में सक्षम होंगे उनका समाज और राष्ट्र.

मानव पूंजी निर्माण के स्रोत

- ✓ शिक्षा पर व्यय

- ✓ स्वास्थ्य पर व्यय
- ✓ नौकरी के प्रशिक्षण पर
- ✓ प्रवास
- ✓ सूचना पर व्यय

शिक्षा पर व्यय

शिक्षा व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह देश में उत्पादक कार्यबल को बढ़ाने और बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। राष्ट्र और व्यक्ति निम्नलिखित उद्देश्य से शिक्षा में निवेश करते हैं:

- उनकी भविष्य की आय में वृद्धि।
- तकनीकी कौशल पैदा करना और जनशक्ति तैयार करना, श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए उपयुक्त है और इस प्रकार, तेजी से आर्थिक विकास को बनाए रखना है।
- जन्म दर को कम करने के लिए जो बदले में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट लाता है। यह प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है।
- शिक्षा से सामाजिक लाभ भी होता है क्योंकि यह दूसरों तक भी फैलता है।

शिक्षा निम्नलिखित कारणों से मानव पूंजी निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

1. एक शिक्षित मनुष्य को अर्थव्यवस्था के लिए एक संपत्ति माना जा सकता है, दायित्व नहीं।
2. शिक्षा किसी व्यक्ति को आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकती है। यह राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है और सरकार की दक्षता बढ़ाता है।
3. यह गुणवत्ता और मात्रा के मामले में व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाता है।
4. क्योंकि शिक्षित होने से जहां व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वहीं समाज के प्रति चेतना भी विकसित होती है।
5. एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में भी जागरूक होता है और इससे अंततः देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

स्वास्थ्य पर व्यय

- स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है।
- चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच के बिना एक बीमार मजदूर को काम से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उत्पादकता में कमी आती है।
- यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो बीमारी से लड़ने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है।
- स्वस्थ रहने से व्यक्ति के समग्र परिणाम में भी वृद्धि होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति की कार्यक्षमता एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है।
- किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे तौर पर उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में काम करने में अधिक समय व्यतीत कर सकता है।
- इस प्रकार, बेहतर स्वास्थ्य से कार्यक्षमता बढ़ेगी। उपर्युक्त बिंदु साबित करते हैं कि यदि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के उपाय किए जाएं जिससे देश में एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो मानव पूंजी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

नौकरी के प्रशिक्षण पर

- नौकरी पर प्रशिक्षण से संबंधित व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है क्योंकि बढ़ी हुई श्रम उत्पादकता के रूप में ऐसे व्यय की वापसी इसकी लागत से अधिक है।
- कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी पर प्रशिक्षण देने पर भारी रकम खर्च करती हैं। यह विभिन्न रूपों में हो सकता है जैसे किसी कर्मचारी को फर्म में ही या किसी कुशल कर्मचारी की देखरेख में प्रशिक्षित किया जा सकता है या ऑफ कैंपस प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है।
- कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि श्रमिकों को उनकी कंपनी में कम से कम कुछ समय के लिए काम करना चाहिए ताकि वे प्रशिक्षण के कारण बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ उठा सकें।

प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा व्यय

उदाहरण: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारतीय युवा आबादी को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाती है। इस प्रशिक्षण से उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिली।

प्रवास

लोग उच्च आय संभावनाओं वाली नौकरियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार लोग नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।
- तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति (जैसे इंजीनियर, डॉक्टर आदि) दूसरे देशों में चले जाते हैं क्योंकि ऐसे देशों में उन्हें अधिक वेतन मिल सकता है।
- इन दोनों मामलों में प्रवासन में दो प्रकार की लागत शामिल होती है: एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन की लागत, प्रवासित स्थानों में रहने की उच्च लागत।

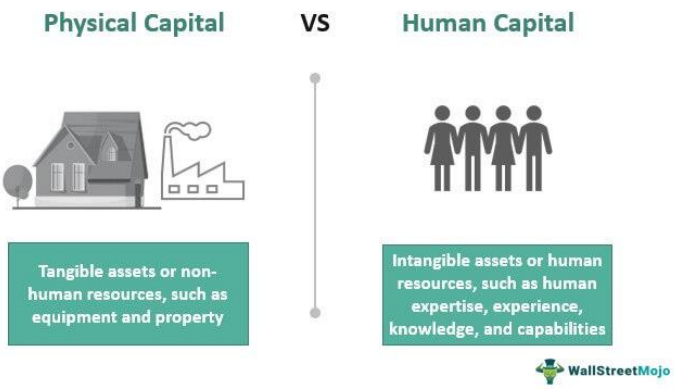

1. प्रवासन पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है क्योंकि प्रवासित स्थान पर बढ़ी हुई कमाई प्रवासन के कारण लागत में वृद्धि से अधिक है।
2. इससे कौशल के उचित उपयोग के माध्यम से पूंजी निर्माण होता है।

सूचना पर व्यय

लोगों ने श्रम बाजार और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य बाजारों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए खर्च किया। उदाहरण के लिए, लोग विभिन्न श्रम बाजारों में उपलब्ध वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, ताकि वे सही नौकरी चुन सकें। श्रम बाजारों और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।

मानव पूंजी निर्माण की समस्याएँ क्या हैं?	
मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएँ हैं:	
(1) बढ़ती जनसंख्या	• बढ़ती जनसंख्या मानव पूंजी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। • यह स्वच्छता, रोजगार, जल निकासी, जल व्यवस्था, आवास, अस्पताल, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, पोषण, सड़क, बिजली आदि जैसी मौजूदा सुविधाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को कम कर देता है।
(2) उच्च क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता	• क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता मानव विकास स्तर को कम करती है। • कम विकसित देशों में अकुशल जनशक्ति नियोजन है जहां तकनीकी श्रम बल की मांग और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न चरणों में शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।
(3) प्रतिभा पलायन	• 'ब्रेन ड्रेन' अत्यधिक कुशल श्रमिकों का प्रवास है। • इसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
(4) उच्च गरीबी स्तर	• जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। • आय के निम्न स्तर के कारण वे उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या महंगी चिकित्सा सुविधाएं वहन नहीं कर सकते।

मानव पूंजी और आर्थिक विकास

- मानव पूंजी निर्माण से भौतिक पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि विशिष्ट इंजीनियर और कुशल श्रमिक निश्चित रूप से मशीनों को दूसरों की तुलना में बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।

- मानव पूंजी उत्पादन के नए तरीकों के आविष्कार की सुविधा प्रदान करती है और इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के रूप में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है।
- इसी प्रकार, शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन की सुविधा प्रदान करती है।
- मानव पूंजी निर्माण से रोजगार दर में वृद्धि होती है। रोजगार बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही, रोजगार के अवसरों में वृद्धि से आय का स्तर बढ़ता है और इससे धन की असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। रोजगार दर में वृद्धि और आय असमानताओं में कमी दोनों ही आर्थिक विकास के सूचक हैं।
- मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाती है जो रूढ़िवादी और पारंपरिक सोच से अलग है, और इसलिए कार्यबल में भागीदारी की दर बढ़ जाती है जिससे उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है

भारत में शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान में सुधार और कौशल विकसित करने के लिए विशेष रूप से स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से है। निम्नलिखित बिंदु शिक्षा के महत्व या उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं-

- यह अच्छे नागरिक पैदा करता है।
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करता है।
- यह देश के सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक और मानव संसाधनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाता है।
- यह लोगों के मानसिक क्षितिज का विस्तार करता है।

शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि

शिक्षा पर सरकारी व्यय को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है

- कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में।

कुल सरकारी व्यय में शिक्षा व्यय का प्रतिशत सरकार की व्यय योजना में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है।
हमारी जीडीपी से शिक्षा पर खर्च यह दर्शाता है कि हम अपने देश में शिक्षा के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।

भारत शिक्षा पर कितना खर्च करता है?

नोट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% निवेश करने का आह्वान करती है। भारत का शिक्षा बजट अभी तक इस संख्या को कभी नहीं छू पाया है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण (2021) के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय था:

- 2019-20: 2.8%
- 2020-21: 3.1%
- 2021-22: 3.1%

- केंद्रीय शिक्षा बजट 2022 मुख्य रूप से डिजिटल शिक्षा, डिजिटल विश्वविद्यालय के निर्माण, रोजगार सृजन, कृषि विश्वविद्यालयों, प्रोग्रामर के कौशल विकास आदि पर केंद्रित है।
- शिक्षा बजट 2022 को 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं - जो पिछले वर्ष से 11,054 करोड़ रुपये अधिक है। 2021-22 के लिए शिक्षा बजट आवंटन रुपये था। 93,223 करोड़.
- सकल घरेलू उत्पाद के 6% मानदंड को पूरा करने के लिए, 2022-23 के लिए शिक्षा बजट पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग दोगुना होना चाहिए था।

CLASS 11

CHAPTER 6

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ ग्रामीण विकास
- ✓ ग्रामीण ऋण
- ✓ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- ✓ कृषि विपणन
- ✓ मंडियां (किसान बाजार)
- ✓ नाबार्ड

- ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु एक कार्य-योजना से है। ग्रामीण विकास की कार्ययोजना के प्रमुख मुद्दे हैं

- ✓ बुनियादी ढांचे का विकास
- ✓ मानव पूंजी निर्माण
- ✓ उत्पादक संसाधनों का विकास
- ✓ गरीबी निर्मूलन
- ✓ भूमि सुधार

- ग्रामीण विकास आमतौर पर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और वित्तीय कल्याण को बढ़ाने की विधि को संदर्भित करता है, विशेष रूप से आबादी वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले।
- ग्रामीण विकास अभी भी देश के समग्र विकास का मूल बना हुआ है। देश के दो-तिहाई से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और ग्रामीण भारत का एक-तिहाई हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। इसलिए, सरकार के लिए उत्पादक होना और उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- ग्रामीण विकास एक ऐसा शब्द है जो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ग्रामीण विकास का महत्व
- ग्रामीण विकास न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र के समग्र आर्थिक विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- आज देश में ग्रामीण विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो ग्रामीण निवासियों के बीच बेहतर उत्पादकता, उच्च सामाजिक-आर्थिक समानता और स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करती है।
- प्राथमिक कार्य लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में मौजूद भूख की समस्याओं को कम करना और पर्याप्त और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है।
- द्वितीयक कार्य कपड़े और जूते, स्वच्छ वातावरण और घर, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन प्रावधान, शिक्षा, परिवहन और संचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण विकास के उद्देश्य

- ग्रामीण लोगों की उत्पादकता और मजदूरी में सुधार करना
- बढ़ी हुई और त्वरित रोजगार संभावनाओं की गारंटी देना

- बेरोजगारी को ध्वस्त करना और अल्परोजगार में उल्लेखनीय गिरावट लाना
- वंचित आबादी के जीवन स्तर में वृद्धि की गारंटी देना
- बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करना: प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आदि।

ग्रामीण ऋण

- ग्रामीण ऋण का अर्थ कृषक परिवारों के लिए ऋण है। नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ग्रामीण वित्तपोषण में सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी।
- ऋण कृषि गतिविधि की जीवन रेखा है। सामान्य भारतीय किसान की ऋण आवश्यकताओं को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. अल्पावधि ऋण- मूल रूप से बीज, उर्वरक आदि जैसे इनपुट की खरीद से संबंधित है। अल्पकालिक उधार आम तौर पर 6 से 12 महीने की अवधि तक चलता है।
2. मध्यम अवधि ऋण- बाड़ बनाने और कुएं खोदने वाली मशीनरी खरीदने के लिए मध्यम अवधि के ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसे ऋण आम तौर पर 12 महीने से 5 साल की अवधि के लिए होते हैं।
3. दीर्घकालिक ऋण- यह अतिरिक्त भूमि की खरीद के लिए है। ऐसे लोन की अवधि 5 से 20 साल के बीच होती है.

ग्रामीण ऋण के स्रोत:

ग्रामीण ऋण की उपलब्धता को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- गैर-संस्थागत स्रोत: ये भारत में कृषि ऋण के पारंपरिक स्रोत हैं। इनमें साहूकार, रिश्तेदार, व्यापारी और जमींदार शामिल हैं।
- संस्थागत स्रोत: संस्थागत स्रोतों में शामिल हैं- वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि।

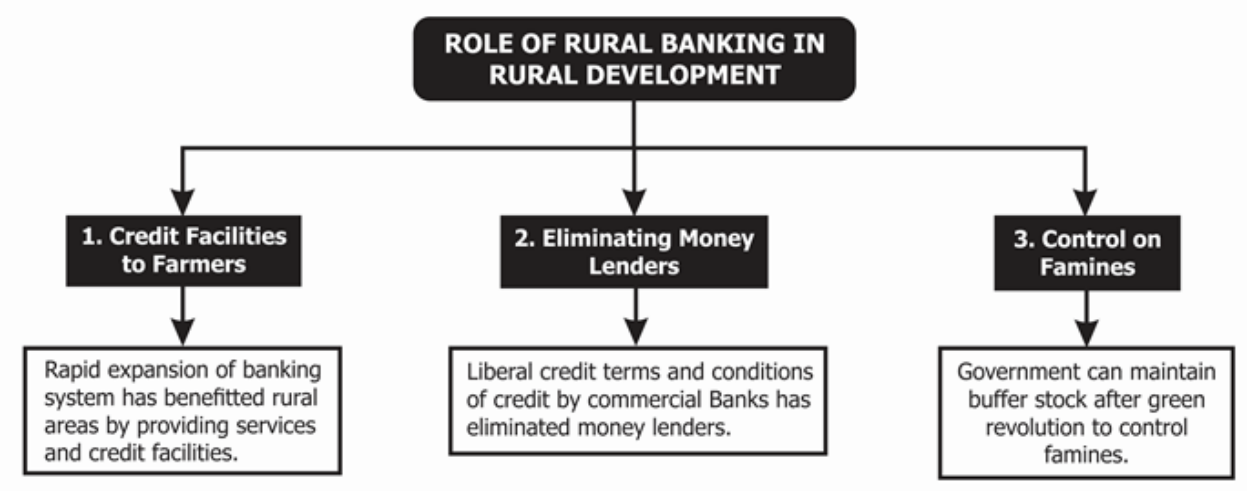

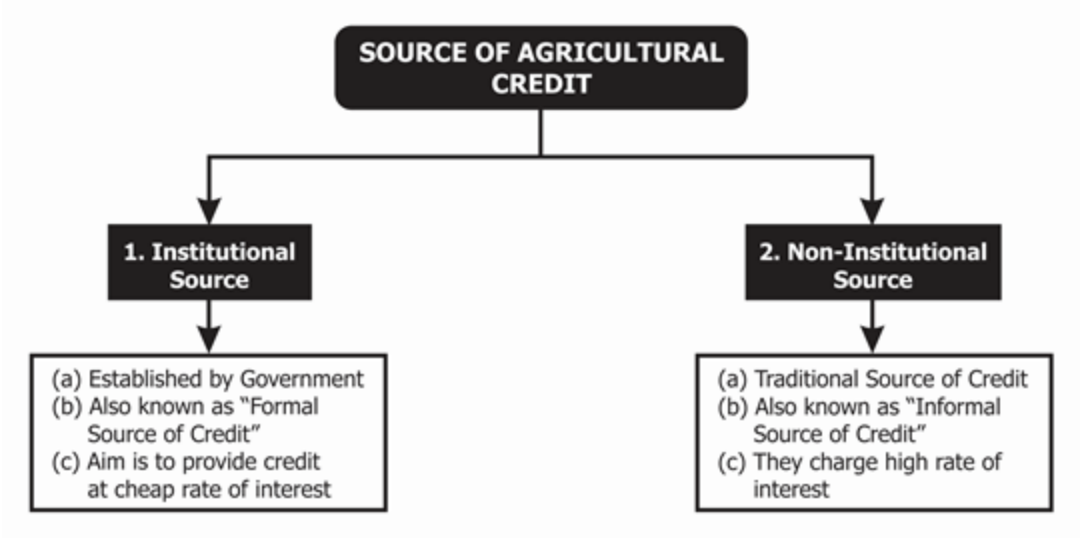
SOURCE OF AGRICULTURAL CREDIT
1. Institutional Source
(a) Established by Government
(b) Also known as "Formal Source of Credit"
(c) Aim is to provide credit at cheap rate of interest
2. Non-Institutional Source
(a) Traditional Source of Credit
(b) Also known as "Informal Source of Credit"
(c) They charge high rate of interest

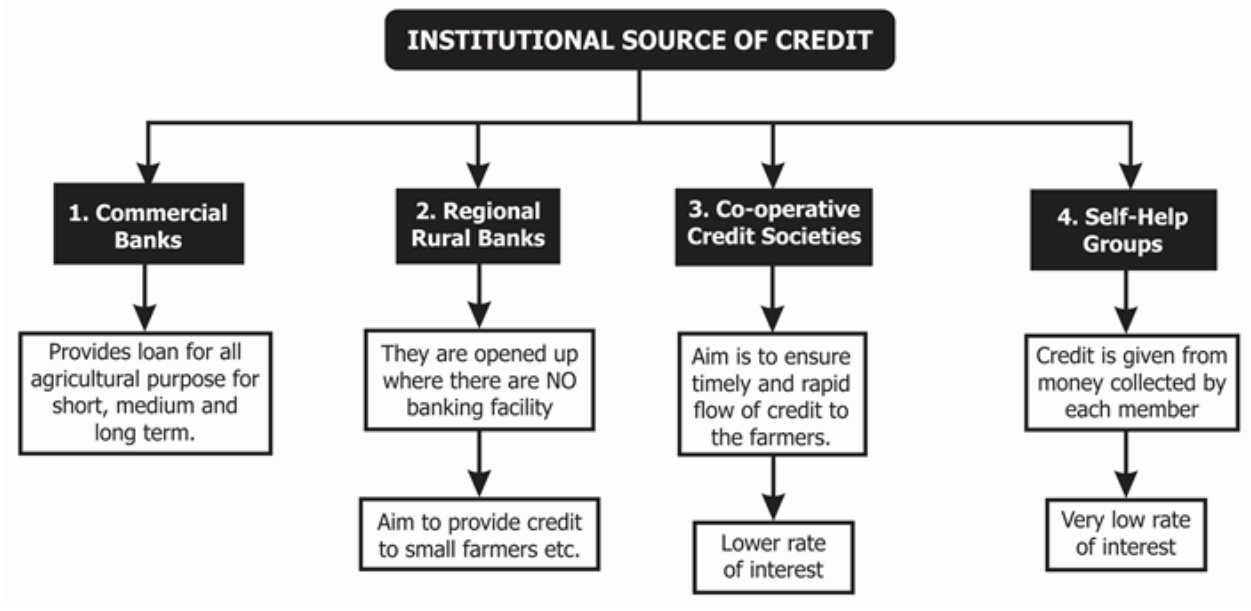
INSTITUTIONAL SOURCE OF CREDIT
1. Commercial Banks
Provides loan for all agricultural purpose for short, medium and long term.
2. Regional Rural Banks
They are opened up where there are NO banking facility
Aim to provide credit to small farmers etc.
3. Co-operative Credit Societies
Aim is to ensure timely and rapid flow of credit to the farmers.
Lower rate of interest
4. Self-Help Groups
Credit is given from money collected by each member
Very low rate of interest

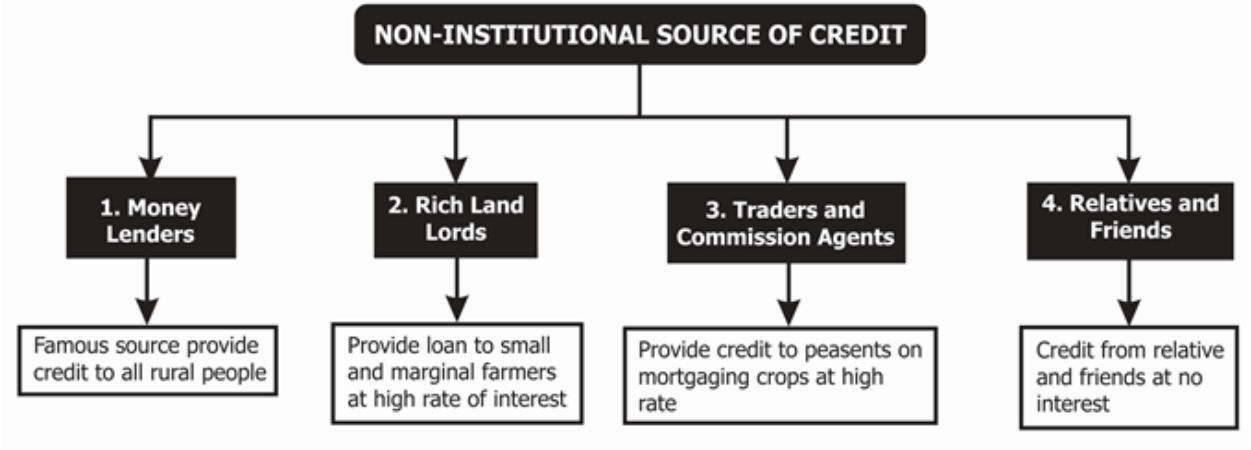
NON-INSTITUTIONAL SOURCE OF CREDIT
1. Money Lenders
Famous source provide credit to all rural people
2. Rich Land Lords
Provide loan to small and marginal farmers at high rate of interest
3. Traders and Commission Agents
Provide credit to peasents on mortgaging crops at high rate
4. Relatives and Friends
Credit from relative and friends at no interest

सहकारी ऋण समिति

- सहकारी क्रेडिट सोसायटी समाज में आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। ऐसी सोसायटी को सहकारी समिति अधिनियम के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसी समितियों का उद्देश्य सदस्यों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाना है जो ऋण पर उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। ऐसी समितियाँ सदस्यों से पूंजी और जमा के रूप में एकत्र की गई राशि से सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं और कम ब्याज दरें वसूलती हैं।
- एक क्रेडिट सहकारी समिति एक क्रेडिट सोसायटी है जो सदस्य-स्वामित्व वाली वित्तीय सहकारी है और इसके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होती है। इलाके के निवासियों के लिए सदस्यता सभी के लिए खुली है।
- वे सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकते हैं और सदस्यों को ऋण दे सकते हैं। लाभ या हानि को सदस्यों के बीच साझा किया जाता है।
- क्रेडिट सहकारी समिति अपने अध्यक्ष और निदेशक मंडल का चुनाव करती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

- आरआरबी वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप (1975) की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के कानून के बाद की गई थी।
- पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "प्रथम ग्रामीण बैंक" 2 अक्टूबर, 1975 को स्थापित किया गया था।
- हितधारक: एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास 50:15:35 के अनुपात में होती है।
- आरआरबी ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के मामले में सहकारी की विशेषताओं और व्यावसायिकता और वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता के मामले में एक वाणिज्यिक बैंक की विशेषताओं को जोड़ते हैं।
- प्रत्येक आरआरबी सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय सीमा के भीतर संचालित होता है।

आरआरबी के मुख्य उद्देश्य हैं

- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जमा के बहिर्प्रवाह को रोकना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

- आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है

कृषि विपणन

- कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। कृषि विपणन में, किसी कृषि उत्पाद की बिक्री विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे उस समय उत्पाद की मांग, भंडारण की उपलब्धता आदि।
- आजादी से पहले, किसानों को व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचते समय बड़े पैमाने पर गलत तौल और खातों में हेराफेरी का सामना करना पड़ता था। किसानों को कीमतों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं थी और उचित भंडारण सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- कभी-कभी, उत्पाद को किसान के गाँव के साप्ताहिक बाज़ार या पड़ोसी गाँव में बेचा जा सकता है। यदि ये दुकानें उपलब्ध नहीं हैं, तो उत्पाद को पास के गांव या कस्बे के अनियमित बाजारों में या मंडी में बेचा जाता है। इसलिए, सरकार ने व्यापारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए

कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- प्रारंभिक कदम बाजार को विनियमित करना और एक स्वच्छ, पारदर्शी और सरल विपणन रणनीति की योजना बनाना था। इस विनियमन से किसानों और उपभोक्ता दोनों को मदद मिली।

- दूसरा उपाय परिवहन सुविधाएं, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और प्रसंस्करण इकाई जैसी खरीद प्रक्रिया थी। हालाँकि, मौजूदा बुनियादी ढाँचा बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- तीसरा पहलू उत्पाद का उचित मूल्य तय करना है। अतीत में, किसान सदस्यों की असमान कवरेज और विपणन, प्रसंस्करण सहकारी समितियों और अकुशल वित्तीय प्रबंधन के बीच उपयुक्त लिंक की अनुपस्थिति के कारण यह एक झटका रहा है। एक सफल सहकारी समिति का उदाहरण गुजरात दुग्ध सहकारी समिति है जिसने गुजरात के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया।
- नीतियां जैसे-

1. कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी
2. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक का भंडारण
3. पीडीएस के माध्यम से भोजन का वितरण

ये सभी उपाय किसानों की आय की रक्षा करने और वंचितों को रियायती दर पर कृषि उत्पाद खरीदने के लिए किए गए थे। हालाँकि, कृषि विपणन में सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद, निजी व्यापारी अभी भी कृषि बाजारों पर हावी हैं।

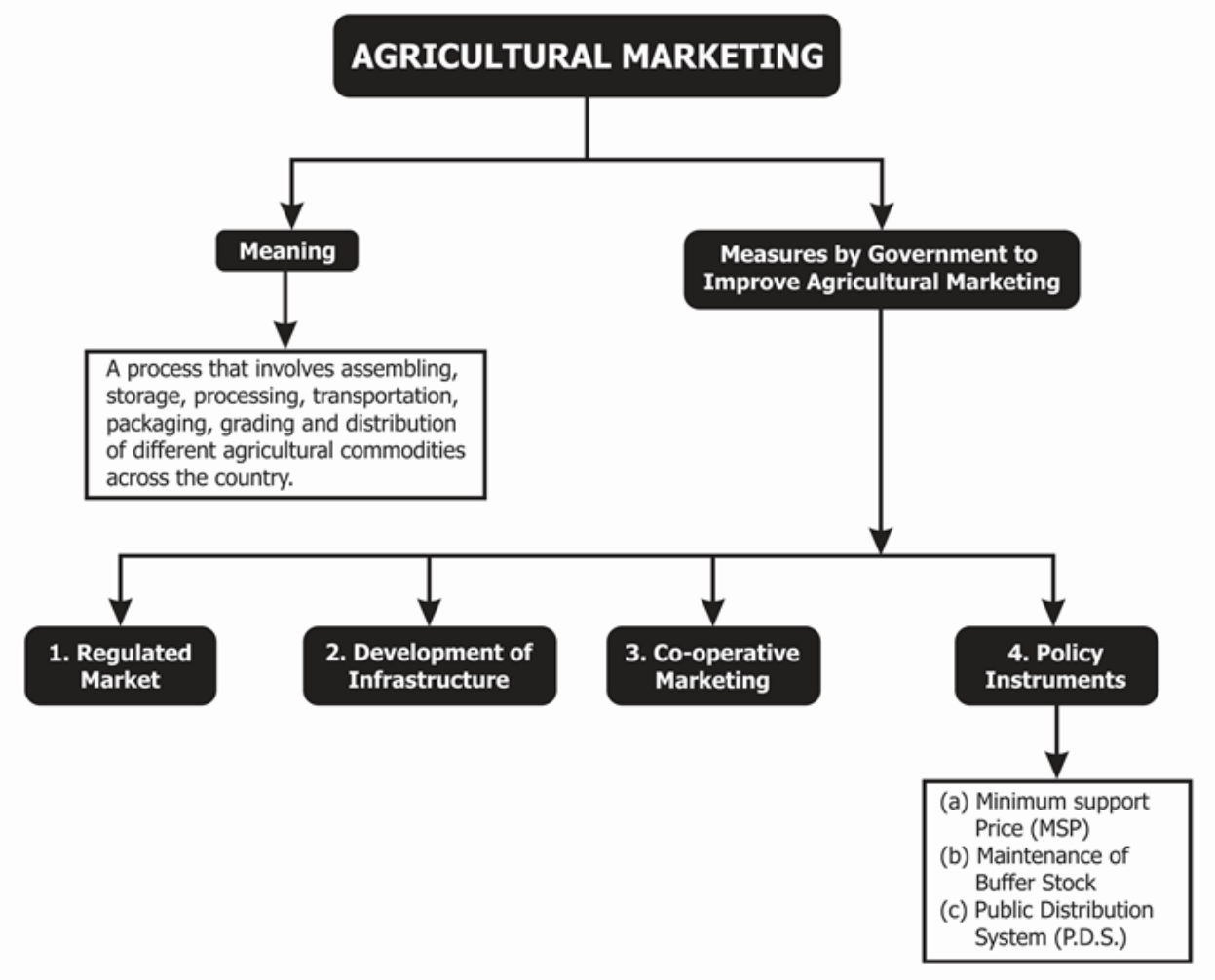

राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग

- कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड श्रृंखलाएं तेजी से किसानों के साथ अनुबंध कर रही हैं।
- वे किसानों को न केवल बीज और अन्य सामग्री प्रदान करके उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बल्कि पूर्व-निर्धारित कीमतों पर उत्पाद की खरीद की गारंटी भी देते हैं।

- इस प्रकार की व्यवस्था से किसानों के लिए मूल्य जोखिम कम होता है और बाजार में कृषि उत्पाद बढ़ता है।

किसान बाज़ार (मंडी/बाज़ार)

यह महसूस किया गया है कि यदि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं, तो इससे उनकी आय बढ़ती है। छोटे किसानों को उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए किसान बाजार की शुरुआत की गई थी।

किसान बाज़ारों के कुछ उदाहरण हैं:

1. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी
2. पुणे में हडस्पर मंडी
3. आंध्र प्रदेश में रायथू बाज़ार
4. तमिलनाडु में उझावर सैंडीज़ (किसान बाज़ार)।

ग्रामीण आबादी के लिए उत्पादन गतिविधि/रोजगार के गैर-कृषि क्षेत्र

पशुपालन-

- पशुपालन कृषि का विज्ञान है जहां जानवरों को मांस, फाइबर, अंडे, दूध और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए पाला, पाला और बड़ा किया जाता है। पशुधन (कृषि पशुओं को एक संपत्ति माना जाता है) उत्पादन अन्य खाद्य उत्पादन गतिविधियों को बाधित किए बिना परिवार के लिए आय, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन और पोषण में स्थिरता प्रदान करता है। आज, अकेले पशुधन क्षेत्र भूमिहीन मजदूरों सहित 70 मिलियन से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को वैकल्पिक आजीविका विकल्प प्रदान करता है।

भारत में पशुपालन

- पशुधन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 4% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25% योगदान देता है।
- पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार, भारत में पशुधन में पिछली जनगणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि देखी गई।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा पशुधन उत्पादकता को आय वृद्धि के सात स्रोतों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

भारत में पशुधन पालन का महत्व

→ **आय:** फसल उत्पादन के विपरीत, पशुधन आय का एक सुरक्षित स्रोत है। इसके अलावा, भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों का उपयोग संकट के समय में शादी, बीमार व्यक्तियों के इलाज जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

→ **रोजगार:** पशुधन ग्रामीण लोगों के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है जो फसल उत्पादन की मौसमी प्रकृति के कारण बेरोजगार रहते हैं। साथ ही, पशुधन कृषि में छिपी बेरोजगारी के जोखिम को कम करता है।

→ **भोजन:** पशुधन बुनियादी पौष्टिक आहार जैसे दूध, अंडा, मांस आदि भी प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक संकट के समय भी स्वस्थ आहार सुनिश्चित होता है।

→ सामाजिक सुरक्षा: जानवर समाज में उनकी स्थिति के संदर्भ में मालिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे परिवार, विशेषकर भूमिहीन जिनके पास जानवर हैं, उन परिवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं जिनके पास जानवर नहीं हैं।

→ **लैंगिक समानता:** पशुपालन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। पशुधन उत्पादन में श्रम की मांग का 3/4 से अधिक हिस्सा महिलाओं द्वारा पूरा किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में पशुधन क्षेत्र में महिला रोजगार की हिस्सेदारी लगभग 90% है।

→ **आपदाओं से सुरक्षा:** सूखे, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ पशुधन सबसे अच्छा बीमा है। अधिकांश पशुधन आबादी सीमांत और छोटे आकार की जोत में केंद्रित है

→ **मत्स्य पालन**- भारत में मछली पकड़ने वाला समुदाय मछली पकड़ने के अंतर्देशीय स्रोतों और समुद्री स्रोतों पर लगभग समान रूप से निर्भर करता है। अंतर्देशीय स्रोतों में नदियाँ, झीलें, तालाब और झरने आदि शामिल हैं।

→ **बागवानी**-बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों और फूलों के अलावा कई अन्य फसलें शामिल हैं। समय के साथ, बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

- बदलती जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के कारण, भारत ने विविध बागवानी फसलें जैसे फल, सब्जियां, कंद फसलें, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले और वृक्षारोपण फसलें उगाने को अपनाया है।
- ये फसलें भोजन, पोषण और रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1991-2003 के बीच की अवधि को 'स्वर्णिम क्रांति' कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान, बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पादक हो गया और यह क्षेत्र एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में उभरा।
- भारत आम, केला, नारियल, काजू, मेवे और कई प्रजातियों जैसे विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन में विश्व नेता के रूप में उभरा है और फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- बागवानी में लगे कई लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और यह कई वंचित वर्गों के लिए आजीविका में सुधार का साधन बन गया है।
- कुटीर और घरेलू उद्योग- इस उद्योग में कताई, बुनाई, रंगाई और ब्लीचिंग जैसी गतिविधियों का वर्चस्व रहा है।

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)

- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है।
- यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ऐसे किसी भी अन्य गांव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है।
- यह 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

नाबार्ड के कार्य

- नाबार्ड की पहल का उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्य-उन्मुख विभागों के माध्यम से एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जिसे मोटे तौर पर तीन प्रमुखों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षण।
  - यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
  - यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योग को मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए जिला स्तरीय ऋण योजनाएँ तैयार करता है।
- यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की निगरानी करता है।
- यह केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को डिजाइन करने और उनके कार्यान्वयन में शामिल है।
- यह हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और इन वस्तुओं को बेचने के लिए एक विपणन मंच विकसित करने में उनकी मदद करता है।
- नाबार्ड के पास अग्रणी वैश्विक संगठनों और विश्व बैंक से संबद्ध संस्थानों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां हैं जो ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में नई जमीनें तोड़ रही हैं।
- ये अंतरराष्ट्रीय साझेदार ग्रामीण लोगों के उत्थान के साथ-साथ विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते हैं।

CLASS 11

CHAPTER 7

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ बेरोजगारी
- ✓ बेरोजगारी के प्रकार
- ✓ श्रमिकों के प्रकार
- ✓ कार्य बल और श्रम बल
- ✓ एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन)
- ✓ बेरोजगारी के कारण
- ✓ बेरोजगारी से निपटना

→ **उत्पादन गतिविधि:** यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। नियोजित व्यक्ति वे हैं जो किसी न किसी उत्पादन गतिविधि में लगे हुए हैं।

- स्व-रोज़गार और किराये पर लिए गए श्रमिक: स्व-रोज़गार श्रमिक वे हैं जो अपने स्वयं के व्यवसाय या स्वयं के पेशे में लगे हुए हैं। किराये पर लिए गए कर्मचारी वे होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। वे दूसरों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं, पुरस्कार के रूप में, वेतन/वेतन प्राप्त करते हैं या शायद उन्हें किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है।
- आकस्मिक और नियमित श्रमिक: आकस्मिक श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा नियमित आधार पर काम पर नहीं रखा जाता है। नियमित कर्मचारी अपने नियोक्ता के स्थायी पे-रोल होते हैं। एक नियमित कर्मचारी आमतौर पर एक कुशल श्रमिक होता है।

→ **श्रम आपूर्ति:** इसका तात्पर्य विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। श्रम की आपूर्ति को कार्य के मानव-दिनों के संदर्भ में मापा जाता है।

→ **श्रम बल:** इसका तात्पर्य वास्तव में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या से है।

→ **कार्यबल:** यह वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करता है और उन लोगों को शामिल नहीं करता है जो काम करने के इच्छुक हैं।

→ कार्यबल का अनौपचारिकीकरण: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल का प्रतिशत घट जाता है और अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाता है।

श्रमिक-जनसंख्या अनुपात:

- श्रमिक-जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जिसका उपयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
- यह अनुपात किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देने वाली जनसंख्या के अनुपात को जानने में उपयोगी है।
- यदि अनुपात अधिक है, तो इसका मतलब है कि लोगों की सहभागिता अधिक है; यदि किसी देश के लिए अनुपात मध्यम या निम्न है, तो इसका मतलब है कि उसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है।

बेरोजगारी:

- बेरोजगारी तब मानी जाती है जब जो लोग निर्धारित वेतन पर काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है।
- बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति हैं वे देनदारी में बदल जाते हैं।

- जब हम बेरोजगार लोगों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों से होता है। बेरोजगारों की संख्या की गणना करते समय 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों पर विचार नहीं किया जाता है
- बेरोजगारी से आर्थिक अधिभार बढ़ता है। बेरोजगारों की कार्यशील जनसंख्या पर निर्भरता बढ़ जाती है
- कार्यबल जनसंख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग शामिल हैं।

बेरोज़गारी का सबसे आम उपाय बेरोज़गारी दर है, जो बेरोज़गार लोगों की संख्या को श्रम बल में लोगों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) किसी व्यक्ति की निम्नलिखित गतिविधि स्थितियों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:

- काम करना (किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना) यानी, 'रोजगार'।
- काम की तलाश करना या उपलब्ध होना अर्थात 'बेरोजगार'।
- न तो काम की तलाश है और न ही काम उपलब्ध है।
- पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के है।
- बेरोज़गारी दर = (बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम बल) × 100

एनएसएसओ की स्थापना 1950 में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। एनएसएसओ के कर्मचारी भारतीय सांख्यिकी सेवा (यूपीएससी के माध्यम से नियुक्त) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त) से हैं।
भारत में बेरोजगारी के प्रकार:

→ **प्रच्छन्न बेरोजगारी:** यह एक ऐसी घटना है जहां वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

- यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है।

→ **मौसमी बेरोज़गारी:** यह एक बेरोज़गारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है।

- भारत में खेतिहर मजदूरों के पास साल भर शायद ही कभी काम होता है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी: यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की एक श्रेणी है।
- भारत में कई लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है और शिक्षा का स्तर ख़राब होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।

→ **चक्रीय बेरोजगारी:** यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ गिरावट आती है।

- भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।

→ **तकनीकी बेरोजगारी:** यह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों का नुकसान है।

- 2016 में, विश्व बैंक के आंकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में स्वचालन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।

→ **घर्षणात्मक बेरोजगारी:** घर्षणात्मक बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, यह नौकरियों के बीच के समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है।

- दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को नई नौकरी खोजने या मौजूदा से नई नौकरी में स्थानांतरित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, यह अपरिहार्य समय विलंब घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण बनता है।
- इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होती है, बल्कि वास्तव में, श्रमिक बेहतर अवसरों की तलाश में खुद ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं।

→ **असुरक्षित रोज़गार:** इसका मतलब है, लोग अनौपचारिक रूप से, बिना उचित नौकरी अनुबंध के और इस प्रकार बिना किसी कानूनी सुरक्षा के काम कर रहे हैं।

- इन व्यक्तियों को 'बेरोजगार' माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता है।
- यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

भारत में बेरोजगारी के कारण:

→ **सामाजिक कारक:** भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है। कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए यह कार्य वर्जित है।

- बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में ऐसे कई व्यक्ति मिल जायेंगे जो कोई काम नहीं करते और परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं।

→ **जनसंख्या में तीव्र वृद्धि:** भारत में जनसंख्या में लगातार वृद्धि एक बड़ी समस्या रही है।

- यह बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है।

→ **कृषि का प्रभुत्व:** भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है।

हालाँकि, भारत में कृषि अविकसित है।

- साथ ही, यह मौसमी रोजगार भी प्रदान करता है।

→ **कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन:** औद्योगिक विकास का कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने लगा और कई कारीगर बेरोजगार हो गये।

→ **श्रम की गतिशीलता:** भारत में श्रम की गतिशीलता कम है। परिवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाते।

- कम गतिशीलता के लिए भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी जिम्मेदार हैं।

→ **शिक्षा प्रणाली में दोष:** नौकरियाँ अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है।

- इस प्रकार, काम करने के इच्छुक कई लोग कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं।

बेरोजगारी से निपटना

- श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना: भारत में कई श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी निर्माता और फर्नीचर, कपड़ा और परिधान और परिधान।
- नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किए गए विशेष पैकेजों की आवश्यकता होती है।

→ **उद्योगों का विकेंद्रीकरण:** औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले।

- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी जिससे शहरी क्षेत्र की नौकरियों पर दबाव कम होगा।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करना: एक राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) की आवश्यकता है जिसमें बहुआयामी हस्तक्षेपों का एक सेट शामिल होगा जिसमें न केवल श्रम और रोजगार के क्षेत्र बल्कि कई नीति क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला शामिल होगी।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंतर्निहित सिद्धांतों में शामिल हो सकते हैं:

– कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी को बढ़ाना।

– औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करना ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके जो उपलब्ध हैं और काम करने के इच्छुक हैं।

– श्रम बाजार में सामाजिक एकजुटता और समानता को मजबूत करना।

– उत्पादक उद्यमों में प्रमुख निवेशक बनने के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन करना।

– स्व-रोज़गार व्यक्तियों को उनकी कमाई में सुधार करने के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करके सहायता करना

CLASS 11

CHAPTER 8

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे
- ✓ बुनियादी ढांचे का महत्व
- ✓ सार्वजनिक एवं निजी अवसंरचना
- ✓ स्वास्थ्य अवसंरचना
- ✓ भारतीय चिकित्सा पद्धति-आयुष
- ✓ ऊर्जा अवसंरचना
- ✓ बुनियादी ढांचे में चुनौतियाँ

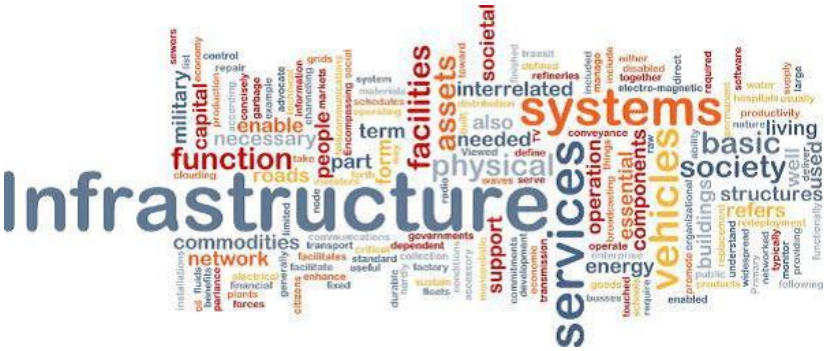

बुनियादी ढांचे को समझना

- यह उन बुनियादी सुविधाओं को संदर्भित करता है जो किसी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करती हैं
- यह सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि जैसे भौतिक संकायों के नेटवर्क को संदर्भित करता है।
- इसमें स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे भी शामिल हैं

⟶ इन्फ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार और वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों में सहायक सेवाएँ प्रदान करता है।

⟶ इन सेवाओं में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली स्टेशन, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूलों और कॉलेजों सहित देश की शैक्षिक प्रणाली, अस्पतालों सहित स्वास्थ्य प्रणाली, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं सहित स्वच्छता प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली शामिल हैं। बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थान।

⟶ इन्फ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा- इन्फ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के ऐसे मूल तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे

इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. आर्थिक अवसंरचना
2. सामाजिक बुनियादी ढाँचा

→ आर्थिक अवसंरचना- इसका तात्पर्य आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों से है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।

→ सामाजिक अवसंरचना- यह सामाजिक परिवर्तन के मूल तत्वों को संदर्भित करता है जो किसी देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

बुनियादी ढांचा और विकास

निम्नलिखित अवलोकनों से पता चलता है कि वास्तव में बुनियादी ढांचा वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में कैसे योगदान देता है।

- बुनियादी ढांचा उत्पादकता को प्रभावित करता है
- बुनियादी ढांचा निवेश को प्रेरित करता है
- बुनियादी ढांचा उत्पादन में जुड़ाव पैदा करता है

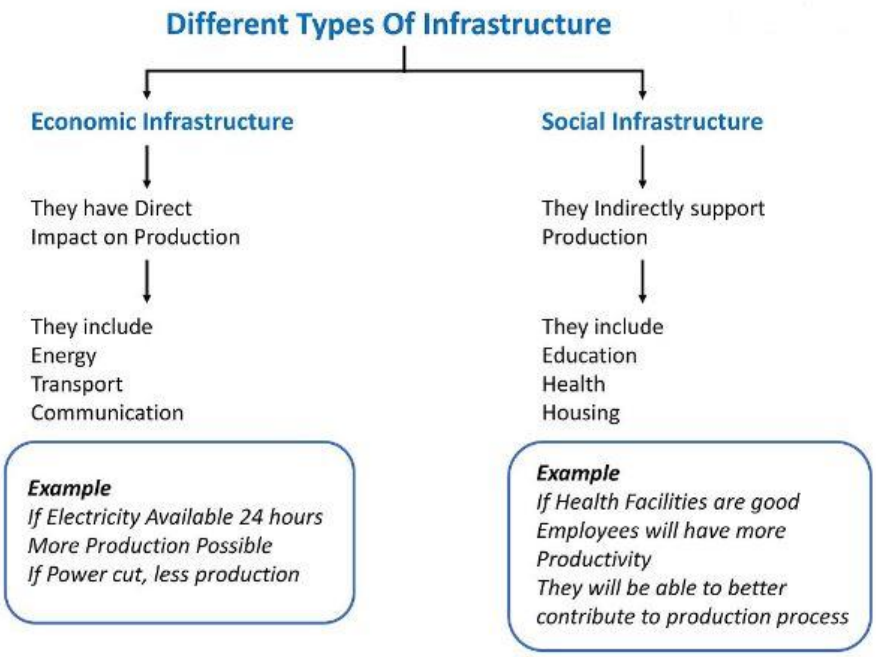

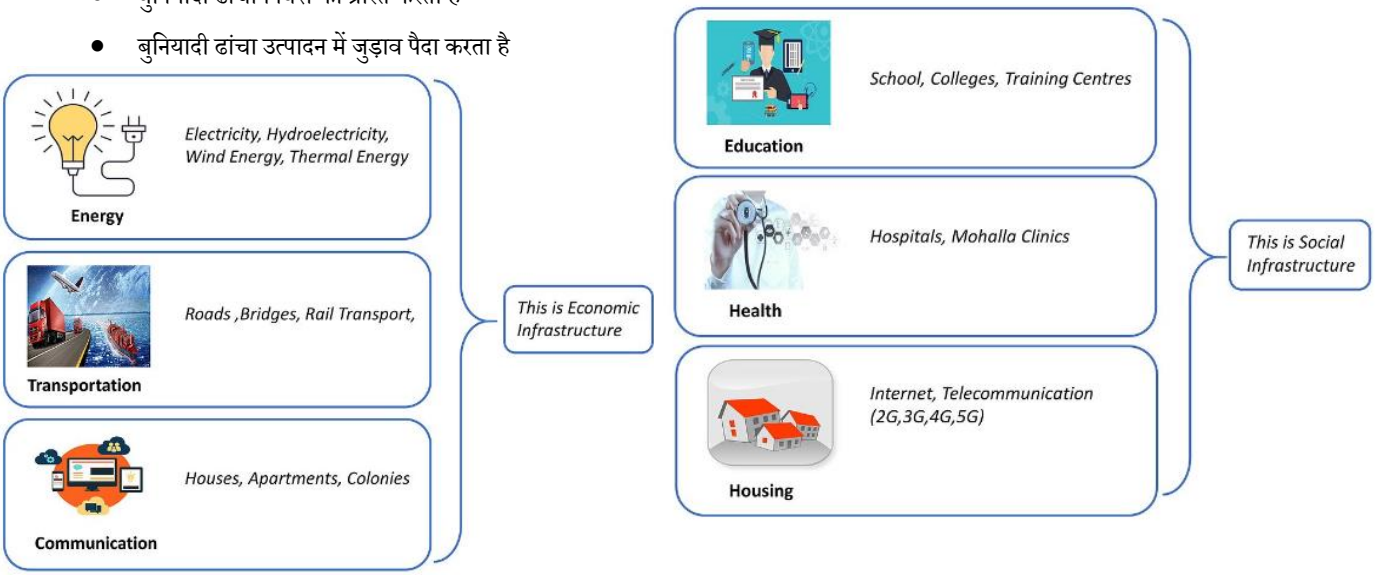

- औद्योगिक विकास में मदद करता है
- इन्फ्रास्ट्रक्चर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सहायक प्रणाली है
- बुनियादी ढांचा सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, पुल प्रदान करता है जो औद्योगिक विकास में मदद करता है
- यह औद्योगिक उत्पादन में आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है

कृषि में मदद करता है

- यह बीज, कीटनाशकों, उर्वरकों के साथ-साथ तैयार माल के परिवहन में मदद करता है
- कृषि बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर करती है
- उदाहरण - किसानों को फसल बीमा के साथ-साथ बैंकों से ऋण की भी आवश्यकता होती है

जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है

- अच्छी स्वच्छता और शिक्षा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करती है
- इसके अलावा, इंटरनेट, पोस्ट और टेलीग्राफ जैसी अच्छी संचार सुविधाएं लोगों को एक-दूसरे से संपर्क करने में मदद करती हैं

रुग्णता को कम करता है

- रुग्णता का अर्थ है बीमार पड़ने की प्रवृत्ति।
- स्वच्छ पेयजल और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं कई बीमारियों को रोकने में मदद करती हैं।

Infrastructure Provides

Clean Drinking Water

Good Medical Facilities

All this help in preventing many diseases (Reduces Morbidity)

भारत में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे वाले विभिन्न राज्य

- इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकास में मदद करता है
- भारत के विभिन्न राज्य जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा है, वे समृद्ध हैं

Different States with Best Infrastructure

Punjab

Haryana

Best Irrigation Facilities
Example-Bhakra Nangal Dam, Canals
These States Prosper in Agriculture

Maharashtra

Gujarat

Best Transportation Facilities (Near Ports)
These States do well in Manufacturing Industry
as raw materials required are easily accessible

Bangalore

Best Communication Facilities and IT Infrastructure
It does well in Software and IT Field
Many companies operate from Bangalore

भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है?

- सार्वजनिक क्षेत्र
- परंपरागत रूप से सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थी
- उदाहरण - सड़कें, पुल आदि बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।

प्राइवेट सेक्टर

- निजी क्षेत्र स्वयं भी कभी-कभी बुनियादी ढांचे के विकास का नेतृत्व करता है
- उदाहरण - रिलायंस जियो को रिलायंस द्वारा, अदानी पोर्ट्स को अदानी द्वारा लॉन्च किया गया था

संयुक्त साझेदारी

- कई परियोजनाएँ सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी में आयोजित की जाती हैं
- उदाहरण - कई टोल सड़कें और टोल प्लाजा सरकार के साथ साझेदारी में निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं

निम्न आय और उच्च आय वाले देशों के लिए बुनियादी ढाँचा विकास किस प्रकार भिन्न है?

- कम आय वाले देशों के लिए
- ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं
- बुनियादी ढांचागत सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं
- उदाहरण-परिवहन, बिजली, सिंचाई

उच्च आय वाले देशों के लिए

इन देशों के लिए कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम है

अधिक सेवा-संबंधी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है

उदाहरण - बेहतर दूरसंचार अवसंरचना (जैसे बेहतर इंटरनेट स्पीड)

क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में निवेश पर्याप्त है?

- नहीं
- भारत अपनी जीडीपी का केवल 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है
- यह चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के % खर्च से काफी कम है
- भारत में अभी भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है

China	India
Investment in Infrastructure 44% of GDP	Investment in Infrastructure 30% of GDP
Drinking Water Resources 96% of Population	Drinking Water Resources 94% of Population
Sanitation Services 72% of Population	Sanitation Services 40% of Population
Consumption of Energy 324 million tones of Oil Equivalent	Consumption of Energy 809 million tones of Oil Equivalent

Infrastructure Facility in India is insufficient
Basic Facilities are still not provided to large chunk of Population especially in Rural Areas

स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास

- स्वास्थ्य न केवल बीमारी की अनुपस्थिति है, बल्कि किसी की क्षमता का एहसास करने की क्षमता भी है
- इसका अर्थ है पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण प्राप्त करना

स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है?

- स्वास्थ्य एक समग्र प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र के समग्र विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है
- यदि देश की जनसंख्या स्वस्थ नहीं है, तो यह किसी राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में योगदान नहीं देगी

What is Health?

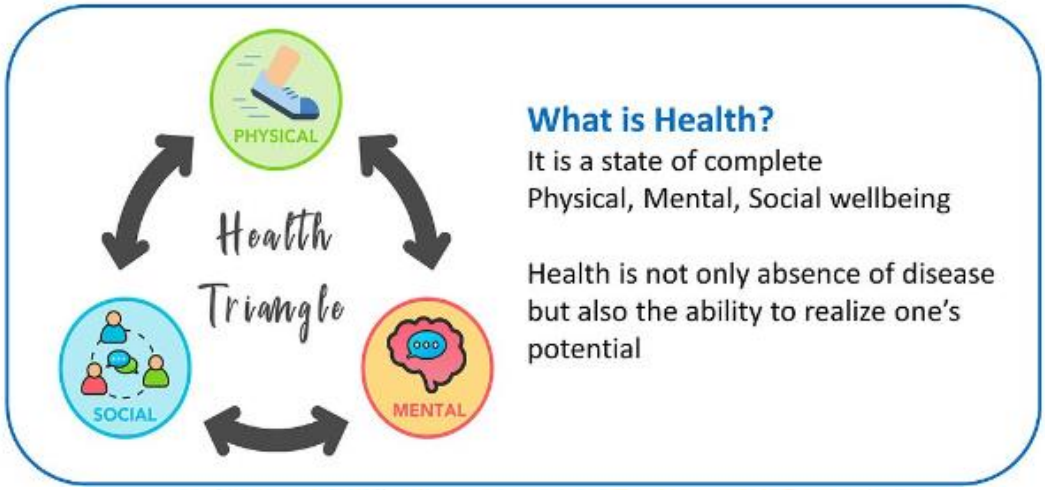

Who Contributes More to Economic Growth?

Healthy Person

He is fit and has higher productivity in job
So, contributes more to Economic Growth

Sick person

He is sick and weak and has lower productivity
Doesn't contribute much To economic Growth

स्वास्थ्य अवसंरचना क्या है?

• हीथ इन्फ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है सार्वजनिक सुविधाओं जैसे- अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बिस्तर, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराना।

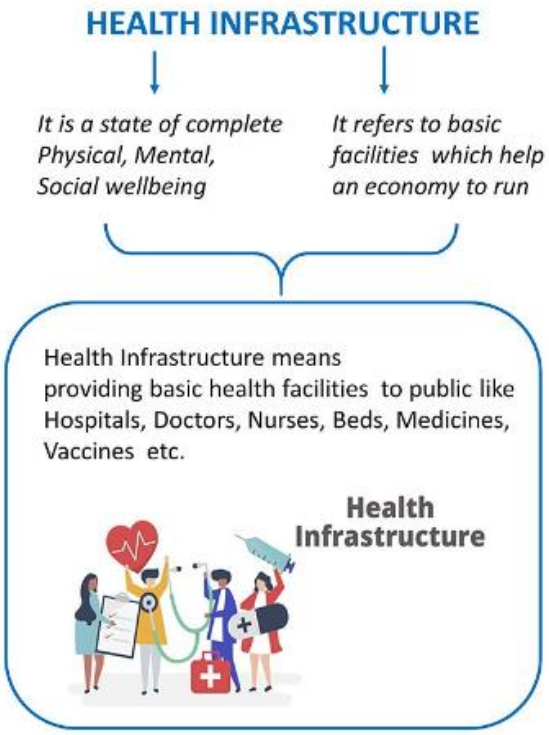

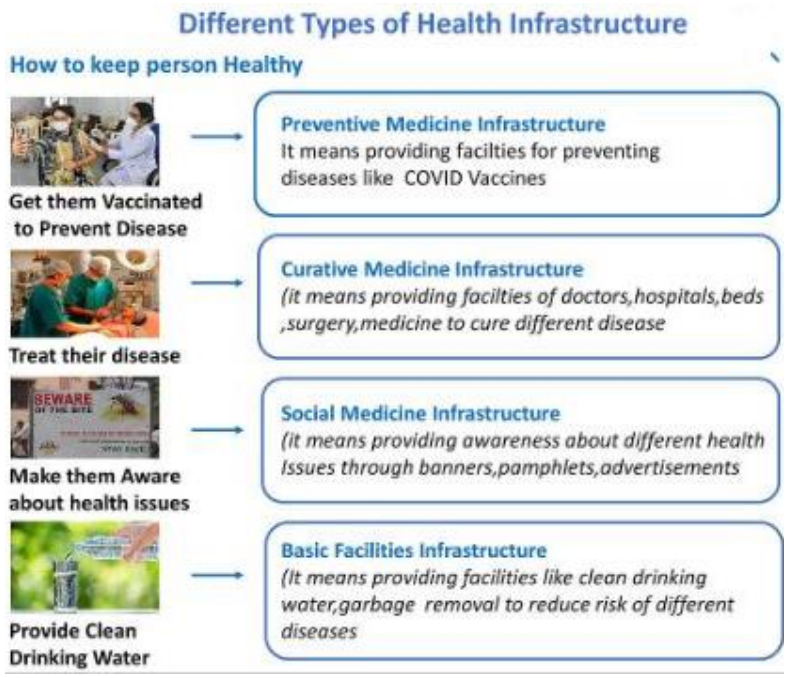

⟶ आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विकास

⟶ स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है. निम्नलिखित मुख्य अंश हैं:

- मृत्यु दर में गिरावट
- शिशु मृत्यु दर में कमी
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि
- जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण
- बाल मृत्यु दर में कमी

स्वास्थ्य अवसंरचना की त्रिस्तरीय प्रणाली

भारत का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा 3 स्तरों से बना है:

1. प्राथमिक क्षेत्र
2. द्वितीयक क्षेत्र
3. तृतीयक क्षेत्र

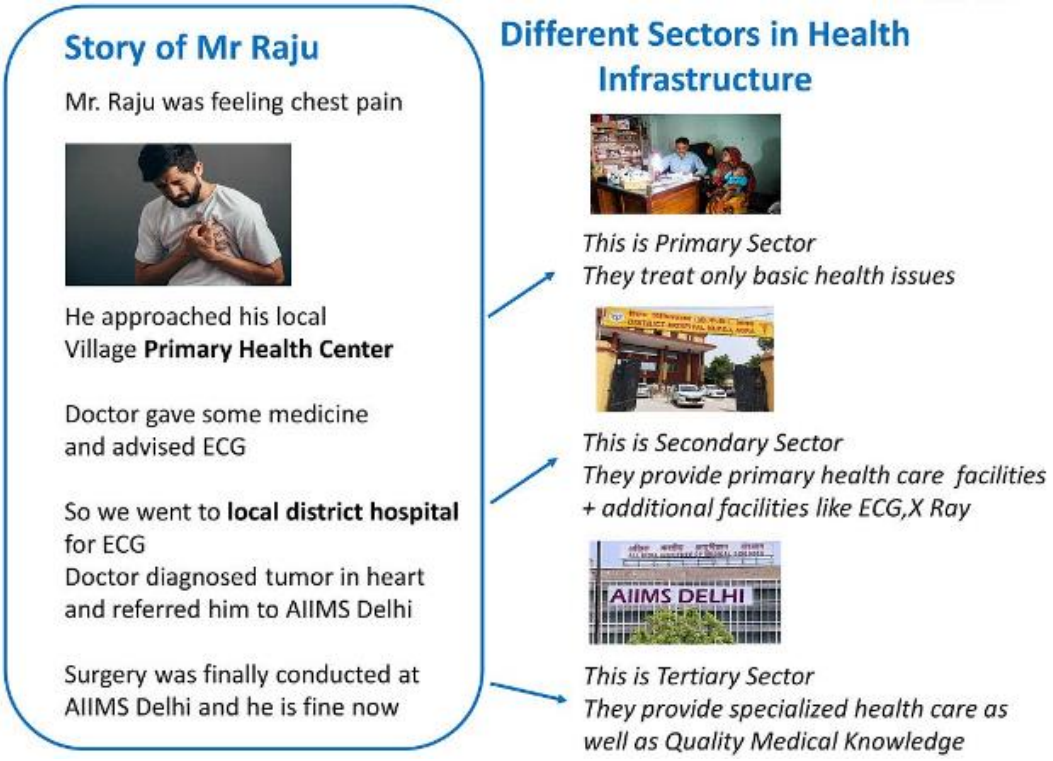

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या हैं?

- वे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं
- वे एकल डॉक्टर, एक नर्स और सीमित चिकित्सा आपूर्ति द्वारा चलाए जाते हैं

Three Tier System of Health Infrastructure

	Primary Sector	Secondary Sector	Tertiary Sector
	They provide Primary Healthcare facilities	They provide Primary Healthcare Facilities + Additional Facilities like X Ray, ECG,MRI, Surgery	They provide Advanced Medical Surgery + Quality Medical Education
	They are present in villages and small towns	They are present in district level	These are present in major cities of India like Delhi
	Less Medical Staff	More Medical Staff and More Facilities	Very high Medica Staff latest machines and Infrastructure
	Example Primary Health Center	Example District Hospital	Example AIIMS

Primary Health Center

Which Tier?	Primary Sector
Where Found?	Rural Areas Small Towns
Which Services?	Primary health care Services like Vaccination TREATING High Fever, Cold etc.
Type of Infrastructure?	Single Doctor Nurse (AXM) Limited Medical Supplies

- वे टीकाकरण और टीकाकरण प्रदान करते हैं और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तेज़ बुखार आदि का इलाज करते हैं।
- जब किसी मरीज की हालत गंभीर होती है, तो वे उन्हें माध्यमिक या तृतीयक अस्पतालों में रेफर करते हैं

Who is AXM?

Full Form	Auxiliary Nursing Midwife
Meaning	It is the first person which provides Primary Healthcare in Rural Areas
Functions	Basic services like checking temperature and Blood pressure of patients, vaccination etc.
Where Present	Primary Healthcare Center in Rural Areas

एएक्सएम कौन है?

- AXM का अर्थ है सहायक नर्सिंग मिडवाइफ
- यह पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है
- एक सहायक नर्स मरीजों के तापमान और रक्तचाप की जांच, टीकाकरण आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में शामिल होती है।

निजी क्षेत्र स्वास्थ्य अवसंरचना

भारत में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र भी शामिल है

उदाहरण - भारत भर में कई निजी तौर पर संचालित अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम हैं

महत्वपूर्ण बिंदु

- 70% से अधिक अस्पताल निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं

- अस्पताल के 2/5 बिस्तर निजी क्षेत्र में हैं
- 80% बाह्य रोगियों (ओपीडी) का प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है
- 46% आंतरिक रोगियों का प्रबंधन निजी क्षेत्र में किया जाता है
- निजी क्षेत्र चिकित्सा पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सा अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल्स की बिक्री आदि में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- उदारीकरण के बाद भारत में कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विकसित किये गये हैं।
- ये भारत को चिकित्सा पर्यटन प्रदान करते हैं

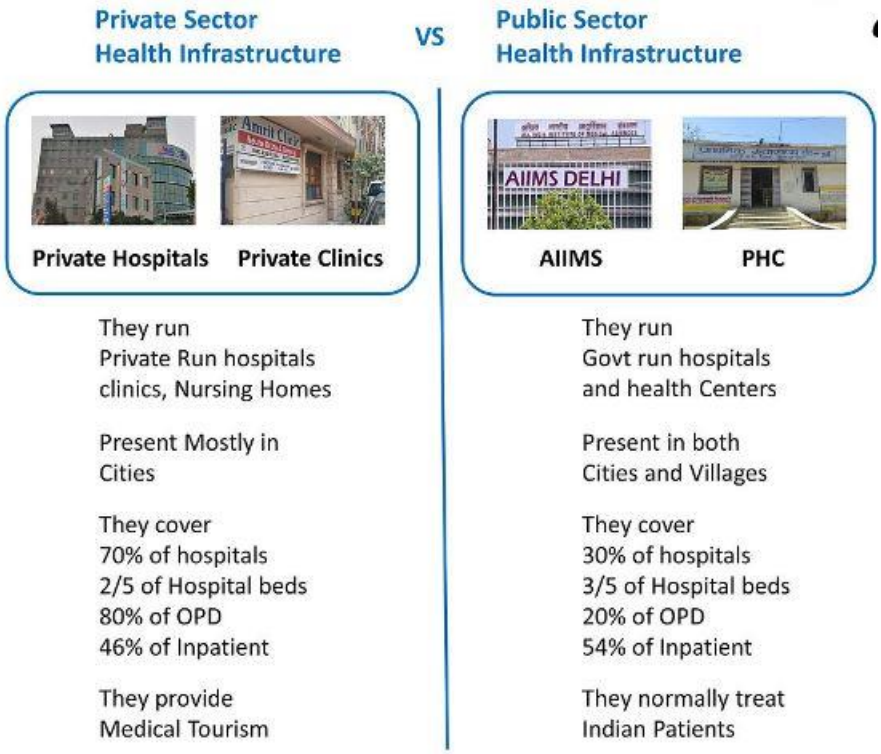

मेडिकल टूरिज्म क्या है?

- बाहरी देशों से बहुत से लोग अपने इलाज के लिए भारत आ रहे हैं, इसे मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है

कारण:

- भारत के पास नवीनतम चिकित्सा प्रौद्योगिकियाँ और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं
- अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में लागत बहुत कम है।

भारत को लाभ

- इससे भारत के लिए विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है और भारत को मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा केंद्र बनने में सक्षम बनाता है।

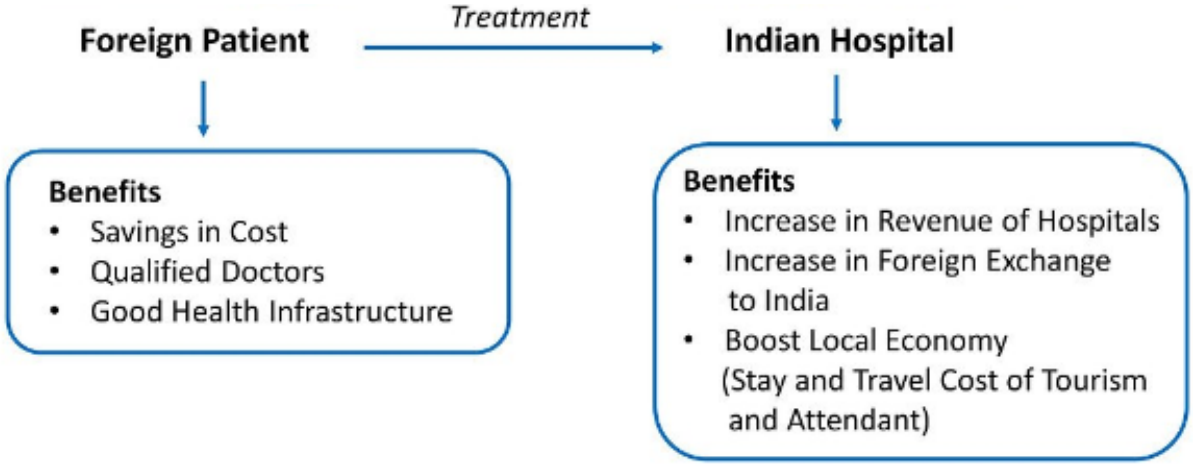

Example 1 -Medical Tourism

USA Patient to undergo Surgery

- **Cost in USA** → *$ 10000* → *This is Expensive*
- **Cost in India** → *Rs 150000 ($ 2000) + $1000 Travelling Cost* → *This is Cheaper*

Example 2 -Medical Tourism

Afghanistan Patient to undergo Surgery

- **Treatment in Afghanistan** → *Not Available (Lack of latest equipment) (Not many Qualified Doctors)* → *This is not an option*
- **Treatment in India** → *Available Reasonable Rates Good Medical Infrastructure* → *So Afghan Patient comes to India for treatment*

भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है?

- यह चिकित्सा की 6 प्रणालियों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक रूप से भारत में उपयोग की जाती थीं। इन्हें सम्मिलित रूप से आयुष कहा जाता है:
  - A-आयुर्वेद
  - वाई-योग
  - उ0—यूनानी
  - स-सिद्ध
- एच-होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा

Allopathy	Ayush
It is conventional system of medicines followed worldwide	It is Indian system of medicines traditionally followed
There are Side effects Of using these medicines	They are effective and safe (no side effects)
Expensive Treatment	They are relatively inexpensive
Standardized Education	No Standardized Education
Proper Research and Development	Lack of Research and Development

आयुष के विकसित मानक

- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं में कच्चे माल के रूप में पौधों, खनिजों, धातुओं, पशु और समुद्री उत्पादों से तैयार विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलेशन शामिल होते हैं। इन प्रणालियों में निर्धारित विशिष्ट विधियों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण के बाद ये फॉर्मूलेशन तैयार किए जाते हैं। इन फॉर्मूलेशनों को उनकी तैयारी की विधि, स्वीकार्यता, जैवउपलब्धता और चिकित्सीय मूल्यों के अनुसार विभिन्न खुराक रूपों में वर्गीकृत किया गया है।
- स्वास्थ्य देखभाल की बहुलवादी योजनाओं के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में घरेलू और वैश्विक समाज में आयुष की बढ़ती उपभोक्ता स्वीकृति को देखते हुए, सरकार। भारत सरकार (उत्कृष्टता केंद्र, आयुष मंत्रालय) ने सरकारी/गैर-सरकारी/गैर-लाभकारी संस्थाओं में शिक्षा/औषधि विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान आदि में लगे प्रतिष्ठित आयुष ज्ञान की पहचान करने और उनके कार्यों को उन्नत करने के लिए उनका समर्थन करने का निर्णय लिया है। उत्कृष्टता के स्तर तक सुविधाएँ।

- राष्ट्रीय आयुष मिशन: एनएएम का मूल उद्देश्य लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करना, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने और एएसयू की स्थायी उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना है। एवं एच कच्चा माल।

औषधि नियंत्रण कक्ष (आयुष मंत्रालय):

- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के लिए नियामक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रावधानों का प्रबंधन करना। यह राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के संबंधित हिस्से एएसयू एंड एच दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के कार्यान्वयन का भी प्रबंधन करता है, जिसके माध्यम से औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों की ढांचागत और कार्यात्मक क्षमता में सुधार के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

शहरी-ग्रामीण और गरीब-अमीर विभाजन

- शहरी-ग्रामीण और गरीब-अमीर के बीच चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में अंतर को नीचे दिए गए बिंदुओं से समझा जा सकता है
- कुल अस्पतालों का केवल पांचवां हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण भारत में औषधालयों की संख्या लगभग आधी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा नहीं है। इससे लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में अंतर आया। 7 लाख बिस्तरों में से, लगभग 11% ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख लोगों के लिए केवल 0.36% अस्पताल हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में इतनी ही संख्या में लोगों के लिए 3.6% अस्पताल हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीएचसी एक्स-रे या रक्त परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान नहीं करते हैं, जो एक शहरवासी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल है। भले ही 315 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज हर साल 30,000 मेडिकल स्नातक पैदा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी डॉक्टरों की कमी है. इनमें से एक-पाँचवाँ डॉक्टर बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं।

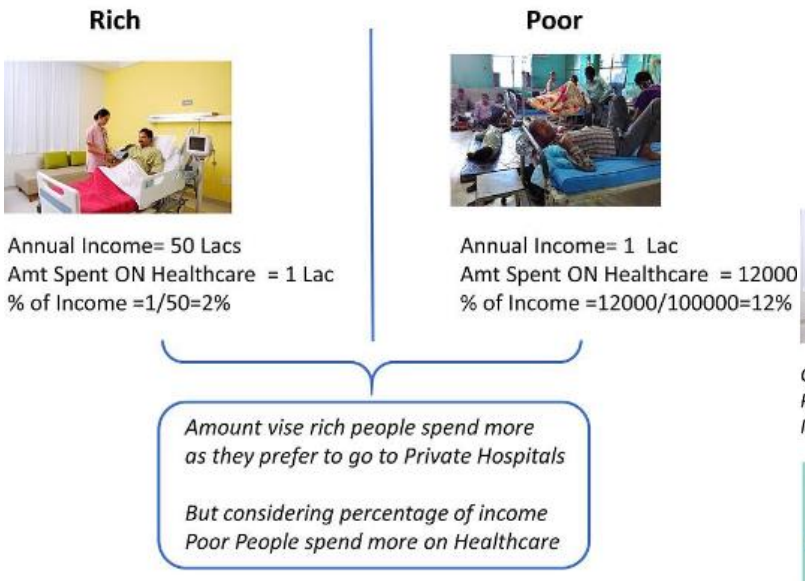

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले सबसे गरीब 20% भारतीय अपनी आय का 12% स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करते हैं जबकि अमीर केवल 2% खर्च करते हैं।

रोग का उच्च वैश्विक बोझ (जीबीडी)

- जीबीडी एक संकेतक है जो किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या या बीमारी के मामले में विकलांगता की स्थिति में बिताए गए वर्षों की संख्या को मापता है।
- भारत वैश्विक बीमारी के बोझ (जीबीडी) का 20% वहन करता है
- इसका मतलब है कि दुनिया भर की बीमारियों से होने वाली मृत्यु और विकलांगता की बड़ी संख्या भारत में पाई जाती है

भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है
- (मुख्य शहरों में केवल कुछ अच्छे अस्पताल होने के बजाय, हमारे पास पूरे भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा होना चाहिए)
2. बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता
- भारत की विशाल आबादी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए अधिक अस्पताल और क्लीनिक खोलने की आवश्यकता है
3. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को विकसित करने की आवश्यकता है
- इससे प्रारंभिक चरण में लक्षणों का इलाज करने और गंभीर बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी
4. बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा
- स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने और विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित शिक्षा लेने की आवश्यकता है
5. स्वास्थ्य में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
- सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरनेट) का उपयोग विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने और उनसे खुद को बचाने के लिए किया जा सकता है

ऊर्जा क्षेत्र

- अर्थशास्त्र में, ऊर्जा का अर्थ मशीनों को चलाने और गर्मी और प्रकाश प्रदान करने के लिए भौतिक या रासायनिक संसाधनों के उपयोग से उपयोग की जाने वाली शक्ति है।

उदाहरण

- हम गर्मी उत्पन्न करने के लिए कोयला जलाते हैं, इसलिए यह ऊर्जा का एक रूप है
- हम अपनी कारों (जो एक मशीन है) को चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम ऊर्जा का एक रूप है

हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है?

- इसका उपयोग उद्योगों में मशीनें चलाने के लिए किया जाता है
- इसका उपयोग घरों में खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है
- इसका उपयोग कृषि में कृषि वस्तुओं, उर्वरकों, बीजों के परिवहन के साथ-साथ सिंचाई के लिए भी किया जाता है (ट्यूबवेल सिंचाई के लिए पानी खींचने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं)

ऊर्जा किन रूपों में उपलब्ध है?

ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध है जैसे:

- •कोयला
- पेट्रोलियम
- बिजली
- ईंधन लकड़ी
- गाय का गोबर आदि।

इनमें से कुछ वाणिज्यिक हैं जबकि अन्य गैर-व्यावसायिक हैं:

⟶ ऊर्जा के विभिन्न स्रोत

⟶ वाणिज्यिक स्रोत

- ऊर्जा के इस स्रोत का व्यावसायिक व्यापार होता है
- इसे आसानी से लाया और बेचा जा सकता है और यह उपभोक्ताओं को कीमत पर उपलब्ध है
- इनका उत्पादन बिजली संयंत्रों में किया जाता है

उदाहरण

- कोयला, पेट्रोलियम, बिजली
- इसका उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाता है
- जलविद्युत ऊर्जा को छोड़कर यह ऊर्जा का एक समाप्ति स्रोत है
- (यह सीमित आपूर्ति में उपलब्ध है और भविष्य में समाप्त हो जाएगा)
- वे ऊर्जा के पारंपरिक या गैर-पारंपरिक स्रोत हो सकते हैं

गैर-वाणिज्यिक स्रोत

- ऊर्जा के स्रोत का कोई वाणिज्यिक व्यापार नहीं होता है
- यह आम तौर पर ग्राहकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है
- ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं

उदाहरण

- गाय का गोबर, जलाऊ लकड़ी
- इसका उपयोग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में किया जाता है
- यह ऊर्जा का अक्षय स्रोत है
- वे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं

भारत में ऊर्जा का उपभोग पैटर्न

अधिक वाणिज्यिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। वाणिज्यिक ऊर्जा का हिस्सा गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा से अधिक है

- वाणिज्यिक ऊर्जा 74%
- गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा 26%

तेल और प्राकृतिक गैस के बाद कोयले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है

- कोयला 54%
- तेल (पेट्रोलियम) 32%
- प्राकृतिक गैस 10%
- हाइड्रो और अन्य नवीकरणीय 4%

भारत की 80% से अधिक ऊर्जा ज़रूरतें तीन ईंधनों से पूरी होती हैं: कोयला, तेल और ठोस बायोमास। कोयले ने बिजली उत्पादन और उद्योग के विस्तार को रेखांकित किया है, और ऊर्जा मिश्रण में सबसे बड़ा एकल ईंधन बना हुआ है। बढ़ते वाहन स्वामित्व और सड़क परिवहन के उपयोग के कारण तेल की खपत और आयात तेजी से बढ़ा है। बायोमास, मुख्य रूप से ईंधन की लकड़ी, ऊर्जा मिश्रण में घटती हिस्सेदारी बनाती है, लेकिन अभी भी खाना पकाने के ईंधन के रूप में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के कवरेज के विस्तार में हालिया सफलता के बावजूद, 660 मिलियन भारतीयों ने पूरी तरह से आधुनिक, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन या प्रौद्योगिकियों पर स्विच नहीं किया है।

प्राकृतिक गैस और ऊर्जा के आधुनिक नवीकरणीय स्रोतों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा का उदय शानदार रहा है; संसाधन क्षमता बहुत बड़ी है, महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं, और नीति समर्थन और प्रौद्योगिकी लागत में कटौती ने इसे नई बिजली उत्पादन के लिए सबसे सस्ता विकल्प बना दिया है।

- कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
- यह एक जीवाश्म ईंधन है और प्रकृति में ख़त्म होने वाला है
- कोयला जलाने से प्रदूषण फैलता है
- परमाणु ऊर्जा का हिस्सा केवल 2.5% है जो वैश्विक औसत 13% से बहुत कम है।
- बिजली के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है

भारत में, बिजली पारंपरिक (थर्मल, परमाणु और हाइड्रो) और नवीकरणीय स्रोतों (पवन, सौर, बायोमास आदि) से उत्पन्न होती है। हालाँकि, बिजली का प्रमुख उत्पादन कोयले, एक तापीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

सितंबर 2021 तक, थर्मल पावर - कोयला, गैस और पेट्रोलियम जलाने से उत्पन्न बिजली - में बिजली उत्पादन में भारत की स्थापित क्षमता का 60% शामिल था। अकेले कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50% थी। तुलनात्मक रूप से, पवन और सौर ऊर्जा और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों का हिस्सा 26% था।

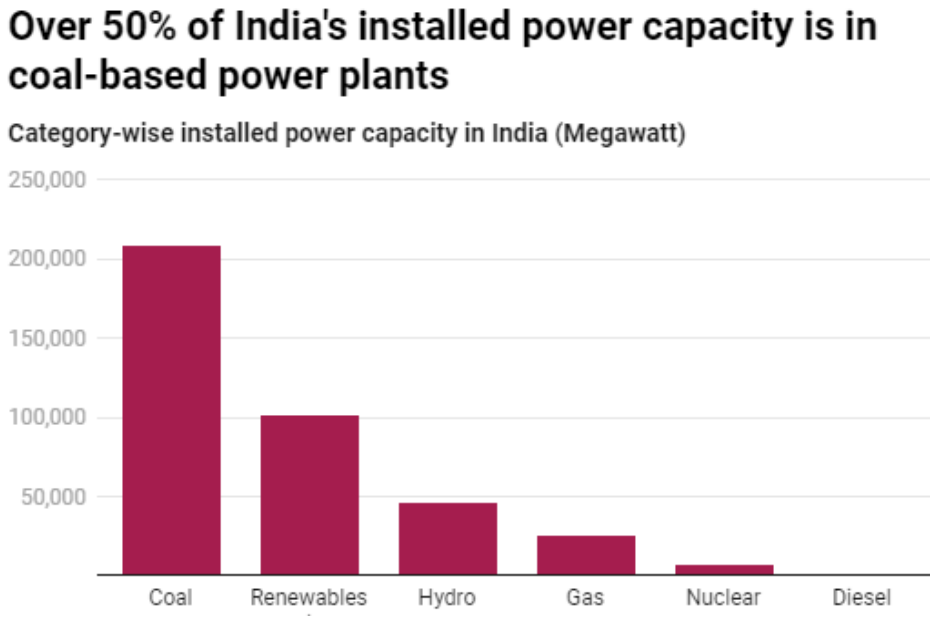

विद्युत क्षेत्र में चुनौतियाँ

1. अपर्याप्त स्थापित क्षमता

- जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक विकास में वृद्धि के कारण भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। तदनुसार ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है।

2. स्थापित क्षमता का कम उपयोग

- जो योजनाएं चल रही हैं वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं. इसलिए, वे अपनी स्थापित क्षमता तक बिजली पैदा करने में सक्षम नहीं हैं।

3. ट्रांसमिशन हानि

- (जो बिजली उत्पन्न होती है उसे पहले बिजली स्टेशनों में स्थानांतरित किया जाता है जो हमारे घरों और कार्यालयों में स्थानांतरित होती है। इस ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारी बिजली खो जाती है और इसलिए उत्पन्न बिजली और उपयोग की गई बिजली के बीच बहुत अंतर होता है।

4. बिजली का गलत मूल्य निर्धारण

- बिजली दरों में विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी सब्सिडी दी जाती है। कई राज्यों में यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इससे राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) को नुकसान होता है।

5. किसानों को निःशुल्क बिजली का वितरण

- कई राज्यों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर बिजली मिलती है। इससे एसईबी को घाटा होता है

6. बिजली की चोरी

- बहुत से लोग बिजली चोरी करते हैं और अपने बिजली मीटरों से छेड़छाड़ करते हैं। इससे एसईबी को घाटा होता है

7. कच्चे माल की कमी

- थर्मल पावर प्लांट मुख्य रूप से कोयले पर चलते हैं। हालाँकि, कई क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति अपर्याप्त है।

8. सार्वजनिक अशांति

- बार-बार बिजली कटौती के साथ-साथ ज्यादा बिजली बिल के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

राज्य विद्युत बोर्डों को भारी घाटे का कारण क्या है?

राज्य विद्युत बोर्डों को निम्नलिखित कारणों से भारी घाटा हो रहा है:

- ट्रांसमिशन हानि
- बिजली का गलत मूल्य निर्धारण
- किसानों को मुफ्त बिजली का वितरण
- बिजली की चोरी

विद्युत क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए किये जाने वाले उपाय:

1. अधिक सार्वजनिक निवेश

- सरकार को बिजली क्षेत्र में पावर प्लांट खोलकर अपना खर्च बढ़ाने की जरूरत है। इससे अतिरिक्त बिजली पैदा होगी

2. बेहतर अनुसंधान एवं विकास प्रयास

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने और कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है (उदाहरण-इलेक्ट्रिक कारें)

3. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग

- वर्तमान में कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और अधिक कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करते हैं। इनकी जगह हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं।

4. ऊर्जा बचाने के लिए सीएफएल और एलईडी बल्ब का उपयोग

- पारंपरिक बल्ब बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं। उनकी जगह सीएफएल बल्ब ने ले ली जिन्हें बाद में एलईडी बल्ब से बदल दिया गया। एलईडी बल्ब सीएफएल बल्ब की तुलना में आधी बिजली और पारंपरिक बल्ब की तुलना में 1/10 ऊर्जा की खपत करता है। इसके अलावा, यह बल्ब पारंपरिक बल्ब की तुलना में अधिक समय तक चलता है

CLASS 11

CHAPTER 9

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ सतत विकास
- ✓ सतत विकास के लिए रणनीतियाँ
- ✓ ग्लोबल वार्मिंग
- ✓ पर्यावरण की अवशोषण क्षमता
- ✓ पर्यावरण की मूल बातें

सतत विकास क्या है?

- इसका अर्थ है वह विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।
- इसका मतलब है कि हमारे आर्थिक विकास से पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़े।

उदाहरण के लिए-

- हमारी फैक्ट्रियों से इतना वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीना मुश्किल हो जाए।

हम सतत विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

1. मानव जनसंख्या को सीमित करना

- जितनी कम जनसंख्या होगी, पर्यावरण पर उतना कम बोझ पड़ेगा (उदाहरण के तौर पर कम पेड़ काटे जाएंगे, कम पानी प्रदूषित होगा, कम कचरा पैदा होगा)

2. तकनीकी प्रगति इनपुट कुशल होनी चाहिए

- हमें नई प्रौद्योगिकियां विकसित करनी चाहिए जो उन इनपुट का उपयोग करती हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं (कोयले से बिजली पैदा करने के बजाय हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं)

3. नवीकरणीय संसाधनों के निष्कर्षण की दर पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए (उदाहरण - पेड़ एक नवीकरणीय संसाधन है, यदि 1000 पेड़ काटे जाते हैं, तो उसके स्थान पर 10000 से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए)

Sustainable → *Something Which can be maintained for long period of time (For future generation)*

\+

Development → *Progress or Economic Development (for current generation)*

=

Sustainable Development → Development which meet needs of current Generation without compromising ability of future generation to meet their needs

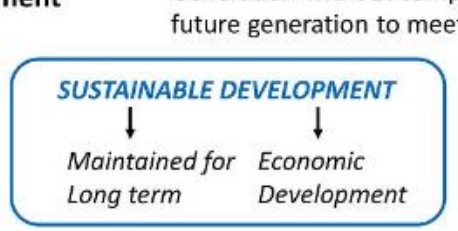

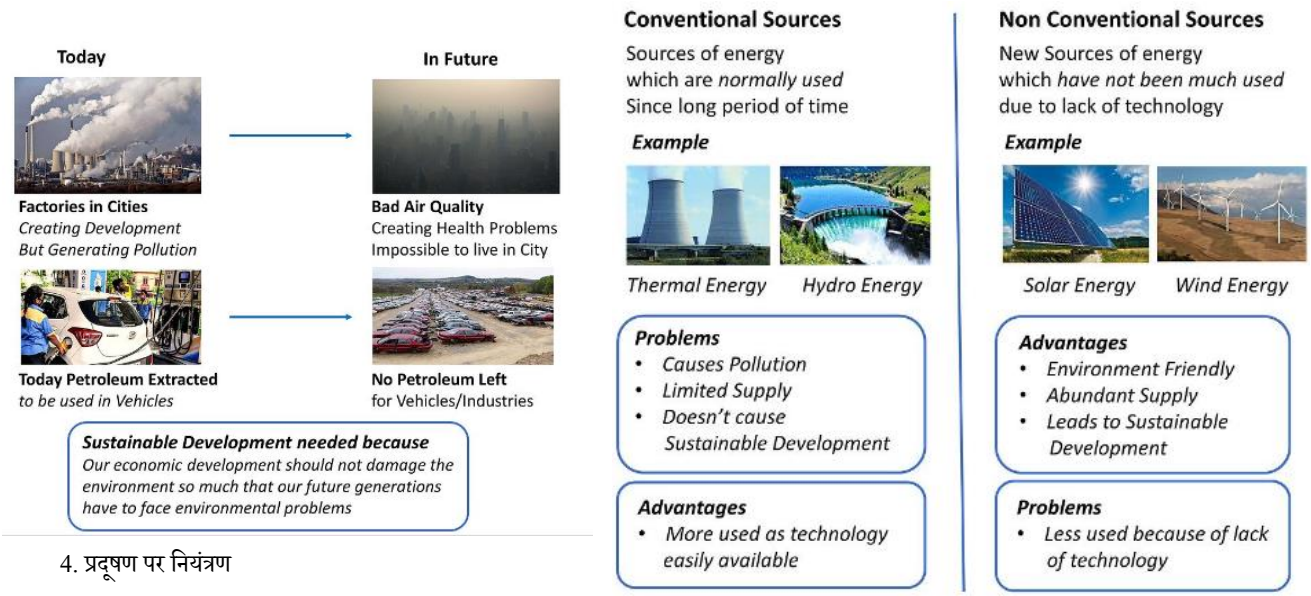

4. प्रदूषण पर नियंत्रण

- वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए
  ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले

ब्रंटलैंड आयोग क्या है?

यह संयुक्त राष्ट्र का एक उपसंगठन है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए देशों को एकजुट करना है। यह आयोग निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर देता है-

- हमें भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा करनी चाहिए
- भावी पीढ़ी को ग्रह को अच्छी स्थिति में सौंपना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
- उनके पास जीवन की गुणवत्ता हमें विरासत में मिली गुणवत्ता से कम नहीं होनी चाहिए
- इसने 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की- 'हमारा साझा भविष्य'। इस रिपोर्ट के अनुसार,
- सतत विकास का अर्थ है सभी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। "सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।"

सतत विकास के लिए रणनीतियाँ

रणनीति-1: ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत का उपयोग

- पारंपरिक ऊर्जा के साथ समस्याएँ
- ऊर्जा के ये स्रोत पर्यावरण अनुकूल नहीं हैं

उदाहरण 1

- थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए कोयले को जलाया जाता है
- इससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है

Thermal Power Plant

Coal is burnt to Generate Electricity

Problems

Burning Coal Releases Carbon dioxide
It is a Green House gas
Raises Temperature
Causes Global Warming

Fly ash also produced
Contaminates Land and Water

Coal Reserves available in Limited Supply Will be exhausted in future

Hydel Power Plant

Water is used to Generate Electricity

Problems

Dams are Created to block flow of water
Natural flow of water is disturbed

Forests are flooded
Lead to loss of Habitat for Plants & Animals

- इससे फ्लाई ऐश भी पैदा होती है जो जल और भूमि प्रदूषण का भी कारण बनती है

उदाहरण 2

- जलविद्युत संयंत्र पानी की सहायता से बिजली उत्पन्न करते हैं
- इससे जंगलों में बाढ़ आ जाती है।
- साथ ही, यह पानी के प्राकृतिक प्रवाह में भी हस्तक्षेप करता है
- ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए?
- क्लीनर-ये प्रदूषण नहीं फैलाते और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- प्रचुर आपूर्ति-वे प्रचुर आपूर्ति में उपलब्ध हैं और ख़त्म नहीं होंगे।
- समस्याएँ/चुनौतियाँ-तकनीकी उपकरणों की कमी के कारण इनका प्रयोग कम होता है।

Wind Energy

Electricity generated using Power of Wind

Benefits
- *Available in abundant supply*
- *Will not be exhausted*
- *Doesn't cause Pollution*

Solar Energy

Electricity Generated using Sun's energy

Benefits
- *Available in abundant supply*
- *Will not be exhausted*
- *Doesn't cause Pollution*

रणनीति 2- ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी और गोबर-गैस का उपयोग

ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन

- पहले के समय में, ग्रामीण परिवार आमतौर पर ईंधन के रूप में गाय के गोबर के उपले या लकड़ी का उपयोग करते थे।

इससे होता है-

- वनों की कटाई (जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ों की कटाई)

- वायु प्रदूषण (लकड़ी/गाय का गोबर जलाने से वायु प्रदूषण होता है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है)

सरकार द्वारा प्रचारित नये तरीके

1. सब्सिडी वाली एलपीजी

- एलपीजी का मतलब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। ये घर में इस्तेमाल होने वाले नियमित गैस सिलेंडर हैं।
- सरकार ने इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसे रियायती दरों पर देना शुरू कर दिया है।
- एलपीजी के उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आती है और पेड़ों को कटने से रोका जाता है।

2. गोबर गैस संयंत्र

- मवेशियों के गोबर को एकत्र किया जाता है और गोबर गैस संयंत्रों को खिलाया जाता है।
- इससे मवेशियों के गोबर से गैस उत्पन्न होती है।
- इस गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए घरों में आपूर्ति की जाती है।
- बचे हुए घोल का उपयोग मृदा कंडीशनर और जैविक खाद के रूप में किया जाता है।
- सरकार ने सब्सिडी और आसान ऋण प्रदान करके गोबर गैस संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

रणनीति 3 - शहरी क्षेत्रों में सीएनजी का उपयोग और ऑड-ईवन योजना

- सीएनजी का मतलब कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है।

सीएनजी के उपयोग के लाभ

स्वच्छ ईंधन- पेट्रोल और डीजल कारों से निकलने वाला धुआं बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। सीएनजी के उपयोग से हवा को स्वच्छ बनाने में मदद मिली है

लागत बचाता है- पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में सीएनजी पर चलने वाले वाहन बेहतर माइलेज देते हैं और लागत बचाते हैं।

लागत बचाता है- पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में सीएनजी पर चलने वाले वाहन बेहतर माइलेज देते हैं और लागत बचाते हैं।

दिल्ली जैसे शहरों ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या पहल की है?

1. सार्वजनिक परिवहन के लिए अनिवार्य सीएनजी

- बसों और ऑटो रिक्शा जैसे सार्वजनिक वाहनों के लिए सीएनजी का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया

2. ऑड ईवन स्कीम

- दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-ईवन योजना भी शुरू की।
- विषम दिनों में विषम संख्या वाली गाड़ियाँ चलती हैं और सम तिथियों पर सम संख्या वाली गाड़ियाँ चलती हैं।

रणनीति 4-पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा क्या है?

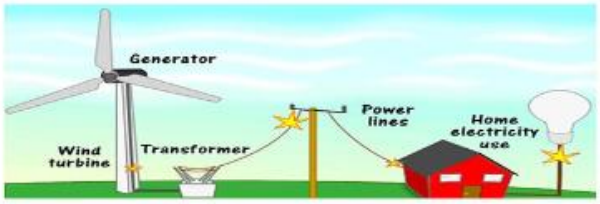

- पवन की ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त की गई शक्ति को पवन ऊर्जा कहा जाता है।
- पवन की शक्ति टरबाइनों को चलाती है और बिजली उत्पन्न करती है।
- पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है?
- इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां हवा की गति अधिक होती है।

Meaning	→	*Power obtained by harnessing energy of wind is called Wind Power*
How it Functions	→	*Power of wind makes the turbines move and generate electricity*
Where Used	→	*In Windy Areas (Open Spaces not surrounded by buildings(*
Benefits	→	*Saves Costs Pollution Free*

उदाहरण

- खुले स्थान जो इमारतों से घिरे न हों।

पवन ऊर्जा के उपयोग से क्या लाभ है?

1. प्रदूषण से मुक्त

- बिजली पैदा करने के लिए कोयले को नहीं जलाया जाता, इसलिए इससे वायु प्रदूषण नहीं होता

2. लागत बचाता है

- पवन ऊर्जा का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है और बड़े क्षेत्रों में बिजली संचारित करने के लिए महंगी ग्रिड लाइनों और केबलों की कोई आवश्यकता नहीं है

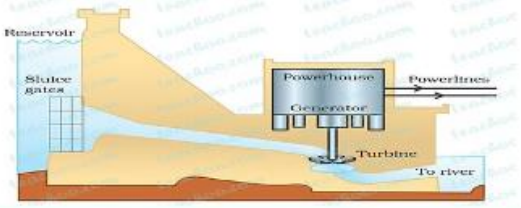

रणनीति 5-मिनी हाइडल संयंत्र

जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र क्या हैं?

- ये ऐसे पावर प्लांट हैं जो पानी की मदद से बिजली पैदा करते हैं
- पानी को टरबाइनों पर गिरने दिया जाता है जो बिजली पैदा करते हुए चलते हैं

मिनी हाइडल प्लांट क्या हैं?

- ये छोटे पैमाने पर पानी के प्रवाह से बिजली भी पैदा करते हैं

Meaning	→	*These are power plants which generate electricity with the help of water*
How it Functions	→	*Energy from streams is used to turn small turbines* *These generate small amt of electricity which can be used electricity*
Where Used	→	*In mountainous areas (where there are lot of streams)*
Benefits	→	*Environment Friendly (No Pollution)* *No Need for Large Investments* *Less Transmission Loss*

- इनका विकास पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ बहुत सारी धाराएँ होती हैं
- धाराओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग छोटी टर्बाइनों को चालू करने के लिए किया जाता है
- ये कम मात्रा में बिजली उत्पन्न करते हैं।

मिनी हाइडल संयंत्रों के लाभ

1. वे पर्यावरण के अनुकूल हैं
   - वे बिजली पैदा करने के लिए कोयला नहीं जलाते हैं और इसलिए प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।
2. बड़े निवेश की कोई आवश्यकता नहीं
   - उन्हें बड़े ट्रांसमिशन टावरों और केबलों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, वे बजट अनुकूल हैं
3. कम ट्रांसमिशन हानि
   - चूंकि बिजली का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जाना है, इसलिए बिजली स्टेशनों से घरों तक बिजली पहुंचाने से ट्रांसमिशन हानि कम होती है।

रणनीति 6 - पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का उपयोग करना

- हमें स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आवास, परिवहन आदि में पारंपरिक भारतीय प्रथाओं का उपयोग करना चाहिए।

उदाहरण

आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, तिब्बती

फ़ायदे

1. ये प्रथाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं
2. कोई हानिकारक रसायन प्रयोग नहीं किया गया
3. कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं
4. इसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक या रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं
5. प्रदूषण न फैलाएं

रणनीति 7 - जैव-खाद का उपयोग करना

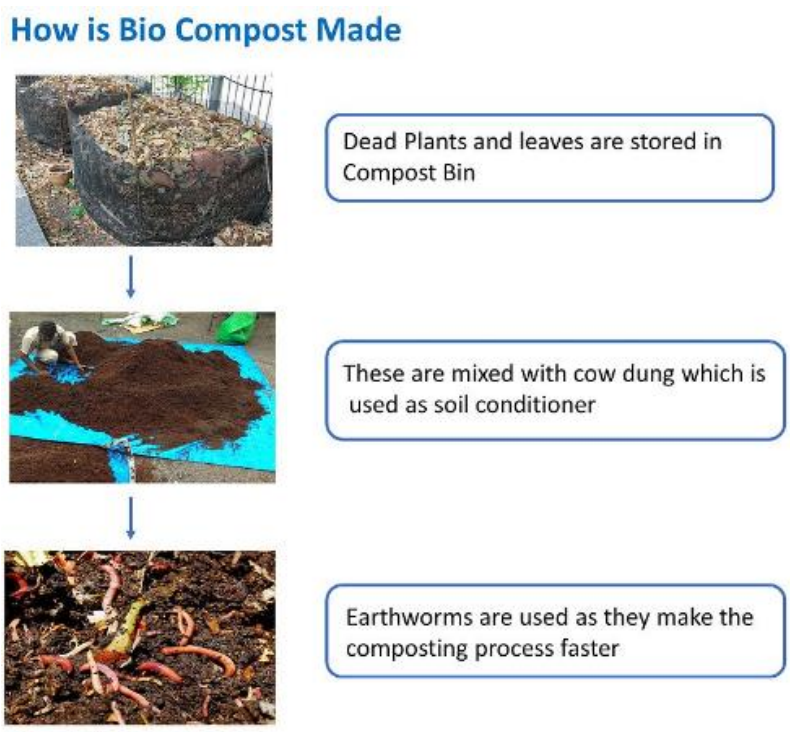

जैव खाद क्या है?

- यह सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है
- इस खाद का उपयोग कृषि के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है
- कम्पोस्ट कैसे बनता है?
- मृत पौधों और पत्तियों को कम्पोस्ट बिन में संग्रहित किया जाता है
- इन्हें गाय के गोबर के साथ मिलाया जाता है जिसका उपयोग मिट्टी कंडीशनर के रूप में किया जाता है
- केंचुओं का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज़ बनाते हैं

उर्वरकों के स्थान पर बायो कम्पोस्ट का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए?

- उर्वरक मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं
- उर्वरकों के प्रयोग से भूजल दूषित हो जाता है
- वे लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देते हैं
- जैविक खाद और बायोकंप्यूटिंग का उपयोग करके उगाई गई फसलें रसायनों से मुक्त होती हैं और उर्वरकों की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक होती हैं

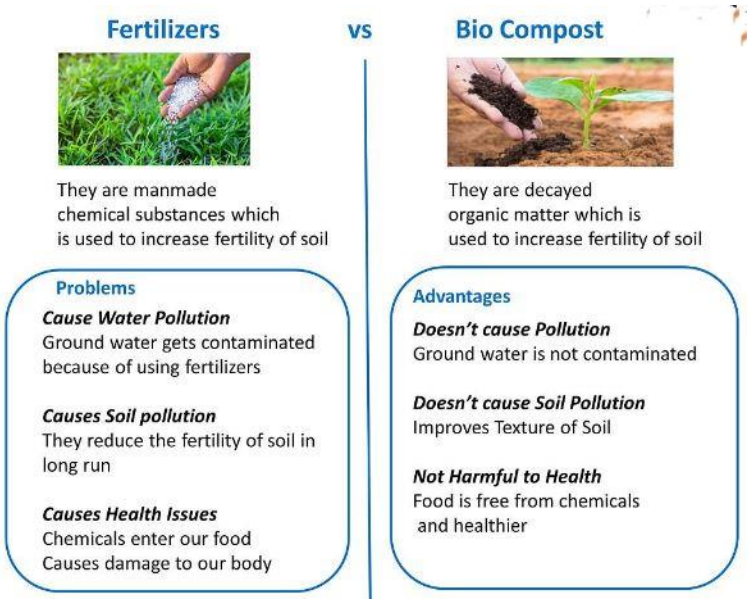

रणनीति 8 जैव-कीट नियंत्रण

कीट क्या हैं?

- वे जानवर और कीड़े जो फसलों और भोजन को नुकसान पहुँचाते हैं, कीट कहलाते हैं।

उदाहरण - चूहे, चींटियाँ, तिलचट्टे आदि।

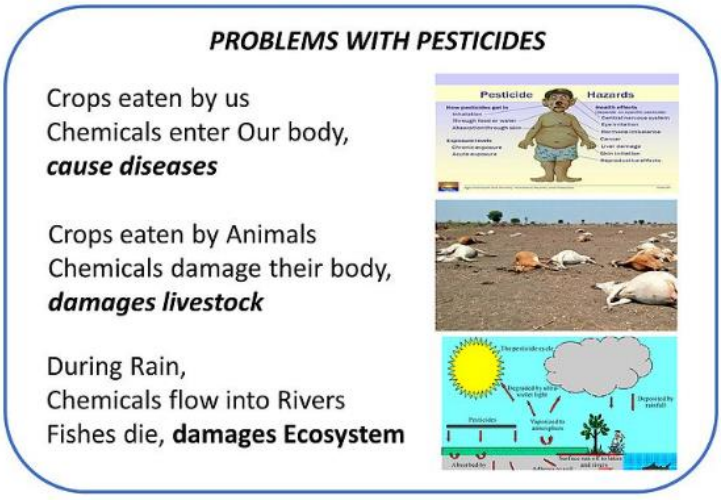

कीटनाशक क्या हैं?

- यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है।
- फसल को नुकसान से बचाने और पैदावार बढ़ाने के लिए इन कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है।

कीटनाशकों के उपयोग के हानिकारक प्रभाव क्या हैं?

- वे मिट्टी को प्रदूषित करते हैं
- जो पानी के साथ मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है
- वे फसल और भोजन को भी प्रदूषित करते हैं

जैव-कीट नियंत्रण क्या है?

- यह प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके कीटों की वृद्धि को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है।

जैव-कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ

नीम निर्मित कीटनाशकों का प्रयोग

- हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के स्थान पर नीम के पेड़ से बने कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है
- ये मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते

मिश्रित फसल

- मिश्रित फसल का अर्थ है भूमि के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना

- कीट मुख्यतः अपनी गंध (गंध) के कारण फसलों की ओर आकर्षित होते हैं।
- 2 या अधिक फसलें उगाने से कीट भ्रमित हो जाते हैं और वे फसल पर कम हमला करते हैं
- कई किसान जाल फसलों (सीमा पर) का भी उपयोग करते हैं - ऐसी फसलें जो कीटों को पसंद नहीं हैं और कीटों को नियंत्रित करने के लिए अंदर के क्षेत्र में मुख्य फसल होती हैं

→ कीटों को नियंत्रित करने के लिए जानवरों और पक्षियों का उपयोग करना

→ विभिन्न जानवर और पक्षी कीटों को खाते हैं

उदाहरण - साँप दर को मारता है, छिपकली कीड़े खाती है

ये जानवर और पक्षी कीटों को प्राकृतिक रूप से मारने में मदद कर सकते हैं

रणनीति 9-सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा या ऊर्जा क्या है?

- सूर्य की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है
- सूर्य की किरणों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है

Meaning	→	*Power obtained by harnessing energy of sun's rays is called Solar Power*
How it Functions	→	*By using Solar PV Cells (Photovoltaic Cells) They absorb sunlight and convert it into electric current*
Where Used	→	*Area closer to equator where plenty of sunlight is received*
Benefits	→	*Saves Costs Pollution Free Suitable for Remote Areas*

सौर ऊर्जा को बिजली में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है?

- सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक कोशिकाओं की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है
- सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और विद्युत प्रवाह बनाने के लिए उस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं।

सौर ऊर्जा भारत के लिए उपयुक्त क्यों है?

- भारत भूमध्य रेखा के करीब है और यहां बड़े खुले मैदान हैं जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है
- भारत में भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी है
- इसलिए, सौर ऊर्जा का उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जहां ग्रिड या बिजली लाइनें या तो संभव नहीं हैं या बहुत महंगी हैं

भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

- भारत सौर ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतरराष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व कर रहा है
- भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट और सोलर वाटर पंप उपलब्ध कराकर गांवों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया है
- सौर जल पंपिंग से जल सिंचाई में सौर ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण पर प्रभाव कम हो जाता है, जिससे यह प्रक्रिया दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और लाभदायक हो जाती है।
- इसलिए पर्यावरण पर प्रभाव में कमी ऊर्जा के स्रोत को सीधे सूर्य से लेकर स्थानांतरित करने से होती है। इससे पेट्रोल/डीजल और बिजली की जरूरत भी कम हो जाती है।

ग्लोबल वार्मिंग

भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि क्या है?

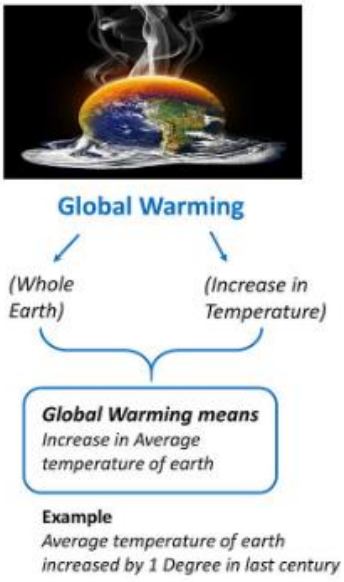

- यह पृथ्वी के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि है
- यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) आदि जैसे ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के कारण होता है।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभाव क्या हैं?
- औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण, जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई में वृद्धि हुई है
- इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि हुई है
- इसके अलावा, मवेशी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है जो पर्यावरण में उच्च मात्रा में मीथेन उत्सर्जित करता है

ग्लोबल वार्मिंग के कारण

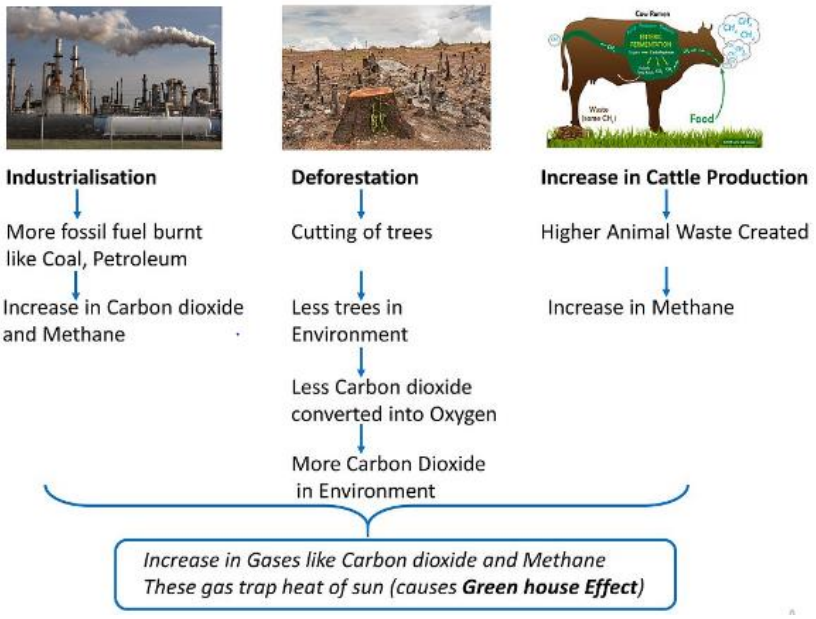

प्रभाव

- इन गैसों में ग्रीनहाउस प्रभाव होता है (सूर्य की गर्मी को फँसाना)
- इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है
- इससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल स्तर बढ़ रहा है
- भविष्य में इसके कारण कई शहर पानी में डूब सकते हैं.

What is Effect of Global Warming?

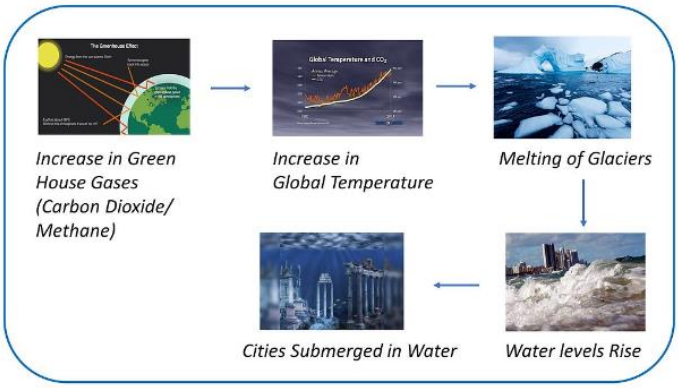

पर्यावरण की अवशोषण क्षमता

जब हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है?

- जब हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो वह समाप्त हो जाता है

What Happens when we use a Resource ?

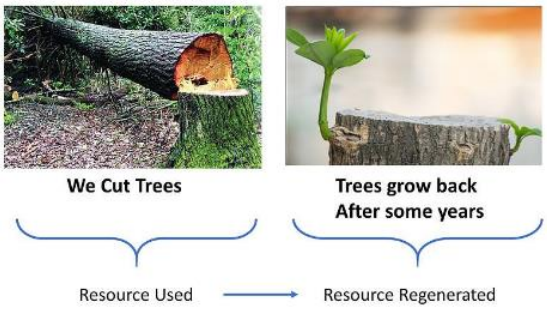

- हालाँकि, यह जल्द ही पर्यावरण द्वारा पुनर्जीवित हो जाता है
- साथ ही अपशिष्ट उत्पाद पर्यावरण में अवशोषित हो जाते हैं

उदाहरण

- जब हम पेड़ों को काटते हैं तो कुछ समय बाद वे फिर से उग आते हैं
- इसके अलावा, मृत पौधों और पेड़ों का अपघटन मिट्टी में पोषक तत्व मिलाता है और इसे उपजाऊ बनाता है।

क्या पुनर्जनन की दर सभी संसाधनों के लिए समान है?

- नहीं
- कुछ संसाधन कुछ महीनों में पुनर्जीवित हो जाते हैं, उदाहरण - पौधे
- कुछ को कई साल लग जाते हैं, उदाहरण - पेड़
- कुछ को तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण - कोयला, पेट्रोलियम

Example 1

Suppose in a Country

Petroleum Available	2000 million tonnes
Petroleum Used every year	500 million tonnes
Time taken for Petroleum to Regenerate	10 million years

Year	*Resource Available*	*Resource Extracted*	*Resource Regenerated*	*Closing Resource*	
1	2000	500	0	1500	
2	1500	500	0	1000	*Resource Getting Depleted*
3	1000	500	0	500	*Resource Getting Depleted*
4	500	500	0	0	*Resource Getting Exhausted*

Rate of Extraction is more — *Rate of Regeneration Is 0*

Due to this Resource gets exhausted in Year 4

संसाधन क्यों ख़त्म हो जाते हैं?

ऐसा इसलिए है क्योंकि हम संसाधनों को पुनर्जीवित करने की तुलना में उनका अधिक उपयोग कर रहे हैं

उदाहरण - हम भारी मात्रा में पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं लेकिन इसे पुनर्जीवित होने में लाखों वर्ष लगेंगे। अत: निकट भविष्य में पेट्रोल समाप्त हो जायेगा

Example 2

Suppose in an Area

No of Trees Available	*100*
No of Trees Cut	*60*
No of Trees Grown	*20*

Year	*Resource Available*	*Resource Extracted*	*Resource Regenerated*	*Closing Resource*	
1	100	60	20	60	*Resource Getting Depleted*
2	60	60	20	20	
3	20	60	20	-20	*Resource Getting Exhausted*

Rate of Extraction is more — Rate of Regeneration Is less

Due to this Resource gets extracted in Year 3

पर्यावरण की अवशोषण या वहन क्षमता क्या है?

- इसका अर्थ है पर्यावरण की क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता
- यदि संसाधन का निष्कर्षण संसाधन के पुनर्जनन की दर से ऊपर नहीं है, तो यह कहा जाता है कि संसाधन का उपयोग वहन क्षमता के भीतर किया जाता है
- यदि हम संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो इससे संसाधन समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है

यदि हम संसाधनों का उसकी वहन क्षमता से अधिक उपयोग करें तो क्या होगा?

- इस मामले में, संसाधन तेजी से ख़त्म हो जाते हैं
- हालाँकि, उनकी भरपाई तेजी से नहीं होती है
- इसलिए, कुछ संसाधनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है (ख़त्म हो जाते हैं) या कम आपूर्ति में रह जाते हैं

उदाहरण - कई जंगली जानवर विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं

- कचरा जमा हो जाता है
- जितना अधिक हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, उतना अधिक कचरा हम उत्पन्न करते हैं
- यह अतिरिक्त कचरा पर्यावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है
- पर्यावरण जीवन को कायम रखने का कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं है
- इंसानों ने सड़कें और शहर बनाने के लिए जंगलों में पेड़ों को काटा है
- इससे कई पौधों और जानवरों का आवास नष्ट हो गया है

प्रदूषण का कारण बनता है

- कारकों और शहरों द्वारा उत्पन्न कचरे को नदियों में फेंक दिया जाता है जो जल जनित बीमारियों का कारण बनते हैं
- कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और वायु प्रदूषण का कारण बनता है

ग्लोबल वार्मिंग

- जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई से कार्बन-डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि हुई है
- इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है
- इससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल स्तर बढ़ रहा है
- इससे जल स्तर में वृद्धि हुई है जिससे कई शहर पानी में डूब सकते हैं

ओज़ोन रिक्तीकरण

- यह पर्यावरण में ओजोन गैस की मात्रा में कमी को संदर्भित करता है
- यह ओजोन गैस हानिकारक गैस को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकने के लिए उपयोगी है
- ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर जैसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं।
- यह फाइटोप्लांकटन की वृद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है और जलीय पौधों को भी प्रभावित करता है

- यह ओजोन क्षरण रेफ्रिजरेटर और एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग के कारण होता है

पर्यावरण क्या है?

- वह स्थान, लोग, वस्तुएँ और प्रकृति जो किसी भी जीवित जीव को घेरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक संयोजन है।

पर्यावरण के घटक क्या हैं?

इसके 2 घटक या तत्व हैं:

1. जैविक तत्व

- यह सभी जीवित तत्वों जैसे जानवरों, पौधों, मनुष्यों आदि को संदर्भित करता है

2. अजैविक तत्व

- यह चट्टानों, सूर्य के प्रकाश जैसे सभी निर्जीव तत्वों को संदर्भित करता है

पर्यावरण के कार्य क्या हैं?

1.यह संसाधनों की आपूर्ति करता है

- पर्यावरण से हमें नवीकरणीय एवं गैर-नवीकरणीय दोनों संसाधन प्राप्त होते हैं

2.यह अपशिष्ट को आत्मसात करता है

- मनुष्य द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण में फेंक दिये जाते हैं

उदाहरण - औद्योगिक कचरा नदियों और समुद्रों में फेंक दिया जाता है

3. यह जीवन को कायम रखता है

- विभिन्न जानवर और पौधे पर्यावरण के कारण ही अस्तित्व में रह पाते हैं
- एक जीव दूसरे के लिए भोजन का काम करता है और हम मिलकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं

4. यह सौंदर्य सेवाएं (दृश्यावली) प्रदान करता है

- सौंदर्यबोध का अर्थ है सुखद, सकारात्मक या कलात्मक उपस्थिति
- पर्यावरण के विभिन्न घटक मिलकर एक सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं

भारत के विशाल प्राकृतिक संसाधन

1.मिट्टी की समृद्ध गुणवत्ता

- भारत में मिट्टी की विशाल विविधता है जिसका उपयोग विभिन्न फसलें उगाने के लिए किया जाता है

उदाहरण - दक्कन क्षेत्रों में काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त है

2.नदियों और सहायक नदियों की संख्या

- भारत में बड़ी मात्रा में नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं जो कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ मछली पकड़ने और परिवहन का स्रोत भी उपलब्ध कराती हैं

3.हरे-भरे जंगल

- भारत में चारों ओर बड़ी संख्या में जंगल फैले हुए हैं।
- वे कई पौधों और जानवरों का निवास स्थान हैं

4. पर्वतों की श्रृंखला

- उत्तर भारत में हिमालय की बहुतायत है जो न केवल पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है बल्कि कई औषधीय पौधे भी उपलब्ध कराता है

5.हिन्द महासागर

- भारत को महासागरों के निकट विशाल क्षेत्र का सौभाग्य प्राप्त है। मछलियों की विशाल विविधता पाई जाती है।

6. उपजाऊ सिन्धु-गंगा का मैदान

- इंडो-गैंगेटिक प्लेन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है
- ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र हैं और इसलिए अत्यधिक आबादी वाले हैं

7. खनिजों की बड़ी मात्रा

- भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सोना आदि जैसे खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं
- कुल लौह अयस्क भंडार का 8% भारत में पाया जाता है
- इन सबके कारण, भारत विश्व के मात्र 2.5% भौगोलिक क्षेत्र में विश्व की 17% मानव आबादी और विश्व की 20% पशुधन आबादी का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है?

भूमि अवक्रमण

- भूमि क्षरण का अर्थ है मिट्टी की उत्पादकता में कमी
- उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि के कारण भारत की उपजाऊ मिट्टी को नुकसान हो रहा है।

जैव विविधता हानि

- आर्थिक विकास के लिए जंगलों में पेड़ों की कटाई से जंगली जानवरों और पौधों के आवास का नुकसान हुआ है
- उनमें से कई विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं

वायु प्रदूषण

- वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दोपहिया वाहन और कार जैसे वाहन हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं
- वायु प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण भी होता है।

ताज़ा जल प्रबंधन

- भारत का ताज़ा पानी नदी और झीलों से आता है
- हालाँकि, ये दूषित हो जाते हैं क्योंकि सीवेज कभी-कभी बिना किसी प्रसंस्करण के लापरवाही से इसमें बहा दिया जाता है
- इसलिए, भारत को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है

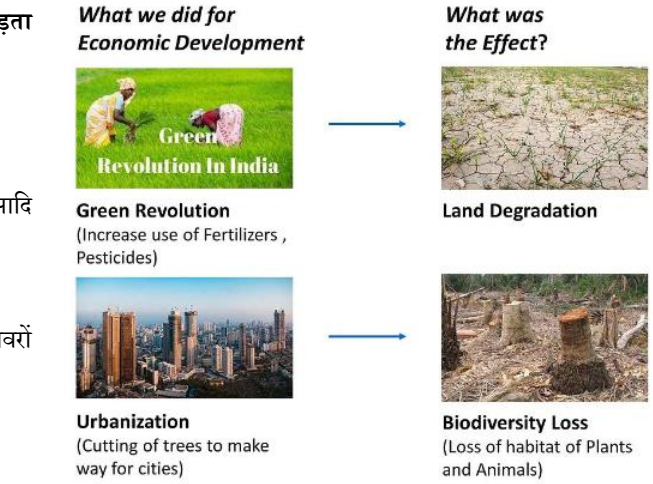

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ उद्योगों द्वारा भी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है
- हालाँकि, उनका निपटान ठीक से नहीं किया जाता है
- इसलिए जगह-जगह कूड़े के ढेर लग जाते हैं जिससे कई बीमारियाँ पैदा होती हैं

CLASS 11

CHAPTER 10

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ अपने पड़ोसियों (चीन और पाकिस्तान) के साथ भारत के विकास की तुलना
- ✓ मानव विकास और उसके संकेतक

भारत जैसे देशों के लिए पड़ोसियों की विकास प्रक्रिया को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

→ बढ़ते वैश्वीकरण के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों के साथ-साथ चीन जैसे विकासशील देशों से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। इसलिए, इन देशों में विकास प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है

1. हम उनके साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं (क्योंकि हम उनके साथ सामान्य आर्थिक गतिविधियाँ साझा करते हैं)
2. हम उनसे अपनाई गई अच्छी आर्थिक नीतियों से सीखकर उन्हें अपने देश में लागू कर पाते हैं हम भी उनके द्वारा की गयी गलतियों को समझ पा रहे हैं और उन्हें अपने देश में नहीं दोहरा रहे हैं
3. पड़ोसियों से तुलना करने पर अपनी ताकत और कमजोरी को समझना बेहतर होता है

विकास पथ - भारत पाकिस्तान और चीन -

विवरण	भारत	पाकिस्तान	चीन
स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी?	(भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली)	(पाकिस्तान 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया)	(पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई थी)

5 साल की योजनाएं कब शुरू की गई थीं?	1951	1956	1953
आजादी के बाद अपनाई गई आर्थिक नीति	विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण	विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण	अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में आ गए
	(सरकार ने विशाल पूंजी-गहन उद्योगों की स्थापना की जबकि निजी क्षेत्र ने छोटे उद्योगों और कारखानों का विकास किया)	(सरकार ने विशाल पूंजी-गहन उद्योगों की स्थापना की जबकि निजी क्षेत्र ने छोटे उद्योगों और कारखानों का विकास किया)	सरकार के पास सारी जमीन और सभी कारखाने और जमीन थी
	नए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों जैसे सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि	नए स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों जैसे सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि	जीएलएफ अभियान (ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन) 1958 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण करना था
कृषि	कृषि निजी क्षेत्र के पास थी	कृषि निजी क्षेत्र के पास थी	सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, गांवों में कम्यून स्थापित किए गए थे जहां सभी लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे
	व्यक्तिगत किसानों के स्वामित्व वाले छोटे खेत	व्यक्तिगत किसानों के स्वामित्व वाले छोटे खेत	

All 3 got Independence around same time

India	Pakistan	China
1947	**1947**	**1949**
(From Britishers)	(From Britishers)	(People's Republic of China was formed)

5 Years Plans announced around the same time

India	Pakistan	China
1951	**1956**	**1953**

Strategies Adopted in 5 Year Plans

India
Mixed Economy

(Govt run large industries while Private Sector owned run small industries)

Pakistan
Mixed Economy

(Govt run large industries while Private Sector owned run small industries)

China
Socialist Economy

(All Major Sectors under Government Control)

Who Owned Land?

India
Private Sector

Small Farms Owned by Individual Farmers

Pakistan
Private Sector

Small Farms Owned by Individual Farmers

China
Government

Govt Owned the land. Communes were set up in villages where all the people collectively cultivated land

चीन के विकास के महत्वपूर्ण वर्ष

⟶ 1949 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन 1949 में हुआ

⟶ सरकार के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भूमि और उद्यमों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया

⟶ 1958 ग्रेट लीप फॉरवर्ड (जीएलएफ) अभियान शुरू किया गया

⟶ देश का औद्योगीकरण बड़े पैमाने पर शुरू किया गया

⟶ लोगों को अपने आँगन में कारखाने स्थापित करने के लिए कहा गया

⟶ ग्रामीण क्षेत्रों में, कम्यून प्रणाली शुरू की गई जहां लोग सामूहिक रूप से भूमि पर खेती करते थे

⟶ जीएलएफ अभियान को सूखे के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसमें 39 मिलियन लोग मारे गए

⟶ रूस के साथ संघर्ष हुआ।

⟶ इन संघर्षों के दौरान, रूस ने अपने पेशेवरों को वापस बुला लिया जिन्हें औद्योगीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए चीन भेजा गया था

⟶ 1966-76 "महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति"

⟶ इस अवधि के दौरान, छात्रों और पेशेवरों को सीखने और काम करने के लिए ग्रामीण इलाकों (गांवों) में भेजा गया था

⟶ 1978 आर्थिक सुधार शुरू किये गये

⟶ प्रारंभिक चरण में सुधार कृषि, विदेश व्यापार और निवेश क्षेत्रों में थे

1978 में किये गये प्रमुख सुधार

कृषि में सुधार

- सामुदायिक भूमि को विभाजित किया गया और उपयोग के लिए अलग-अलग परिवारों को आवंटित किया गया
- हालाँकि, स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा
- इन खेत मालिकों को सरकार को कर चुकाने के बाद सारा लाभ अपने पास रखने की अनुमति थी।

निजी क्षेत्र में सुधार

- निजी क्षेत्र को माल का उत्पादन करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (जिन्हें एसओई-राज्य स्वामित्व वाले उद्यम कहा जाता है) के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी।

दोहरी कीमत

- कृषि और निजी क्षेत्र को 2 कीमतों पर सामान खरीदना और बेचना पड़ता था
- सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर एक निश्चित निश्चित मात्रा
- बाजार मूल्यों पर संतुलन मात्रा

टिप्पणी

- पहले के वर्षों में सरकारी मूल्य पर उत्पादन अधिक होता था
- बाद के वर्षों में, जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ा, बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं में वृद्धि हुई

निवेश क्षेत्र में सुधार

- सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करने की अनुमति देकर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया
- सरकार ने इन एसईजेड में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को कर रियायतें दीं
- बुनियादी ढांचे में निवेश
- सड़कों, पुलों, बिजली आपूर्ति, नए शहरों के निर्माण, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया
- इनसे न केवल नौकरियाँ मिलीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला

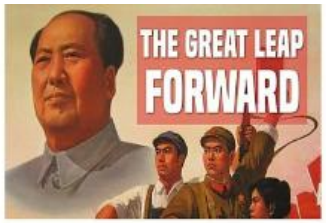

Great Leap Forward Reforms of 1958	1978 Reforms of China
Commune System was Launched People collectively Cultivated Lands Income from Farming went to Govt)	**Commune land divided into Small Plots** (These were allocated for use to individual households) Income from Farming went to Individual households after paying applicable taxes
All Major Sectors with Government State Owned Enterprises did not face any completion from private sectors)	**Private Sector firms allowed** State Owned Enterprises faced competition

Great Leap Forward Reforms of 1958	1978 Reforms of China
Foreign Investment Not allowed China was a closed economy and there was very little foreign investment	**Foreign Investment Encouraged** Govt set up SEZ (Special Economics Zone) where tax concessions were given to foreign investors
Less focus on Infrastructure Not much development in Roads, Electricity supply et)	**Large Scale Infrastructure Development** Massive Investment in Infrastructure was undertaken like Building of roads,bridges,electriocity supply, new cities ,extension of basic health services

Comparison-India vs China Development Policies

	India	China
Independence	1947	1949
5 Year Plans	Started 1951	Started 1953
Who Owned Land	Private Sector	Government
Agriculture	Small Farmers owned small prices of land	Commune System and collective Farming
Reforms in Agriculture	Green Revolution (1960'S)	1978 Reforms, Commune land divided and allocated to Small Households)
Industry	Public Sector Undertakings run large Industries Private Sector operated small business	Earlier, Only Govt Sector run major sectors Later in 1978, Private Sector also allowed
Reforms in Industry	1991 Reforms (Policy of Liberalization, Globalization, Privatization)	1978 Reforms (Dual Pricing, Foreign Investment allowed, Infrastructure Improvement

पाकिस्तान के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण चरण

1947

- 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली
- उस दौरान पाकिस्तान भी भारत की तरह ही काफी हद तक आयात पर निर्भर था

1950-60

- पाकिस्तान ने आयात प्रतिस्थापन आधारित औद्योगीकरण के लिए निम्नलिखित सुधार पेश किए
- उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए टैरिफ संरक्षण
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी
- मशीनीकरण द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई

1970 का दशक

- पूंजीगत वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ

1970-1980 के अंत में

- अराष्ट्रीयकरण हुआ और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया
- पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई
- इसे कई पाकिस्तानी नागरिकों से मध्य पूर्व (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात) में विदेशी प्रेषण भी प्राप्त हुआ।

1988

- प्रमुख सुधार किये गये
- व्यापार उदारीकरण, निर्यात संवर्धन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार

Comparison-India vs Pakistan Development Policies

	India	Pakistan
Independence	14-Aug-47	14-Aug-47
5 Year Plans	Started 1951	Started 1956
Policy followed 1950-60	Import Substitution Protection of Domestic Industries Public Investment in Infrastructure Green Revolution	Import Substitution Protection of Domestic Industries Public Investment in Infrastructure Green Revolution
Nationalization of Capital Goods Industries	Already under Govt (PSU)	1970'S
Denationalization	1991	Late 1970-80
Major Reforms	Started 1991 (Liberalization, Globalization, Privatization)	Started in 1988 Trade Liberalization, Export Promotion, Financial Sector Reforms

विकास संकेतकों की तुलना - भारत बनाम पाकिस्तान बनाम चीन

जनसंख्या

- चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसके बाद भारत है
- पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है (भारत या चीन का लगभग 1/10)

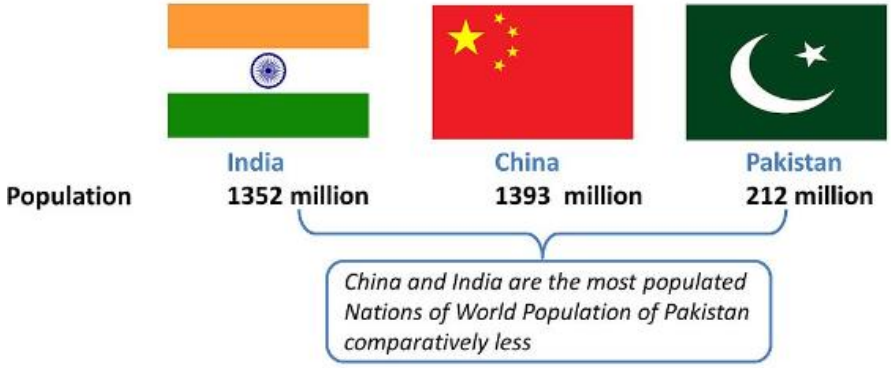

जनसंख्या वृद्धि

- पाकिस्तान में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत में कम तेजी से
- चीन में एक बच्चे की नीति थी जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कम थी

जनसंख्या घनत्व

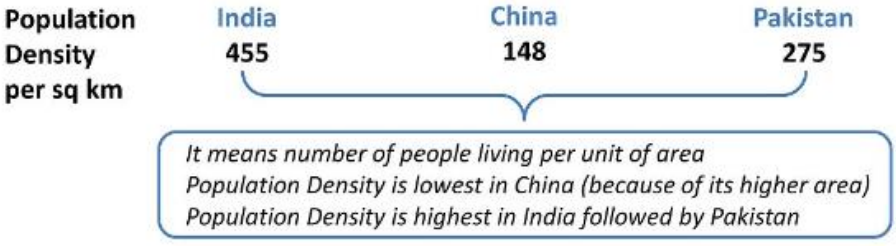

- इसका तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है
- चीन में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है (अधिक क्षेत्रफल के कारण)
- जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है और उसके बाद पाकिस्तान का स्थान है

लिंग अनुपात

- इसका मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है
- आदर्श रूप से, यह प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होनी चाहिए
- लेकिन पितृसत्तात्मक समाज (पुरुष प्रधान समाज) और कन्या भ्रूण हत्या (जन्म से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता है) के कारण यह तीनों देशों - भारत, चीन और पाकिस्तान में कम है।

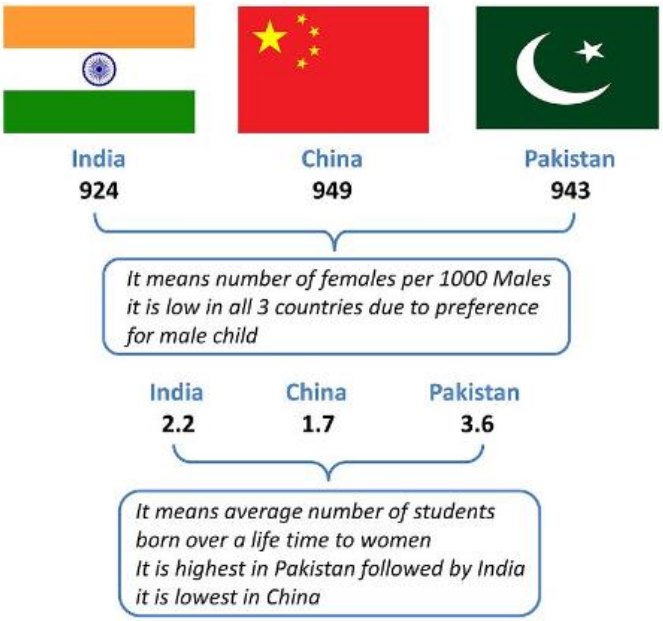

प्रजनन दर

- इसका मतलब है महिलाओं द्वारा जीवनकाल में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या
- यह भारत के बाद पाकिस्तान में सबसे अधिक है
- चीन में यह सबसे कम है

शहरीकरण

- इसका मतलब शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत है
- यह भारत की तुलना में चीन के बाद पाकिस्तान में सबसे अधिक है
- इसका मतलब है कि भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं

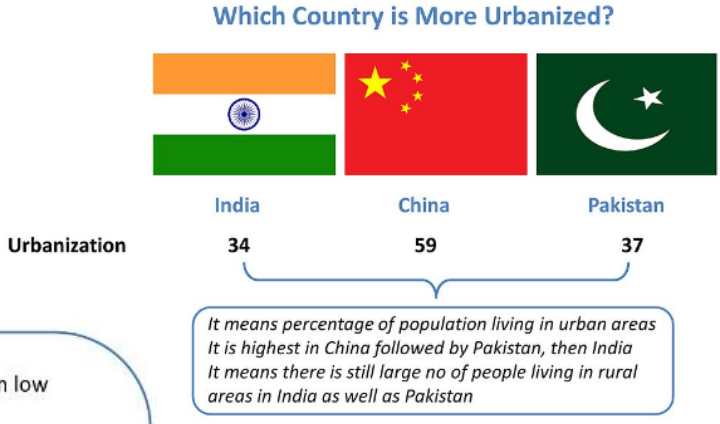

Population	China and India very high, Pakistan low
Population Growth	Highest in Pakistan, then India, then China
Area	China much higher, India smaller, Pakistan smallest
Population Density	Very high in India and Pakistan, less in China
Sex Ratio	Poor in All 3 countries
Fertility Rate	Highest in Pakistan, then India, then China
Urbanization	China much more urbanized, India and Pakistan rural

जीडीपी की तुलना - भारत, पाकिस्तान और चीन

सकल घरेलू उत्पाद

- इसका मतलब देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य है

जीडीपी बढ़त

- पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि % में

What is GDP and GDP Growth Rate?

Example

Suppose in a country,
Gross Value of Goods and Services produced in Country =

In Year 2021 *1000 Crores*
In Year 2021 *1040 Crores*

What is Increase in GDP?

		2021	2022
GDP	=	1000	1030

What is GDP?
Value of Goods and Service Produced

Increase in GDP *30*

GDP Growth Rate *30/1000*100 = 3%*

What is GDP Growth Rate?
increase in GDP Compared to previous year in %

⟶ औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में, अधिक उद्योग और सेवा क्षेत्र राष्ट्रों के विकास में योगदान करते हैं। कम औद्योगीकृत राष्ट्र में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक होती है।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा

- यह चीन में सबसे कम (7%) है, इसके बाद भारत (16%) और पाकिस्तान (24%) का स्थान है।
- इसका मतलब है कि चीन कृषि पर बहुत कम निर्भर है जबकि भारत और पाकिस्तान अधिक निर्भर हैं

सेवा क्षेत्र का हिस्सा

- यह सभी 3 देशों में उच्च है -भारत: 54%, चीन: 52%, पाकिस्तान: 57%

औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा

- चीन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक 41% है
- भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 30%
- पाकिस्तान तीन देशों में सबसे कम 19% औद्योगिकीकरण वाला देश है

कार्यबल का वितरण

- कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
- भारत और पाकिस्तान में अभी भी बड़ी संख्या में लोग कृषि पर निर्भर हैं
- चीन में यह काफी कम है
- (भारत में 43%, पाकिस्तान में 41% जबकि चीन में 26%)

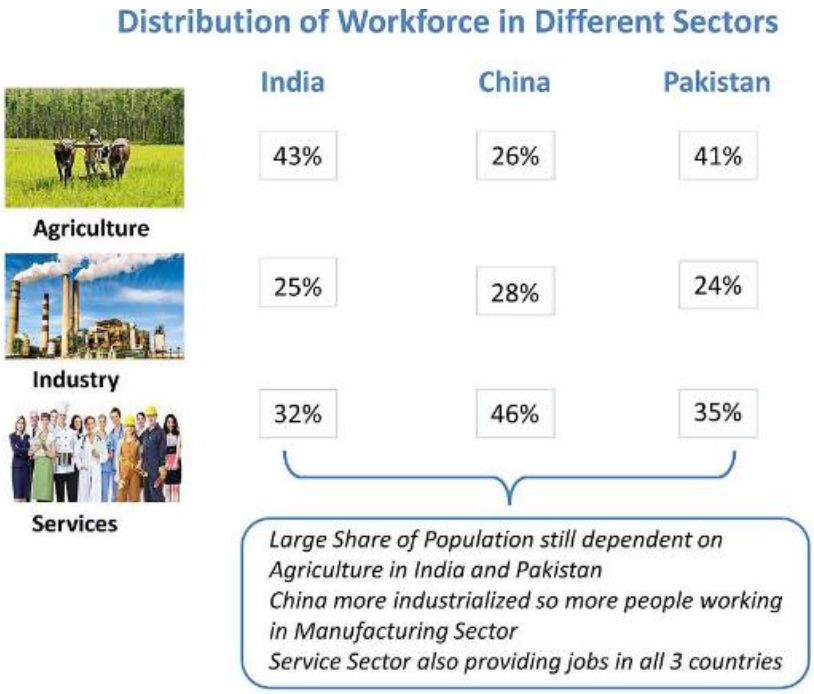

मानव विकास सूचकांक क्या है?

यह एक सूचकांक है जो मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि को मापता है

- लंबा और स्वस्थ जीवन
- ज्ञान
- सभ्य जीवन स्तर

विभिन्न मानव विकास संकेतक क्या हैं?

इस मामले में, हम निम्नलिखित मापते हैं:

संकेतक	अर्थ
जीवन प्रत्याशा	व्यक्ति से कितने वर्षों तक जीवित रहने की अपेक्षा की जाती है?
स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष	किसी व्यक्ति द्वारा स्कूल जाने के वर्षों की संख्या
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय	प्रति व्यक्ति आय
गरीबी रेखा से नीचे के लोग	गरीबी रेखा से नीचे कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या
शिशु मृत्यु दर	जन्म के समय मरने वाले बच्चों की संख्या
मातृ मृत्यु दर	बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली महिलाओं की संख्या
कम से कम बुनियादी स्वच्छता वाली जनसंख्या	शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता
कम से कम बुनियादी पेयजल वाली जनसंख्या	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते

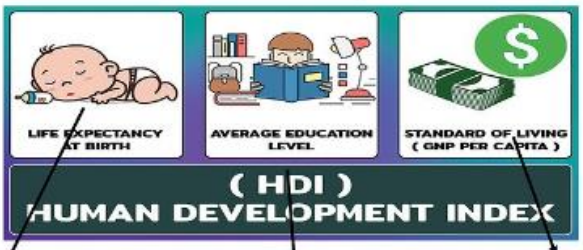

Long and Healthy Life

Life Expectancy

No of Years Person is expected to live

Infant Mortality Rate

No of children who die at birth

Maternal Mortality Rate

No of women who die during child birth

Percentage of Undernourished Children

No of Children who do not get sufficient nutrients

Knowledge

Mean Years of Schooling

No of years a person has attended school

Decent Standard of living

Gross National income per Capita

Income per Person

Population with at least Basic Sanitation facilities

Availability of Sanitation Facilities like Toilet

Population with at least Basic Drinking after

Availability of clean drinking water

विभिन्न मानव विकास संकेतकों पर भारत, पाकिस्तान और चीन की रैंकिंग कैसी है?

⟶ चीन लगभग सभी मानव विकास संकेतकों पर भारत और पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन करता है

उदाहरण

- चीन का मानव विकास सूचकांक रैंक और मूल्य उच्च है
- इसमें उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा के उच्च औसत वर्ष भी हैं
- इसमें शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषित बच्चों का प्रतिशत भी कम है
- बुनियादी स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में भी यह भारत और पाकिस्तान से बेहतर है

Long and Healthy Life Comparison –
India, China and Pakistan in HDI

	India	China	Pakistan	
Life Expectancy	69.4	76.7	67.1 ⟶	*Higher the better*
Infant Mortality Rate	29.9	8.5	57.2 ⟶	*Lower the better*
Maternal Mortality Rate	174	27	178 ⟶	*Lower the better*
Percentage of Undernourished Children	37.9	8.1	37.6 ⟶	*Lower the better*

China has better health facilities so has better life expectancy and lower mortality Rate compared to India and Pakistan

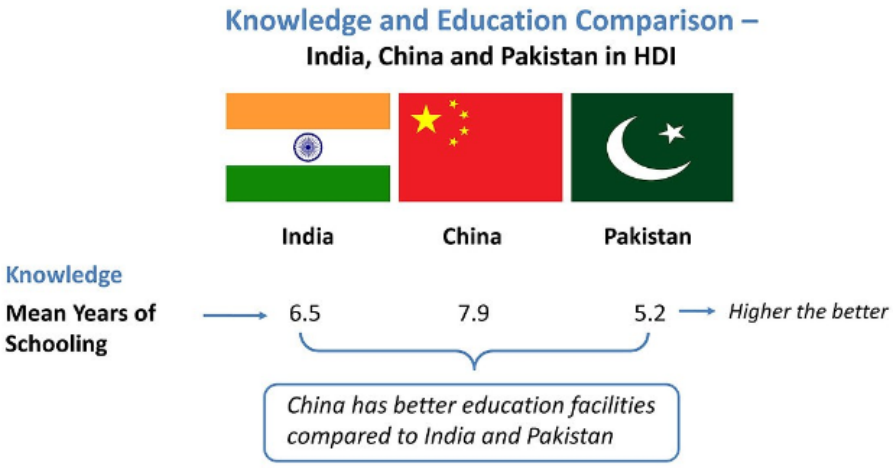

चीन भारत पाकिस्तान लिबर्टी संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं?

स्वतंत्रता संकेतकों पर भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से काफी ऊपर है

भारत में,

- विरोध करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायपालिका है
- भारत में भी ठोस लोकतंत्र है जहाँ नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार बनती है।

चाइना में

- एक पार्टी का नियम है
- इसलिए, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने जैसे मौलिक अधिकार नहीं हैं

पाकिस्तान में

- यहां लोकतंत्र है और सरकार नियमित रूप से चुनी जाती है
- लेकिन पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुए हैं जहां सेना ने सरकारों पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है

सारांश

- चीन मानव विकास संकेतकों में बेहतर है लेकिन स्वतंत्रता संकेतकों में उसका अभाव है
- भारत स्वतंत्रता संकेतकों में काफी बेहतर प्रदर्शन करता है लेकिन मानव विकास संकेतकों में अभी भी काम करना बाकी है
- गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या कम करने में पाकिस्तान ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अन्य मोर्चों पर वह पीछे है

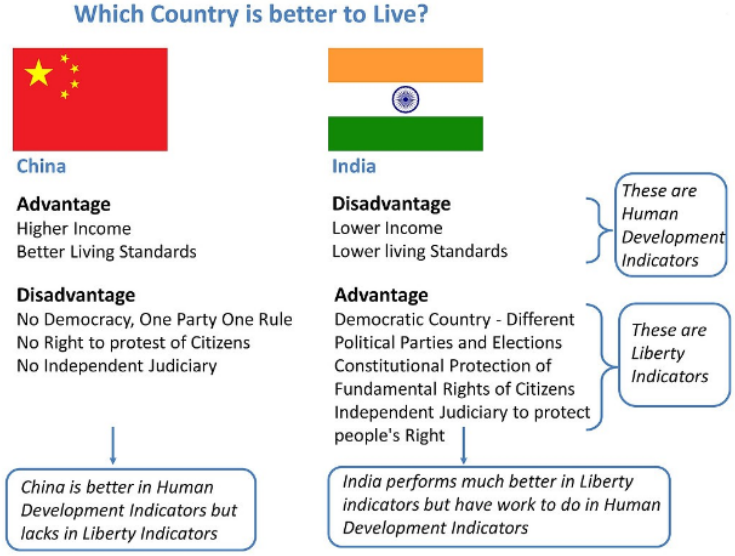

पाकिस्तान में सुधार प्रक्रिया

पाकिस्तान ने सुधारों से पहले और बाद में कैसा प्रदर्शन किया?

→ सुधारों के बाद पाकिस्तान का प्रदर्शन वास्तव में ख़राब रहा।

सुधारों से पहले

1970-80 में

→ पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर भारत से बेहतर थी (भारत की 5.7% की तुलना में पाकिस्तान की 6.3%)

सुधारों के बाद

→ पाकिस्तान की विकास दर घटकर 5.3% रह गई

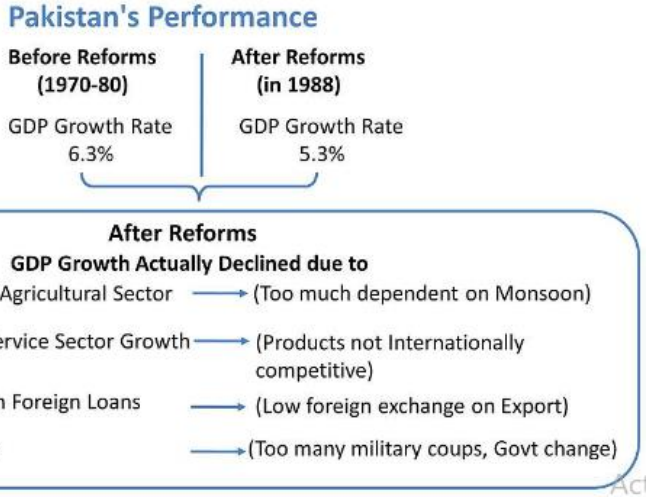

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि का मुख्य कारण

1. कृषि क्षेत्र का अस्थिर प्रदर्शन

- पाकिस्तान एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जो मानसून पर अत्यधिक निर्भर है
- अच्छी फसल के वर्षों के दौरान, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया
- हालाँकि, खराब मौसम के दौरान, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता या नकारात्मक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा

2. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के विकास में कमी

- पाकिस्तान अपने औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम नहीं है
- इसलिए, पाकिस्तान से निर्मित वस्तुओं का निर्यात बहुत कम है (जैसे चीन के मामले में)
- इसके अलावा, इसने अपने आईटी क्षेत्रों का विकास नहीं किया है (भारत की तरह आईटी सेवाओं का निर्यात बहुत कम है)

3. विदेशी ऋण पर बढ़ती निर्भरता

- पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत निर्यात नहीं है
- यह मध्य पूर्व (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात) से धन भेजने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों से है
- इसके अलावा, पाकिस्तान को अक्सर चीन और अमेरिका से बड़ी रकम उधार लेनी पड़ती थी
- अधिक ब्याज के बोझ के कारण यह समृद्ध नहीं हो पाया है

4. राजनीतिक स्थिरता का अभाव

- पाकिस्तान में सेना द्वारा लगातार तख्तापलट होते रहते हैं
- इसके कारण इसे विदेशी निवेश प्राप्त नहीं हो सका जो इसके विकास के लिए आवश्यक था

CLASS 12
CHAPTER 1

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- विभिन्न प्रकार के सेक्टर
- विभिन्न प्रकार के सामान
- सूक्ष्मअर्थशास्त्र बनाम समष्टिअर्थशास्त्र

अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, बिक्री और खरीददारी की जाती है।

एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के प्रकार और वस्तुओं के प्रकार

Example

Suppose there are only 2 people in an area -Factory and Mr. A

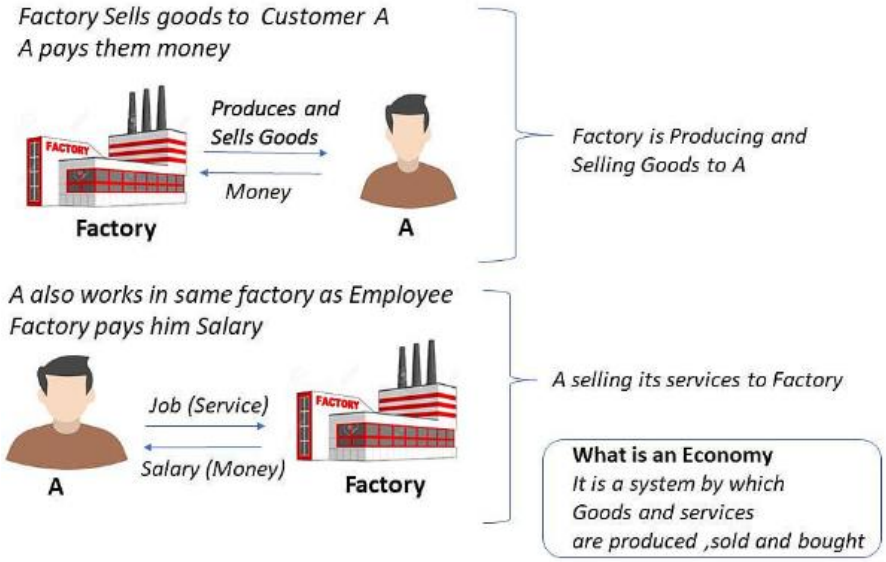

⟶ अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र

⟶ आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

1. निजी क्षेत्र:

- निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले सभी उद्यम निजी क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र में भारत की वे कंपनियाँ/फर्म/उद्यम शामिल हैं जिनका स्वामित्व सरकार के पास नहीं है।

2. सरकारी क्षेत्र:

- इस क्षेत्र में सार्वजनिक प्रशासन, पुलिस, रक्षा, कानून बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है। कर लगाने और विभिन्न बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा आदि पर पैसा खर्च करने के अलावा, सरकार अपनी कंपनियों जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) आदि के माध्यम से उत्पादन गतिविधि भी करती है। इसलिए, सभी कंपनियों का स्वामित्व केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) भी सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं।

3. घरेलू क्षेत्र:

- व्यक्तियों का एक समूह जो आम तौर पर एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से भोजन करते हैं, एक परिवार कहलाता है। एक घर का आकार घर में व्यक्तियों की कुल संख्या है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि घरों का निर्माण लोगों से होता है। ये लोग फर्मों में श्रमिक के रूप में काम करते हैं और वेतन कमाते हैं। वे वही हैं जो सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन कमाते हैं और वे फर्मों के मालिक हैं और मुनाफा कमाते हैं। अतः सभी मनुष्य (जनसंख्या) घरेलू क्षेत्र के हैं।
- मान लीजिए कि "जॉन" नाम का एक व्यक्ति "कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)" में काम करता है, जो एक सरकारी कंपनी है तो जॉन घरेलू क्षेत्र से संबंधित है और कंपनी सीआईएल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है।

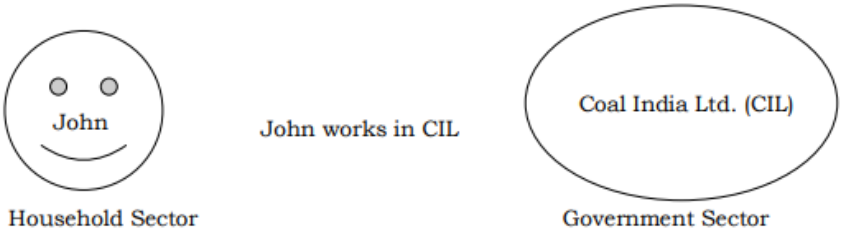

- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का स्वामित्व मुकेश अंबानी के पास है, लेकिन मुकेश अंबानी घरेलू क्षेत्र से संबंधित हैं और "आरआईएल" (जो एक निष्क्रिय वस्तु है और जिसके नाम पर सारा कारोबार किया जा रहा है) निजी क्षेत्र से संबंधित है।

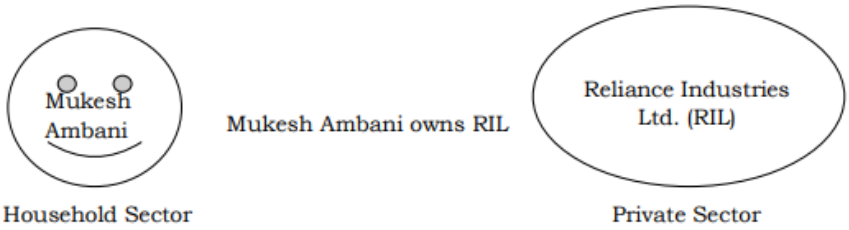

4. बाहरी क्षेत्र

- इस क्षेत्र में देश में या देश से बाहर आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात शामिल है। इसमें घरेलू देश से और देश में होने वाला वित्तीय प्रवाह भी शामिल है।

4. बाहरी क्षेत्र: इस क्षेत्र में देश में या देश से बाहर आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात शामिल है। इसमें घरेलू देश से और देश में होने वाला वित्तीय प्रवाह भी शामिल है।

सरकार की उत्पादन गतिविधियाँ

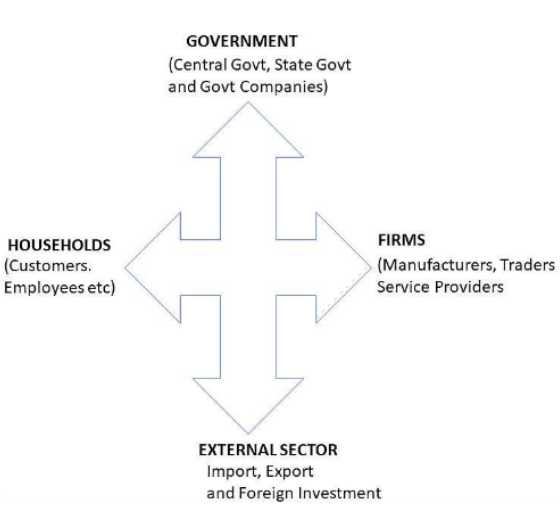

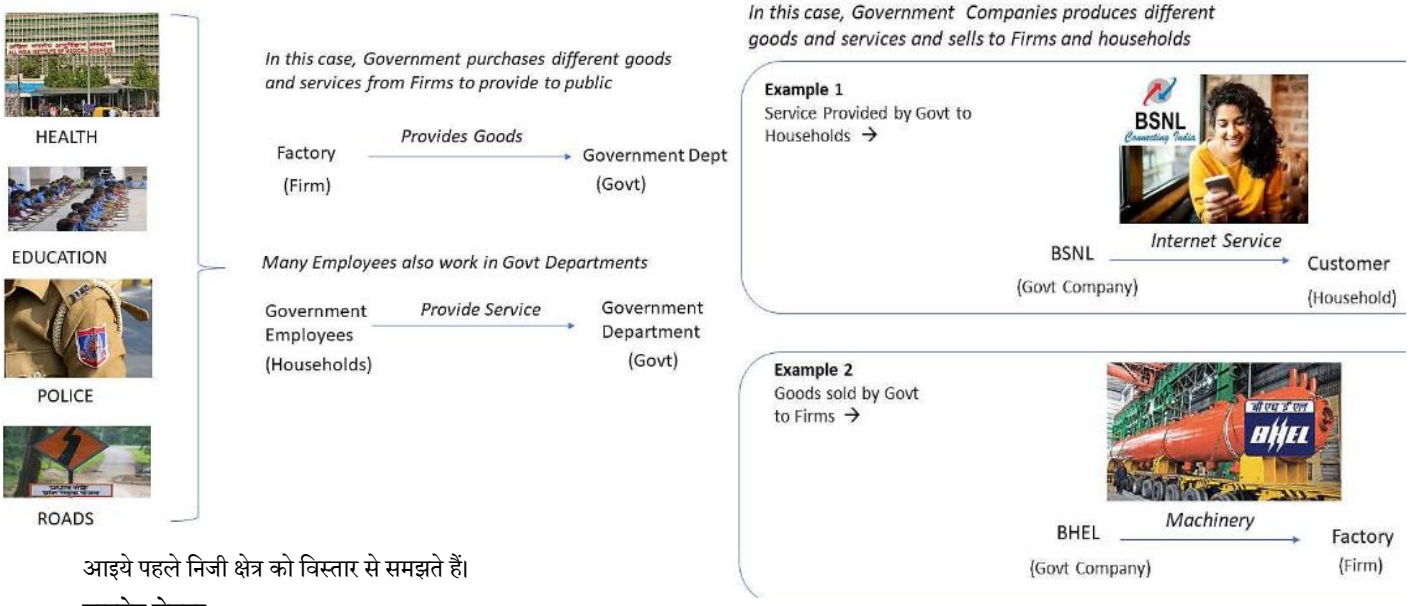

आइये पहले निजी क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं।

प्राइवेट सेक्टर

- निजी व्यक्तियों या उद्यमियों के स्वामित्व वाली सभी फर्में या उद्यम निजी क्षेत्र से संबंधित हैं और उनका मूल कार्य आउटपुट यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। आउटपुट का उत्पादन करने के लिए, किसी भी उद्यम को कुछ इनपुट की आवश्यकता होगी। किसी उद्यम को वांछित आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट की आवश्यकता हो सकती है या सैकड़ों इनपुट की आवश्यकता हो सकती है। किसी उद्यम को जिन सभी इनपुट की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है यानी उद्यमी, पूंजी, प्राकृतिक संसाधन और श्रम।

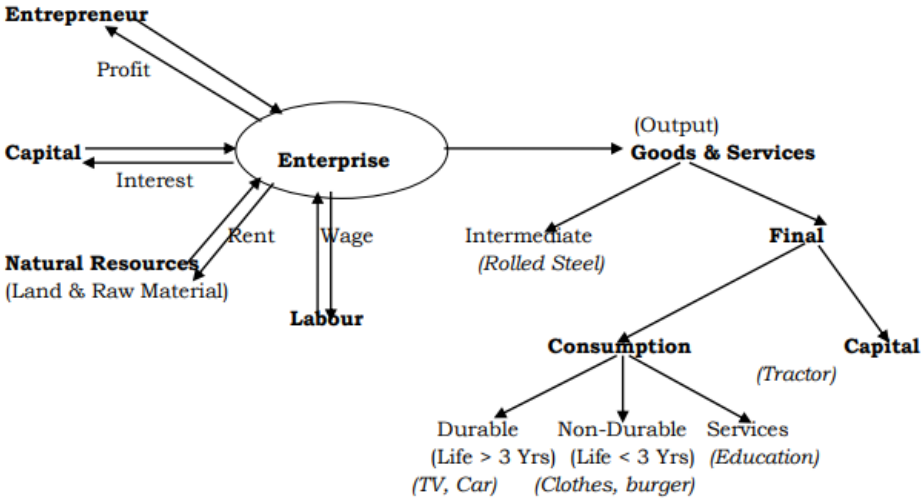

- किसी उद्यम को आउटपुट (वस्तुओं और सेवाओं) का उत्पादन करने के लिए जिन चार इनपुट की आवश्यकता होती है, उन्हें चार "उत्पादन के कारक" या "उत्पादन के इनपुट" कहा जाता है। उत्पादन के ये चार कारक निम्नलिखित हैं (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है):

1. उद्यमी: वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है और नया व्यवसाय शुरू करता है। यह व्यक्ति पूंजी, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों को एक उद्यम के रूप में एक साथ लाने का जोखिम उठाता है और बदले में "लाभ" की उम्मीद करता है। उद्यमी एक इंसान है और वह घरेलू क्षेत्र से संबंधित है।

2. पूंजी: आज की दुनिया में पूंजी भौतिक, वित्तीय या बौद्धिक हो सकती है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से केवल भौतिक पूंजीगत वस्तुओं को ही पूंजी माना जाता है। तो, पूंजी में भवन, मशीनरी, उपकरण आदि शामिल हैं। पूंजी के प्रतिफल को "ब्याज" कहा जाता है।

3. प्राकृतिक संसाधन: प्राकृतिक संसाधनों में भूमि और कच्चे माल शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और मानव निर्मित प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित नहीं किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रतिफल को "किराया" कहा जाता है।

4. श्रम: यह मानव श्रम है जो शारीरिक या मानसिक हो सकता है अर्थात यह अकुशल, अर्ध-कुशल या कुशल हो सकता है। जब कोई मनुष्य उद्यम को अपना श्रम प्रदान करता है, तो बदले में वह "मजदूरी" की अपेक्षा करता है। श्रमिक (जो श्रम सेवाएँ प्रदान कर रहा है) एक इंसान है और घरेलू क्षेत्र से संबंधित है।

सामान के प्रकार

सहायक सामग्री

- ये अर्ध-तैयार सामान हैं जो एक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किए गए हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और अंतिम उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आगे की उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए, स्टील शीट. स्टील शीट का उपयोग वैसे ही नहीं किया जा सकता है और इसे ऑटोमोबाइल, उपकरण आदि जैसे अंतिम उत्पादों में बदलने की आवश्यकता है।

अंतिम माल

- इन वस्तुओं में उत्पादन प्रक्रिया में कोई और परिवर्तन नहीं होता है। अंतिम वस्तुएँ दो प्रकार की हो सकती हैं - उपभोग वस्तुएँ और पूँजीगत वस्तुएँ।

1. उपभोग वस्तुएं: वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाती हैं या उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करती हैं, उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। वे तीन श्रेणियों के हो सकते हैं-

(i) टिकाऊ उपभोग वस्तुएं: उपभोग की वस्तुएं जो तुरंत समाप्त नहीं होती बल्कि लंबे समय तक चलती हैं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का जीवन आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक होता है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर आदि।

(ii) गैर-टिकाऊ उपभोग वस्तुएँ: उपभोग वस्तुएँ जो तुरंत उपभोग हो जाती हैं और जिनका जीवन आमतौर पर 3 वर्ष से कम होता है। उदाहरण के लिए, सौंदर्य प्रसाधन, भोजन, ईंधन, कागज, कपड़े आदि।

(iii) सेवाएँ: सेवाएँ अमूर्त हैं और केवल एक प्रकार की उपभोग वस्तुएँ हैं, क्योंकि, इसका तुरंत उपभोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, बैंकिंग, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा आदि।

2. पूंजीगत वस्तुएँ: कोई विशेष वस्तु प्रकृति में तभी पूँजी होगी जब उसमें निम्नलिखित तीन विशेषताएँ हों:

(i) यह मानव निर्मित प्रक्रिया का उत्पादित टिकाऊ आउटपुट है

(ii) यह फिर से आगे की उत्पादन प्रक्रिया (बाज़ार में बेचे जाने के लिए) के लिए एक इनपुट के रूप में कार्य करता है।

(iii) इनपुट के रूप में कार्य करते समय, यह परिवर्तित या उपभोग नहीं होता है

उदाहरण के लिए, ट्रैक्टर. ट्रैक्टर का उत्पादन किसी कारखाने में किया गया होगा इसलिए यह एक टिकाऊ उत्पादन है। ट्रैक्टर फिर से गेहूं और चावल जैसे कृषि उत्पादों के उत्पादन में एक इनपुट के रूप में कार्य करता है। और एक इनपुट के रूप में कार्य करते समय यह रूपांतरित नहीं होता है और जैसा है वैसा ही बना रहता है। (ट्रैक्टर में टूट-फूट लंबे समय तक होती है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ट्रैक्टर बदल रहा है या ख़त्म हो रहा है)।

सही मायने में अर्थशास्त्री भौतिक पूंजी को ही पूंजी मानते हैं लेकिन आज की दुनिया में अमूर्त पूंजी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। अतः पूंजी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

(i) भौतिक पूंजी (पूंजीगत सामान)

(ii) वित्तीय पूंजी (पैसा)

(iii) बौद्धिक पूंजी (पेटेंट, कॉपीराइट आदि)

टिप्पणी:

उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं: एक विशेष वस्तु उपभोग के साथ-साथ पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन. जब कोई व्यक्ति अपने कपड़े धोने के लिए अपने घर में वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहा है तो यह उपभोग वस्तु के रूप में कार्य करेगा।

लेकिन, यदि वही वॉशिंग मशीन किसी व्यवसायी द्वारा कपड़े धोने की सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदी जाती है तो यह पूंजीगत वस्तु के रूप में कार्य करती है। क्योंकि बाद के मामले में, वॉशिंग मशीन का उपयोग बाजार के लिए धुले हुए कपड़े का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है, न कि स्वयं के उपभोग के लिए।

इसलिए कोई वस्तु उपभोग है या पूंजी, यह उस उद्देश्य पर भी निर्भर करता है जिसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी वस्तु का उपयोग बाजार में बेचने के लिए कुछ अन्य वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जा रहा है तो यह पूंजीगत वस्तु होगी। उदाहरण के लिए, जब हम अपने घर के लिए कार खरीदते हैं तो यह उपभोग के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब "ओला कैब्स" बाजार के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए कार खरीदती है तो कार पूंजीगत वस्तु बन जाती है।

टिप्पणी:

मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु: एक विशेष वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, "चाय की पत्तियां"। जब कोई व्यक्ति अपने घरेलू उपभोग के लिए "चाय की पत्तियाँ" खरीद रहा है तो "चाय की पत्तियाँ" ही अंतिम वस्तु होगी।

लेकिन जब एक चाय विक्रेता "चाय" तैयार करने और उसे बाजार में बेचने के लिए "चाय की पत्तियां" खरीद रहा है तो "चाय की पत्तियां" मध्यवर्ती वस्तु है और "चाय" अंतिम वस्तु है। कोई वस्तु अंतिम हो या मध्यवर्ती, इसकी विशिष्ट विशेषता "बाज़ार में अंतिम लेन-देन" है।

चाय विक्रेता के मामले में, बाजार में अंतिम लेनदेन चाय का होता है, इसलिए "चाय" अंतिम वस्तु है। लेकिन घरेलू प्रयोजन के लिए चाय की पत्तियां खरीदने वाले व्यक्ति के मामले में, "चाय की पत्तियां" बाजार में अंतिम लेनदेन वाली वस्तु है, इसलिए "चाय की पत्तियां" अंतिम वस्तु होगी।

सूक्ष्मअर्थशास्त्र और व्यापकअर्थशास्त्र

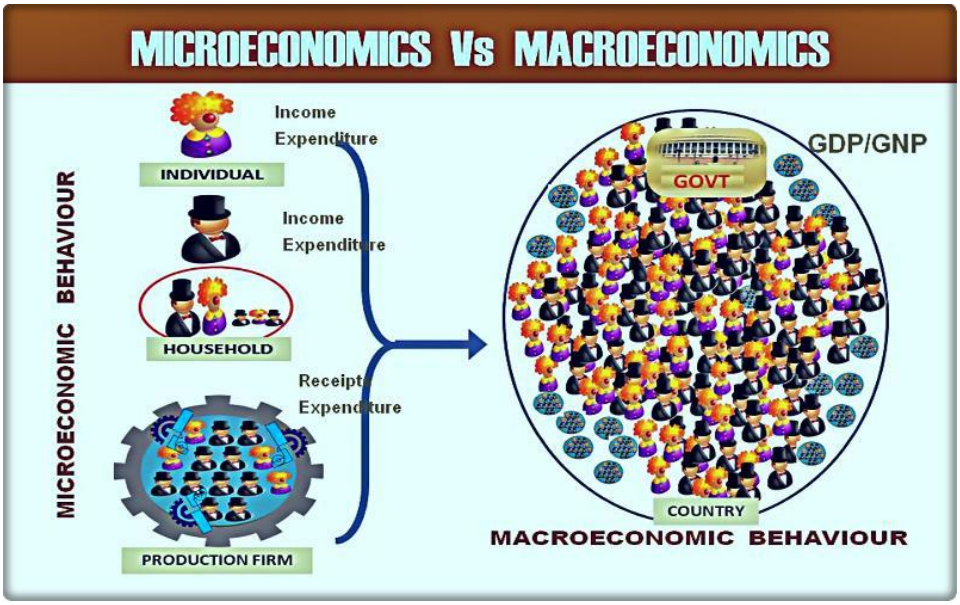

→ अर्थशास्त्र को दो महत्वपूर्ण वर्गों में विभाजित किया गया है: मैक्रोइकॉनॉमिक्स और माइक्रोइकॉनॉमिक्स।

→ मैक्रोइकॉनॉमिक्स समग्र अर्थव्यवस्था के व्यवहार से संबंधित है और माइक्रोइकॉनॉमिक्स व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर केंद्रित है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र

→ सूक्ष्मअर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की लागत में उतार-चढ़ाव के संबंध में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यवसायों द्वारा चुने गए विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र कई पहलुओं को शामिल करता है, जैसे -

- विभिन्न बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति और मांग।
- संसाधनों के आवंटन और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के संबंध में लोगों और व्यवसायों द्वारा लिए गए निर्णय।
- उपभोक्ता व्यवहार, एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में।
- सेवा और श्रम की मांग, जिसमें व्यक्तिगत श्रम बाजार, मांग और कर्मचारी के वेतन जैसे निर्धारक शामिल हैं।
- अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
- यह तय नहीं करता कि बाज़ार में क्या बदलाव हो रहे हैं, बल्कि यह बताता है कि बाज़ार में बदलाव क्यों हो रहे हैं।

उदाहरण: व्यक्तिगत मांग, किसी उत्पाद की कीमत, व्यक्तिगत आय आदि।

समष्टि अर्थशास्त्र

- मैक्रोइकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो इस बात से संबंधित है कि एक अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर कैसे कार्य करती है। यह सूक्ष्मअर्थशास्त्र से भिन्न है, जो इस बात से संबंधित है कि उपभोक्ता और फर्म जैसे व्यक्तिगत आर्थिक खिलाड़ी कैसे निर्णय लेते हैं।

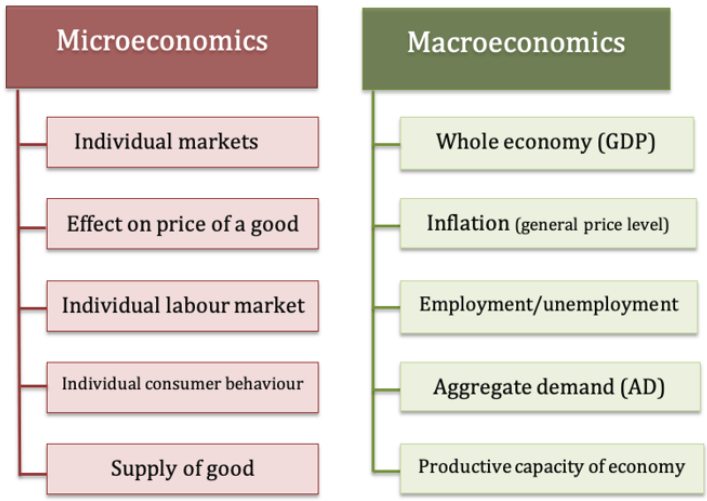

- यह व्यक्तिगत एजेंटों या विशिष्ट बाजारों के बजाय समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के मुद्दों से संबंधित है।
- मैक्रोइकॉनॉमिक्स का संबंध आर्थिक विकास, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सरकार की राजकोषीय नीतियों, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी समग्र घटनाओं की समझ से है।

सूक्ष्मअर्थशास्त्र और व्यापकअर्थशास्त्र के बीच अंतर

व्यष्टि अर्थशास्त्र	**वृहद अर्थशास्त्र**
सूक्ष्मअर्थशास्त्र मुख्य रूप से व्यक्तिगत आय, उत्पादन, वस्तुओं की कीमत आदि से संबंधित है।	मैक्रोइकॉनॉमिक्स राष्ट्रीय उत्पादन, आय, साथ ही सामान्य मूल्य स्तर जैसे समुच्चय का अध्ययन है।
यह निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तिगत, घरेलू और फर्म के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है।	यह कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन के अध्ययन से संबंधित है। मैक्रोइकॉनॉमिक्स में अध्ययन किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और विकास दर आदि शामिल हैं।
सूक्ष्मअर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के विशेष बाजार खंड का अध्ययन करता है	मैक्रोइकॉनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें कई बाज़ार खंड शामिल होते हैं
सूक्ष्मअर्थशास्त्र संसाधनों के आवंटन, मांग, आपूर्ति, कारक मूल्य निर्धारण, उत्पाद मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उत्पादन, उपभोग आदि जैसे मुद्दों पर काबू पाने पर केंद्रित है।	समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, वितरण, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, धन जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित है
सूक्ष्मअर्थशास्त्र किसी विशेष वस्तु की मांग और आपूर्ति जैसे कारकों का हिसाब रखता है।	मैक्रोइकॉनॉमिक्स किसी देश की अर्थव्यवस्था की कुल मांग और आपूर्ति का हिसाब लगाता है।
यह अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादन के कारकों (श्रम, भूमि, उद्यमी, पूंजी और अधिक) की कीमतों के साथ-साथ किसी उत्पाद की कीमतों को विनियमित करने में उपयोगी है।	यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों जैसे अपस्फीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी को हल करता है।

1929 की महामंदी

- उत्तरी अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में महामंदी आई। यह 1929 से 1939 की अवधि के दौरान हुआ। इस अवधि के दौरान, उत्पाद की कम मांग थी। कम मांग के कारण उत्पादन और रोजगार का स्तर कम था। वहां बेरोजगारी दर बहुत ऊंची थी. शेयर बाज़ार धराशायी हो गया. बहुत से लोग दिवालिया हो गये

सकारात्म असर

- इसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को जन्म दिया। इस संबंध में मुख्य योगदान जॉन मेनार्ड कीन्स (ब्रिटिश अर्थशास्त्री) का था। इसी अवधि के दौरान उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स पर 'द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी' नामक पुस्तक प्रकाशित की।

CLASS 12

CHAPTER 2

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा:

- ✓ एक राष्ट्र का धन
- ✓ उत्पादन का प्रवाह
- ✓ मध्यवर्ती और अंतिम सामान
- ✓ स्टॉक एवं प्रवाह
- ✓ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी
- ✓ बाजार मूल्य और कारक लागत
- ✓ सामान्य निवासी और गैर-निवासी
- ✓ विदेश से शुद्ध कारक आय (एनएफआईए)
- ✓ राष्ट्रीय आय
- ✓ घरेलू क्षेत्र

राष्ट्र की आर्थिक संपदा किससे उत्पन्न होती है?

- मान लीजिए कि दो देश A और B हैं
- A के पास अधिक प्राकृतिक संसाधन और उपजाऊ भूमि है
- B एक रेगिस्तान है। लेकिन B के पास अधिक उद्योग और कारखाने हैं
- B, A से कच्चा माल खरीदता है और उसका निर्माण करता है

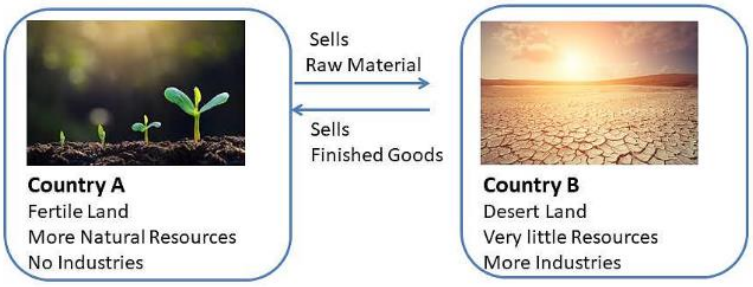

Which Country will be More Rich?

Country B
Possessing of Natural Resources doesn't make a country rich
It needs to be transformed by a production process

कौन सा देश होगा ज्यादा अमीर-

- B अधिक अमीर देश होगा
- ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़ा होने से कोई देश अमीर नहीं बन जाता
- संसाधनों को उत्पादन प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित करना होगा

राष्ट्र की आर्थिक संपदा किससे उत्पन्न होती है?

- किसी देश की आर्थिक संपत्ति संसाधनों के कब्जे पर निर्भर नहीं करती है।
- यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है।
- इस उत्पादन से आय और धन की प्राप्ति होती है।

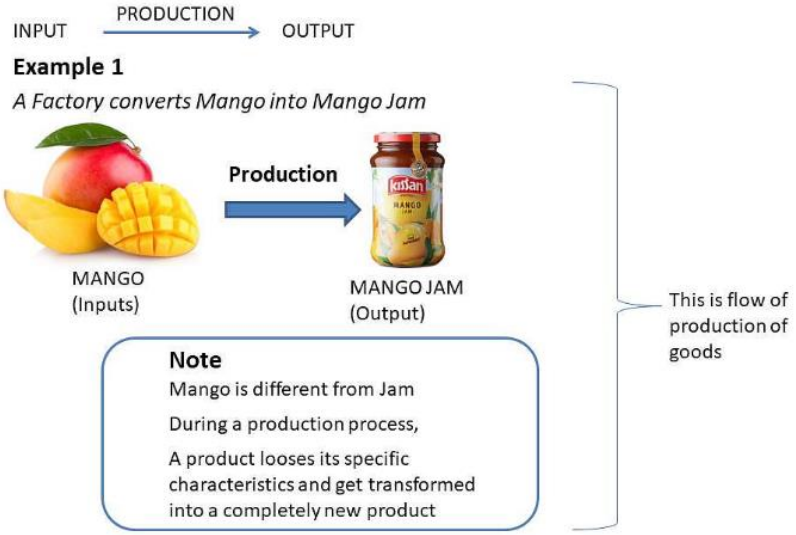

उत्पादन का प्रवाह क्या है?

- इसका अर्थ है विभिन्न इनपुट का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना।
- उत्पादन वस्तुओं या सेवाओं का हो सकता है।
- एक उत्पादन प्रक्रिया का आउटपुट अन्य उत्पादन प्रक्रिया का इनपुट बन सकता है

उदाहरण

- मान लीजिए कि एक किसान कच्चा कपास पैदा करता है
- वह इसे कताई मिल को बेचता है
- स्पिनिंग मिल सूत का उत्पादन करती है जिसे वह कपड़ा मिल को बेचती है
- कपड़ा मिल कपड़े का उत्पादन करती है जिसे वह दर्जी को बेचती है
- यह दर्जी इस कपड़े से एक शर्ट बनाता है और इसे उपभोक्ता को बेचता है

टिप्पणी

- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, एक उत्पाद अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो देता है और एक पूरी तरह से नए उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है

उदाहरण

- सूत कपास से बिल्कुल अलग है; कपड़ा सूत से अलग है और शर्ट कपड़े से बिल्कुल अलग है

किसान------>	कताई मिल------>	कपड़ा मिल------>	दर्जी------>	उपभोक्ता
कपास का उत्पादन	सूत निर्माण	वस्त्र निर्माण	कमीज बनाना	

Output of One production process may become Input of Other Production Process

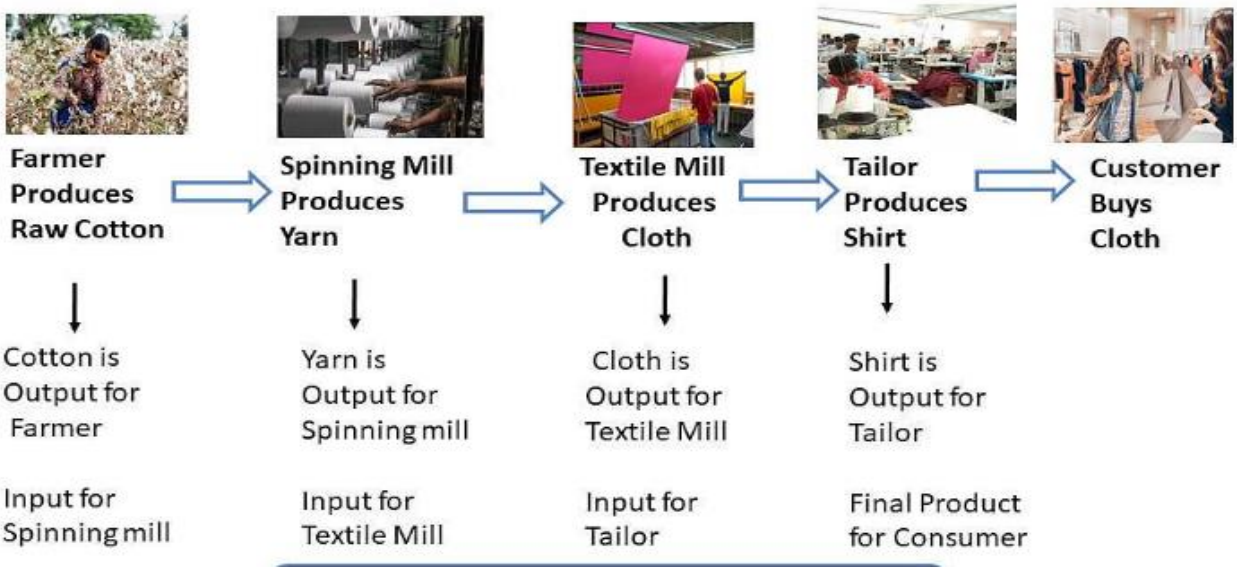

मध्यवर्ती और अंतिम माल

Example

Suppose a Farmer grows Sugarcane
A sugar factory uses this sugarcane to make Sugar
A sweetshop uses this sugar to make Sweets
which is purchased by consumer

Sugarcane and Sugar are Intermediate Goods as they are used for further production

Jalebi is Final Good as it is used for consumption

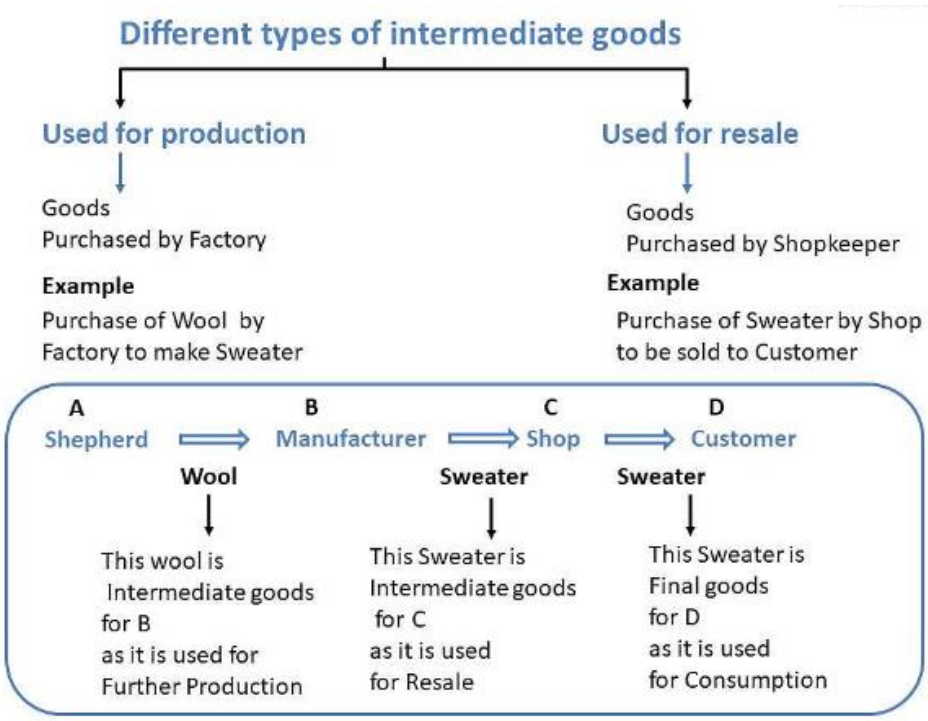

Different types of intermediate goods

Used for production

Goods
Purchased by Factory

Example

Purchase of Wool by Factory to make Sweater

Used for resale

Goods
Purchased by Shopkeeper

Example

Purchase of Sweater by Shop to be sold to Customer

A Shepherd ⟹ B Manufacturer ⟹ C Shop ⟹ D Customer

Wool ↓ This wool is Intermediate goods for B as it is used for Further Production

Sweater ↓ This Sweater is Intermediate goods for C as it is used for Resale

Sweater ↓ This Sweater is Final goods for D as it is used for Consumption

Same good may be Intermediate for One & Final for Other

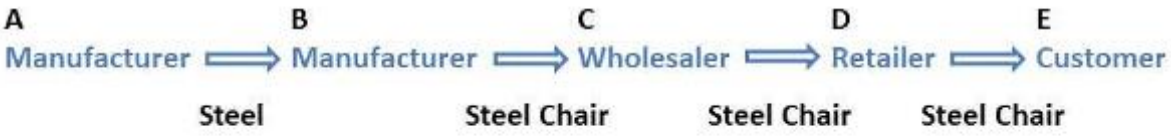

Example 2

Suppose a company A manufactures steel
It is used by company B to make Steel Chair
This Steel Chair is sold to Wholesaler C
who sells it to Retailer D
D sells it to Customer E

A Manufacturer ⟹ B Manufacturer ⟹ C Wholesaler ⟹ D Retailer ⟹ E Customer

Steel (A ⟹ B), **Steel Chair** (B ⟹ C), **Steel Chair** (C ⟹ D), **Steel Chair** (D ⟹ E)

In this case

Steel is a Intermediate goods as it is used for Further production
Steel chair is also intermediate goods for C and D as it is used for Resale
Steel Chair is Final goods for E as it is used for Consumption

मूल्य संवर्धन

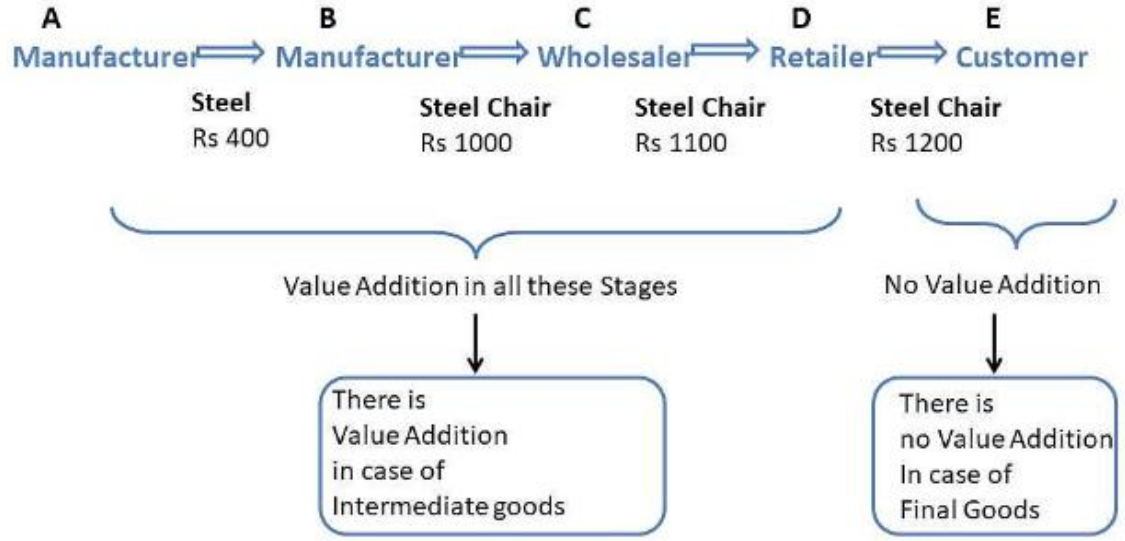
A
Manufacturer
Steel
Rs 400
B
Manufacturer
Steel Chair
Rs 1000
C
Wholesaler
Steel Chair
Rs 1100
D
Retailer
Steel Chair
Rs 1200
E
Customer
Value Addition in all these Stages
No Value Addition
There is Value Addition in case of Intermediate goods
There is no Value Addition In case of Final Goods

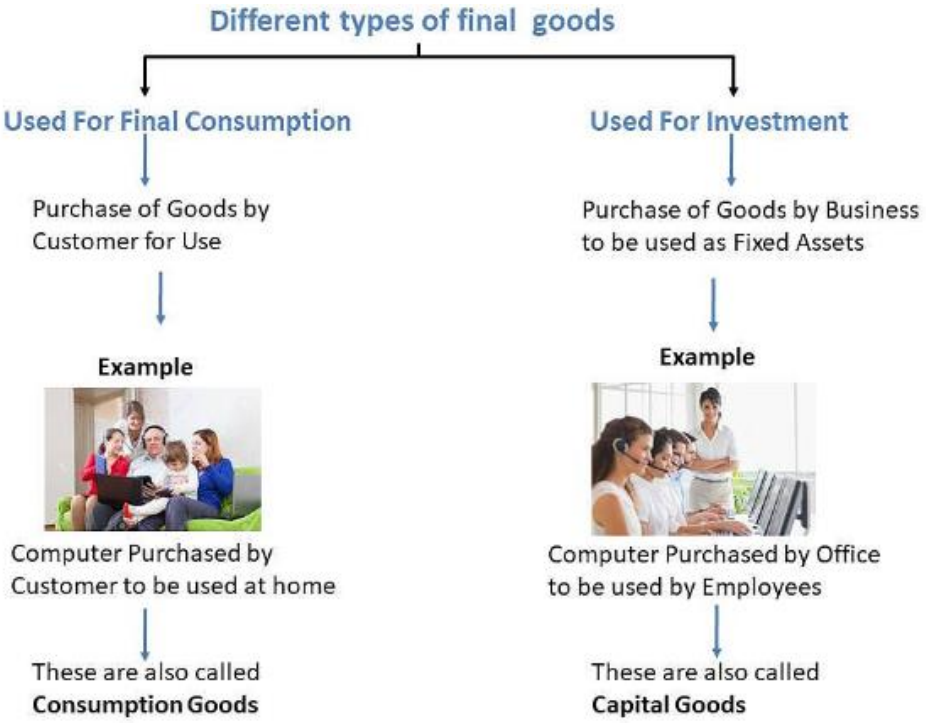
Different types of final goods
Used For Final Consumption
Used For Investment
Purchase of Goods by Customer for Use
Purchase of Goods by Business to be used as Fixed Assets
Example
Example
Computer Purchased by Customer to be used at home
Computer Purchased by Office to be used by Employees
These are also called Consumption Goods
These are also called Capital Goods

What is Production Boundary?

It is the imaginary line around the production process

It includes all the producers and activities which causes value addition

Example 1

In above case,

Production Boundary covers Farmers, Spinning mill, Textile Mill and Tailor

It is because all these are involved in production process

Consumer is not part of production process as they do not create any value addition

Why concept of Production Boundary is Important?

All goods purchased within the production boundary are Intermediate goods

All goods falling outside the production boundary are Final Goods

Example

Note

Raw Cotton, Yarn and Cloth are Intermediate goods as they fall within the production boundary

Shirt is a final goods as it lies outside the production boundary

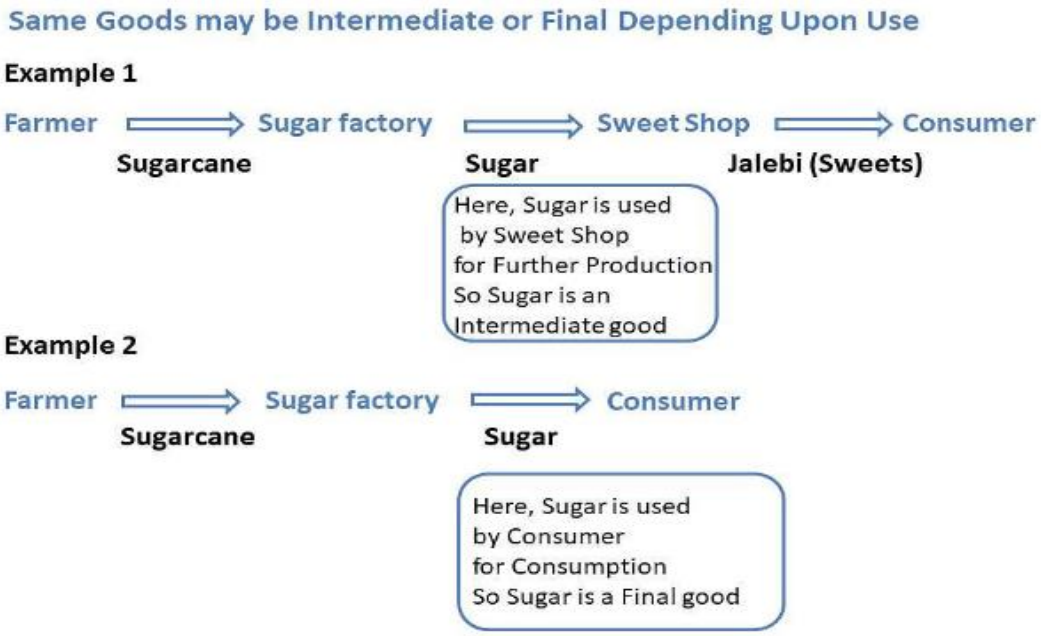

अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह अवधारणा

- स्टॉक एक वैरिएबल है जिसे एक विशेष समय पर मापा जाता है
- प्रवाह एक चर है जिसे बिंदु की अवधि में मापा जाता है

उदाहरण 1

- मान लीजिए कि 1 जनवरी को मेरे बैंक खाते में 50000 रुपये हैं
- मैंने जनवरी महीने में 10,000 रुपये खर्च किये
- अब 31 जनवरी को मेरे पास 40,000 रुपये बचे हैं

टिप्पणी:

- इस मामले में,
- बैंक बैलेंस स्टॉक है
- (इसे समय के विशेष बिंदु पर मापा जाता है (1 जनवरी या 31 जनवरी को)
- खर्च की गई राशि प्रवाह है
- इसे समय की अवधि (जनवरी के दौरान) में मापा जाता है

उदाहरण 2

- मान लीजिए किसी नल से पानी टंकी में बह रहा है
- सुबह 9 बजे तक टंकी में 20 लीटर पानी है
- सुबह 9.01 बजे तक टैंक में 30 लीटर है

- इसका मतलब है कि नल से 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है

स्टॉक और फ्लो क्या है?

- प्रति मिनट टैंक में प्रवाहित होने वाली पानी की मात्रा प्रवाह का उदाहरण है
- किसी विशेष समय में टैंक में पानी की मात्रा स्टॉक का एक उदाहरण है।
- नल से प्रति मिनट बहने वाली पानी की मात्रा प्रवाह का उदाहरण है

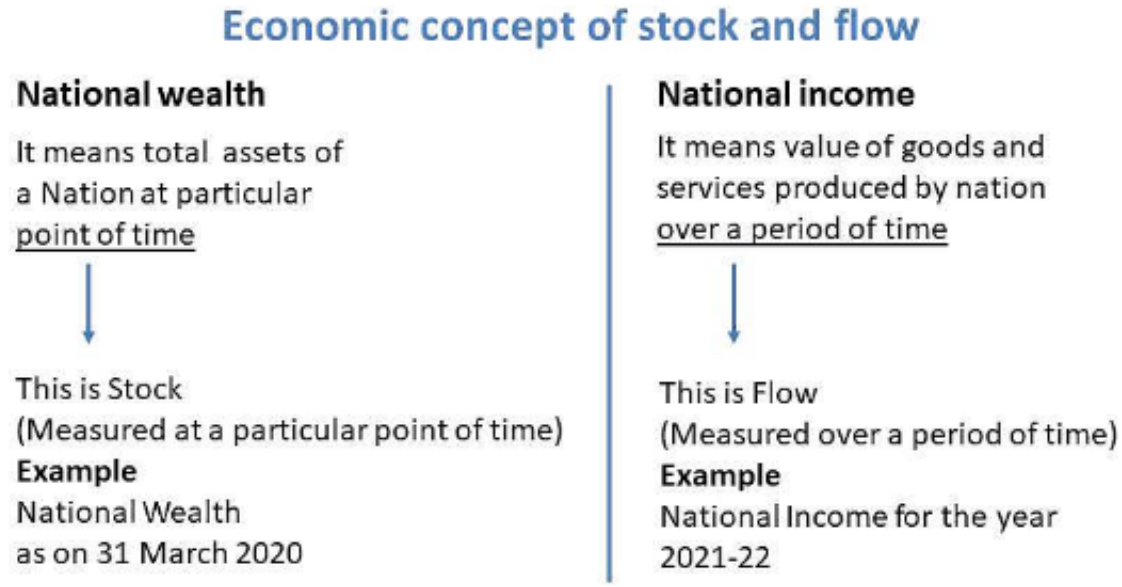

टाइम डायमेंशन-स्टॉक या फ्लो किसका है?

- समय आयाम का अर्थ है
- किसी चीज़ को एक समय से दूसरे समय तक मापना
- स्टॉक को एक विशेष समय पर मापा जाता है
- (समय का केवल एक ही बिंदु है)
- प्रवाह को समय की अवधि में मापा जाता है (एक बिंदु से दूसरे तक)
- (समय के दो बिंदु हैं - प्रारंभ और समाप्ति)
- इसलिए प्रवाह का समय आयाम है (स्टॉक नहीं)

कौन सी स्थिर है और कौन सी गतिशील अवधारणा है?

- स्थैतिक का अर्थ है- कोई चीज़ जो स्थिर हो।
- गतिशील का अर्थ है- कोई ऐसी वस्तु जो निरंतर गतिमान हो।

आइए, टैंक में बहते पानी का एक उदाहरण लें

- प्रति मिनट टैंक में बहने वाले पानी की मात्रा प्रवाह का उदाहरण है
- टैंक में पानी की मात्रा स्टॉक का एक उदाहरण है
- किसी विशेष समय पर टैंक में पानी की मात्रा स्थिर (निश्चित) होती है

- इसलिए, हम कह सकते हैं कि स्टॉक स्थिर अवधारणा है
- टैंक में बहने वाले पानी की मात्रा गतिशील (गतिशील) होती है।
- इसलिए, हम कह सकते हैं कि प्रवाह गतिशील अवधारणा है।

स्टॉक और फ्लो के बीच अंतर:

भंडार	प्रवाह
यह एक चर है जिसे किसी विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है।	यह एक चर है जिसे समय की अवधि में मापा जाता है।
इसमें समय का आयाम नहीं है	इसमें समय का आयाम है
यह स्टेटिक कॉन्सेप्ट है	यह गतिशील अवधारणा है
उदाहरण:	उदाहरण:
31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय संपत्ति	2020-21 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय
1 अप्रैल 2020 तक कोविड मामले	अप्रैल 2020 के दौरान कोविड मामले बढ़े
31 मार्च 2021 तक प्रचलन में कुल धन	2020-21 के दौरान नया पैसा छपा

आरेखों के माध्यम से जीडीपी और संबंधित शर्तों को समझना

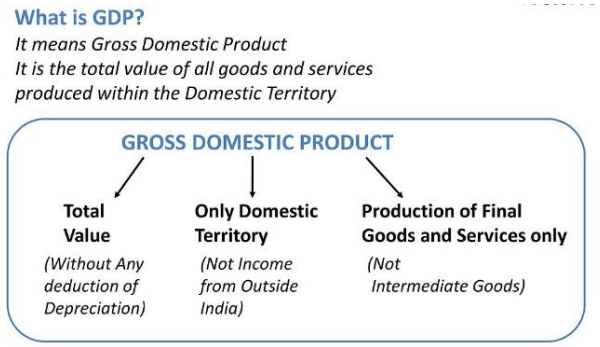

घरेलू क्षेत्र की अवधारणा

*GDP includes Total Production within **Domestic Territory***
So it does not include income earned by Indian citizen working abroad
It may include income of Foreigners working in India

Example 1

Suppose in a country ,there are only 3 persons A,B and C
A and B are working in the country while C is working Outside the Country
Aggregate Value of Final Goods Produced of
A,B and C is 1000,2000,2500 respectively
What is GDP of Country?

Answer

GDP of Country =1000+2000=3000

Note

(We will not take income earned by C as he earns this income working outside the country)

Example 2

Suppose in a country ,there are only 3 persons A,B and C
A and B are working in the country while C is working Outside the Country
Also D is a foreign Citizen working in the country
Aggregate Value of Final Goods Produced of
A,B, C and D is 1000,2000, 2500,4000 respectively
What is GDP of Country?

Answer

GDP of Country = 1000+2000+4000 = 7000

> ***Note***
> *(We will take into account income earned by D also as he is working in the country also)*

टिप्पणी

जीडीपी 2 प्रकार की होती है

- बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद
- कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

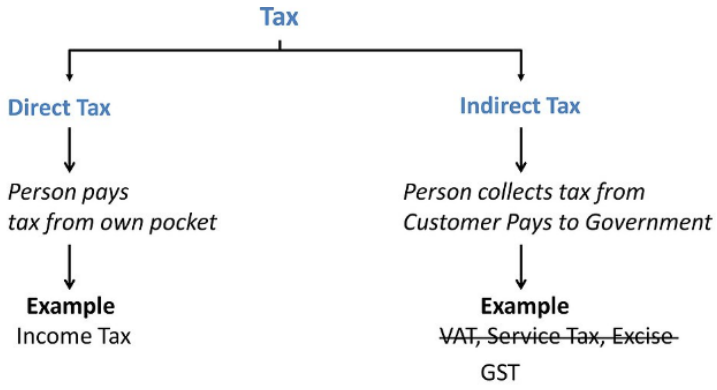

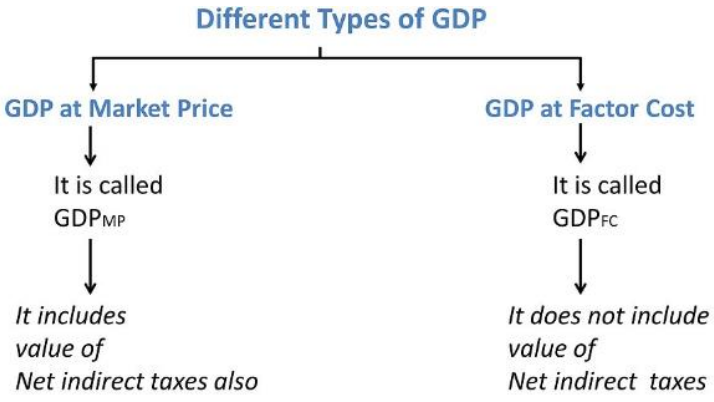

Example of Indirect Tax-GST

Suppose P Sells goods to Q for Rs 2000

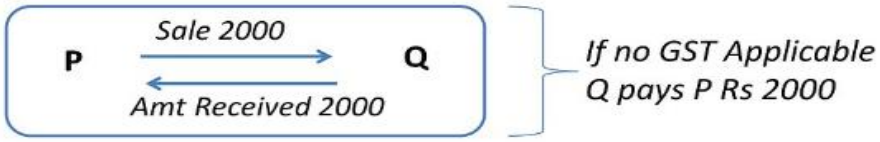

Suppose P Sells goods to Q for Rs 2000 +5% GST

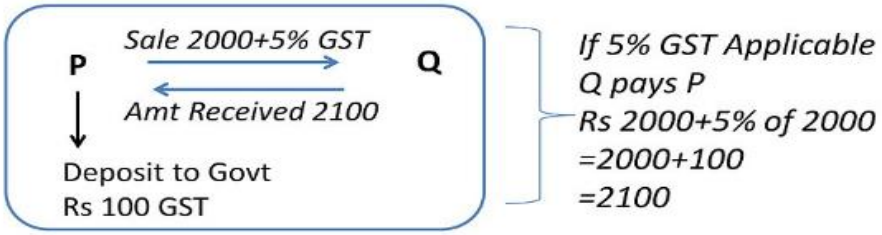

If GST Applicable, Seller charges GST on Invoice from Buyer
He collects GST from buyer and deposits to Government

Different Types of GDP

GDP at Market Price

GDP_{MP}

It includes value of net indirect taxes also

GDP_{MP}
2100

GDP at Factor Cost

GDP_{FC}

It does not include value of net indirect taxes

GDP_{FC}
GDP_{MP}-Indirect Taxes
=2100-100
=2000

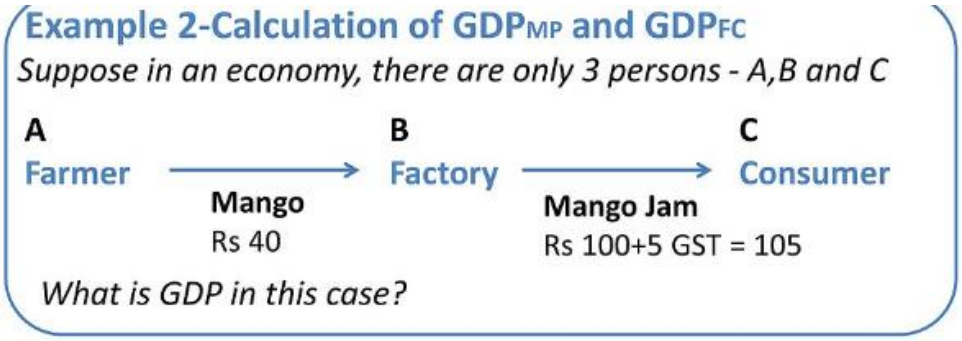

बाज़ार मूल्य बनाम कारक लागत

बाजार मूल्य (एमपी)

→ हम परिभाषा लिखते हैं

- 'वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य'

उदाहरण

- जीडीपी एमपी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल बाजार मूल्य।
- जीएनपी एमपी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल बाजार मूल्य।

कारक लागत (एफसी)

हम परिभाषा लिखते हैं

→ 'वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य'

उदाहरण

- जीडीपी एफसी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल धन मूल्य।
- जीएनपी एफसी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल धन मूल्य।

What is Subsidy?

Subsidy is Discount or Economic Assistance provided by Govt
It leads to reduction in price paid by consumer

Example

Price of Cooking Gas	1000
Less Subsidy provided by Govt	300
Net Amount paid by Consumer	700

→ *Less amount paid by consumer due to Subsidy*

Why govt provides Subsidy?

To Make Product cheaper so that poor people can afford it

Example -
Subsidy on Cooking Gas

To promote Use of product

Example
Subsidy on Electric Cars

Difference between GDP_{MP} and GDP_{FC}

GDP at Market Price

GDP_{MP}

It is Gross Market value of all final goods and services produced within Domestic Territory

It includes Net Indirect Taxes

It is not considered for calculating Domestic and National Income

GDP at Factor Cost

GDP_{FC}

It is Gross Money value of all final goods and services produced within Domestic Territory

It does not Include net Indirect Taxes
$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - Net Indirect Taxes
$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - (Net Indirect Taxes-Subsidy)
$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - Net Indirect Taxes+ Subsidy

It is considered for calculating Domestic and National Income

Note
National income and Domestic Income is always calculated at Factor Cost, Not Market Price

विदेश से शुद्ध कारक आय

- उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता हैं
- कारक भुगतान उत्पादन के कारकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है।
- जैसे वेतन, ब्याज, किराया, मुनाफ़ा.
- ये कारक भुगतान प्राप्तकर्ता पक्षों की कारक आय हैं।

Suppose A works in Factory as a labour
Factory pays him wages

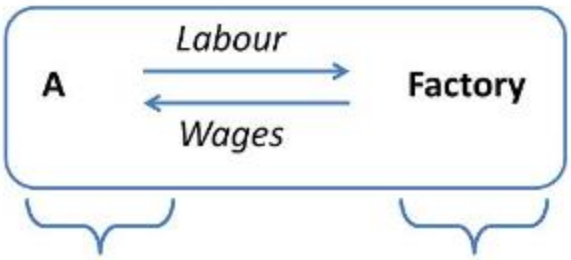

In this Case
A is Factor of Production

Wages earned is
Factor Income of A

In this Case
Factory is using this Factor of Production

Wages paid is
Factor Payment of Factory

साधन आय क्या है?

- यह मालिकों द्वारा उत्पादन के कारकों से प्राप्त आय है

कारक आय का उदाहरण

उत्पादन के विभिन्न कारक	विभिन्न कारक आय (या कारक भुगतान)
श्रम	वेतन
भूमि	किराया
पूंजी	ब्याज/लाभांश
उद्यमशीलता	लाभ

विदेश से प्राप्त साधन आय क्या है?

- यह बाहरी देश से उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा प्राप्त आय है।

उदाहरण

- एक भारतीय कर्मचारी अमेरिका स्थित अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए घर से काम कर रहा है
- इस मामले में, भारतीय कर्मचारी को यूएसए से वेतन (कारक आय) प्राप्त होगा
- तो हम कहते हैं, यह विदेश से प्राप्त कारक आय है

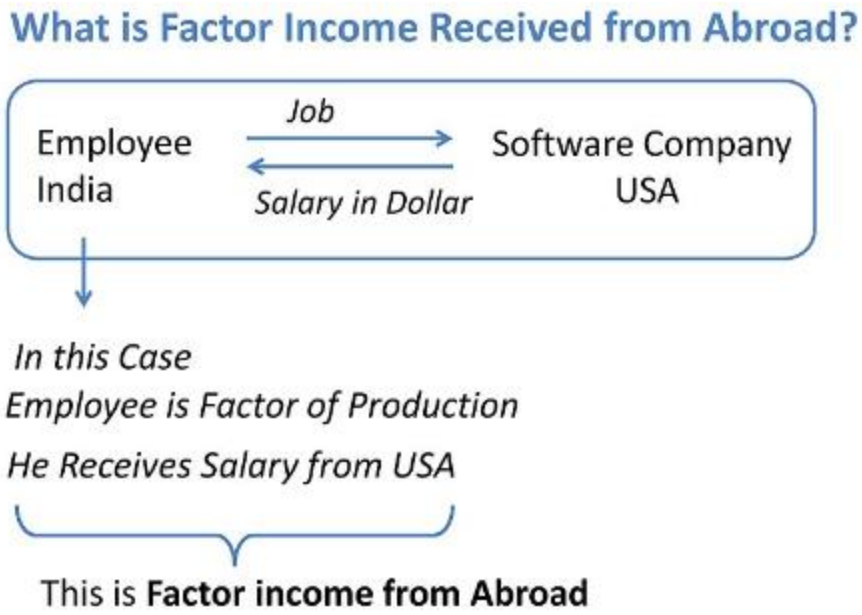

विदेश में भुगतान की गई कारक आय क्या है?

- यह घरेलू क्षेत्र (भारत) से उत्पादन के विदेशी कारकों द्वारा आय है

उदाहरण

- एक अमेरिकी कर्मचारी भारत स्थित अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए घर से काम कर रहा है
- इस मामले में, अमेरिकी कर्मचारी को भारत से वेतन (कारक आय) प्राप्त होगा
- तो हम कहते हैं, यह विदेश में भुगतान की जाने वाली फैक्टर आय है

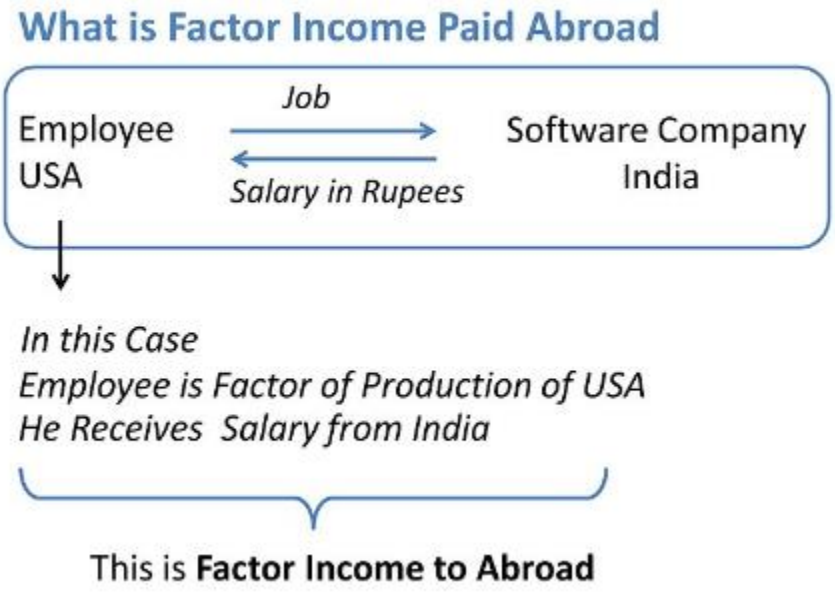

विदेश से शुद्ध कारक आय (एनएफआईए) क्या है?

- यह विदेश से अर्जित कारक आय और विदेश को भुगतान की गई कारक आय के बीच का अंतर है।
- यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है
- इसका उपयोग GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) की गणना के लिए किया जाता है

What is Net Factor Income from Abroad?

	Case 1	*Case 2*
Factor Income Received from Abroad	400	400
Less		
Factor Income Paid to Abroad	300	600
Net Factor Income form Abroad (NFIA)	100	-200
	↓ *NFIA Positive* *Good for Economy*	↓ *NFIA Negative* *Bad for Economy*

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

- यह देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है
- इसलिए, इसमें देश के बाहर के नागरिकों द्वारा अर्जित कारक आय शामिल है।
- साथ ही, यह भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित कारक आय को भी कम करता है
- जीएनपी वह आय या उत्पाद है जो उन आर्थिक एजेंटों को प्राप्त होती है जो देश के निवासी हैं। (यानी अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा अर्जित आय भारत के जीएनपी का हिस्सा नहीं होगी)।
- जीएनपी की गणना करने के लिए, हम विदेशों से भारतीयों की कारक आय को जीडीपी में जोड़ते हैं और भारत की जीडीपी में विदेशियों के योगदान को घटाते हैं।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) = जीडीपी + शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय - घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय
- यानी जीएनपी = जीडीपी + देश के बाहर काम करने वाले नागरिकों की कारक आय - देश में काम करने वाले विदेशी नागरिकों की कारक आय
- जीएनपी = जीडीपी + विदेश से शुद्ध कारक आय (एनएफआईए)।
- कारक आय मूल रूप से उत्पादन के चार कारकों यानी लाभ, किराया, ब्याज और मजदूरी से अर्जित आय है लेकिन इसमें स्थानांतरण आय/भुगतान शामिल नहीं है।
- इसलिए जीएनपी जीडीपी और कारक आय का योग है और इसमें शेष विश्व से स्थानांतरण भुगतान (उदाहरण के लिए प्रेषण) शामिल नहीं है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) को सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है।

Different Types of incomes	***GDP***	***GNP***
Income earned by Indian Citizen in India	*Included (Domestic Territory)*	*Included (Normal Residents)*
Income earned by Foreign nationals in India	*Included (Foreign Territory)*	*Not Included (Foreign Residents)*
Income earned by Indian Nationals Outside India	*Not Included (Domestic Territory)*	*Included (Normal Residents)*

Example of GDP and GNP

Income earned by Indian Citizen in India	1000
Income earned by Foreign nationals in India	600
Income earned by Indian Nationals Outside India	200

What Is GDP And GNP?

GDP

Total value of Goods and Services Produced in Domestic Territory
= 1000 + 600
= 1600

GNP

Total value of Goods and Services Produced by Normal Residents
= 1000 + 200
= 1200

Second Method
GDP = 1600
NFIA = 200 – 600= -400
GNP = GDP + NFIA
= 1600 + (-400)
= 1600 – 400 = 1200

GROSS NATIONAL PRODUCT

Total Value	Income of all Normal residents	Production of Final Goods and Services only
(Without Any deduction of Depreciation)	*(Whether in India or Outside India)*	*(Not Intermediate Goods)*
	(Doesn't have Income of Foreign Citizens working in India)	

GNP is Total value of Goods and Services Produced by *Normal Residents*

Suppose in a country ,there are only 3 persons A,B and C
A and B are working in the country while C is Outside Country
Also D is a foreign Citizen working in the country
Aggregate Value of Final Goods Produced of A,B, C and D is 1000, 2000, 2500, 4000 respectively
What is GDP and GNP of Country?

GDP
Total value of Goods and Services Produced in Domestic Territory
= A +B +D
= 1000+2000+4000
= 7000

GNP
Total value of Goods and Services Produced by Normal Residents
= A +B +C
= 1000+2000+2500
= 5500

Second Method
NFIA = Income of C - Income of D
= 2500-4000
= -1500
GNP = GDP + NFIA
= 7000 – 1500
= 5500

घरेलू आय

- यह मूल्यह्रास के बाद घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य है
- इसे कारक मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी एफसी) भी कहा जाता है।

FORMULA

एनडीपी एफसी = जीडीपी एफसी – मूल्यह्रास

What is Domestic Income?
It is net money value of Goods and Services Produced in domestic territory after Depreciation
It is also called Net Domestic Product at Factor Price (NDP_{FC})
Formula
$NDP_{FC} = GDP_{FC}$ - Depreciation

GDP_{FC}
It is gross money value of Goods and Services Produced in domestic territory
Formula
$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - Net Indirect Taxes
It is not Domestic Income

NDP_{FC}
It is net money value of Goods and Services Produced in domestic territory
Formula
$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ - Net Indirect Taxes
$NDP_{FC} = GDP_{FC}$ - Depreciation
It is called Domestic Income

उदाहरण

- मान लीजिए घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य 100 है
- अचल संपत्तियों के रखरखाव पर मूल्यह्रास 20 है

घरेलू आय क्या है?

जीडीपी एफसी	100
कम: विभाग	20
एनडीपी एफसी (घरेलू आय)	80

यह मूल्यह्रास क्यों कम किया गया है?

⟶ इसे पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट के हिसाब से घटा दिया जाता है

⟶ किसी देश द्वारा अर्जित आय का एक हिस्सा मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं (अचल संपत्ति) को बनाए रखने में खर्च किया जाता है

⟶ इसलिए हम सही शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसे कम करते हैं

उपरोक्त मामले में

- देश को 100 रुपये की आय हुई लेकिन इसमें से 20 रुपये मूल्यह्रास में खर्च हो गये
- इसलिए, देश ने वास्तव में 80 रुपये की घरेलू आय अर्जित की

सामान्य निवासी की अवधारणा

- किसी देश के सामान्य निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति या संस्था से है जो सामान्यतः उस देश में रहता है और जिसके आर्थिक हित का केंद्र भी उसी देश में होता है।
- सामान्य निवासियों में व्यक्ति और संस्थाएं दोनों शामिल हैं।

'आर्थिक हित केंद्र' का तात्पर्य दो बातों से है:

1. निवासी घरेलू क्षेत्र में रहता है या स्थित है; और
2. निवासी उस स्थान से कमाई, खर्च और संचय की बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ करता है।

निम्नलिखित को सामान्य निवासियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है:

1. विदेशी पर्यटक और आगंतुक जो मनोरंजन, छुट्टियों, चिकित्सा उपचार, अध्ययन, खेल, सम्मेलन आदि के लिए किसी देश में आते हैं।
2. दिए गए देश में स्थित किसी विदेशी देश के दूतावासों, अधिकारियों, राजनयिकों और सशस्त्र बलों के सदस्यों के विदेशी कर्मचारी;
3. अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आदि को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है जहां वे काम करते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य निवासियों के रूप में माना जाता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को उन देशों का निवासी माना जाता है जिनसे वे संबंधित हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के। उदाहरण के लिए, भारत में स्थित यूएनओ कार्यालय में काम करने वाले एक अमेरिकी को अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाएगा।

हालाँकि, यदि कर्मचारी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, तो वे उस देश के सामान्य निवासी बन जाते हैं जहाँ ऐसे संस्थान स्थित हैं। इसका मतलब है, दिए गए उदाहरण में, यदि कोई अमेरिकी एक वर्ष से अधिक समय से भारत में यूएनओ कार्यालय में काम कर रहा है, तो उसे भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा।

1. विदेशी जहाजों के चालक दल के सदस्य, वाणिज्यिक यात्री और मौसमी श्रमिक, बशर्ते उनका प्रवास एक वर्ष से कम हो।
2. सीमा कार्यकर्ता जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं और दूसरे देश में काम करने के लिए नियमित आधार पर सीमा पार करते हैं। उनके साथ उस देश के सामान्य निवासियों के रूप में व्यवहार किया जाता है जहां वे रहते हैं, न कि जहां वे काम करते हैं।

जीएनपी से तात्पर्य किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी आर्थिक उत्पादन से है, चाहे वे राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थित हों या विदेश में।

राष्ट्रीय आय क्या है?

- यह मूल्यह्रास के बाद किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सकल धन मूल्य है
- इसे कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपीएफसी) भी कहा जाता है।

FORMULA

एनएनपी एफसी = जीएनपी एफसी – मूल्यह्रास

GDP_{FC}	NDP_{FC}
It is gross money value of Goods and Services Produced by Normal Residents of a country	*It is net money value of Goods and Services Produced by Normal Residents of a country*
Formula	**Formula**
$GNP_{FC} = GNP_{MP}$ - Net Indirect Taxes	$GNP_{FC} = GNP_{MP}$ - Net Indirect Taxes $NNP_{FC} = GNP_{FC}$ - Depreciation
It is not National Income	It is called National Income

उदाहरण

- मान लीजिए कि किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य 140 है
- अचल संपत्तियों के रखरखाव पर मूल्यह्रास 20 है

राष्ट्रीय आय क्या है?

जीएनपी एफसी	140
मूल्यह्रास	20
एनएनपी एफसी (राष्ट्रीय आय)	120

यह मूल्यह्रास क्यों कम किया गया है?

⟶ इसे पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट के हिसाब से घटा दिया जाता है

⟶ किसी देश द्वारा अर्जित आय का एक हिस्सा मौजूदा पूंजीगत वस्तुओं (अचल संपत्ति) को बनाए रखने में खर्च किया जाता है

⟶ इसलिए, हम सही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसे कम करते हैं

उपरोक्त मामले में

⟶ देश को 140 रुपये की आय हुई लेकिन इसमें से 20 रुपये मूल्यह्रास की ओर खर्च किए गए

⟶ इसलिए, देश ने वास्तव में 120 रुपये की घरेलू आय अर्जित की

Domestic Income

NDP_{FC}

It is net money value of Goods and Services Produced in Domestic Territory after Depreciation

Formula

$NDP_{FC} = GDP_{FC}$ - Depreciation

It includes

- Income earned by Indian Citizen in India
- Income earned by Foreign nationals in India

It does not include

- Income earned by Indian Nationals Outside India

National Income

NNP_{FC}

It is net money value of Goods and Services Produced by Normal Residents of a country after Depreciation

Formula

$NNP_{FC} = GNP_{FC}$ - Depreciation

It includes

- Income earned by Indian Citizen in India
- Income earned by Indian Nationals Outside India

It does not include

- Income earned by Foreign nationals in India

How to get National Income from Domestic Income?

National Income = Domestic Income+ Net Factor income from Abroad

$NNP_{FC} = NDP_{FC} + NFIA$

Example

Domestic Income	5000
Income earned by Foreign nationals in India	100
Income earned by Indian Nationals Outside India	200

In this case

NFIA = 200-100
= 100

$NNP_{FC} = NDP_{FC} + NFIA$
= 5000 + 100
= 5100

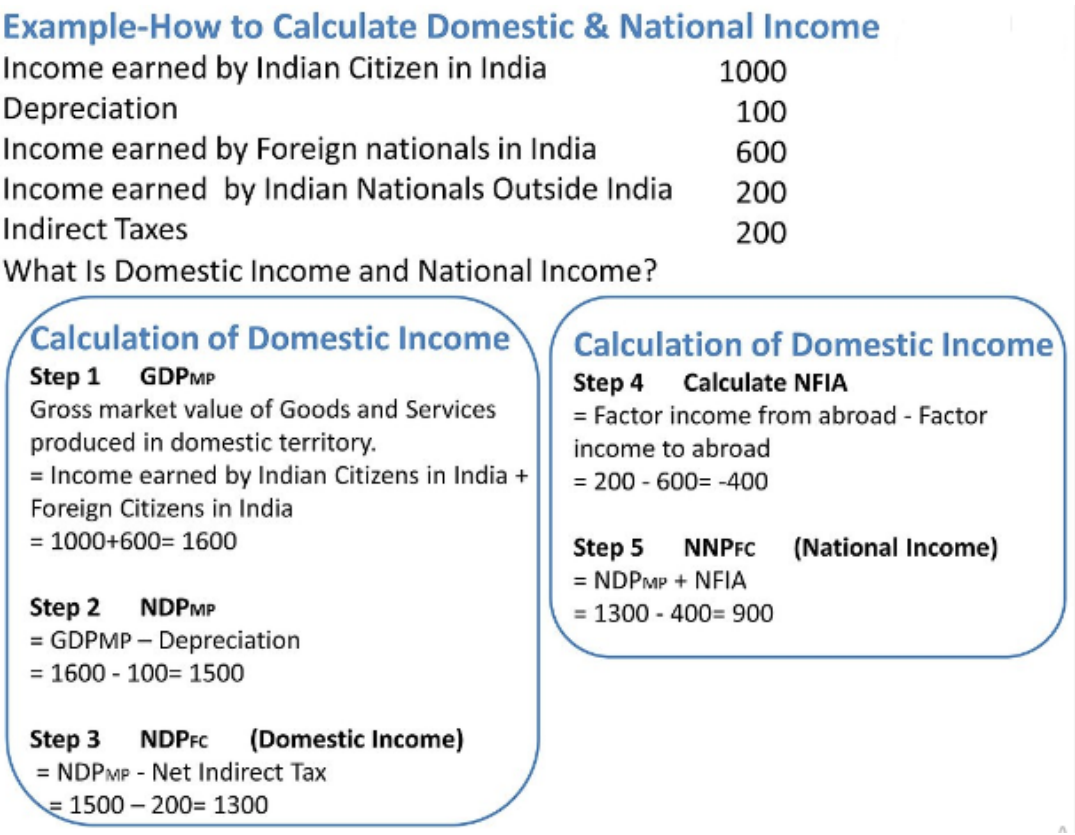

घरेलू और राष्ट्रीय की अवधारणा

⟶ सभी घरेलू अवधारणाओं के लिए.

हम उल्लेख करते हैं

⟶ घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ
(यह भारत में भारतीय नागरिकों या भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित किया जा सकता है, इसमें विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की आय शामिल नहीं है)

उदाहरण

⟶ एनडीपी एफसी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य।

⟶ जीडीपी एफसी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल धन मूल्य।

⟶ जीडीपी एमपी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल बाजार मूल्य।

⟶ एनडीपी एमपी = किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध बाजार मूल्य।

सभी राष्ट्रीय अवधारणाओं के लिए.

हम उल्लेख करते हैं

⟶ किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ। (यह भारत में भारतीय नागरिकों द्वारा या विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित किया जा सकता है (इसमें भारत में विदेशी नागरिकों की आय शामिल नहीं है)

उदाहरण

- जीएनपी एमपी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल बाजार मूल्य।
- एनएनपी एफसी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य।

- जीएनपी एफसी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल धन मूल्य।
- एनएनपी एमपी = किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध बाजार मूल्य।

For all Domestic Concepts.

We mention
Goods and Services Produced in Domestic Territory

(This may be earned by Indian Citizens In India or Foreign Citizens in India)

(It does not include Income of Indian Citizens working abroad)

Examples
Domestic Income
= GDP_{FC}
= Gross Money value of all final goods and services produced within Domestic territory of a Country.

For all National Concepts.

We mention
Goods and Services Produced by Normal Residents of a Country

(This may be earned by Indian Citizens In India or Indian Citizens work in abroad

(It does not include Income of Foreign Citizens in India)

Examples
National Income
= NNP_{FC}
= Net Money value of all final goods and services produced by Normal Residents of a country.

घरेलू से राष्ट्रीय कैसे बनें?

- हम विदेश से शुद्ध कारक आय (NFIA) जोड़ते हैं
- घरेलू + एनएफआईए =राष्ट्रीय
- घरेलू + (विदेश से अर्जित कारक आय - विदेश में भुगतान की गई कारक आय) = राष्ट्रीय

We add Net Factor Income from Abroad (NFIA)
Domestic + NFIA =National

Here NFIA =
Factor Income earned from Abroad
less *Factor income Paid Abroad*

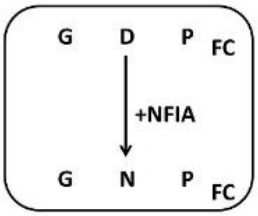

Example 1
GDP_{FC} = 100
Factor income from abroad = 35
Factor income to abroad = 20
Calculate GNP_{FC}

NFIA = 35 – 20 =15

NNP_{FC}
=GDP_{FC} + NFIA
=100 + 15
=115

Example 2
GDP_{FC} = 100
Factor income from abroad = 35
Factor income to abroad = 40
Calculate GNP_{FC}

NFIA = 35 – 40 =-5

NNP_{FC}
=GDP_{FC} + NFIA
=100 +-5
=85

घरेलू क्षेत्र की अवधारणा

⟶ यह एक सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर व्यक्ति, सामान और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है।

इसमें शामिल है:

1. देश की राजनीतिक सीमाएँ।

2. 2 या अधिक देशों के बीच सामान्य निवासियों द्वारा स्वामित्व और संचालित जहाज और विमान। जैसे- अमेरिका और इटली के बीच एयर इंडिया द्वारा संचालित विमान भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होगा।
3. अंतरराष्ट्रीय जल में किसी देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिग और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जहां उनके पास विशेष अधिकार हैं। उदाहरण के लिए- हिंद महासागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय मछुआरों द्वारा संचालित मछली पकड़ने वाली नावें भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होंगी।
4. विदेश में स्थित किसी देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान।

इसमें शामिल नहीं है:

1. किसी विदेशी देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान। जैसे- भारत में चीनी दूतावास भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा।
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, WHO आदि भौगोलिक सीमाओं में स्थित हैं।

घरेलू क्षेत्र की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है?

- जीडीपी की गणना करना महत्वपूर्ण है
- हम पहले ही इसका अध्ययन कर चुके हैं
- जीडीपी में घरेलू क्षेत्र के भीतर कुल उत्पादन शामिल है
- इसलिए, इसमें विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिक द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है

विविध विवरण

सामान्य निवासी

- एक सामान्य निवासी, चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था, वह होता है जिसके आर्थिक हित का केंद्र उस देश के आर्थिक क्षेत्र में होता है जिसमें वह रहता है।
- आर्थिक हित का केंद्र दो बातों में निहित है:
  - निवासी एक वर्ष से अधिक समय से आर्थिक क्षेत्र में रहता है या स्थित है
  - निवासी उस स्थान से कमाई, खर्च और संचय की बुनियादी आर्थिक गतिविधियाँ करता है।
- सामान्य निवासी (निवासी) और नागरिक (या राष्ट्रीय) शब्दों में अंतर है। कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक इसलिए बन जाता है क्योंकि वह उस देश में पैदा हुआ है या किसी अन्य कानूनी मानदंड के आधार पर।
- किसी व्यक्ति को आर्थिक मानदंड के आधार पर किसी देश का निवासी माना जाता है।
- यह आवश्यक नहीं है कि कोई निवासी उस देश का नागरिक भी हो। यहां तक कि विदेशी भी निवासी हो सकते हैं यदि वे उपर्युक्त आर्थिक मानदंड को पूरा करते हैं।

उदाहरण के लिए, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इन देशों के निवासियों (नागरिक के रूप में नहीं) के रूप में बस गए हैं। भारत के लिए, वे अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं लेकिन भारतीय नागरिक बने रहेंगे।

निम्नलिखित को सामान्य निवासियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है:

I. मनोरंजन, छुट्टियां, चिकित्सा उपचार, अध्ययन दौरे, सम्मेलन, खेल आयोजन, व्यवसाय आदि जैसे उद्देश्यों के लिए देश में विदेशी आगंतुक (उन्हें एक वर्ष से कम समय के लिए मेजबान देश में रहना होगा। यदि वे जारी रखते हैं मेज़बान देश में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने के लिए, उन्हें मेज़बान देश के सामान्य निवासियों के रूप में माना जाएगा)।

II. विदेशी जहाजों के चालक दल के सदस्य, वाणिज्यिक यात्री और देश में मौसमी श्रमिक (विदेशी श्रमिक जो श्रम की अलग-अलग मौसमी मांग के जवाब में देश में वर्ष का कुछ हिस्सा काम करते हैं और अपने घरों में लौटते हैं और सीमा पार करने वाले श्रमिक जो नियमित रूप से पार करते हैं) सीमा पर प्रतिदिन या कुछ हद तक कम नियमित रूप से, (अर्थात् प्रत्येक सप्ताह) पड़ोसी देश में काम करने के लिए अपने ही देश के सामान्य निवासी आते हैं। उदाहरण: नेपाल।

III. किसी विदेशी देश के अधिकारी, राजनयिक और सशस्त्र बलों के सदस्य।

IV. विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों को उस देश का निवासी नहीं माना जाता है जिसमें ये संगठन संचालित होते हैं, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासियों के रूप में माना जाता है। हालाँकि, इन निकायों के कर्मचारियों को उस देश के सामान्य

निवासियों के रूप में माना जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निकाय संचालित होता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत का सामान्य निवासी नहीं है, लेकिन उसके कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले अमेरिकियों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा।

V. विदेशी जो अनिवासी उद्यमों के कर्मचारी हैं और जो अपने नियोक्ताओं से खरीदी गई मशीनरी या उपकरण स्थापित करने के उद्देश्य से देश में आए हैं। (उन्हें एक वर्ष से कम समय तक रहना होगा। यदि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय तक रहना जारी रखते हैं, तो उन्हें मेजबान देश के सामान्य निवासियों के रूप में माना जाएगा)।

आर्थिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आर्थिक क्षेत्र एक सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर व्यक्ति, सामान और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है।
- उपरोक्त परिभाषा "व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचलन की स्वतंत्रता" की कसौटी पर आधारित है। जाहिर है, किसी देश की राजनीतिक सीमाओं (या सीमाओं) के वे हिस्से जहां उस देश की सरकार को उपरोक्त "स्वतंत्रता" प्राप्त नहीं है, उन्हें उस देश के आर्थिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- एक उदाहरण दूतावास है। भारत सरकार को भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में उपरोक्त स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसलिए, इन्हें भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। उन्हें उनके संबंधित देशों के आर्थिक क्षेत्रों का हिस्सा माना जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में अमेरिकी दूतावास संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसी तरह, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास भारत के आर्थिक क्षेत्र का एक हिस्सा है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आदि किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित हैं।
- सामान्य शब्दों में, किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्र को किसी देश की राजनीतिक सीमाओं (या सीमाओं) के भीतर स्थित क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन में घरेलू क्षेत्र शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। 'स्वतंत्रता' मानदंड के आधार पर, आर्थिक क्षेत्र का दायरा निम्नलिखित को कवर करने के लिए परिभाषित किया गया है:
- दो या दो से अधिक देशों के बीच सामान्य निवासियों के स्वामित्व और संचालन वाले जहाज और विमान। उदाहरण के लिए, चीन और भारत के बीच नियमित रूप से आवाजाही करने वाले भारतीय जहाज भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा हैं।
- इसी तरह, रूस और जापान के बीच एयर इंडिया द्वारा संचालित विमान भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसी तरह, भारत और जापान के बीच मलेशियाई एयरलाइंस द्वारा संचालित विमान मलेशिया के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा हैं।
- मछली पकड़ने के जहाज, तेल और प्राकृतिक गैस रिग और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म किसी देश के निवासियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जल में संचालित होते हैं जहां उनके पास संचालन का विशेष अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय मछुआरों द्वारा संचालित मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा।
- विदेश में स्थित किसी देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान। उदाहरण के लिए, रूस में भारतीय दूतावास भारत के घरेलू क्षेत्र का एक हिस्सा है। 'वाणिज्य दूतावास' एक कार्यालय या भवन है जिसका उपयोग कौंसल द्वारा किया जाता है (एक अधिकारी जिसे सरकार द्वारा उस देश के हित को बढ़ावा देने के लिए विदेशी देश में रहने के लिए नियुक्त किया जाता है जहां वह रहता है)।

वर्तमान एमपी में जीएनपी:

- जब जीएनपी में शामिल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन वर्तमान एमपी पर किया जाता है, यानी, उस वर्ष में प्रचलित कीमतें जिसके लिए जीएनपी मापा जा रहा है, तो इसे वर्तमान एमपी पर जीएनपी या नाममात्र जीएनपी कहा जाता है।

स्थिर एमपी पर जीएनपी:

- जब जीएनपी में शामिल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्थिर कीमतों, यानी आधार वर्ष की कीमतों पर किया जाता है, तो इसे स्थिर एमपी या वास्तविक जीएनपी पर जीएनपी कहा जाता है।

जीएनपी डिफ्लेटर:

- इसे नाममात्र जीएनपी और वास्तविक जीएनपी के अनुपात के रूप में मापा जाता है, जिसे 100 से गुणा किया जाता है।

$$\textbf{GNP deflator} = = \frac{\text{Nominal GNP}}{\text{Real GNP}} \times 100$$

हरित जीएनपी:

- ग्रीन जीएनपी का तात्पर्य (ए) पर्यावरणीय गिरावट के कारण मूल्य के नुकसान के लिए समायोजित जीएनपी से है; और (बी) अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन गतिविधि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी

जीडीपी या जीएनपी से बाहर की गई गतिविधियाँ:

गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

(ए) विशुद्ध रूप से वित्तीय लेनदेन: यह तीन प्रकार का हो सकता है:

I. प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री
II. सरकारी स्थानांतरण भुगतान
III. निजी हस्तांतरण भुगतान
IV. (बी) प्रयुक्त वस्तुओं का स्थानांतरण।
V. (सी) गैर-बाजार वस्तुएं और सेवाएं
VI. (डी) अवकाश गतिविधियाँ।

प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री:

- वित्तीय बाजारों में संभावित बचतकर्ता और निवेशक शेयर और बांड जैसी वित्तीय संपत्तियां खरीदते और बेचते हैं।
- जबकि कोई शेयर खरीदता है, तो केवल स्वामित्व अधिकार का हस्तांतरण होता है। यह संपत्ति के स्वामित्व का दावा है।
- वित्तीय साधनों में व्यापार का तात्पर्य अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं है। इस प्रकार ये जीएनपी में शामिल नहीं हैं।

सरकारी स्थानांतरण भुगतान:

→ स्थानांतरण भुगतान वे भुगतान हैं जिनके बदले में कोई सामान और सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं। पेंशन भुगतान कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा उपाय आदि सरकारी हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं क्योंकि स्थानांतरण भुगतान के जवाब में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता है, स्थानांतरण भुगतान जीएनपी में शामिल नहीं होते हैं।

निजी स्थानांतरण भुगतान:

→ माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली पॉकेट मनी, बड़ों द्वारा युवाओं को पैसे उपहार में देना जैसी चीजें निजी हस्तांतरण भुगतान हैं। यह महज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन का हस्तांतरण है। इसलिए, यह जीएनपी में शामिल नहीं है।

प्रयुक्त माल का स्थानांतरण:

→ जीएनपी किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को संदर्भित करता है। इसलिए, पिछली समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं को जीएनपी में शामिल नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, मिस्टर ए अपनी पुरानी बाइक मिस्टर बी को रुपये में बेचता है। 25 अप्रैल 2011 को 30,000 रुपये में जिसे मिस्टर ए ने 1 मार्च 2010 को रुपये में खरीदा था। 45,000.

→ इस लेनदेन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे पहले ही 2010 जीएनपी में शामिल किया जा चुका है और अगर हम इसे फिर से शामिल करते हैं, तो यह दोहरी गिनती की समस्या पैदा करेगा

गैर-बाजार वस्तुएँ और सेवाएँ:

- कई अंतिम वस्तुएं और सेवाएं नियमित बाजार लेनदेन के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती हैं। सब्जियाँ सुपर मार्केट से खरीदने के बजाय पिछवाड़े में उगाई जा सकती हैं या बिजली की खराबी को इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखने के बजाय घर का मालिक खुद ही ठीक कर सकता है।
- ये गैर-विपणित वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं जिनका उपभोग संगठित बाजारों का उपयोग करके किया गया है क्योंकि जीएनपी में केवल वे लेनदेन शामिल हैं जो बाजार गतिविधियों के माध्यम से होते हैं।

अवकाश के समय की गतिविधियाँ:

- पेंटिंग, किचन गार्डन में फूल उगाना आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि खाली समय को अपने शौक या मनोरंजन में व्यतीत करना है।

CLASS 12

CHAPTER 3

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा:

- ✓ वस्तु विनिमय प्रणाली और संबंधित समस्याएं
- ✓ पैसे की क्रय शक्ति
- ✓ कानूनी निविदा
- ✓ आंतरिक मूल्य और फिएट मनी
- ✓ धन आपूर्ति
- ✓ विभिन्न प्रकार के पैसे
- ✓ विभिन्न प्रकार के बैंक
- ✓ जमा और खातों के प्रकार
- ✓ बैलेंस शीट को समझना
- ✓ मुद्रा जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- ✓ मनी सर्कुलेशन
- ✓ मुद्रा जमा अनुपात (सीडीआर)
- ✓ आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर)
- ✓ धन गुणक
- ✓ मुद्रास्फीति: प्रकार और कारण
- ✓ महँगाई का प्रभाव
- ✓ मुद्रास्फीति मापने के तरीके
- ✓ मौद्रिक नीति समिति
- ✓ मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण
- ✓ आरक्षित अनुपात
- ✓ खुला बाज़ार संचालन
- ✓ प्रतिभूतियाँ: इक्विटी और ऋण
- ✓ सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक)
- ✓ वित्तीय बाजार

पैसा क्या है?

यह सिक्कों और बैंक नोटों के रूप में विनिमय का एक माध्यम है। जब हम सामान बेचते हैं, तो हम पैसे के बदले सामान का आदान-प्रदान करते हैं। जब हम सामान खरीदते हैं, तो हम सामान के बदले पैसे का आदान-प्रदान करते हैं। अतः यह आदान-प्रदान का एक माध्यम है।

Suppose you go to a Shop
to buy a 5 Star Chocolate

What Transaction Occurred in this case?

Customer exchange Money to get Chocolate

Shopkeeper exchanges Chocolate to get Money

What is Money ?
It is a Medium of Exchange in form of coins & bank notes

When we buy goods, we exchange money for goods
When we sell goods, we exchange goods for money

उस समय क्या हुआ जब पैसा नहीं था?

इस मामले में, हमारे पास वस्तु विनिमय प्रणाली थी

Example

Suppose a Mango Farmer wanted to purchase Jewelry for his wife
He gave 1000 mangoes to Jeweller and in return purchased one necklace

Farmer
Grew Mangoes

Jeweller
Sold Jewellery

What is Barter System?
Exchanging one commodity with other without mediation of money

वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएँ क्या हैं?

विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता है। 2. उदाहरण के लिए, गेहूं को कपड़े से बदला जा सकता है; घोड़ों आदि के लिए घर, या एक शिक्षक को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में गेहूं या चावल का भुगतान किया जा सकता है।

Problem 1 -Barter System

Problem of Double Coincidence of Wants

Suppose in the below example

1000 Mangoes

1 Necklace

Farmer
Grew Mangoes

Jeweller sold
Jewellery

What if Farmer doesn't need Necklace?
What if Jeweler doesn't need so many Mangoes?
Is Barter System Possible?

Barter System Possible
Only if by chance
Farmer Wants Necklace
and
Jeweler Wants mangoes

This is called
Double Coincidence of Wants
it means
Both person should need each other's goods for Barter System to happen

वस्तुओं की एक दूसरे को आवश्यकता हो। यह चाहतों का दोहरा संयोग है।

- चाहतों के दोहरे संयोग का मतलब है कि दो अलग-अलग व्यक्तियों के पास मौजूद सामान एक-दूसरे के लिए उपयोगी और आवश्यक होना चाहिए। यह विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य आधार है। लेकिन यह दुर्लभ है.
- हर वक्त ऐसा इंसान मिलना मुश्किल होता

Problem 3 -Barter System

Difficult to Carry forward one's wealth in Barter System

Suppose in the below example

1000 Mangoes

1 Necklace

Farmer
Grew Mangoes

Jeweller
Sold Jewellery

Now Jeweller is owner of 1000 Mangoes
He saves it in his home for future generations
After 1 Year, he dies
His son becomes owner of wealth of Mangoes
Now, Son tries to sell these Mangoes
But Mango Stock get Spoiled ,cant be sold

Difficult to Carry forward one's wealth in Barter System
(not possible to transfer wealth to future generation)
as goods are perishable

ऐसा विनिमय सी-सी अर्थव्यवस्था (वस्तु से वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था) में मौजूद है। नोट: सी-सी अर्थव्यवस्था में सी का मतलब कमोडिटी है।

सी-सी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता है। सी-सी विनिमय विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली को संदर्भित करता है। इसलिए, सी-सी अर्थव्यवस्था विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली पर हावी अर्थव्यवस्था है।

वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ हैं:-

विनिमय की एक प्रणाली के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है:

आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव:

- वस्तु विनिमय तभी संभव है जब दो व्यक्तियों द्वारा उत्पादित

Problem 2 -Barter System

High Storage Costs

Suppose in the below example

1000 Mangoes

1 Necklace

Farmer
Grew Mangoes

Jeweller
Sold Jewellery

Now Jeweller is owner of 1000 Mangoes
He takes a room on rent and Stores these 1000 Mangoes

There is Storage cost of storing these mangoes
In a room
(if he had received money instead of mangoes, there would not be any storage cost)

है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय काफी सीमित हो जाता है।

- विभाज्यता का अभाव:
- वस्तु विनिमय में वस्तु को विभाजित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। (ii) उदाहरण के लिए, जानवरों को छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।

धन संचय करने में कठिनाई:

- भविष्य में उपयोग के लिए धन का संचय करना बहुत कठिन है। गेहूं, चावल, मवेशी आदि जैसे अधिकांश सामान समय के साथ खराब होने या भंडारण की भारी लागत शामिल होने की संभावना है।

- इसके अलावा, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में भारी परिवहन लागत शामिल होती है। अचल वस्तुओं (जैसे घर, खेत, भूमि, आदि) का हस्तांतरण लगभग असंभव हो जाता है।

मूल्य के सामान्य माप का अभाव:

अलग-अलग वस्तुएं अलग-अलग मूल्य की होती हैं। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का अर्थ है बाज़ार में उसके बदले में दी जा सकने वाली अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई सामान्य माप नहीं है।

Problem 4 -Barter System

No Proper Unit of Account

Suppose there are 3 persons A,B and C
Who sell Watermelons, Apples and Oranges respectively

Farmer A agrees to give his 1 Watermelon to get 3 Apples from B

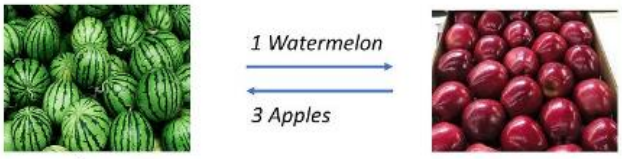

But Farmer A agrees to give his 1 Watermelon to get 4 Oranges

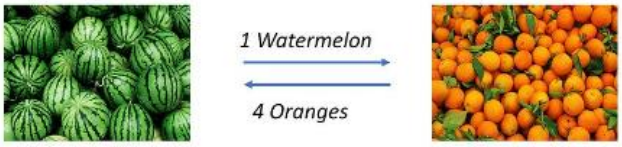

What is Price of Watermelon?
It is 3 Apple per watermelon
Or
4 oranges per watermelon

*There is **no proper unit of account***

It is Difficult to measure how much quantity in exchange of another commoditv

ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि दोनों वस्तुओं का आदान-प्रदान किस अनुपात में किया जाए।

आस्थगित भुगतान के मानक का अभाव:

वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में भविष्य के भुगतान को विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में बताना होगा। इससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं:

Problem 5-Barter System

Goods not acceptable to Other Person

Example
Suppose a Farmer sells Mangoes
Customer is a Butcher who is willing to purchase Mangoes in exchange of chicken
But Farmer is Vegetarian and doesn't eat chicken?

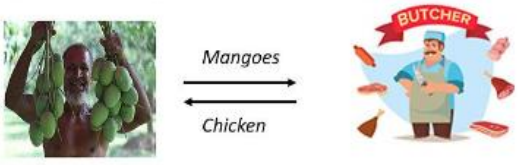

He is Vegetarian (Doesn't eat chicken)

- भुगतान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में असहमति हो सकती है।
- इस बात पर असहमति होगी कि पुनर्भुगतान के लिए किन विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा।

Problem 6 -Barter System

No Standard of Deferred Payment

Example
Suppose there are 2 Farmers
Farmer 1 Grows Mango
Farmer 2 Grows Wheat
Both agree to exchange their crop with each other
Crop of Mango is Ready
But Crop of Wheat will take 3 months to be ready

Problems in this Barter Transaction
In this case Farmer 2 will make payment at later date
(It is Deferred Payment)
How much wheat will grow in farm?
(No Standard quantity of Deferred Payment)
What if Wheat crop gets damaged due to flood, drought etc?
(No Standard quality of deferred payment)

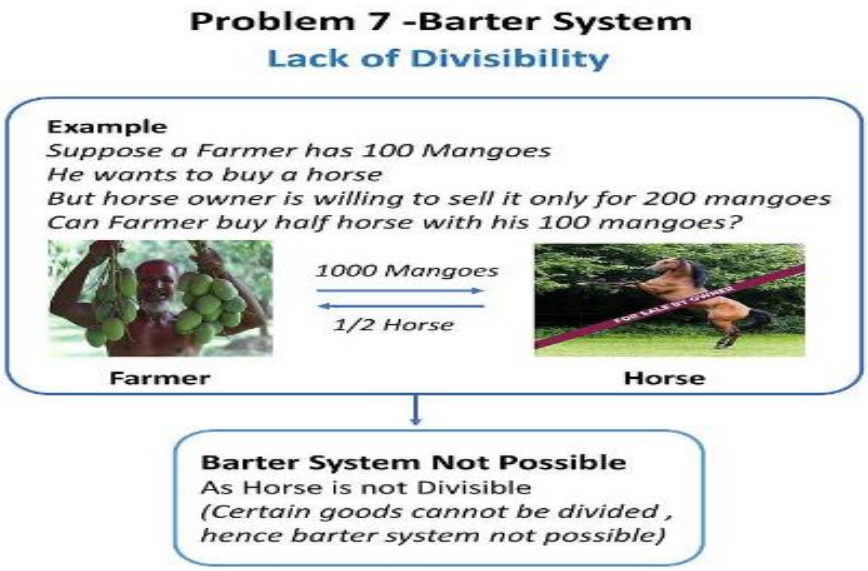

पैसा क्यों लाया गया?

इसे वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था।

वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएँ	मुद्रा प्रणाली के लाभ
इच्छाओं का दोहरा संयोग	चाहत एक व्यक्ति की भी हो सकती है (दोनों की नहीं)
खाते की कोई उचित इकाई नहीं	खाते की उचित इकाई
किसी के धन को आगे ले जाना कठिन है	भविष्य में पैसा ले जाना आसान
उच्च भंडारण लागत	पैसा आसानी से संग्रहित किया जा सकता है
हर किसी को स्वीकार्य नहीं	सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत
विभाज्यता का अभाव	आसानी से विभाज्य

How does Money overcome shortcoming of Barter System

BARTER SYSTEM PROBLEMS		MONEY SYSTEM BENEFITS
Double Coincidence of Wants *(Both person should need each other goods or service)*	→	**Want Can be of One person also** *(Only one person may need the good And not both person)*
High Storage Cost *(Product purchased or sold has to be stored in warehouse/godown)*	→	**Money Can be easily stored** *(It is easier to save notes than goods No need of godown/warehouse)*
Difficult to Carry forward wealth *(Some items are perishable, cannot be transferred to future generation)*	→	**Easier to carry forward money to future** *(Father can save his wealth in form of bank notes and give to his future generation)*
No Proper Unit of Account *(No fixed price of a product, price varies with product exchanged)*	→	**Proper Unit of Account** *(Price of All goods is measured in terms of Rupees)*

Definition of Money → **Functions of Money**

Money is

Medium of Exchange → **Money Act as Medium of Exchange**
Goods and Services can be exchanged for money

Measure of Value → **Money Act as Measure of Value**
We decide Price of different goods and services in terms of money

Store of Value → **Money Act as Store of Value**
Money can be saved and Stored for use by future generation

And
Means for Standard Deferred Payment → **Money Act as Means for Standard of Deferred Payment**
If Payment to be made in future , we know amount to be paid

क्या पैसा केवल मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है?

नहीं, अन्य परिसंपत्तियाँ भी मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती हैं, जैसे संपत्ति, सोना, स्टॉक आदि।

इन संपत्तियों का उपयोग धन के स्थान पर क्यों नहीं किया जाता?

क्योंकि ये आसानी से परिवर्तनीय नहीं हैं. साथ ही, उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी नहीं है

पैसे की क्रय शक्ति क्या है?

धन की क्रय शक्ति से तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से है जो इससे खरीदी जा सकती हैं।

जैसे: यदि किसी व्यक्ति के पास 60 रुपये हैं और वह बिस्कुट खरीदना चाहता है। अब बिस्किट के 1 पैकेट की कीमत 10 रुपये है. यहां पैसों से 6 पैकेट बिस्किट खरीदा जा सकता है। (60/10=6)

पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट का क्या कारण है?

वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में मुद्रास्फीति के कारण धन की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि से है।

अब, 2021 में

व्यक्ति के पास बिस्कुट पर खर्च करने के लिए 100 रुपये हैं। महंगाई के कारण बिस्किट के 1 पैकेट की कीमत 12 रुपये तक बढ़ गई है. नतीजा यह हुआ कि 2021 में पैसों से सिर्फ 5 पैकेट बिस्किट ही खरीदे जा सकेंगे

(60/12=5). तो, हम देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण पैसे की क्रय शक्ति कम हो गई है।

पैसे की अवसर लागत क्या है?

यदि हम धन को नकद रूप में रखने के बजाय बैंक में जमा करते हैं। हमें ब्याज मिलता है.

यह पैसे की अवसर लागत है

लोग पैसा क्यों रखते हैं?

उन्हें तरलता की प्राथमिकता है. यह इस कारण उत्पन्न होता है-

1. पैसे का लेन-देन का मकसद

इसका अर्थ है नकदी-आधारित लेनदेन के लिए धन रखने की इच्छा

जैसे: एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। उनके पास 2 विकल्प हैं या तो उन्हें खर्च करें या बैंक में जमा करें। यदि व्यक्ति को किसी लेन-देन/खरीदारी के लिए धन का उपयोग करने की इच्छा है तो वह इसे बैंक में जमा नहीं करेगा और अपने पास रखेगा।

2. पैसे का सट्टा उद्देश्य

यह एक व्यापारी/निवेशक की पैसा रखने की इच्छा को संदर्भित करता है ताकि बाद में निवेश का अच्छा अवसर आने पर इसका उपयोग किया जा सके।

3. धन का एहतियाती मकसद

यह उन अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होने के लिए धन रखने की इच्छा है जिनके लिए नकद परिव्यय की आवश्यकता होती है।

उदाहरण: किसी व्यक्ति को भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में पैसा रखने की इच्छा हो सकती है।

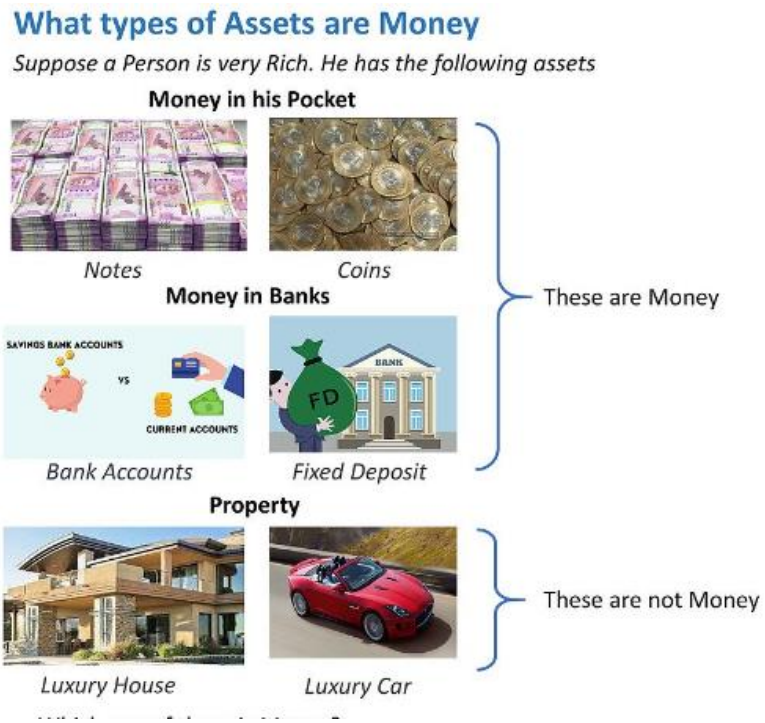

धन की आपूर्ति

- ⟶ धन में करेंसी नोट और सिक्के शामिल होते हैं-
- ⟶ इसमें डिमांड डिपॉजिट + टर्म डिपॉजिट भी शामिल हैं

मुद्रा नोट

- इन्हें देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है
- भारत में, यह भारतीय रिज़र्व बैंक है

सिक्के

- वे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं

डिमांड डिपॉज़िट्स

- बैंकों के बचत और चालू खातों में शेष राशि को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है
- इसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है क्योंकि इसे मांग पर कभी भी निकाला जा सकता है (चेक आदि जारी करके)

टर्म डिपॉज़िट

- वे एक निश्चित अवधि के लिए जमा हैं

उदाहरण - फिक्स्ड डिपॉजिट की एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है

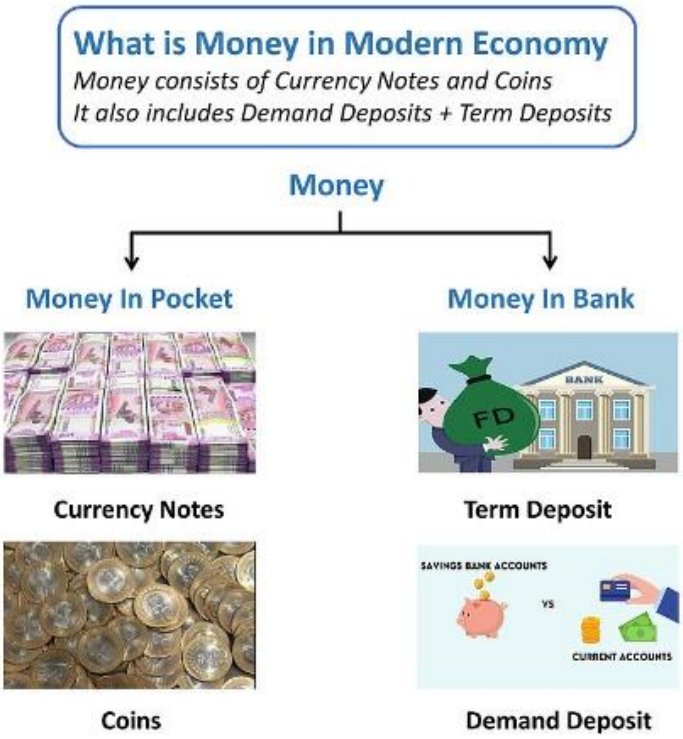

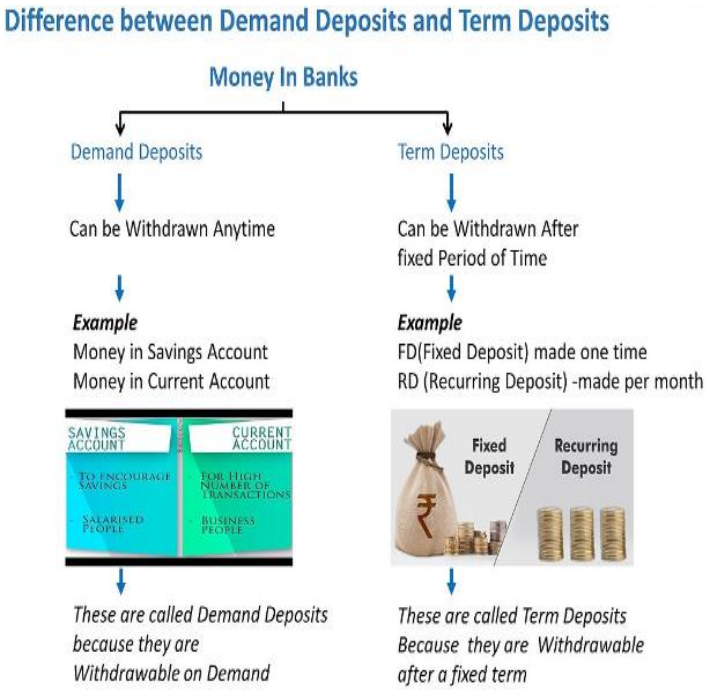

कानूनी निविदा क्या है?

Example

Suppose you go to Mc Donald's to purchase a Mc Veggie Burger for Rs 70

Can you make payment by 7 Bank Notes of Rs 10? → Yes, shopkeeper has to accept Bank Notes

Can you make payment by 70 Coins of Rs 1 each → Yes, shopkeeper has to accept coins

Can you make payment by Cheque of Rs 70 ? → No, shopkeeper may refuse to take cheque

Can you make payment by FD of Rs 70? → No, shopkeeper may refuse to take FD

What is Legal Tender?
It is a form of money which cannot be refused by any citizen for settlement of any kind of transaction

- यह धन का एक रूप है जिसे कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के लेनदेन के निपटारे के लिए देने से इनकार नहीं कर सकता है

उदाहरण-

- अगर मुझे किसी दुकानदार को 500 रुपये का भुगतान करना है, तो मैं उसे भुगतान के रूप में कोई भी नोट या सिक्का दे सकता हूं
- व्यक्ति किसी भी प्रकार का करेंसी नोट लेने से इंकार नहीं कर सकता
- इसलिए, सिक्के और करेंसी नोट वैध मुद्रा हैं।

अपवाद

हालाँकि, वह व्यक्ति 500 का चेक या 500 की सावधि जमा लेने से इनकार कर सकता है, क्योंकि ये कानूनी निविदाएं नहीं हैं।

पैसे की कानूनी परिभाषा:

(ए) कानूनी तौर पर, पैसा कानून द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में घोषित कुछ भी है।

(बी) कागजी नोट और सिक्के (एक साथ मुद्रा कहलाते हैं) कानूनी तौर पर पैसा हैं।

(सी) कोई भी इसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है।

(डी) दूसरे शब्दों में, यह कानूनी निविदा है। इसका मतलब है कि लोगों को विभिन्न भुगतानों के लिए इसे कानूनी रूप से स्वीकार करना होगा।

मुद्रा को FIAT मुद्रा भी कहा जाता है क्योंकि यह सरकार के 'FIAT' (आदेश/अधिकार) को नियंत्रित करती है।

Different Types of Money

Legal Tender

Cant be Refused by Any citizen in settlement of any transaction

Example

Currency Notes

Coins

Not Legal Tender

Can be Refused by Any citizen in settlement of any transaction

Example

Fixed Deposit

Demand Deposit

Note

Legal Tender is also of 2 Types

- *Limited legal Tender*
- *Unlimited Legal Tender*

भारत में करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है?

- आम तौर पर सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं।

अपवाद

- 1 रुपये का करेंसी नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है (आरबीआई द्वारा नहीं)

Suppose I want to Purchase a Car for Rs 10 lacs
Can I make Payment of Rs 10 lacs by Coins

Legal Tender

Limited Legal Tender

Payment upto a Certain Amount is allowed

Example

Coins
can be used to make Payment only upto Rs 1000 in India

Unlimited Legal Tender

Payment upto any amount is allowed

Example

Currency Notes
can be used to make Payment up to any amount In India

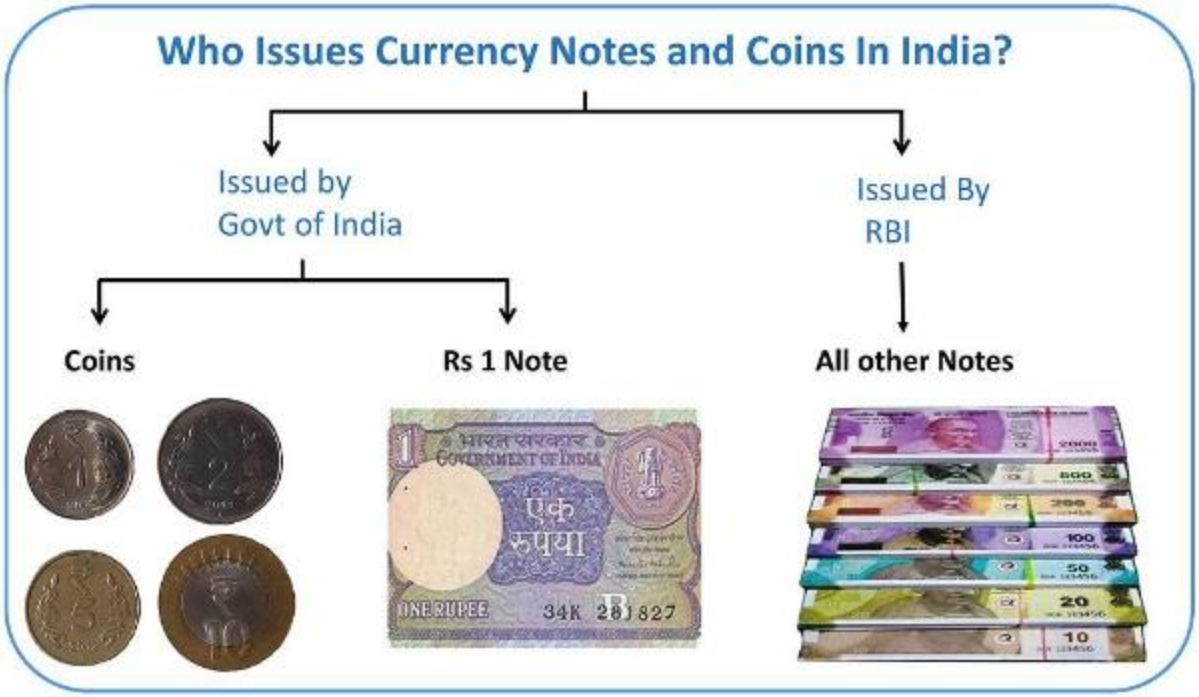

आंतरिक मूल्य और फिएट मनी

फिएट मनी क्या है?

- यह एक करेंसी नोट या सिक्का है जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इन्हें केवल सरकारी विनियमन के कारण कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किया जाता है।

उदाहरण- करेंसी नोट और सिक्के जो आजकल उपयोग में आते हैं।

करेंसी नोटों और सिक्कों को फिएट मनी क्यों कहा जाता है?

पहले के समय में,

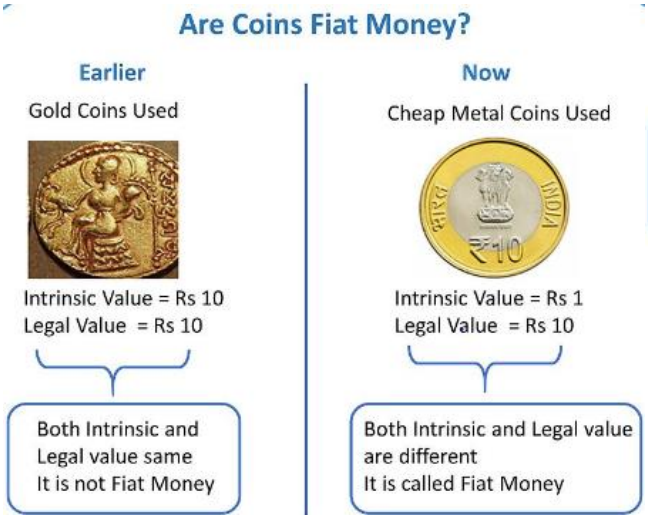

अब,

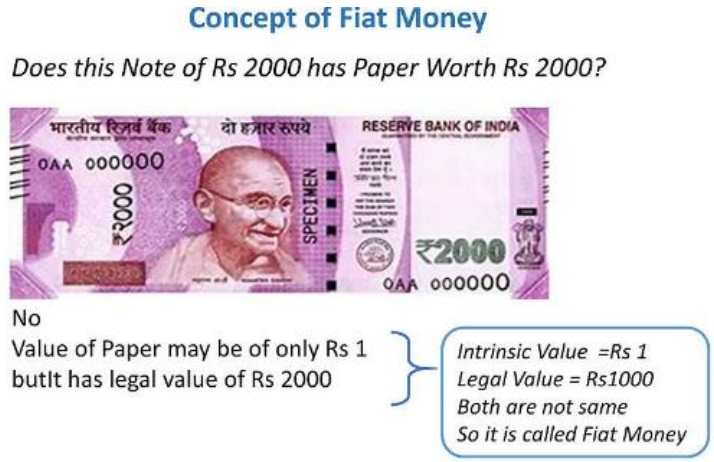

What is Fiat Money

It is a currency note or a coin which does not have intrinsic value
They are used as legal tender only because of government regulation
Example-Currency Notes and Coins used now a days

- सोने और चाँदी के सिक्के जारी किये गये। सोना और चाँदी बहुमूल्य धातुएँ थीं जिनका आंतरिक मूल्य था। तो, 100 रुपये के चांदी के सिक्के का वास्तविक मूल्य 500 रुपये था

तांबा, निकल, एल्यूमीनियम जैसी सस्ती धातुओं के सिक्कों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा करेंसी नोटों का भी उपयोग किया जाता है जो कागज के बने होते हैं। 10 रुपए के सिक्के में 10 रुपए की धातु नहीं हो सकती। 500 रुपये के करेंसी नोट में 500 रुपये का कागज नहीं होता है। इसलिए, इन सिक्कों और नोटों को फिएट मनी कहा जाता है क्योंकि इनमें सोने और चांदी के सिक्कों की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता है। हालाँकि, सरकारी विनियमन (सरकारी नियमों) के कारण इन्हें कानूनी रूप से कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मुद्रा आपूर्ति स्टॉक है या प्रवाह?

Example

Suppose a Glass is of 300 ml
It is filled up by tap water in 5 seconds
It means water is flowing from Tap into glass at speed of
300/5= 60 ml per second

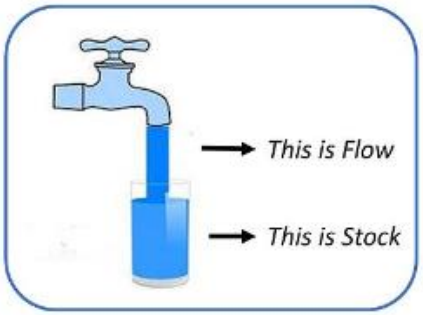

This is Flow → *Water is **flowing** at a speed of 60ml per second*

This is Stock → *There is **Stock** of 300 ml of Water after 5 seconds*

What is Stock
It is a variable which is measured at a Particular Point of Time
Example
Amount of Water in a Glass

What is Flow
It is a variable which is measured over a period of time
Example
Amount of Water flowing from tap into glass per second

Suppose I have Rs 50000 in my bank account as on 1 Jan
I spent 10000 during the month of January
Now I am left with 40000 as on 31 Jan
What is Stock and Flow in above case?

Bank Balance as on 1 January → It is Stock (Measured at Particular Point of Time)

Cash Withdrawn During January → It is flow (Measured over a period of time)

Bank Balance as on 31 January → It is Stock (Measured at Particular Point of Time)

Difference Between Stock and Flow

Stock	Flow
It is variable measured at a Particular Point of time	*It is variable measured over a period of time*
Example – Bank balance as on 31st Jan	*Period- Cash withdrawn during January*

मुद्रा आपूर्ति क्या है?

यह एक विशेष समय में जनता के पास प्रचलन में मौजूद धन का कुल स्टॉक है।

क्या मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक परिवर्तनीय या प्रवाह परिवर्तनीय है?

मनी सप्लाई एक स्टॉक वैरिएबल है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे एक विशेष समय पर मापा जाता है

उदाहरण - आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक धन आपूर्ति के आंकड़े प्रकाशित किए, जिसका मतलब है कि 31 मार्च 2021 को जनता के बीच प्रचलन में कुल धन

What is Money Supply in an Economy

What is Money Supply?

It is total stock of Money in circulation with public at a particular point of time

Example

As per RBI Press Release, total money supply as on 31 March 2021 was Rs 188 Lakhs Crores →

Is Money Supply Stock or Flow?

Money Supply is Measured at a Particular Date
So it is a Stock

मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

Different Types of Money Supply

Legal Tender

Coins
Currency Notes

Note
Both these are called 'CU'

Not Legal Tender

Balance with Banks

Demand Deposits (DD)
Saving Account
Current Account

Term Deposits
Fixed Deposit in Bank
Recurring Deposit in Bank

Balance with Post Office

Demand Deposits
Post Office Savings Account

Term Deposits
Fixed Deposit in Post Office
(Except NSC*)

All these are Categorized into 4 legal Definitions of Money-M1,M2.M3,M4

**What is NSC?*
It means National Savings Certificate
It is a scheme of Post office where public invest their money for fixed period of time and get higher amount on maturity.
This is not counted in definition of money supply

मुद्रा आपूर्ति के लिए RBI द्वारा प्रकाशित आंकड़े

आरबीआई मनी सप्लाई के मामले में 4 तरह के आंकड़े प्रकाशित करता है

एम1,एम2,एम3,एम4

आइए एक-एक करके इसके बारे में जानें

What is M1

M1 is total of currency notes and coins (CU)
+
Net demand deposits issued of Bank(DD)
M1=CU+DD

What is Covered in M1

Legal Tender

Coins (CU)
Currency Notes (CU)

Not Legal Tender

Balance with Banks
*Demand Deposits (DD)**
Saving Account
Current Account

~~*Term Deposits*~~
~~Fixed Deposit in Bank~~
~~Recurring Deposit in Bank~~

~~**Balance with Post Office**~~
Demand Deposits
~~Post Office Savings Account~~

~~Term Deposits~~
~~Fixed Deposit in Post Office~~
~~(Except NSC)~~

Note
Only Net Demand Deposits covered in M1,
Not term Deposits and that too of bank (Not Post office)
Net demand Deposits means Demand Deposits of public and not demand deposit of one bank with other bank

What is M2

In M2,We include savings deposits with Post office savings banks also with M1
M2=M1+Post office savings banks
M2=CU+DD+ +Post office savings banks

What is Covered in M2

Legal Tender

Coins (CU)
Currency Notes (CU)

Not Legal Tender

Balance with Banks
Demand Deposits (DD)
Saving Account
Current Account

~~*Term Deposits*~~
~~Fixed Deposit in Bank~~
~~Recurring Deposit in Bank~~

Balance with Post Office
Demand Deposits
Post Office Savings Account

~~*Term Deposits*~~
~~Fixed Deposit in~~
~~Post Office~~
~~(Except NSC)~~

M3
In M3,We include Net time deposits of commercial banks also with M1
M3=M1+Net time deposits of commercial banks
M3=CU+DD+ +Term Deposits of Bank
(No post office here deposits here)

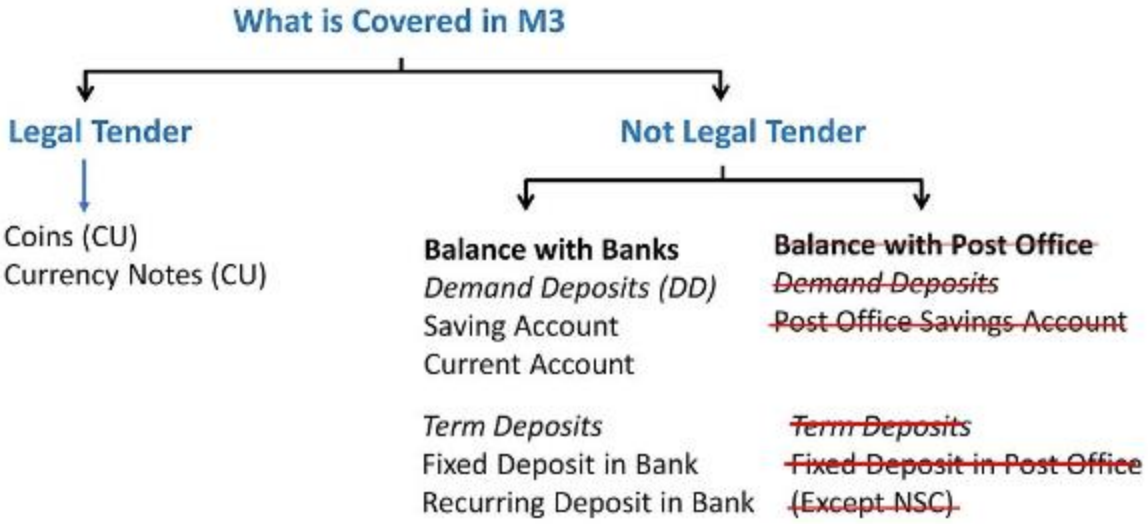

M4
In M4,we include M3+ total deposits with Post office savings organizations
(however, National savings Certificate is not included)
M4=M3+Total Deposits of Post Office
(hence, it includes all forms of money)

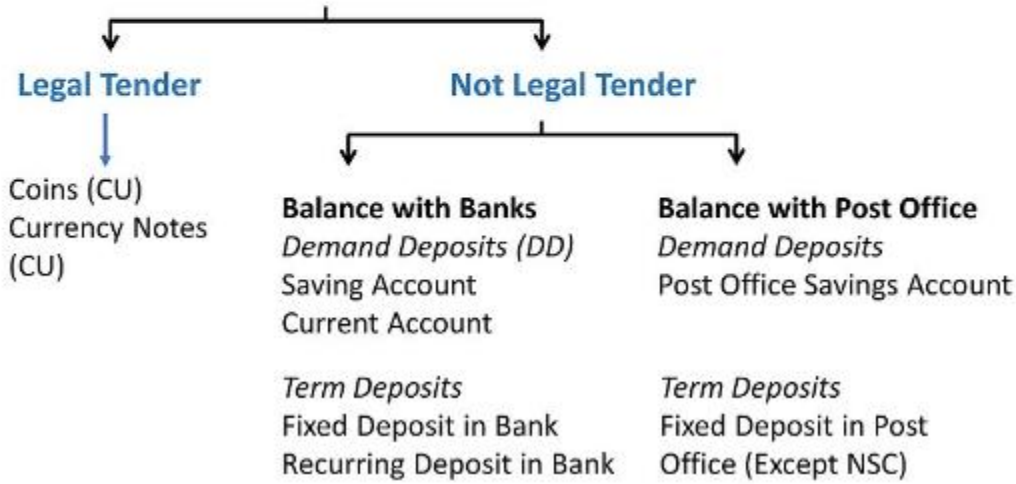

Comparison Chart of M1,M2 ,M3 & M4

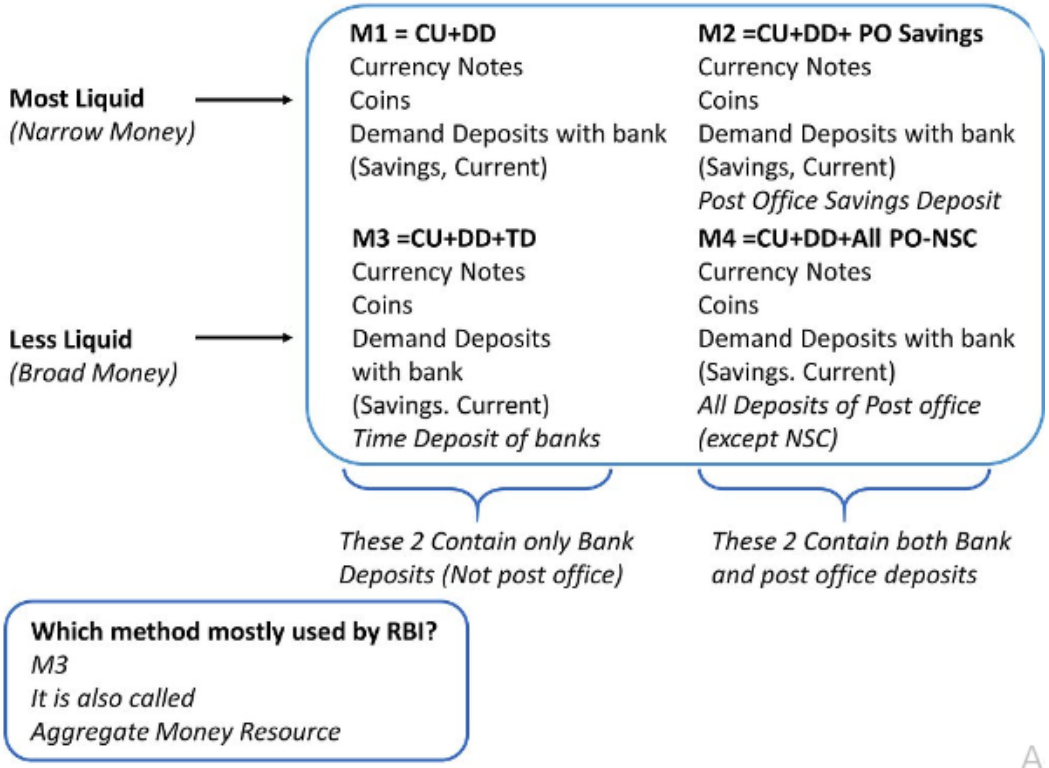

Which method mostly used by RBI?
M3
It is also called
Aggregate Money Resource

Different Measures of Money Supply

M1→ CU+ DD
(Currency Notes and Coins +Demand Deposits of Commercial banks)

M2→ M1 +Savings Account with Post Office
(Currency Notes and Coins +Demand Deposits of Commercial Banks+ Savings Account of Post Office)

M3→ M1 + Net Time Deposit of Banks
(Currency Notes and Coins +Demand Deposits of Commercial Banks+ Term Deposits of Bank)

M4→ M3 + Total Deposits of Post Office (Excluding NSC)
(Currency Notes and Coins +Demand Deposits of Commercial Banks+ Term Deposits of Bank)+ All deposits of Post office

एम1

एम1 मुद्रा नोटों और सिक्कों (सीयू)+ जारी की गई शुद्ध मांग जमा राशि (डीडी) का योग है

एम1 = सीयू+डीडी

एम2

एम2 में, हम डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को भी एम1 के साथ शामिल करते हैं

एम2 = एम1 + डाकघर बचत बैंक

एम3

एम3 में, हम एम1 के साथ वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा को भी शामिल करते हैं

एम3 = एम1 + वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा

एम 4

एम4 में, हम एम3 + डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा को शामिल करते हैं

(हालांकि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र शामिल नहीं है)

M4 = M3 + डाकघर की कुल जमा

उपरोक्त में से कौन सा सर्वाधिक तरल है?

M1 सबसे अधिक तरल है, M2 थोड़ा कम, M3 उससे भी कम और M4 सबसे कम तरल है

जो कानूनी आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका है

एम3

इसे समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है

ब्रॉड मनी और नैरो मनी क्या है?

संकीर्ण धन

वह मुद्रा जो सर्वाधिक तरल होती है, संकीर्ण मुद्रा कहलाती है

M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है

व्यापक मुद्रा

यह अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा है जिसमें अत्यधिक तरल और कम तरल दोनों रूप शामिल हैं

एम3 और एम4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है

आइए ब्रॉड मनी और नैरो मनी के बीच अंतर को समझें

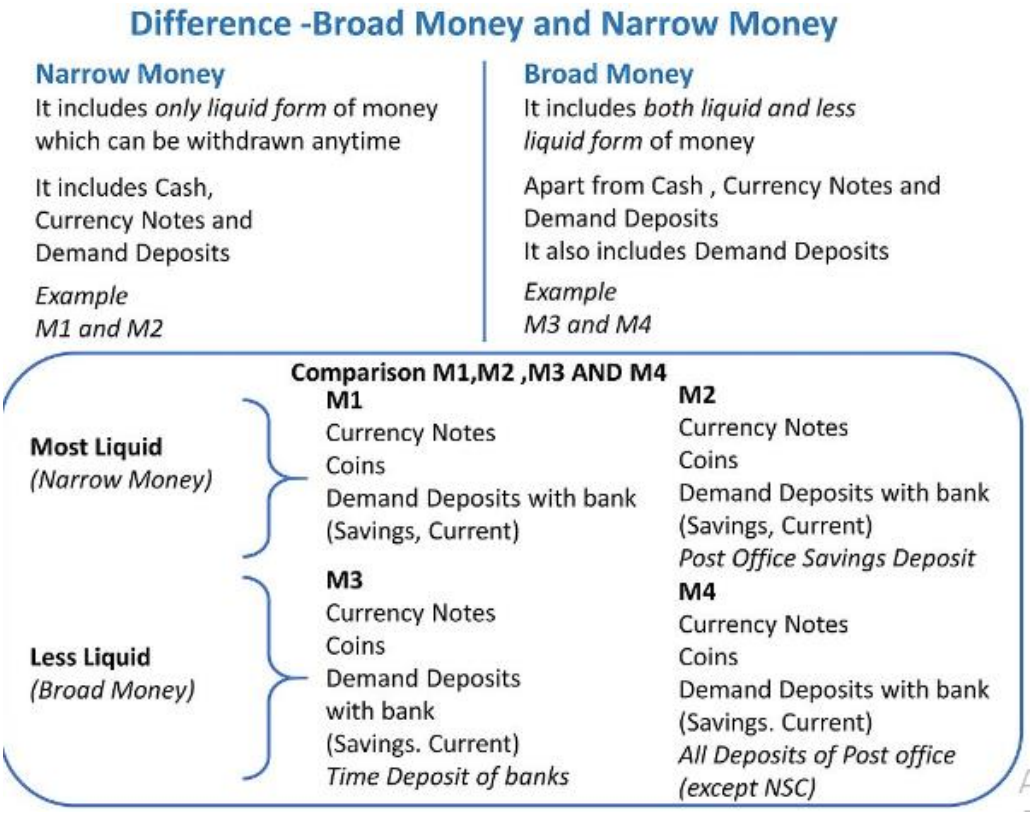

सेंट्रल बैंक और वाणिज्यिक बैंक के बीच अंतर

बैंक 2 प्रकार के होते हैं

- वे बैंक जो पब्लिक डीलिंग करते हैं

उदाहरण- PNB, SBI, ICICI

- इन्हें वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है
- जो बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं

उदाहरण- भारत में RBI

- इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है

Central Bank vs Commercial Bank

Reserve Bank of India
(Central bank)

State Bank of India
(Commercial Bank)

Questions

In which Bank can we open an account?
SBI (Commercial Bank)

Which bank can give loan to us?
SBI (Commercial Bank)

Which bank can give loan to SBI?
RBI(Central Bank)

Which Bank can issue Currency?
RBI (Central Bank)

Commercial Bank is
Bank of Public
(Deals with Public)

Central bank(Reserve Bank) is
bank of bank

Difference between Central Bank and Commercial Banl

Central Bank

It is the main body
which regulates Banking
and Monetary Policy of Country

It is banks of banks,
it does not deal with public directly

There is only 1 Central Bank
in Country
Example
Reserve bank in India

It has power to print and
issue currency

Commercial Bank

It refers to the Institutions
which accept deposits with public
and give loan to public

It is the bank which
deals with public

There are many Commercial banks
in the Country
Example
State bank of India, ICICI Bank

It cannot issue currency

एक वाणिज्यिक बैंक की बुनियादी अवधारणाएँ

बैंक की उधार दर क्या है?

Suppose Ajay takes Loan from Bank of Rs 100000 @ 11%

loan Rs 500000

Ajay ← **BANK**

It is a Loan taken *(Liability)*

It is a Loan Given *(Assets)*

Ajay will Pay Interest
So, It is Interest Expense for Ajay

Bank will Receive Interest
So, It is Interest Income for Bank

What is Rate of interest of bank?
11%

What is Lending Rate of Bank
11%

What is Lending Rate
Percentage charged by bank on Loan given is called **Lending Rate**

बैंक की उधार दर क्या है?

Suppose Bharat Makes Fixed Deposit (FD) in Bank of Rs 100000 @ 6%

Deposit Rs 100000

Bharat → **BANK**

It is like a Loan Given to Bank (Assets)

It is a Loan taken from Public called Term Deposits (Liability)

B will Receive Interest of 6000
It is *Interest Income for B*

Bank will pay Interest of 6000
It is *Interest expense*

What is Rate of interest of FD
6%

What is Borrowing Rate of bank
6%

Note
Same case applicable in case of Savings Account also (Demand Deposits)

What is Borrowing Rate
(Rate of Interest at which Bank borrows Money from others is called **Borrowing Rate**)

कोई बैंक पैसे कैसे कमाता है?

- एक बैंक जनता से कम ब्याज दर पर पैसा लेता है
- यह जनता और व्यवसायियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है
- शेष इसकी आय है

Example

Suppose Bharat deposits Rs 100000 FD in Bank @ 6%
Bank uses this money to give loan to Ajay @ 11%

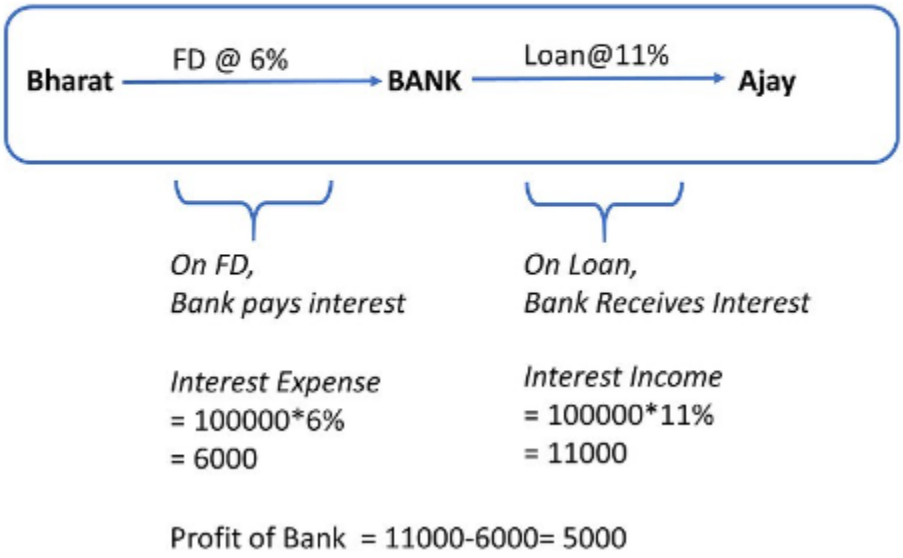

इस मामले में बैंक की उधार दर क्या है?

- बैंकों की उधार दर बैंकों द्वारा जमा धारक को दी जाने वाली ब्याज दर है
- हमारे उदाहरण में उधार दर = 6%

इस मामले में बैंक की ऋण दर क्या है?

- ऋण दर बैंक द्वारा धन उधार देने पर ली जाने वाली दर है
- हमारे उदाहरण में उधार दर = 11%

स्प्रेड क्या है?

- स्प्रेड का अर्थ है उधार दर और उधार दर के बीच अंतर
- हमारे मामले में प्रसार = 11% - 6% = 5%
- नोट- जितना अधिक प्रसार होगा, बैंक का लाभ उतना अधिक होगा

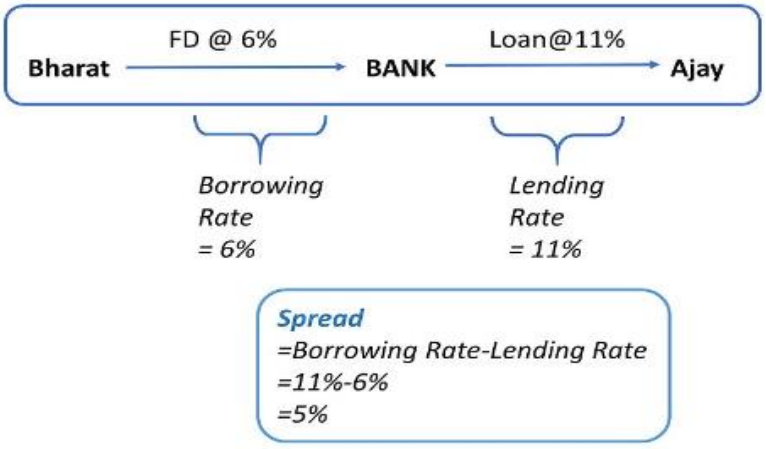

लोन देते समय बैंक क्या जाँचता है?

बैंक चेक-

- व्यक्ति की ऋण पात्रता (क्या व्यक्ति ऋण चुकाने में सक्षम होगा)

- संपार्श्विक (प्रस्तावित संपत्ति के रूप में सुरक्षा)
- चुकौती क्षमता
- वित्तीय अनुपात

Suppose a Customer C approaches bank for Loan of Rs 500000

In this case, Bank will check

Credit Worthiness of C
Whether C has Repaid Past loans on time

Collateral of C
Whether C is offering any security
as a guarantee for Repayment like property papers

Repayment Capacity of C
Whether C will generate enough income to repay back the loan and interest
Bank will check Income Tax Returns, Bank Statements and Profit and loss Balance sheet

Financial Ratios of C
Bank will check whether C's Balance sheet Profit and loss and Calculate Ratios like Current Ratio,
Net Current Assets

वाणिज्यिक बैंक के विभिन्न कार्य

जमा के प्रकार:

1. डिमांड डिपॉजिट: डिमांड डिपॉजिट में रखे गए फंड को डिपॉजिटरी संस्था को बिना किसी अग्रिम सूचना के किसी भी समय मांग पर निकाला जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट की मांग खाताधारक द्वारा किसी भी समय की जा सकती है और डिमांड डिपॉजिट के लिए परिपक्वता की कोई निश्चित अवधि नहीं है। बैंक इस प्रकार की जमाओं पर चेक जारी करते हैं और इन जमाओं पर चेक जारी किए जा सकते

Accepting Deposits

Example
- Saving Account
- Current Account
- Fixed Deposit

On this
Bank Pays
Interest Expense

Advancing Loans

Example
- Housing loan
- Car Loan
- Overdraft

On this
Bank Receives
Interest Income

Agency Function

Example
- Purchase Sale of Foreign Currency
- Collection of Tax
- Purchase Sale of Shares

On this
Bank Receives
Commission Income

हैं और इसलिए मांग जमाओं को चेक-सक्षम जमा भी कहा जाता है।

2. सावधि जमा: सावधि जमा में रखी गई धनराशि केवल डिपॉजिटरी संस्था को अग्रिम सूचना देकर ही निकाली जा सकती है। जमा को एक निर्दिष्ट समय अवधि या परिपक्वता के लिए रखा जाता है। बैंक इस प्रकार की जमाओं पर चेक जारी नहीं करते हैं और इसलिए ये गैर-चेक योग्य जमाएँ हैं। इन्हें सावधि जमा भी कहा जाता है।

खातों के प्रकार:

1. चालू खाता: यह हमेशा एक मांग जमा खाता होता है और बैंक मांग पर पैसे का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। लेनदेन की संख्या और लेनदेन के मूल्य की कोई सीमा नहीं है और ये सबसे अधिक तरल जमा हैं। चालू खाते का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य/कंपनियों के लिए किया जाता है और

इसका उपयोग कभी भी बचत के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। इन खातों पर बैंकों द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और बैंक इन खातों पर कुछ सेवा शुल्क लेते हैं। बैंक इन खातों पर सुविधाजनक परिचालन सुविधाएं प्रदान करते हैं और चेक बुक भी जारी करते हैं।

2. बचत खाता: यह खाता मुख्य रूप से व्यक्तियों के लिए है। ये भी डिमांड डिपॉजिट हैं लेकिन एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान लेनदेन की संख्या और लेनदेन के मूल्य पर प्रतिबंध हैं। बैंक आम तौर पर ऐसी जमाओं को बनाए रखने और सेवा प्रदान करने की लागत की भरपाई के लिए खातों में न्यूनतम शेष राशि निर्धारित करते हैं। इन खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।

3. आवर्ती जमा खाता: ये सावधि जमा हैं जो उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास बचत की एकमुश्त राशि नहीं है लेकिन हर महीने या त्रैमासिक या छमाही में छोटी राशि बचाने के लिए तैयार हैं। ऐसी जमाओं पर पहले से जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता है जैसा कि सावधि जमा पर लागू होता है। यह बच्चे की शिक्षा या विवाह के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। परिपक्वता आम तौर पर 6 महीने से 10 साल के बीच होती है।

4. सावधि जमा खाता: ये सावधि जमा हैं जिनकी अवधि 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक होती है। ये जमा निश्चित अवधि के लिए हैं लेकिन बैंक को अग्रिम सूचना और कुछ जुर्माना देकर समय से पहले वापस लिया जा सकता है

वाणिज्यिक बैंक के कार्य क्या हैं?

1. जमा स्वीकार करना

बैंक कई रूपों में जमा स्वीकार करते हैं जैसे:

(i) चालू खाता/मांग जमा

- ये वे जमाएँ हैं जो बैंक द्वारा माँग पर चुकाई जाती हैं
- इन्हें चेक द्वारा निकाला जा सकता है
- उनकी कोई ब्याज दर नहीं है

(ii) सावधि/सावधि जमा

- ये वे जमाएँ हैं जिनमें एक निश्चित अवधि के लिए माँग जमा की जाती है
- उनके पास जांच योग्य सुविधा नहीं है
- इनकी ब्याज दर अधिक होती है

(iii) बचत जमा

- इन जमाओं में डिमांड और फिक्स्ड डिपॉजिट की संयुक्त विशेषताएं हैं
- उनके पास जांच योग्य सुविधा है
- इनकी ब्याज दर सावधि जमा से कम होती है

2. ऋण अग्रिम करना

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के ऋण और अग्रिम हैं:

(i) नकद ऋण

यह उधारकर्ता को उनकी मौजूदा परिसंपत्तियों जैसे शेयर, स्टॉक आदि के बदले दिए गए ऋण को संदर्भित करता है

(ii) ऋण की मांग करना

डिमांड लोन (डीएल) एक सुरक्षित ऋण है जिसे ऋणदाता की मांग पर उधारकर्ता को चुकाना होता है। आमतौर पर इन ऋणों की अवधि न्यूनतम सात दिन से लेकर अधिकतम एक वर्ष तक हो सकती है। व्यक्ति और व्यवसाय अधिकतर इन ऋणों का उपयोग अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं।

(iii) अल्पावधि ऋण

इन्हें कुछ सिक्योरिटी पर पर्सनल लोन के तौर पर दिया जाता है

3. एजेंसी के कार्य

वाणिज्यिक बैंक कुछ एजेंसी कार्य भी करते हैं। इन सेवाओं के लिए वे अपने ग्राहकों से कुछ कमीशन लेते हैं

उदाहरण:

1. निधियों का स्थानांतरण 2. विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री

3. आयकर परामर्श 4. प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री

5. सन्दर्भ पत्र

एक वाणिज्यिक बैंक की बैलेंस शीट को समझना

जब हम बैंक में रकम जमा करते हैं

- यह हमारे लिए संपत्ति है (क्योंकि यह हमारी संपत्ति है)
- लेकिन यह बैंक के लिए दायित्व होगा (क्योंकि बैंक को हमें वापस भुगतान करना होगा)

जब हम बैंक से लोन लेते हैं

- यह हमारे लिए दायित्व है (क्योंकि हमें इसे वापस चुकाना होगा)
- लेकिन यह बैंक के लिए संपत्ति है

Suppose a company has Rs 10000 in ICICI Bank Current Account
It also has FD of 20000 in ICICI Bank
It also has taken a loan of 80000 from ICICI Bank

Balance Sheet of a Company

BALANCE SHEET			
Liabilities	**Amt**	**Assets**	**Amt**
		Bank	10000
		FD	20000
Loan	80000		

For a Business
Loan taken is liability
FD and Bank A/c are our Assets (Property)

Balance Sheet of ICICI Bank

BALANCE SHEET			
LIABILITIES	**AMT**	**ASSETS**	**AMT**
Demand Deposits	50000	Loan	60000
Term Deposits	10000		

For the Bank
Loan given is Asset
Money of Public in Current A/c is Demand Deposit (Liability)
Money of Public in FD A/c is Term Deposit (Liability)

Different Assets and Liabilities of a Commercial Bank

	BALANCE SHEET				
	LIABILITIES	**AMT**	**ASSETS**	**AMT**	
Initial Money Invested	Share Capital		Vault Cash		*Cash kept in Bank for Withdrawal by customers*
Sometimes bank borrows money from RBI	Loan taken from Central Bank if any		Deposits with Central Bank		*Amount deposited by Bank with RBI*
Saving Account, Current Account	Demand Deposits		Loans		*Loan Given to Public*
Fixed Deposits/ Recurring Deposits	Term Deposits		Investment in Government Securities		*Amt invested in Government Bonks*
	Total		**Total**		

मुद्रा जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा कौन जारी करता है?

यह सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया जाता है

भारत में करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करते हैं?

- सिक्के भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं
- 1 रुपये के करेंसी नोट भी भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं
- सभी शेष करेंसी नोट सेंट्रल बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं

Who issues this Note?
Reserve Bank of India (Central Bank)

What line does it contain?
It contains a line
I promise to pay the bearer the Sum of 500 Rupees
This is Signed by Governor

Promise to Pay
RBI has to pay
So,It means it's a liability of RBI

जब आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, तो क्या यह आरबीआई के लिए संपत्ति या देनदारी है?

- यह RBI के लिए एक दायित्व है
- क्योंकि इस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर है 'मैं भुगतान करने का वादा करता हूं'।
- चूंकि, यह भुगतान करने का वादा है, यह आरबीआई के लिए दायित्व है

सेंट्रल बैंक और वाणिज्यिक बैंक के बीच अलग-अलग लेनदेन

लेन-देन मुख्यत: 2 प्रकार के होते हैं

- ऋण लेनदेन

वाणिज्यिक बैंक केन्द्रीय बैंकों से ऋण लेता है

- जमा लेनदेन

वाणिज्यिक बैंक अपना अधिशेष धन केंद्रीय बैंकों के पास जमा करते हैं

Loan Transaction between Central Bank and Commercial Banks

Central Bank Gives loans to Commercial Banks
Commercial Bank use this amount for lending to Public
Example
Suppose RBI provides Loan to SBI @ 6%
SBI provides loan to public @ 11%

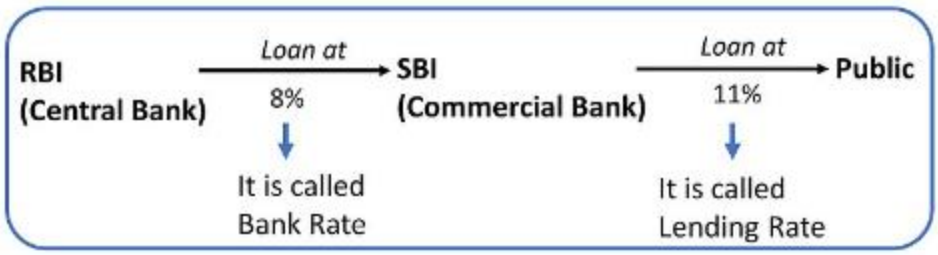

Is Loan given by Central Bank Asset or Liability?

For Central Bank	For Commercial banks
Loan given	it is Loan taken
It is an Assets	Liability

Deposit Transaction between Central Bank and Commercial Banks

Public deposit their money in Savings Account and FD of Banks
Similarly commercial banks deposit their surplus money with Central Bank

Are Deposits of Commercial Bank with Central Bank Assets or Liability ?

For Commercial banks	For Central Bank (RBI)
It is Deposits Made (Assets)	It is Deposits Received (Liability)

सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच जमा लेनदेन

- वाणिज्यिक बैंक अपना अधिशेष धन सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। कभी-कभी सरकार अपनी अधिशेष निधि भी केन्द्रीय बैंक के पास जमा कर देती है।

Different Deposits of Central Bank (RBI)

Deposits of Commercial Bank With Central Bank

Commercial banks deposit their surplus funds with Central Bank

This we have already studied

Deposits of Government Bank With Central Bank

Government deposit their surplus funds with Commercial Bank

This we will study now

Note
Both these deposits are Liabilities of Central Bank

Suppose Government earns Revenue of Rs 1000 Crore from tax and other sources
Out of this, It spends Rs 900 Crore on welfare of public
So it is left with Surplus of 100 Crore
Now, Government deposits these surplus money with Central Bank (RBI)
These are called Treasury Deposits

Government

Revenue	1000
Less	
Expenditure	900
Surplus	**100**

→ *Treasury Deposits* → **Central Bank**

Is this Liability or Assets of Central Bank?
It is Liability
as
RBI has to pay back these deposits to Govt

पैसे की आपूर्ति

- किसी अर्थव्यवस्था में धन में मुख्य रूप से करेंसी नोट, सिक्के और बैंकों में जनता की जमा राशि शामिल होती है। भारत में सिक्के और करेंसी नोट भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रचलन के लिए जारी किए जाते हैं, जो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण (या सेंट्रल बैंक) है।
- एक रुपये का नोट और सभी सिक्के और सहायक सिक्के, जिनका आकार अपेक्षाकृत छोटा है, भारत सरकार द्वारा ढाले/मुद्रित किए जाते हैं, जबकि अन्य सभी मुद्रा नोट आरबीआई द्वारा मुद्रित किए जाते हैं।
- सभी करेंसी नोट और सिक्के केवल आरबीआई के माध्यम से प्रचलन में लाए जाते हैं, जो भारत में मुद्रा और सिक्के जारी करने का एकमात्र प्राधिकरण है।
- एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है (और सरकार द्वारा मुद्रित किया जाता है) इस साक्ष्य के रूप में कि यह मुद्रा प्रणाली की आधार इकाई है।
- सिक्के और एक रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा ढाला/मुद्रित किया जाता है और इसलिए यह भारत सरकार का दायित्व बनता है।
- सर्कुलेशन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, RBI भारत सरकार से एक रुपये का नोट और ढाले हुए सिक्के खरीदता है और इसलिए सिक्के और एक रुपये का नोट RBI की बैलेंस शीट के परिसंपत्ति अनुभाग के अंतर्गत आते हैं।
- आरबीआई द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट (एक रुपये के नोट को छोड़कर) सोने, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों जैसी संपत्तियों द्वारा समर्थित हैं, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33 में परिभाषित किया गया है। "मैं धारक को रुपये का भुगतान करने का वादा करता हूं ... "बैंकनोट धारक के प्रति आरबीआई के दायित्व को दर्शाता है कि आरबीआई बैंकनोट के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। RBI की इस देनदारी की गारंटी RBI अधिनियम, 1934 की धारा 26 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- करेंसी नोटों और सिक्कों का मूल्य इन वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई गारंटी से प्राप्त होता है। प्रत्येक करेंसी नोट पर आरबीआई का एक वादा अंकित होता है कि यदि कोई व्यक्ति आरबीआई या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को नोट पेश करता है, तो आरबीआई उस व्यक्ति को नोट पर मुद्रित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति/मूल्य देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- सिक्कों के लिए भी यही सच है। करेंसी नोटों और सिक्कों का आंतरिक मूल्य नहीं होता है, यानी रुपये के नोट के मामले में कागज के टुकड़े या सिक्के के मामले में लोहे का भौतिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन इसका मूल्य आरबीआई के वादे से प्राप्त होता है। इसलिए करेंसी नोट और सिक्कों को फिएट मनी कहा जाता है। इन्हें कानूनी निविदाएं भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश का कोई भी नागरिक किसी भी ऋण के भुगतान के लिए मना नहीं कर सकता है।

मुद्रा = नोट + सिक्के

प्रचलन में मुद्रा = जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास मुद्रा

किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में धन के कुल भंडार को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है।

RBI ने मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों के आंकड़े प्रकाशित किए। वे इस प्रकार हैं: M1 = जनता के पास मुद्रा + बैंकों के पास जनता की मांग जमा

एम2 = एम1 + डाकघर बचत बैंक में बचत जमा

एम3 = एम1 + बैंकों में जनता की सावधि जमा

एम4 = एम3 + डाकघर बचत बैंक में कुल जमा

केवल बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि (व्यवसाय भी शामिल है) धन आपूर्ति का हिस्सा है और अंतर-बैंक जमा को बाहर रखा गया है। वाणिज्यिक बैंकों के नकद भंडार को धन आपूर्ति के एक घटक के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि धन के रचनाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (आरबीआई, सरकार और बैंकों) द्वारा रखी गई नकदी को कभी भी धन आपूर्ति के घटक के रूप में नहीं माना जाता है।

- M1 सबसे अधिक तरल है और M4 सबसे कम तरल है।
- M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है।
- M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और इसे "समग्र मौद्रिक संसाधन" भी कहा जाता है।
- 1 से 4 तक की संख्या तरलता के घटते क्रम में है।
- अब RBI द्वारा अधिकतर M1 और M3 शब्दों का उपयोग किया जाता है

Procedure Followed By Central Bank To Issue Currency

When Govt wants to print a currency,
it gives securities to the RBI (called Govt Security)
against which RBI issues currency

Example

Suppose Govt issues Securities for Rs 100 Crore to RBI
RBI issues currency notes of Rs 100 Crore and gives it to bank.
Bank issues 80 Crore notes to Public and keep 20 Crore in its Safety Vault

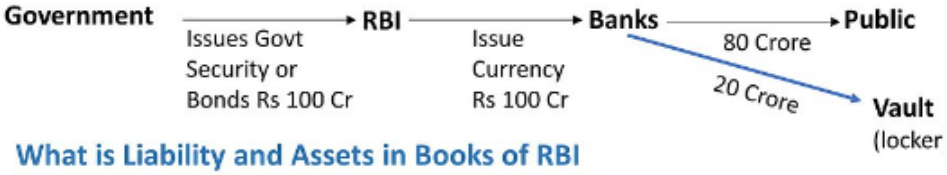

What is Liability and Assets in Books of RBI

BALANCE SHEET			
LIABILITIES	**AMT**	**ASSETS**	**AMT**
Currency Held by Public	80	Government Securities	100
Vault Cash held by Commercial banks	20		
Total	**100**	**Total**	**100**

सोने और विदेशी मुद्रा के बदले जारी की गई मुद्रा

Sometimes, Central Bank purchases Gold and Foreign exchange from market against which it issues currency

Example

Suppose RBI purchase gold from Market of Rs 140 Crore and Gold of 60 Crore.
Against this 100 Crore , it issues currency to Public of 200 Crore as show below

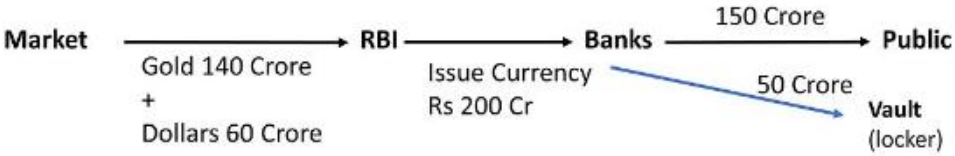

What is Liability and Assets in Books of RBI

BALANCE SHEET OF RBI			
LIABILITIES	**AMT**	**ASSETS**	**AMT**
Currency Held by Public	150	Gold	140
Vault Cash held by Commercial banks	50	Foreign Currency	60
Total	**200**	**Total**	**200**

मनी सर्कुलेशन

- अब आइए देखें कि व्यक्तियों/जनता, बैंकों और आरबीआई के बीच पैसा कैसे प्रसारित होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास रुपये का भौतिक सोना है। 500. वह इस भौतिक सोने को आरबीआई के पास जमा करता है और आरबीआई उसे रुपये के मूल्य का मुद्रा नोट जारी करता है। 500. (वैकल्पिक रूप से, यह भी कहा जा सकता है कि, आरबीआई ने बाजार से 500 रुपये का सोना खरीदा और जनता/व्यक्ति को 500 रुपये का नोट जारी किया)।

इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है:

Individual

Rs. 500 Note

Commercial Bank

Assets	Liability

RBI

Assets	Liability
Gold = Rs. 500	Currency held by Public = Rs. 500
Rs. 500	Rs. 500

Money Supply = Rs. 500

मान लीजिए कि व्यक्ति सोचता है कि उसे केवल रुपये की आवश्यकता है। उनके नकद लेनदेन और जमा के लिए 200 रु. सुरक्षा उद्देश्य और ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक में 300 रु.

इसे निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है:

Individual

Rs. 200 Note + Rs. 300 in A/c

Commercial Bank

Assets	Liability
Vault Cash = Rs. 300	Deposits of Public = Rs. 300
Rs. 300	Rs. 300

RBI

Assets	Liability
Gold = Rs. 500	Currency held by Public = Rs. 200 Vault Cash held by banks = Rs. 300
Rs. 500	Rs. 500

Money Supply = Rs. 500

मान लीजिए कि बैंक को केवल रुपये की आवश्यकता है। जनता की रोजमर्रा की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए 100 रु. जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई के पास 200 रु. इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

Individual

Rs. 200 Note + Rs. 300 in A/c

Commercial Bank

Assets	Liability
Vault Cash = Rs. 100 Deposits with RBI = Rs. 200	Deposits of Public = Rs. 300
Rs. 300	Rs. 300

RBI

Assets	Liability
Gold = Rs. 500	Currency held by Public = Rs. 200 Vault Cash held by banks = Rs. 100 Deposits of bank = Rs. 200
Rs. 500	Rs. 500

Money Supply = Rs. 500

मान लीजिए सरकार. रुपये एकत्र करता है. व्यक्ति से 50 रुपये टैक्स वसूला जाता है और यह पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है।

Individual Commercial Bank RBI

Rs. 150 Note + Rs. 300 in A/c

Money Supply = Rs. 450

Assets	Liability
Vault Cash = Rs. 100 Deposits with RBI = Rs. 200	Deposits of Public = Rs. 300
Rs. 300	Rs. 300

Assets	Liability
Gold = Rs. 500	Currency held by Public = Rs. 150 Vault Cash held by banks = Rs. 100 Deposits of bank = Rs. 200 Deposits of Govt. (Treasury Deposits) = Rs. 50
Rs. 500	Rs. 500

आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए अपनी सोने की संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच सकता है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

Individual Commercial Bank RBI

Rs. 150 Note + Rs. 300 in A/c

Money Supply = Rs. 450

Assets	Liability
Vault Cash = Rs. 100 Deposits with RBI = Rs. 200	Deposits of Public = Rs. 300
Rs. 300	Rs. 300

Assets	Liability
Gold = Rs. 100 Foreign Exchange Reserve = Rs 200 Govt. Securities = Rs. 200	Currency held by Public = Rs. 150 Vault Cash held by banks = Rs. 100 Deposits of bank = Rs. 200 Deposits of Govt. (Treasury Deposits) = Rs. 50
Rs. 500	Rs. 500

देश के मौद्रिक प्राधिकरण (RBI) की कुल देनदारी को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या आरक्षित मुद्रा [M0] कहा जाता है। और उपरोक्त उदाहरण में मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाली मुद्रा रु. 500 और धन आपूर्ति रु. 450.

मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक आधार दो अलग-अलग शब्द हैं; धन की आपूर्ति जनता के पास नकद या बैंकों में जमा राशि के रूप में होती है और मौद्रिक आधार [एम0] आरबीआई की कुल देनदारी है।

आइए एक और उदाहरण लें:

सेंट्रल बैंक की विभिन्न देनदारियाँ

बैंक से जमा

- बैंकों के पास अधिशेष धनराशि सेंट्रल बैंक के पास जमा की जाती है
- तो यह सेंट्रल बैंक के लिए एक दायित्व है

Sample Balance Sheet of Central Bank

BALANCE SHEET -RBI			
Liabilities	**Amt**	**Assets**	**Amt**
Currency Held by Public	90000	Gold	25000
Vault Cash held by Commercial Banks	20000	Foreign Exchange	20000
Deposits of Commercial bank with Central Bank	10000	Government Securities	100000
Treasury Deposits of Govt of India	37500	Loan to Commercial Banks	12500
Total	**157500**	**Total**	**157500**

Cash with Public ← Currency Held by Public

Cash with Bank Locker ← Vault Cash held by Commercial Banks

Bank deposit amt with RBI ← Deposits of Commercial bank with Central Bank

Govt deposit amt with RBI ← Treasury Deposits of Govt of India

Gold → *Gold purchased from Market*

Foreign Exchange → *Forex Purchased from Market*

Government Securities → *Govt Bonds (Loan Given to Govt)*

Loan to Commercial Banks → *Amt invested in Government Bonks*

*Liabilities of Central Bank are called **High Powered Money***

जनता द्वारा धारित मुद्रा एवं सिक्के

- करेंसी नोट सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं
- ये नोट में उल्लिखित एएमटी के बराबर मूल्य के वाहक के वादे हैं
- तो, यह दायित्व भी है

वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी तिजोरी नकदी

- विभिन्न बैंकों द्वारा लॉकर में रखी गई नकदी को वॉल्ट कैश कहा जाता है
- ये सेंट्रल बैंक के लिए भी दायित्व हैं क्योंकि इन्हें सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया है

सेंट्रल बैंक की विभिन्न संपत्तियाँ

सरकारी प्रतिभूतियाँ

- सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार के लिए ऋण की तरह हैं
- जब सरकार कोई मुद्रा छापना चाहती है, तो वह केंद्रीय बैंक को प्रतिभूतियाँ देती है (जिन्हें सरकारी सुरक्षा कहा जाता है)
- जिसके विरुद्ध केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है
- तो यह सरकारी सुरक्षा सेंट्रल बैंक द्वारा सरकार को दिए गए ऋण की तरह है

सोना और विदेशी मुद्रा

- सेंट्रल बैंक बाजार से सोना और विदेशी मुद्रा खरीदता है जिसके बदले वह मुद्रा जारी करता है

बैंकों को ऋण

- सेंट्रल बैंक विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है जिसके लिए वह ब्याज अर्जित करता है
- चूँकि, यह ऋण दिया गया है। यह एक संपत्ति है

उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या मौद्रिक आधार क्या है [M0]

सेंट्रल बैंक की कुल देनदारी को उच्च मौद्रिक मुद्रा या मौद्रिक आधार कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- जनता के पास प्रचलन में मुद्रा नोट
- बैंकों के पास नकदी जमा करना
- विभिन्न बैंकों द्वारा सेंट्रल बैंक में जमा राशि
- सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक में जमा राशि

Difference between Money and High Powered Money

Money	High Powered Money
It includes CU +DD (Currency +Demand Deposits of Public)	It includes Currency Notes +Deposits of banks Deposits of Govt *(It doesn't include demand deposits of Public)*

धन सृजन एवं धन गुणक

मुद्रा जमा अनुपात (सीडीआर)

मुद्रा जमा अनुपात (सीडीआर) = जनता द्वारा धारित मुद्रा/बैंकों में जनता की जमा राशि।

It is the Ratio of
Money held by Public in Currency
to
Money held by Public in Deposits

$$\text{Currency Deposit Ratio} = \frac{\text{Money held by Public in currency}}{\text{Money held by Public in Deposits}}$$

$$CDR = \frac{CU}{DD}$$

Example

Suppose a person earns Rs 100000 Salary in Cash
He spends Rs 80000 in cash
He deposits balance Rs 20000 in his bank account

In this case

$$\text{Currency Deposit Ratio} = \frac{\text{Money held by Public in currency}}{\text{Money held by Public in Deposits}} = \frac{80000}{20000} = 4$$

1 के बराबर सीडीआर का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ राशि नकद मिलती है, जैसे रु। 100, तो वह रुपये रखेगा. 50 नकद और रु. बैंकों में जमा राशि 50 रुपये है, ताकि हाथ में नकदी और बैंकों में जमा का अनुपात 50 रुपये/50 = 1 हो

क्या सीडीआर हमेशा एक समान रहती है?

नहीं, इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। उदाहरण- त्योहारी सीजन के दौरान यह बढ़ जाता है (क्योंकि लोग अधिक खर्च करते हैं)।

आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर)

- आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर) = बैंकों का आरक्षित/बैंकों में जनता की जमा राशि
- मान लीजिए, आरडीआर 0.2 या 20% के बराबर है, इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति एक निश्चित राशि, मान लीजिए रु. जमा करता है। बैंक को 100 रुपये अपने पास रखने होंगे. 20 आरक्षित धन के रूप में और शेष रु. 80 वे किसी और को उधार दे सकते हैं।
- बैंकों का "आरक्षित धन" बैंकों में तिजोरी नकदी के रूप में हो सकता है या वे आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं या सरकार के पास रख सकते हैं

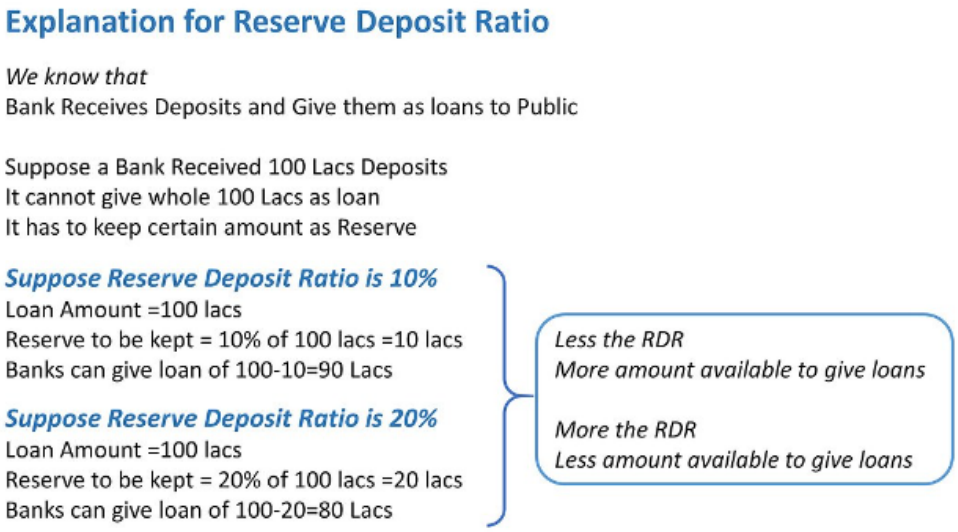

टिप्पणी:

- सीडीआर जितनी अधिक होगी, जनता के पास नकदी उतनी ही अधिक होगी।
- आरडीआर जितना अधिक होगा, बैंकों के पास ऋण देने के लिए उतनी कम राशि होगी।
- अब हम मौद्रिक प्राधिकरण यानी आरबीआई द्वारा धन सृजन के तंत्र को समझेंगे। मान लीजिए कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है। आइए मान लें कि आरबीआई कुछ संपत्तियां खरीदता है, जैसे सरकारी बांड या रुपये का सोना। एच बाजार से और बदले में रुपये के मूल्य का मुद्रा नोट जारी करता है। उस व्यक्ति को H (P1).

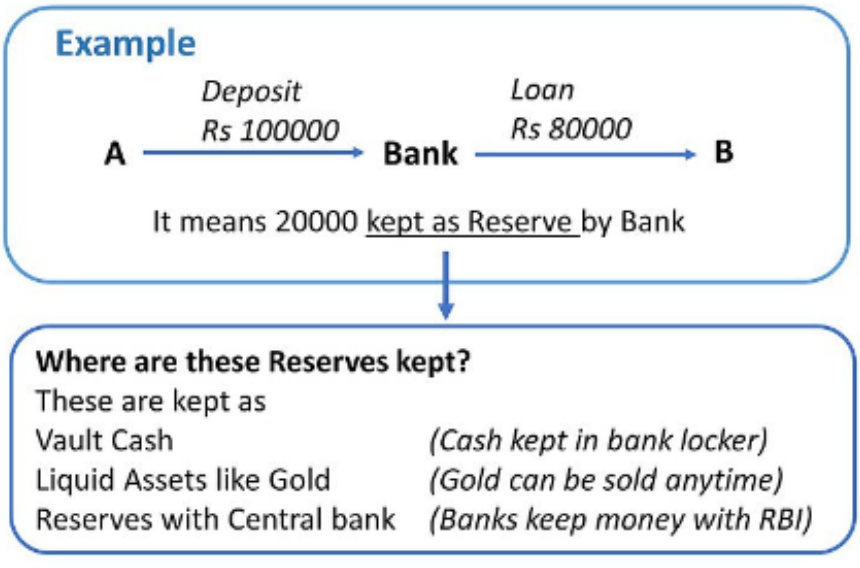

- तो, इस स्थिति में, धन आपूर्ति H है और मौद्रिक आधार भी H है। अब, चूंकि हमने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में CDR 1 है, पहला व्यक्ति (P1) आधा पैसा नकद के रूप में रखेगा और आधा वह जमा करेगा। बैंक के साथ.
- और यदि बैंक सभी जमा धन को नकद रूप में अपनी तिजोरी में रखता है, तो धन की आपूर्ति H होगी।

	Currency with Public	Vault Cash	Deposits of Public	Total Money Supply
P1	H/2	H/2 ←	H/2	H

यदि आरडीआर 20% है, तो बैंक अपनी तिजोरी में जमा धन का केवल 20% नकद (आरक्षित धन) के रूप में रखेगा और बाकी किसी अन्य व्यक्ति (पी2) को उधार देगा।

तो, अब पहले व्यक्ति के पास पैसा H (H/2 नकद के रूप में और H/2 जमा के रूप में) है और दूसरे व्यक्ति (P2) के पास पैसा 0.8 (H/2) यानी 0.4 H है। तो, अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति H से बढ़कर H + 0.4H = 1.4H हो जाती है।

ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बैंकों को यह छूट दी गई है कि वे जमा किए गए धन का केवल कुछ हिस्सा ही अपनी तिजोरियों में आरक्षित रखें और बाकी को वे दूसरों को उधार दे सकते हैं। (इसे "फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग" कहा जाता है)।

इसलिए, फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग के माध्यम से अतिरिक्त धन सृजित हो रहा है। इसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है

	Currency with Public	Vault Cash	Deposits of Public	Total Money Supply
P1	H/2	0.2 (H/2) ←	H/2	H
		money creation		
P2	0.8 (H/2)			

अब व्यक्ति P2 फिर से बैंक से प्राप्त धन का केवल आधा हिस्सा नकद के रूप में रखेगा और बाकी वह बैंक में जमा कर देगा। बैंक फिर से जमा धन का केवल 20% ही अपनी तिजोरी में आरक्षित रखेगा और बाकी को किसी तीसरे व्यक्ति (P3) को उधार देगा। तीसरा व्यक्ति P3 फिर से बैंक से प्राप्त धन का केवल आधा हिस्सा नकद के रूप में रखेगा और बाकी वह बैंक में जमा कर देगा और यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में अंतहीन रूप से चलती रहेगी। इसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

	Currency with Public	Vault Cash	Deposits of Public	Money Supply
P1	H/2	0.2 (H/2) ←	H/2	H
P2	1/2(0.8 (H/2))	0.2/2 (0.8 (H/2)) ←	1/2(0.8 (H/2))	0.8 (H/2)
P3	0.8/2 (0.8 (H/2))	.	.	.
P4	.	.	.	.
.				
.	.	.	.	.
Sum	1/2 (5H/3)	0.2/2 (5H/3)	1/2 (5H/3)	**5H/3**

(कुल) धन आपूर्ति = 5H/3

मौद्रिक आधार [M0] = H

$$\text{Money Multiplier} = \frac{\text{Money Supply (M3)}}{\text{Monetary Base (Reserve Money M0)}} = \frac{(5H/3)}{H} = 5/3$$

इसलिए, शुरुआत में एच मौद्रिक आधार और एच धन आपूर्ति के साथ, आरबीआई फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के माध्यम से धन आपूर्ति को 5H/3 तक बढ़ाने/बनाने में सक्षम रहा है। तो, मुद्रा आपूर्ति अब मौद्रिक आधार का 5/3 गुना है, इसलिए धन गुणक 5/3 है।

यदि RBI धन आपूर्ति को और बढ़ाना चाहता है तो वह RDR को 0.2 से कम कर देगा और यदि वह धन आपूर्ति को कम करना चाहता है तो वह RDR को बढ़ा देगा।

जैसा कि हम जानते हैं, बैंक रिजर्व में दो चीजें शामिल होती हैं - उनकी तिजोरियों में नकदी और बैंकों की आरबीआई के पास जमा राशि। इसलिए आरडीआर को दो भागों सीआरआर (आरबीआई के पास रखा गया) और एसएलआर (बैंकों के पास रखा गया) में बांटा गया है।

नोट: वर्तमान में, आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर) = 22.5% (सीआरआर = 4.5%, एसएलआर = 18%)

मुद्रा स्फ़ीति

- मुद्रास्फीति को वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि की दर के रूप में परिभाषित किया गया है।

आइए एक उदाहरण लें:

- यदि पिछले वर्ष बादाम की कीमत 1500 प्रति किलोग्राम थी और वर्तमान में यह 1800 प्रति किलोग्राम है, तो बादाम की दर में मुद्रास्फीति होगी:
  - लागत में वृद्धि: 1800-1500=300
  - इसलिए बादाम में मुद्रास्फीति: (300/1500)*100=20%

अपस्फीति- जब समग्र मूल्य स्तर इस प्रकार घट जाता है कि मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है, तो इसे अपस्फीति कहा जाता है। यह मुद्रास्फीति के विपरीत है.

डिस-इन्फ्लेशन- यह मुद्रास्फीति की दर में मंदी है।

उदाहरण के लिए: यदि प्रति किलोग्राम सेब की कीमत है: 2019 में 160 रुपये, 2018 में 158 रुपये, 2017 में 156 रुपये और 2016 में 154 रुपये।

- तो वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति है: [(156-154)/154]*100=1.30 %
- वर्ष 2018 में मुद्रास्फीति है: [(158-156)/156]*100=1.28 %
- वर्ष 2019 में मुद्रास्फीति है: [(160-158)/158]*100=1.26%
- इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति की दर कम हुई है लेकिन सेब की कीमतें बढ़ी हैं। यह अवस्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

महँगाई के कारण

दो परिदृश्यों पर विचार करें:

1. अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाती है तो वह गिटार जैसे और सामान खरीदने के बारे में सोच सकता है जिसे वह पहले नहीं खरीद पाता था। तो गिटार की मांग बढ़ जाएगी और गिटार बेचने वाले के पास उसकी दुकान में बहुत कम गिटार होंगे इसलिए वह गिटार की कीमत बढ़ा देगा। इस प्रकार, मुद्रास्फीति गिटार बाजार में प्रवेश करती है। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है।

2. जब बाजार में अनाज, खाद्य उत्पाद आदि वस्तुओं की कमी हो, लेकिन मांग लगातार बनी रहे। फिर विक्रेता भी इन वस्तुओं को बहुत ऊंचे दाम पर बेचता है। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है।

अत: मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण हैं-

- मांग खींचें कारक
- लागत बढ़ाने वाले कारक

डिमांड पुल मुद्रास्फीति के पीछे कारण

यह आम तौर पर क्रय शक्ति में वृद्धि यानी लोगों के हाथों में अधिक पैसा आने के कारण होता है।

1. सरकारी खर्च: जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार स्तनपान कराने वाली माताओं (जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है) को 6000 रुपये देती है। ये नई माताएं निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए जॉनसन के शिशु उत्पाद खरीदेंगी और चूंकि इन उत्पादों की मांग बढ़ेगी, इससे इन सामानों की लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह, पेंशन, विधवा भत्ता और ऋण माफी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार विभिन्न लाभार्थियों को हजारों करोड़ रुपये देती है। इस प्रकार, लोगों को अतिरिक्त आय मिलती है और इसलिए बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

2. घाटे का वित्तपोषण: घाटे के वित्तपोषण में सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जननी सुरक्षा योजना आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से ऋण मिलता है। इसलिए यह अतिरिक्त पैसा लोगों तक पहुंचता है और मांग बढ़ाता है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

3. काला धन: जब सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं, तो उनके हाथ में पैसा (और क्रय शक्ति) बढ़ जाएगी और इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इसके अलावा, अगर हम टैक्स बचाने के लिए अपनी आय छिपाते हैं, तो हमारे पास अधिक पैसा होता है जो अन्यथा सरकार के पास चला जाता। इसलिए मांग बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है.

4. अधिक जनसंख्या: जितनी अधिक लोगों की संख्या उतनी अधिक मांग।

5. विदेशी निवेश में वृद्धि: अगर एप्पल जैसे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे तो अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उन्हें उच्च वेतन मिलेगा जिससे उनकी क्रय शक्ति और मांगें बढ़ेंगी।

6. अतिरिक्त तरलता: तरलता का अर्थ है धन की आपूर्ति। आरबीआई की घटती ब्याज दरों जैसी मौद्रिक नीतियों के कारण बाजार में धन की आपूर्ति (अंततः लोगों के पास) बढ़ जाती है।

लागत वृद्धि मुद्रास्फीति के कारण

यह आम तौर पर वस्तुओं की कमी के कारण होता है।

1. मौसमी अनियमितताएँ (मानसून) - मानसून में किसी भी परिवर्तनशीलता से फसल उत्पादन प्रभावित होगा और मूल्य में विकृति आ सकती है।

2. जमाखोरी- आपूर्ति कम करने और कृत्रिम मूल्य वृद्धि का कारण बनने के लिए वितरकों द्वारा अपने गोदामों में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी लागत वृद्धि मुद्रास्फीति के मुख्य कारणों में से एक है।

3. कार्टेलाइजेशन- यह बाजार में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए विक्रेताओं द्वारा कीमतें तय करना है। इससे कृत्रिम मूल्य वृद्धि होती है क्योंकि बाजार में कोई मोलभाव उपलब्ध नहीं है।

4. डीजल की कीमतों में वृद्धि- इससे वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ जाती है और वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है।

5. आयातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि- उदाहरण के लिए यदि दक्षिण कोरिया से आयात किए जाने वाले सैमसंग फोन की कीमत बढ़ जाती है तो स्थानीय बाजारों में कीमत बढ़ जाती है।

Effects of Inflation

1. Effect on bank rates-

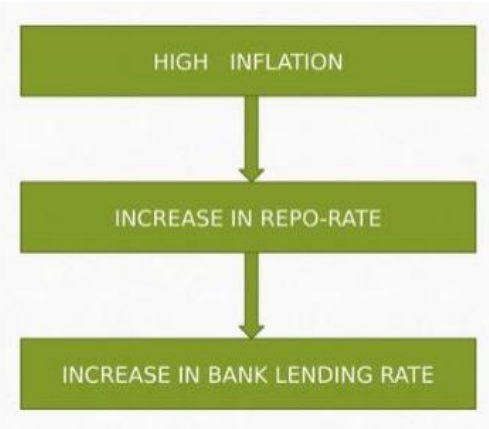

2. **Effect on government**

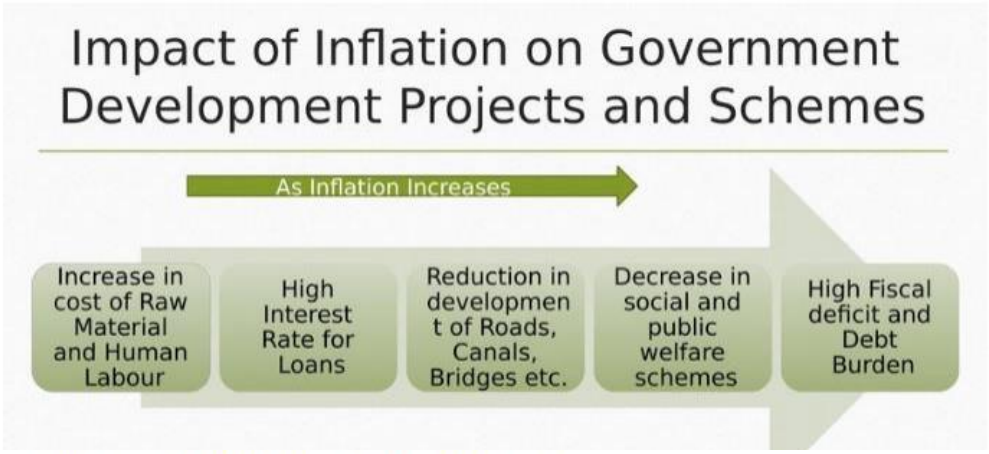

3. **Impact of Inflation on Industries**

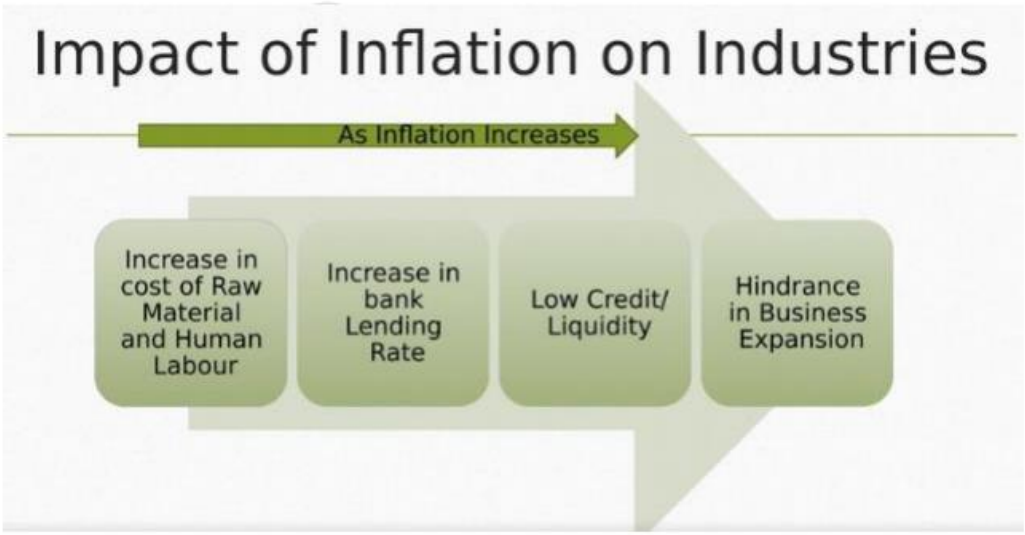

4. **Impact of Inflation on Growth of the Country**

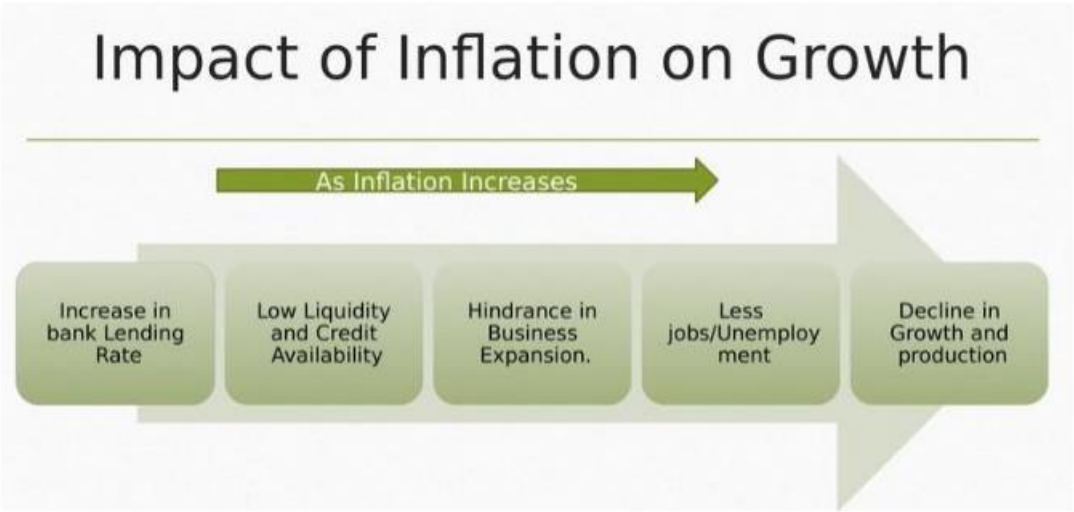

मुद्रास्फीति मापने के तरीके

मुद्रास्फीति मापने के दो तरीके हैं.

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)
2. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)

यह घरों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की बाजार टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है और इंगित करता है। यहां कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं:

- भोजन
- पेय पदार्थ
- कपड़े
- ईंधन
- वाहन
- इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि।

उपरोक्त वस्तुओं का उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है:

भोजन > ईंधन > पेय पदार्थ > कपड़े > इलेक्ट्रॉनिक्स > वाहन

- सीपीआई में उपभोक्ताओं यानी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऐसी सभी वस्तुओं की कीमत को एक साथ जोड़ दिया जाता है और अलग-अलग वस्तुओं को उनके महत्व और प्राथमिकता के अनुसार अलग-अलग महत्व दिया जाता है। इस प्रकार, ये सभी वस्तुएं मिलकर सीपीआई की उपभोग टोकरी बनाती हैं। उपभोग टोकरी में सैकड़ों उत्पाद होते हैं जिन्हें हम साल भर में खरीदते हैं सीपीआई के माध्यम से, नागरिकों और सरकार को उन दैनिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दर के बारे में पता चलता है जो लोग खरीदते हैं।
- सीपीआई खुदरा बाजार में अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में बदलाव को मापता है। चूँकि विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न भिन्न-भिन्न होते हैं; कीमत में अंतर हो सकता है उपभोग की वस्तुओं की टोकरी में वृद्धि गरीब लोग और अमीर लोग।
- इसलिए, भारत में, पहले हमारे पास विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए तीन सीपीआई सूचकांक थे, और बाद में 2010 में हमने 3 नए सीपीआई सूचकांक डिजाइन किए। सीपीआई की विभिन्न श्रंखलाएं हैं जिनकी गणना मासिक आधार पर की जाती है:
- सीपीआई - औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू): यह सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली कमोडिटी बास्केट की कीमत में बदलाव को मापता है
- सीपीआई - कृषि मजदूर (सीपीआई -एएल): यह सूचकांक कृषि मजदूरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु टोकरी की कीमत में बदलाव को मापता है
- सीपीआई - ग्रामीण मजदूर: यह सूचकांक ग्रामीण मजदूरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु टोकरी की कीमत में बदलाव को मापता है
- ये सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। चूँकि उपरोक्त तीन सूचकांकों ने जनसंख्या के केवल एक हिस्से को कवर किया, न कि समग्र राष्ट्र को, सीपीआई के तीन और सूचकांक डिजाइन किए गए-
- सीपीआई - ग्रामीण: यह सूचकांक ग्रामीण आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु टोकरी की कीमत में बदलाव को मापता है
- सीपीआई - शहरी: यह सूचकांक शहरी आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु टोकरी की कीमत में बदलाव को मापता है
- सीपीआई - संयुक्त: इसकी गणना सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी सूचकांक को मिलाकर की जाती है

नोट-उपरोक्त तीन सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2011-12 है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। मुद्रास्फीति की निगरानी के लिए आरबीआई सीपीआई-संयुक्त का उपयोग करता है

सीपीआई-आईडब्ल्यू

- सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) के निर्धारण के अलावा खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने, अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए किया जाता है।
- सीपीआई-आईडब्ल्यू को श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय, श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और रखरखाव किया जाता है।

सीपीआई का उपयोग करने के लाभ

- सीपीआई खुदरा कीमतों से संबंधित है जो हर किसी की जेब पर असर डालती है। अगर 1 किलो प्याज की कीमत 30 रुपये से बढ़कर 80 रुपये हो जाती है तो इससे आम लोगों के मासिक बजट पर असर पड़ेगा. इसलिए सीपीआई लोगों के जीवन स्तर को निर्धारित करता है क्योंकि इसमें उन वस्तुओं की लागत शामिल होती है जिनसे लोगों का कोयला आदि जैसे खनिज संसाधनों के विपरीत सीधा संबंध होता है। इसलिए यदि सीपीआई को मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और अचानक यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो सरकार कर सकती है। कीमतें कम करके या सब्सिडी के माध्यम से सस्ते भोजन की उपलब्धता की व्यवस्था करें।
- चूंकि सीपीआई सीधे लोगों की जेब को प्रभावित करती है, इसलिए इसका उनके निवेश व्यवहार पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन की कीमतें बहुत अधिक हो जाती हैं, तो लोगों को भोजन खरीदने के लिए अधिक राशि खर्च करनी होगी। इस प्रकार, वे बैंकों में कम बचत करेंगे, म्यूचुअल फंड और अन्य बीमा योजनाओं में कम निवेश करेंगे। इसलिए यदि सीपीआई को मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आरबीआई और सरकार मुद्रास्फीति को कम करने के लिए त्वरित निर्णय ले सकते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कैसे की जाती है?

- सीपीआई की गणना आधार वर्ष के संदर्भ में की जाती है, जिसका उपयोग बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। मूल्य परिवर्तन उस वर्ष से संबंधित है। याद रखें, जब आप सीपीआई की गणना करते हैं, तो ध्यान दें कि 1 वर्ष में टोकरी की कीमत को पहले आधार वर्ष की बाजार टोकरी की कीमत से विभाजित किया जाना चाहिए। फिर, इसे 100 से गुणा किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सूत्र:

सीपीआई = (आधार वर्ष में टोकरी की लागत से विभाजित टोकरी की लागत) 100 से गुणा किया गया

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

- यह थोक बाजार के मूल्य स्तर में बदलाव को मापता है और इंगित करता है यानी वे सामान जो थोक में बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच कारोबार किया जाता है। हम जानते हैं कि थोक बाज़ार में सामान की कीमत खुदरा दुकानों की तुलना में कम होती है।
- हालाँकि, आम तौर पर लोग थोक बाज़ार से सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि ये सामान केवल थोक में ही बेचे जाते हैं। प्रत्येक वस्तु जनता तक पहुँचने से पहले, पहले एक थोक विक्रेता के पास जाती है जो फिर उस सामान को विभिन्न स्थानीय दुकानों में वितरित करता है।
- WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच अंतर:

1. सीपीआई = डब्ल्यूपीआई + परिवहन की लागत + खुदरा विक्रेता का मार्जिन

2. सीपीआई की कमोडिटी बास्केट डब्ल्यूपीआई बास्केट से कम है।

उदाहरण के लिए: खनिजों का उपभोग सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता है इसलिए उन्हें सीपीआई बास्केट में शामिल नहीं किया जाता है।

3.CPI में सेवाएँ भी शामिल हैं जबकि WPI में नहीं।

उदाहरण के लिए- आपको किसी भी संस्थान में कोचिंग के लिए फीस का भुगतान करना होगा, इसलिए शिक्षण सेवा एक उपभोग सेवा है और अन्य वस्तुओं के विपरीत इसे पहले थोक बाजार में नहीं लाया जाता है और फिर कोचिंग सेंटरों में वितरित किया जाता है। सेवाएँ सीधे कोचिंग सेंटरों को दी जाती हैं।

WPI का उपयोग करने के लाभ

1. इसमें सीपीआई की तुलना में कई अधिक सामान शामिल हैं

2. डेटा साप्ताहिक उपलब्ध है, जबकि सीपीआई डेटा मासिक उपलब्ध है। इसलिए, WPI का उपयोग करके तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाया गया है।

3. WPI की गणना अखिल भारतीय आधार पर की जाती है जबकि CPI की गणना विशिष्ट केंद्रों के लिए की जाती है और फिर अखिल भारतीय सूचकांक में एकत्रित की जाती है।

इसलिए WPI पूरे भारत में व्याप्त मुद्रास्फीति की स्थिति की बेहतर तस्वीर देता है। नोट- 2015 से, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर सरकार ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सीपीआई का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

महँगाई पर नियंत्रण के उपाय

- आरबीआई बाजार में तरलता को विनियमित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है।
- सरकार सरकारी खर्चों और खर्चों को बढ़ाने या घटाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती है।
- वस्तुओं की जमाखोरी को नियंत्रित करना जिससे बाजार में वस्तुओं का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे मुद्रास्फीति के लागत कारक कम हो जाते हैं।
- बाजार में खाद्य उत्पादों की पर्याप्त उपज बनाए रखने के लिए मौसमी परिवर्तनों और मानसून की अनियमितताओं के खिलाफ किसानों की मदद करने के लिए सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना।

मौद्रिक नीति

- मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण (RBI) अर्थव्यवस्था में धन के निर्माण और आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
- आरबीआई खुले बाजार संचालन, बैंक दर नीति, सीआरआर, एसएलआर, आरक्षित प्रणाली, क्रेडिट नियंत्रण नीति, नैतिक अनुनय आदि के माध्यम से मौद्रिक नीति लागू करता है।

मौद्रिक नीति का उद्देश्य

- आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए - स्वस्थ मुद्रास्फीति सीमा को लक्षित करके।
- विकास के उद्देश्य के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना।
- इष्टतम मुद्रास्फीति स्तर को बनाए रखते हुए बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना।
- आर्थिक विकास को समर्थन देने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- एमपीसी 2016 में आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था है।
- एमपीसी को मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते में परिभाषित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक रेपो दर (नीतिगत दर) तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- एमपीसी की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती हैं और यह ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णय प्रकाशित करती है।
- एमपीसी में 6 सदस्य हैं, तीन आरबीआई से (आरबीआई गवर्नर सहित) और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- सभी सदस्यों का एक वोट होता है और वोट बराबर होने की स्थिति में राज्यपाल को दूसरा या निर्णायक वोट मिलता है।
- एमपीसी का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी है।
- एमपीसी के पास केवल रेपो रेट तय करने का अधिकार है, सीआरआर या एसएलआर का नहीं।

एमपीसी की संरचना

एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:

- आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में,
- मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर,
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी,

केंद्र सरकार द्वारा तीन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

- नियुक्तियों की यह श्रेणी "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले योग्य, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों" से होनी चाहिए।

मुद्रास्फीति का लक्ष्य

- मुद्रास्फीति का लक्ष्य आरबीआई गवर्नर से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है।
- समिति का वर्तमान अधिदेश 6% की अधिकतम बैंडविड्थ और 2% की न्यूनतम सीमा के साथ 4% वार्षिक मुद्रास्फीति बनाए रखना है।
- यदि लक्ष्य विफल हो जाता है: यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक 4% +/- 2% क्षेत्र में नहीं रहती है तो समिति को सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी। कारणों और उपायों के साथ और एक अनुमानित समय अवधि जिसके भीतर लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
- मुद्रास्फीति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एनएसओ-राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) द्वारा प्रकाशित "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) - संयुक्त" है।

निम्नलिखित प्रमुख उपकरण/उपकरण हैं जिनका उपयोग आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के संचालन के लिए करता है:

- गुणात्मक उपकरण
- मात्रात्मक उपकरण

गुणात्मक उपकरण:

1. ऋण से मूल्य अनुपात नियंत्रण: यदि कोई रुपये की बाइक खरीदना चाहता है। 60000 का ऋण लेता है और इसके लिए उसे ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में बैंक को संपार्श्विक देना होगा। आरबीआई रुपये का ऋण लेने के लिए आवश्यक संपार्श्विक राशि को अनिवार्य करता है। 60000. मान लीजिए रु. 60000 का लोन लेने के लिए 1 लाख गिरवी रखनी पड़ती थी. आप 1 लाख रुपये की संपत्ति के कागजात अपने पास रख सकते हैं. 1 लाख और लोन ले लो. हालाँकि, यदि RBI कहता है कि केवल रु. रुपये की संपार्श्विक के लिए 20,000 ऋण। 1 लाख ले सकते हैं तो लोन न लें. इस प्रकार RBI बैंकों द्वारा लोगों को वितरित किये जाने वाले ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है।
2. उपभोक्ता ऋण नियंत्रण: फिर, यदि कोई रुपये की बाइक खरीदना चाहता है। 60000, होंडा कंपनी उनसे 10% का डाउन-पेमेंट और बाकी ऋण के रूप में देने के लिए कहती है। अब यदि आरबीआई आदेश देता है कि बाइक खरीदने के लिए 30% का डाउन-पेमेंट आवश्यक है तो किसी के पास डाउन-पेमेंट का भुगतान करने के लिए 30% हाथ में नहीं होगा। इसलिए वह व्यक्ति बाइक नहीं खरीदेगा। इस प्रकार आरबीआई उपभोक्ता व्यवहार को नियंत्रित करता है।
3. राशनिंग: इसमें बैंकों को अनिवार्य रूप से कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक ऋण देने के लिए कहना शामिल है। उदाहरण के लिए, आरबीआई प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के माध्यम से कृषि ऋण को 18% से बढ़ाकर 30% करने के लिए कह सकता है, जिससे उस क्षेत्र में अधिक धन उपलब्ध हो सके।
4. नैतिक दबाव: कभी-कभी आरबीआई द्वारा रेपो दर कम करने के बाद भी बैंक ऋण दरों में कमी नहीं करते हैं। इसलिए रेपो रेट का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और आरबीआई मुद्रास्फीति को लक्षित नहीं कर सकता है। ऐसे में आरबीआई गवर्नर किसी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू या किसी कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं कि वह देश में महंगाई की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और महंगाई में कमी लाने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। इस तरह RBI अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों को नीतिगत दरों का पालन करने के लिए धमकाता है अन्यथा बाद में RBI उनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई करेगा।
5. सीधी कार्रवाई: अब, अगर इतनी धमकी के बाद भी बैंक आरबीआई की बात नहीं मानते हैं, तो आरबीआई उन्हें अपनी बात मानने के लिए बैंकों पर जुर्माना आदि जैसी कार्रवाई करेगा।

मात्रात्मक उपकरण

रेपो दर:

- जब RBI बैंकों को रात भर (1 दिन) या 7, 14 या 28 दिनों की अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण देता है तो इसे रेपो कहा जाता है।
- रेपो दर 'पुनर्खरीद विकल्प' या 'पुनर्खरीद समझौते' से संबंधित है
- आरबीआई कुछ जी-सेक बांड को सुरक्षा (संपार्श्विक) के रूप में अपने कब्जे में ले लेता है।
- इस अल्पावधि के बाद, बैंकों को ब्याज देकर आरबीआई से इन जी-सेक बांड को फिर से खरीदना पड़ता है जिसे रेपो रेट कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में, वाणिज्यिक बैंक एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक निश्चित तिथि पर प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों या बांडों को बेचकर भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं।
- वर्तमान रेपो दर 6.50% है।

- रेपो रेट को "पॉलिसी रेट" कहा जाता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर "तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ)" के अंतर्गत आती है।

रिवर्स रेपो-

- जब बैंक आरबीआई को अल्पावधि के लिए ऋण देते हैं तो इसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। बैंक आरबीआई से सिक्योरिटी के तौर पर जी-सेक बॉन्ड लेते हैं।
- अल्पावधि अवधि के बाद, आरबीआई ब्याज देकर जी-सेक बांड वापस खरीदता है जो रिवर्स रेपो दर है। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई को जरूरत के समय बैंकों से पैसा दिलाने में मदद करता है। बदले में, आरबीआई उन्हें आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है।
- बैंक स्वेच्छा से अतिरिक्त धनराशि केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देते हैं क्योंकि इससे उन्हें बेकार पड़े अधिशेष धन पर अधिक ब्याज अर्जित करने का अवसर मिलता है।
- वर्तमान रिवर्स-रेपो दर 3.35% है

रिवर्स रेपो रेट सिस्टम में धन के प्रवाह को कैसे नियंत्रित करता है?

- रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से बैंकों को अल्पकालिक आधार पर अपने अधिशेष धन को केंद्रीय बैंक के पास पार्क करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम हो जाती है।
- संक्षेप में, आरबीआई रातोंरात आधार पर पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से अधिशेष धन को अवशोषित करता है। यह रिवर्स रेपो रेट के तहत तरलता समायोजन सुविधा या एलएएफ के तहत होता है।
- बैंकों को RBI के पास अधिशेष निधि रखने से हतोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो दर रेपो दर से कम है

बैंक दर-

- यह वह दर है जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है।
- बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋणों पर लगाया जाता है, जबकि, रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक को बेची गई प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के लिए लगाया जाता है।
- बैंक दर चार्ज करते समय कोई संपार्श्विक शामिल नहीं होता है, लेकिन रेपो रेट चार्ज करते समय प्रतिभूतियां, बांड, समझौते और संपार्श्विक शामिल होते हैं।
- रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होता है।
- बैंक दर का उपयोग अब नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में डिफ़ॉल्ट पर दंड की गणना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, भंडार में कमी पर वर्तमान दंड दर बैंक दर प्लस 3 प्रतिशत है।
- वर्तमान बैंक दर 6.75 % है

एनडीटीएल: शुद्ध मांग और समय देनदारियां

- जनता की जमा राशि बैंकों की देनदारी है। जनता की मांग जमा राशि बैंक की मांग देनदारी है और सावधि जमा बैंकों की सावधि देनदारी है और जनता की मांग और सावधि जमा का कुल योग बैंकों की शुद्ध मांग और सावधि देनदारियां (एनडीटीएल) कहा जाता है।

दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ):

- RBI बैंकों को रेपो दर पर बैंक के NDTL का केवल 0.25% तक ऋण देता है। आरबीआई समय-समय पर बैंकिंग प्रणाली में समग्र एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक रेपो दर से ऊपर ऋण देता है। और इस मामले में ब्याज दर आम तौर पर नीलामी द्वारा तय की जाती है, यानी, यदि बैंक अधिक पैसा चाहते हैं, तो ब्याज दर अधिक हो जाएगी, यदि कुछ बैंक आरबीआई के पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो ब्याज दर कम होगी लेकिन यह हमेशा रेपो दर से ऊपर होती है। . आरबीआई, नीलामी आयोजित करते समय स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि रेपो रेट से नीचे और उसके बराबर की बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी)।
- इसे "लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (LTRO)" कहा जाता है, जिसका मतलब है कि RBI एक निश्चित लंबी अवधि के लिए पैसा देता है। एलटीआरओ आम तौर पर नीलामी द्वारा तय की गई परिवर्तनीय दर पर होता है जो रेपो दर से ऊपर होता है लेकिन यह आम तौर पर रेपो दर पर किया जाता है।
- जैसे-जैसे बैंकों को कम दरों पर दीर्घकालिक फंड मिलते हैं, उनकी फंड की लागत कम हो जाती है। बदले में, वे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें कम करते हैं।

- नोट: रेपो बैंकों के लिए दैनिक आधार पर उपलब्ध है लेकिन एलटीआरओ लंबी अवधि के लिए है और आरबीआई द्वारा सूचित किए जाने पर ही कम बार किया जाता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ):

- यह 2011 में शुरू की गई एक सुविधा है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में डुबकी लगाकर (रेपो दर के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध राशि के अलावा) रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार ले सकते हैं। दंडात्मक ब्याज दर पर एक सीमा तक।
- यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटके के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। जब बैंक रेपो दर पर आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो बैंकों को सरकारी रखने की आवश्यकता होती है।
- आरबीआई के पास प्रतिभूतियां, लेकिन यह सुरक्षा एसएलआर की आवश्यकता के अतिरिक्त है। रेपो दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक एसएलआर प्रतिभूतियां नहीं रख सकते हैं।
- लेकिन एमएसएफ के तहत, बैंक एसएलआर रिजर्व में डुबकी लगाकर आरबीआई से पैसा/नकद उधार ले सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंक एसएलआर प्रतिभूतियों का 3% आरबीआई के पास रख सकते हैं (यानी, एसएलआर सामान्य एसएलआर सीमा से 3% नीचे जा सकता है) और आरबीआई से नकद उधार ले सकते हैं। इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) कहा जाता है।
- एमएसएफ दर = रेपो दर + 0.25%
- इसके अलावा, एमएसएफ दर = बैंक दर

रिज़र्व आवश्यकताएँ (आंशिक रिज़र्व बैंकिंग):

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल (पाक्षिक आधार पर) के संबंध में आरबीआई के पास जो नकदी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उसे सीआरआर कहा जाता है। सीआरआर को आरबीआई के पास रखने का एक मूल कारण जनता की जमा राशि को सुरक्षा प्रदान करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अनुसार सीआरआर बनाए रखना आवश्यक है (देश में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, आरबीआई एससीबी के लिए बिना किसी न्यूनतम या अधिकतम मूल्य के सीआरआर निर्धारित करने के लिए अधिकृत है)। वर्तमान में सीआरआर 4.50% है

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, सोने और नकदी जैसी सुरक्षित और तरल संपत्तियों में दैनिक आधार पर अपने पास आरक्षित राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे एसएलआर कहा जाता है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है।
- एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% है.
- वर्तमान में एसएलआर 18.00 % है

सीआरआर एवं एसएलआर की आवश्यकता

- सीआरआर और एसएलआर की आवश्यकता सार्वजनिक जमा को सुरक्षित और तरल बनाना है और आरबीआई को बैंकों द्वारा बनाई जा सकने वाली धनराशि को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना है।
- यह सुनिश्चित करता है कि जब खाताधारक भुगतान करना चाहते हैं तो बैंकों के पास परिसंपत्तियों का एक सुरक्षित गद्दी है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं के अभाव में, अधिक लाभ कमाने के लिए बैंक अधिकांश जमा राशि उधार दे सकते हैं और यदि निकासी के लिए अचानक भीड़ होती है, तो बैंक पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे।
- सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों (या तो अनुसूचित या गैर-अनुसूचित) को सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है।
- अनुसूचित बैंकों के लिए, सीआरआर का रखरखाव भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (धारा 24) सभी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) वाणिज्यिक और सहकारी के लिए एसएलआर के रखरखाव को नियंत्रित करता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक)

- सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, उन्हें जोखिम-मुक्त गिल्ट-एज उपकरण कहा जाता है। (सरकार केवल ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करती है)।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ RBI द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं। नीलामी आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), प्राथमिक डीलर (पीडी), बीमा कंपनियां और भविष्य निधि इस मंच के सदस्य हैं। इस बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भी भाग लेते हैं। व्यक्ति (खुदरा निवेशक) भी सरकार में सीधे भाग ले सकते हैं। प्रतिभूति बाज़ार।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ):

- अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद को खुले बाजार संचालन कहा जाता है।
- यदि अतिरिक्त तरलता है, तो आरबीआई प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है और रुपये की तरलता को चूस लेता है।
- इसी तरह, जब तरलता की स्थिति कठिन होती है, तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे बाजार में तरलता जारी होती है।
- यह ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर किया गया है।

क्या होता है जब RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है?

इस सरल उदाहरण पर विचार करें:

एक बैंक के साथ कुल संपत्ति	**ओएमओ**	**बैंक के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य**	**उधार देने के लिए उपलब्ध राशि**
100	कोई नहीं	20	80
100	आरबीआई 10 रुपये की प्रतिभूतियां बेचता है, और बैंक इसे खरीदता है	20 + 10 = 30	80-10 = 70

आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उधार देने के लिए उपलब्ध राशि कम हो गई है यानी मुद्रा आपूर्ति सिकुड़ गई है।

Effect of Inflation on CRR/SLR, Repo rates, OMO

1) Effect on Reserve ratios-

INFLATION	RESERVE RATIOS (CRR-SLR)
Increases	Increases
Decreases	Decreases

2) Effect on Repo rates and Bank rates

INFLATION	REPO RATE	MONEY SUPPLY	Effect on Inflation
Increases	Increases	Decreases	Reduces
Decreases	Decreases	Increases	Increases

3) Effect on Open Market operations

INFLATION	G-sec (Government Securities)	Effect on Inflation
Increases	RBI will sell G-sec to banks	Reduces
Decreases	RBI will buy G-sec from banks	Increases

प्रतिभूतियों और वित्तीय बाजारों को समझना

प्रतिभूति

- प्रतिभूतियां वित्तीय साधन (रसीदें/पर्चियां) हैं जो भविष्य में रिटर्न (भुगतान) का वादा करती हैं और जिनका व्यापार किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने रुपये जमा किए। उसके खाते में 1 लाख रुपये और एक खाता विवरण/पासबुक मिला। जिस व्यक्ति के पास खाता विवरण है उसे भविष्य में ब्याज मिलेगा लेकिन उसे इस कागज (खाता विवरण) को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है। इसलिए खाता विवरण को सख्त अर्थों में सुरक्षा नहीं माना जाता है।
- प्रतिभूतियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इक्विटी और ऋण.

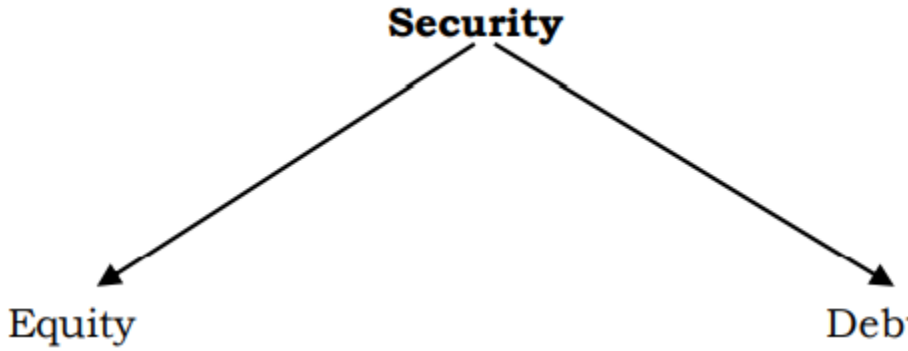

1. इक्विटी सुरक्षा (स्टॉक/शेयर) किसी कंपनी/निगम में शेयरधारकों (मालिकों) द्वारा रखे गए स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। इक्विटी सुरक्षा धारकों को लाभ/लाभांश और पूंजीगत लाभ (शेयर मूल्य प्रशंसा) प्राप्त होता है। इक्विटी प्रतिभूतियाँ धारक को आनुपातिक आधार पर कंपनी के कुछ नियंत्रण का अधिकार देती हैं यानी इक्विटी धारकों को मतदान का अधिकार मिलता है और इस प्रकार व्यवसाय पर कुछ नियंत्रण मिलता है।
2. ऋण सुरक्षा उस धन का प्रतिनिधित्व करती है जो उधार लिया गया है और इसे उन शर्तों के साथ चुकाया जाना चाहिए जो उधार ली गई राशि, ब्याज दर और परिपक्वता तिथि को परिभाषित करते हैं। ऋण सुरक्षा धारकों को ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान प्राप्त होता है।

नोट: वह इकाई (कंपनी) जो प्रतिभूतियाँ जारी करती है, सुरक्षा जारीकर्ता के रूप में जानी जाती है।

जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी/प्रोजेक्ट में निवेश (पैसा लगाता है) करता है तो यह निवेश मोटे तौर पर दो तरह से किया जा सकता है:

1. इक्विटी प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा। इस स्थिति में निवेशक कंपनी में पैसा लगाता है और उसे कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा मिल जाता है। इस मामले में व्यक्ति को कोई निश्चित रिटर्न नहीं मिलता है बल्कि कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर लाभ/लाभांश प्राप्त होता है। यह निवेशक द्वारा कंपनी की इक्विटी प्रतिभूतियों की खरीद का रूप है।
2. ऋण प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा। इस मामले में निवेशक एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर कंपनी में पैसा लगाता है और परिपक्वता अवधि के अंत में ब्याज (नियमित रूप से) और मूलधन वापस प्राप्त करता है। यह निवेशक द्वारा कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों की खरीद का रूप है।

==========

प्रतिभूतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम एक नई पंजीकृत कंपनी "XYZ प्राइवेट लिमिटेड" का उदाहरण लें।

- कंपनी अपना खाता बैलेंस शीट के रूप में रखती है (नीचे दिखाया गया है) और बैलेंस शीट में कंपनी की संपत्ति और देनदारियां हमेशा बराबर होती हैं। शुरुआत में कंपनी के पास कोई पैसा/पूंजी नहीं थी और उसने अपना पैसा रखने के लिए एक विशेष बैंक में एक खाता खोला हुआ था।
- मालिक/उद्यमी शुरू में कुछ पैसे, मान लीजिए रु. लगाता है। कंपनी में 1 करोड़ रुपये (जो कंपनी के खाते में जमा किया जाएगा) और बदले में कंपनी उसे एक 'स्वामित्व दस्तावेज़'/शेयर जारी करती है।
- कंपनी के खाते में मौजूद नकदी कंपनी के लिए एक परिसंपत्ति होगी क्योंकि कंपनी उस नकदी रुपये से कुछ भी कर सकती है। 1 करोर।
- इस राशि के बदले में कंपनी मालिक को एक दस्तावेज़ जारी करेगी जो कंपनी में 100% स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करेगा, और कंपनी के दायित्व पक्ष में "मालिक का पैसा" या "शेयरधारकों का पैसा" के रूप में दर्शाया जाएगा।
- स्वामित्व दस्तावेज़ या शेयर मालिक के लिए संपत्ति है लेकिन कंपनी के लिए दायित्व के रूप में कार्य करेगा।
- यह लेन-देन निम्नलिखित जैसा दिखेगा:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability
Cash = Rs. 1 cr	Owner's Money = Rs. 1 cr
Rs. 1 cr	Rs. 1 cr

→ यदि कंपनी अपना कारोबार बढ़ा रही है और अधिक फंड चाहती है तो वह बैंक से संपर्क कर सकती है। मान लीजिए कि बैंक ने कंपनी को रु। का ऋण दिया। 2 करोड़. कंपनी को मिलने वाली नकदी कंपनी के लिए एक संपत्ति होगी लेकिन कंपनी को रुपये का प्रतिनिधित्व करने वाले "ऋण दस्तावेज़" पर हस्ताक्षर करना होगा। कंपनी को 2 करोड़ रुपये का ऋण और यह ऋण दस्तावेज़ कंपनी के लिए एक देनदारी (बैंक ऋण के रूप में देनदारी पक्ष में दर्शाया गया) और बैंक के लिए संपत्ति होगी। यह लेनदेन इस प्रकार दिखेगा:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability
Cash = Rs. 1 cr Cash = Rs. 2 cr	Owner's Money = Rs. 1 cr
	Bank Loan = Rs. 2 cr
Rs. 3 cr	Rs. 3 cr

→ यदि कंपनी अधिक धन चाहती है, तो वह एक विशेष/निश्चित ब्याज दर पर कंपनी में पैसा लगाने के लिए व्यक्तिगत लोगों यानी खुदरा बाजार से संपर्क कर सकती है (जिस तरह लोग बैंकों में पैसा डालते हैं)।

→ मान लीजिए कि कंपनी ने 1 लाख व्यक्तियों से संपर्क किया जो रुपये का निवेश कर सकते थे। कंपनी में 10% की निश्चित ब्याज दर पर 5 साल के लिए 100 प्रत्येक (कुल = 1 करोड़ रुपये) (बस मान लें कि बैंक 9% ब्याज दर की पेशकश कर रहे थे, इसलिए कंपनी ने 1% अधिक की पेशकश की)।

→ लोगों ने बैंकों के बजाय कंपनी में पैसा लगाने का फैसला किया क्योंकि कंपनी बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर की पेशकश कर रही थी। इस लेनदेन से कंपनी की संपत्ति में रु. 1 करोड़ और कंपनी की देनदारियां भी 1 करोड़ बढ़ जाएंगी।

→ कंपनी रुपये मूल्य की कागजी "पर्ची" जारी करेगी। व्यक्तियों को 100 रुपये जो व्यक्तियों के लिए संपत्ति होगी लेकिन कंपनी के लिए दायित्व के रूप में कार्य करेगी। पर्चियाँ निम्नलिखित की तरह दिखेंगी:

"Slips"

XYZ Pvt. Ltd.
Value = Rs. 100
Time = 5 years
Interest Rate = 10%

Bank Interest Rate = 9%

- अब, कुछ समय बाद, यदि बैंक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपनी ब्याज दर बढ़ाकर 12% कर देते हैं, तो "पर्ची" रखने वाले लोग पर्चियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पर्ची उन्हें केवल 10% ब्याज दे रही है। दर।
- लेकिन अगर वे बाजार में पर्चियां बेचने जाएंगे तो बाजार में इन पर्चियों को कोई भी रुपये में खरीदने को तैयार नहीं होगा। 100 क्योंकि अगर कोई 100 रुपये जमा कर सकता है तो 10% ब्याज दर पर पर्चियाँ क्यों खरीदेगा। बैंकों में 100 और 12% ब्याज दर अर्जित कर सकते हैं।
- इसलिए, अगर पर्ची धारक चाहते हैं कि इसे बाजार में बेचा जाए तो वे रियायती/कम कीमत पर पर्चियां पेश करेंगे। लेकिन इससे कम कीमत क्या होगी.
- कोई भी पर्चियां खरीदने के लिए इच्छुक होगा यदि वह बाजार में दी जा रही ब्याज दर यानी 12% की तुलना में पर्चियों पर अधिक ब्याज दर अर्जित कर सकता है। मान लीजिए कि कोई खरीदार इस पर्ची को रुपये में खरीदता है। बाजार से 80 रु.

आइये देखते हैं उनकी कमाई या ब्याज दर:

Money spent by the purchaser in purchasing the slip = Rs. 80
Annual interest received by the purchaser = Rs. 10 (10% of Rs 100)
Effective Interest rate earned by the purchaser = Rs. 10/Rs. 80 = 12.5%

⟶ इसलिए क्रेता इस पर्ची को रुपये में खरीदेगा। 80 क्योंकि उसे बैंक की 12% की ब्याज दर की तुलना में 12.5% का अधिक रिटर्न (जिसे उपज भी कहा जाता है) मिल रहा है।

⟶ जिस व्यक्ति ने शुरू में पर्ची खरीदी थी वह पर्ची रुपये में क्यों बेचेगा? 80? क्योंकि उनका मानना है कि अगर बैंक की ब्याज दर 13% या 14% तक बढ़ गई तो कोई भी रुपये में भी पर्ची खरीदने को तैयार नहीं होगा। 80. (सभी व्यापारिक गतिविधियां भविष्य के अनुमानों के आधार पर होती हैं)।

⟶ इन पर्चियों को बांड कहा जाता है। इसलिए, जब बैंक की ब्याज दर बढ़ती है तो बाजार में बांड की कीमतें कम हो जाती हैं। और जब बैंक की ब्याज दर गिरती है तो बाजार में बांड की कीमतें बढ़ जाती हैं। कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह दिखेगी:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability
Cash = Rs. 1 cr Cash = Rs. 2 cr Cash = Rs. 1 cr	Owner's Money = Rs. 1 cr Bank Loan = Rs. 2 cr Bonds = Rs. 1 cr
Rs. 4 cr	Rs. 4 cr

यदि कंपनी अपनी नकदी को भवन और मशीनरी खरीदने में परिवर्तित करती है तो बैलेंस शीट इस तरह दिखेगी:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability
Building1 = Rs. 1 cr Building2 = Rs. 2 cr Machinery1 = Rs. 1 cr	Owner's Money = Rs. 1 cr
	Bank Loan = Rs. 2 cr Bonds = Rs. 1 cr
Rs. 4 cr	Rs. 4 cr

अब, मान लीजिए कि कंपनी लाभ कमा रही है और अधिक से अधिक लोग कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक लाख लोगों ने रुपये निवेश किए। कंपनी में मालिक बनने के लिए प्रत्येक को 100 रुपये (कुल 1 करोड़ रुपये) देने होंगे और कंपनी ने इस रुपये से मशीनरी खरीदी। 1 करोड़ नकद.

बैलेंस शीट इस तरह दिखेगी:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability
Building1 = Rs. 1 cr Building2 = Rs. 2 cr Machinery1 = Rs. 1 cr Machinery2 = Rs. 1 cr	Owner's Money = Rs. 1 cr Owner's Money = Rs. 1 cr
	Bank Loan = Rs. 2 cr Bonds = Rs. 1 cr
Rs. 5 cr	Rs. 5 cr

अब कंपनी में मालिकों की वैल्यू 10 लाख रुपये हो जाएगी. 2 करोड़ 100% स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। और नए मालिक अपने स्वामित्व के अनुपात में स्वामित्व/शेयर दस्तावेज़ रखना चाहेंगे। तो, शुरुआती उद्यमी के पास जो स्वामित्व दस्तावेज था (जिसकी कीमत अब 2 करोड़ रुपये हो गई है) उसे दो लाख टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा।

So now, 100% ownership = Rs. 2 crore = 2 lakh shares x Value of each share
Hence, value of each share = Rs. 100

उद्यमी के पास 50% स्वामित्व और रुपये के एक लाख शेयर होंगे। 100 प्रत्येक. और नए एक लाख मालिकों के पास संयुक्त रूप से 50% स्वामित्व होगा और प्रत्येक शेयर की कीमत रु। 100.

अब, यदि कंपनी की संपत्ति इमारत के मूल्यांकन में वृद्धि से बढ़ती है या कंपनी लाभ कमा रही है तो प्रत्येक शेयर का मूल्य बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी रु. 2 करोड़ का लाभ, तो यह लाभ कंपनी की संपत्ति (कंपनी के खाते में जमा) होगी और दो लाख शेयरों का मूल्य रु. हो जाएगा। 4 करोड़, तो शेयर की कीमत बढ़कर रु. 200 प्रति शेयर. इसलिए कंपनी के शेयर की कीमत लाभ में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बैलेंस शीट इस तरह दिखेगी:

"XYZ Pvt. Ltd."

Asset	Liability	
Building1 = Rs. 1 cr Building2 = Rs. 2 cr Machinery1 = Rs. 1 cr Machinery2 = Rs. 1 cr	Shareholder's Money = Rs. 4 cr *(Two lakh shares X Rs. 200 each)*	**Equity**
Cash (from profit) = Rs. 2 cr	Bank Loan = Rs. 2 cr Bonds = Rs. 1 cr	**Debt**
7 cr	7 cr	

उपरोक्त उदाहरण में, निवेशक निम्नलिखित दो तरीकों से कंपनी में निवेश/पैसा लगा रहे हैं:

- एक विशेष/निश्चित ब्याज दर पर और ऋण सुरक्षा प्राप्त होती है
- लाभ या हानि पर और मालिक बन जाता है और इक्विटी सुरक्षा प्राप्त करता है

→ इसलिए, कुल संपत्ति के विरुद्ध, कंपनी निवेशकों को या तो ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियां जारी करती है और उसे देनदारी पक्ष पर कंपनी की खाता बही में दर्शाया जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक)

- सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, उन्हें जोखिम-मुक्त गिल्ट-एज उपकरण कहा जाता है। (सरकार केवल ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करती है)।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ RBI द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से जारी की जाती हैं। नीलामी आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), प्राथमिक डीलर (पीडी), बीमा कंपनियां और भविष्य निधि इस मंच के सदस्य हैं। इस बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भी भाग लेते हैं। व्यक्ति (खुदरा निवेशक) भी सरकार में सीधे भाग ले सकते हैं। प्रतिभूति बाज़ार।

सरकारी प्रतिभूतियाँ चार प्रकार की होती हैं:

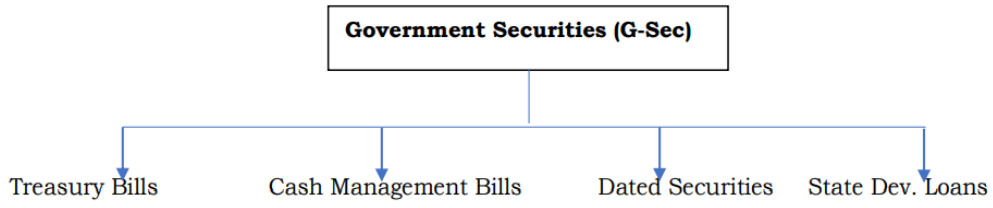

1. ट्रेजरी बिल या टी-बिल: ये भारत सरकार द्वारा एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और उन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इसके बजाय, उन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। उदाहरण के लिए, ₹100/- (अंकित मूल्य) का 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल मान लीजिए ₹ 98.20 पर जारी किया जा सकता है, यानी, ₹1.80 की छूट पर और ₹100/- के अंकित मूल्य पर भुनाया जाएगा। . (ट्रेजरी बिल का कारोबार मुद्रा बाजार में किया जाता है)।
2. नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी): 2010 में, भारत सरकार ने आरबीआई के परामर्श से सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों को पूरा करने के लिए एक नया अल्पकालिक उपकरण पेश किया, जिसे नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) के रूप में जाना जाता है। भारत। सीएमबी में टी-बिल का सामान्य चरित्र होता है लेकिन ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।
3. दिनांकित प्रतिभूतियाँ: दिनांकित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की अवधि एक वर्ष से अधिक से लेकर 40 वर्ष तक होती है। वे विभिन्न श्रेणियों के हो सकते हैं:

- निश्चित दर बांड: परिपक्वता तक ब्याज दर तय होती है
- फ्लोटिंग रेट बांड: ब्याज/कूपन दर निश्चित नहीं है और इसे ट्रेजरी बिलों की आय से जोड़ा जा सकता है
- मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड: ब्याज और मूलधन दोनों मुद्रास्फीति से सुरक्षित हैं और इन्हें सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से जोड़ा जा सकता है
- विशेष प्रतिभूतियाँ: बाजार उधार कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार समय-समय पर तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम आदि जैसी संस्थाओं को विशेष प्रतिभूतियाँ भी जारी करती है (जिन्हें लोकप्रिय रूप से तेल बांड, उर्वरक बांड कहा जाता है)। और क्रमशः खाद्य बांड) इन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले मुआवजे के रूप में।
- बैंक पुनर्पूंजीकरण बांड: भारत सरकार ने 2018 में विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बैंक पुनर्पूंजीकरण बांड भी जारी किए हैं।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी): एसजीबी अद्वितीय उपकरण हैं, जिनकी कीमतें कमोडिटी की कीमत जैसे सोने से जुड़ी होती हैं। एसजीबी का बजट बाजार उधार के बदले में भी तय किया जाता है।

4. राज्य विकास ऋण (एसडीएल): राज्य सरकारें भी बाजार से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले ऋण उठाती हैं जिन्हें एसडीएल कहा जाता है। राज्य सरकारों द्वारा जारी एसडीएल भी एसएलआर के लिए योग्य हैं।

सरकार. प्रतिभूति बाज़ार:

- यह बाज़ार RBI द्वारा विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। जब सरकार. (केंद्र या राज्य) पैसा चाहते हैं, आरबीआई सरकार में प्रतिभूतियां/बॉन्ड जारी करके उनके लिए पैसा जुटाता है। प्रतिभूति बाज़ार।
- पहली बार सरकार. प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूति बाजार (मूल रूप से प्राथमिक बाजार लेनदेन) में जारी की जाती हैं और फिर द्वितीयक बाजार लेनदेन भी उसी बाजार में होते हैं।
- सभी चार प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों यानी "नकद प्रबंधन बिल", "ट्रेजरी बिल", "दिनांकित प्रतिभूतियां" और "राज्य विकास ऋण" का सरकार में कारोबार किया जाता है। प्रतिभूति बाज़ार।
- चूंकि "दिनांकित प्रतिभूतियों" और "राज्य विकास ऋण" की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, इसलिए ये सरकारी ऋण हैं। प्रतिभूतियों का कारोबार बीएसई/एनएसई जैसे पूंजी बाजार में भी किया जाता है क्योंकि "नकद प्रबंधन बिल" और "ट्रेजरी बिल" की परिपक्वता एक वर्ष से कम है, ये सरकार। मुद्रा बाज़ार में प्रतिभूतियों का भी कारोबार होता है।

आर्थिक बाज़ार

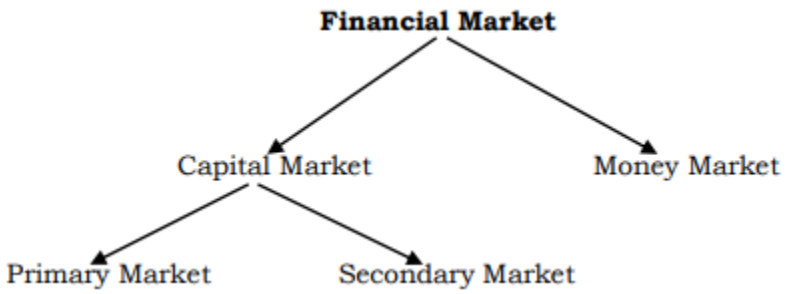

वित्तीय बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जो खरीदारों और विक्रेताओं को वित्तीय प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव, मुद्राएं आदि में व्यापार करने के लिए एक साथ लाता है। वित्तीय बाज़ार मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं:

1. पूंजी बाजार: ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए वित्तीय बाजार। इस बाज़ार में एक वर्ष से अधिक की मध्यम और लंबी अवधि की प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। पूंजी बाज़ार दो प्रकार के होते हैं:

i. प्राथमिक बाजार: यह पूंजी बाजार को संदर्भित करता है जहां प्रतिभूतियां बनाई जाती हैं। इसी बाज़ार में कंपनियां पहली बार नए शेयर और बांड (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, आईपीओ) बेचती हैं। इस बाज़ार में लेनदेन सुरक्षा जारीकर्ता (कंपनी) और निवेशक के बीच होता है। उपरोक्त प्रतिभूतियों के उदाहरण में, जिस बाज़ार में कंपनी ने पहली बार एक लाख निवेशकों को बांड जारी किए, वह प्राथमिक बाज़ार है।

ii. द्वितीयक बाज़ार: एक बार जब जारीकर्ता द्वारा प्राथमिक बाज़ार में प्रतिभूतियाँ जारी कर दी जाती हैं, तो इसका निवेशकों के बीच द्वितीयक बाज़ार में कारोबार होता है। इस बाजार में, निवेशक सुरक्षा जारीकर्ता (कंपनी) की भागीदारी के बिना पहले जारी की गई प्रतिभूतियों का आपस में व्यापार करते हैं। उदाहरण, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रतिभूतियों के उदाहरण में, जिस बाज़ार में निवेशकों ने आपस में बांड खरीदना और बेचना शुरू किया वह द्वितीयक बाज़ार है।

2. मुद्रा बाजार: वित्तीय बाजार का एक खंड जिसमें उच्च तरलता और बहुत कम परिपक्वता (एक वर्ष से कम) वाले वित्तीय साधनों का कारोबार किया जाता है। मुद्रा बाजार उपकरण मूल रूप से ऋण उपकरण हैं और इसमें ट्रेजरी बिल, नकद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र शामिल हैं। जो खिलाड़ी मुद्रा बाजार में व्यापार कर सकते हैं वे वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक और उच्च श्रेणी निर्धारण वाली कॉर्पोरेट/कंपनियां हैं।

CLASS 12

CHAPTER 5

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा:

- ✓ बजट
- ✓ बजट के कार्य
- ✓ सार्वजनिक सामान और निजी सामान
- ✓ सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन
- ✓ बजट के घटक
- ✓ प्राप्ति के प्रकार: राजस्व और पूंजी
- ✓ व्यय के प्रकार: राजस्व और पूंजी
- ✓ संतुलित, अधिशेष और घाटे वाला बजट
- ✓ राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा
- ✓ घाटे की वित्त व्यवस्था
- ✓ सरकारी ऋण
- ✓ रिकार्डियन समतुल्यता
- ✓ घाटे में कमी

बजट क्या है?

- बजट एक समयावधि में राजस्व और व्यय का अनुमान है
- सरकारी बजट क्या है?

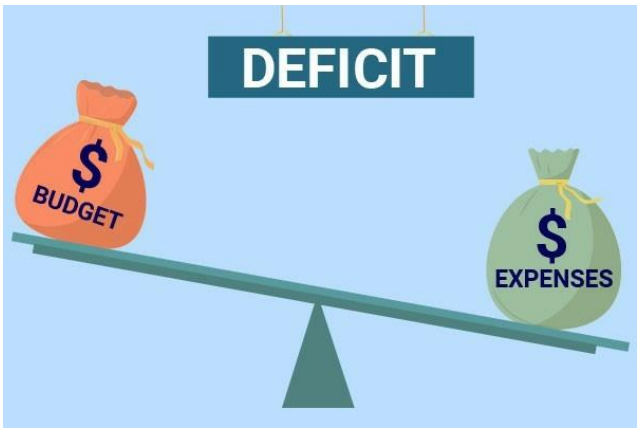

- यह सरकार द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का मदवार विवरण शामिल है
- बजट की संवैधानिक आवश्यकता
- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सरकारी बजट के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु

- यह अनुमानित आधार पर तैयार किया गया है न कि वास्तविक आधार पर
- इसे 1 साल के लिए तैयार किया जाता है. हम वित्तीय वर्ष का अनुसरण करते हैं (कैलेंडर वर्ष का नहीं)

उदाहरण- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट का अर्थ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बजट है।

- यह सभी प्रकार की सरकारों - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका द्वारा तैयार किया जाता है
- हालाँकि, हम केंद्र सरकार के बजट के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे यूनियन बजट कहा जाता है
- इसे हर साल फरवरी के आसपास वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है

उदाहरण

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट का अर्थ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए बजट है। इसे फरवरी 2020 में अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का अर्थ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए बजट। इसे फरवरी 2021 में अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

बजट के कार्य

1.आवंटन समारोह

- सरकार राष्ट्रीय रक्षा, सड़क, न्यायपालिका जैसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना चाहती है।
- यदि सरकार कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो वह इन वस्तुओं पर कर रियायतें देती है
- इसके अलावा, सरकार कुछ वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहती है, इसके लिए वह इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती है
- इसके अतिरिक्त, सरकार जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में सीधे माल का उत्पादन कर सकती है क्योंकि ये गैर-लाभकारी हैं।

2. वितरण समारोह

- सरकार आय का उचित वितरण सुनिश्चित करना और अमीर और गरीब के बीच असमानता को कम करना चाहती है। इसलिए, यह बजट में अमीरों के लिए अधिक कर वसूलता है और गरीबों को सब्सिडी और कर रियायतें देता है

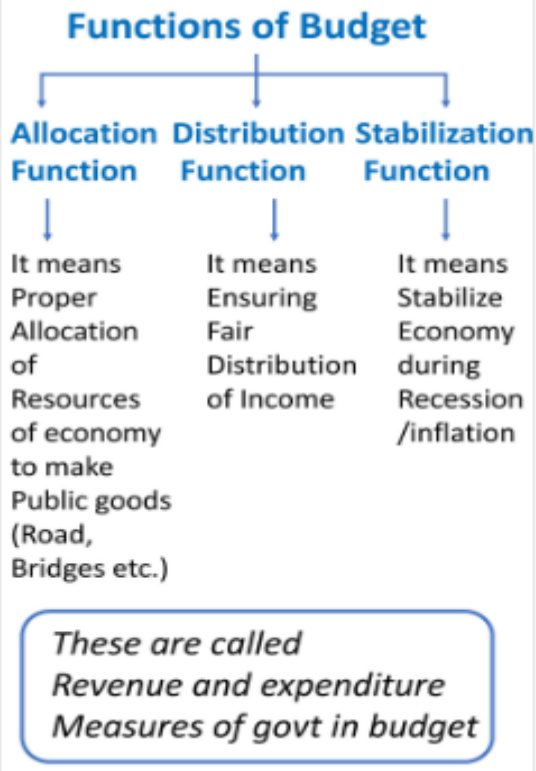

3.स्थिरीकरण समारोह

- यदि देश मंदी और मांग में गिरावट से गुजर रहा है। वस्तुओं की अधिक मांग पैदा करने के लिए सरकार बजट में अपना सार्वजनिक खर्च बढ़ाती है। अगर देश महंगाई से जूझ रहा है. वस्तुओं की मांग कम करने के लिए सरकार बजट में अपना खर्च घटाती है।

4. आर्थिक विकास

- सरकार बिजली, सड़क, बांध आदि जैसे बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च कर सकती है।
- इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है
- इसके अलावा, सरकार उन क्षेत्रों को कर रियायतें देती है जहां अधिक विकास की संभावना होती है
- उदाहरण-निर्यात क्षेत्र और सॉफ्टवेयर कंपनियों को कर लाभ

5. सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन

- सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसाय को सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है
- उदाहरण-पीएसयू जैसे एसबीआई, ओएनजीसी, बीएसएनएल
- सरकार को इन कंपनियों से लाभांश आय प्राप्त होती है
- इसके अलावा, यदि ये लाभदायक नहीं हैं, तो सरकार विनिवेश के लिए जा सकती है और अपने शेयर बेच सकती है
- दोनों ही मामलों में, यह सरकार के लिए रसीद का एक स्रोत है जिसका उपयोग विभिन्न व्यय करने के लिए किया जा सकता है

6. क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करें

- भारत के कुछ क्षेत्र कम विकसित हैं जबकि कुछ अधिक विकसित हैं
- इसलिए इन क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर रियायतें या सब्सिडी दे सकती है
- इससे पिछड़े इलाकों का विकास होगा

सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं के बीच अंतर

निजी वस्तुएँ क्या हैं?

- कोई भी सामान जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के उपभोग के लिए है।
- और किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।

उदाहरण-

→ मान लीजिए एक व्यक्ति एक कार खरीदता है। उस कार का उपयोग करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होता है

→ उनकी इजाजत के बिना कोई दूसरा व्यक्ति कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता

→ अतः, कार एक निजी वस्तु है

नोट- घरों और व्यवसाय द्वारा खरीदे गए सभी उत्पाद निजी सामान हैं

उदाहरण - कपड़े, वाहन, टीवी, मोबाइल आदि।

सार्वजनिक वस्तुएँ क्या हैं?

→ सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो समाज के सभी सदस्यों के उपभोग के लिए उपलब्ध हैं। सभी लोग इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उदाहरण- सड़कें, पुल आदि।

→ इस मामले में, जनता के सभी सदस्य इन सड़कों और पुलों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो, यह एक सार्वजनिक भलाई है।

सार्वजनिक वस्तुओं के महत्वपूर्ण बिंदु

1. वे गैर-प्रतिद्वंद्वी हैं

- एक व्यक्ति उसी वस्तु से दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को कम किए बिना वस्तुओं से अपनी संतुष्टि बढ़ा सकता है
- उदाहरण- कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार सड़क का उपयोग कर सकता है, इससे दूसरे व्यक्ति के सड़क उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

2. वे गैर-बहिष्कृत हैं

- किसी भी व्यक्ति को सामान का उपयोग करने से बाहर नहीं किया जा सकता (रोका नहीं जा सकता)।
- उदाहरण- सरकार द्वारा तैयार की गई सड़क का उपयोग कोई भी कर सकता है

3. आम तौर पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है

- चूंकि ये सामान गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-बहिष्कृत (किसी के लिए भी उपयोग के लिए मुफ़्त) हैं, इसलिए इनके लिए शुल्क एकत्र करना मुश्किल है
- इसलिए, निजी उद्यमों के लिए ये सामान बनाना लाभदायक नहीं है
- तो, ये सामान आम तौर पर सरकार द्वारा बजट में प्रदान किए जाते हैं

निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच अंतर

निजी सामान	सार्वजनिक माल
निजी सामान से तात्पर्य किसी भी ऐसे सामान से है जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के उपभोग के लिए होता है और अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है।	सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो समाज के सभी सदस्यों के उपभोग के लिए उपलब्ध हैं

वे प्रकृति में प्रतिद्वंद्वितापूर्ण हैं (केवल एक व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं और अन्य व्यक्तियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं)	वे प्रकृति में गैर-प्रतिद्वंद्वी हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु से दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को कम किये बिना वस्तु से अपनी संतुष्टि बढ़ा सकता है।
वे बहिष्कृत हैं (अन्य व्यक्तियों को सामान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है)	वे गैर-बहिष्कृत हैं. किसी भी व्यक्ति को सामान का उपयोग करने से बाहर नहीं किया जा सकता (रोका नहीं जा सकता)।
इन्हें आम तौर पर निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है क्योंकि इसे बेचना और शुल्क एकत्र करना उनके लिए लाभदायक होता है	वे आम तौर पर निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं इसलिए वे बजट में सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं (सार्वजनिक प्रावधान उसी के लिए किया जाता है)

सार्वजनिक प्रावधान का क्या अर्थ है?

- सार्वजनिक प्रावधान का अर्थ उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्रावधान है जो सरकारी बजट द्वारा वित्तपोषित हैं और वे किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं
- आसान भाषा में इसका मतलब उन वस्तुओं और सेवाओं से है जो सरकार द्वारा सभी को मुफ्त प्रदान की जाती है।

उदाहरण

- पुल, बांध जैसी सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा बजट में प्रावधान करके निःशुल्क प्रदान की जाती हैं

टिप्पणी

- माल का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा पैसे का भुगतान किया जाता है।

सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन के बीच अंतर

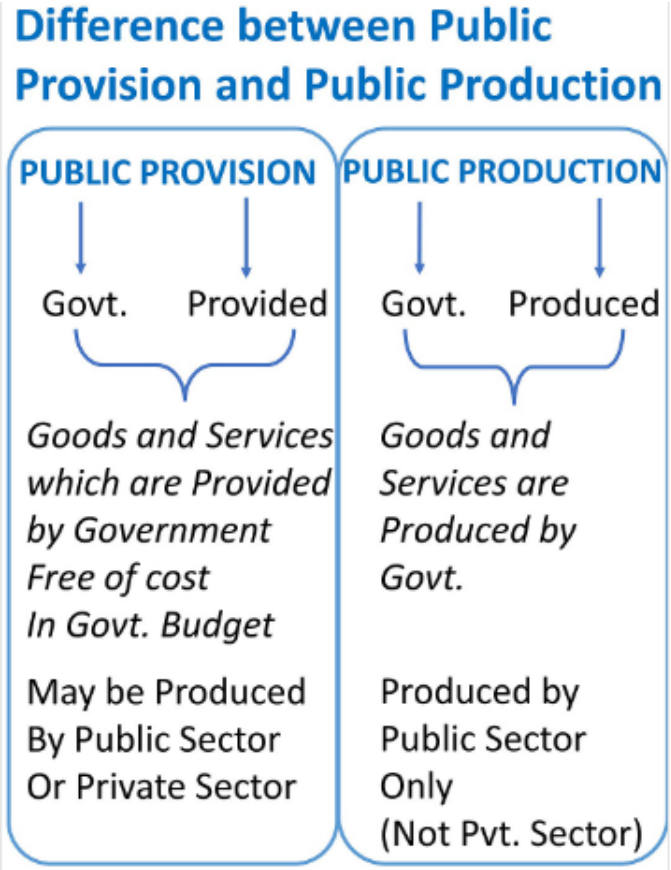

सार्वजनिक प्रावधान	सार्वजनिक उत्पादन
सभी खर्चों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है	सभी वस्तुएँ और सेवाएँ सरकार द्वारा उत्पादित की जाती हैं
इनका उत्पादन किसी के द्वारा भी किया जा सकता है (निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र)	इनका उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) द्वारा किया जाता है

सरकारी बजट के घटक

बजट 2 प्रकार के होते हैं:

- राजस्व बजट
- पूंजीगत आय - व्यय का लेखा

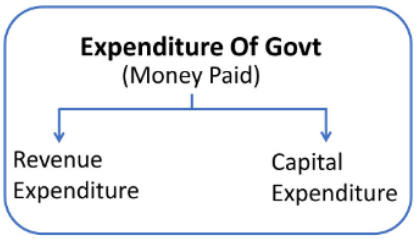

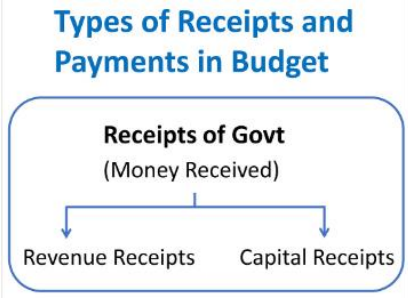

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ

- सरकार की वे प्राप्तियाँ जो गैर-प्रतिदेय होती हैं (जिन्हें सरकार से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता) राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं। ये प्रकृति में आवर्ती (दोहराए जाने वाले) होते हैं।

यह विभिन्न प्रकार का होता है

- राजस्व का टैक्स
- गैर-कर राजस्व

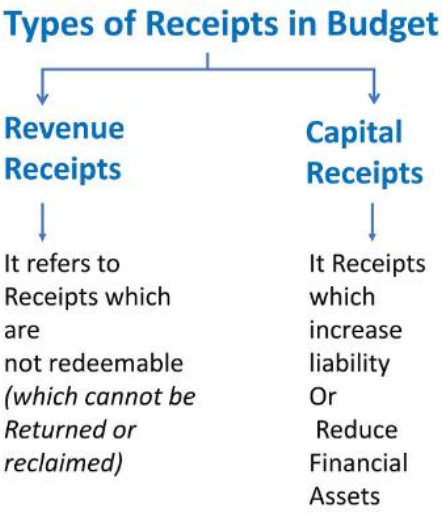

राजस्व का टैक्स

- वे विभिन्न करों की आय हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी, आयकर जैसे लगाए जाते हैं।
- ये कर प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर हो सकते हैं।

सीधा कर

- आयकर व्यक्तियों (व्यक्तिगत आयकर कहा जाता है) के साथ-साथ कंपनियों (कॉर्पोरेट कर कहा जाता है) पर भी लगाया जाता है।
- जितनी अधिक आय, उतनी अधिक कर दर

अप्रत्यक्ष कर

- पहले अलग-अलग कर लगाए जाते थे जैसे सेवा कर (सेवाओं पर), केंद्रीय बिक्री कर (वस्तुओं की बिक्री पर) और उत्पाद शुल्क (विनिर्माण पर)
- अब, इन सभी को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है
- अपवाद: कुछ वस्तुओं पर अभी भी वैट और उत्पाद शुल्क लागू है, पेट्रोल, डीज़ल की तरह जीएसटी नहीं
- माल के आयात, निर्यात पर भी; सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी ली जाती है जो कर राजस्व का भी हिस्सा है

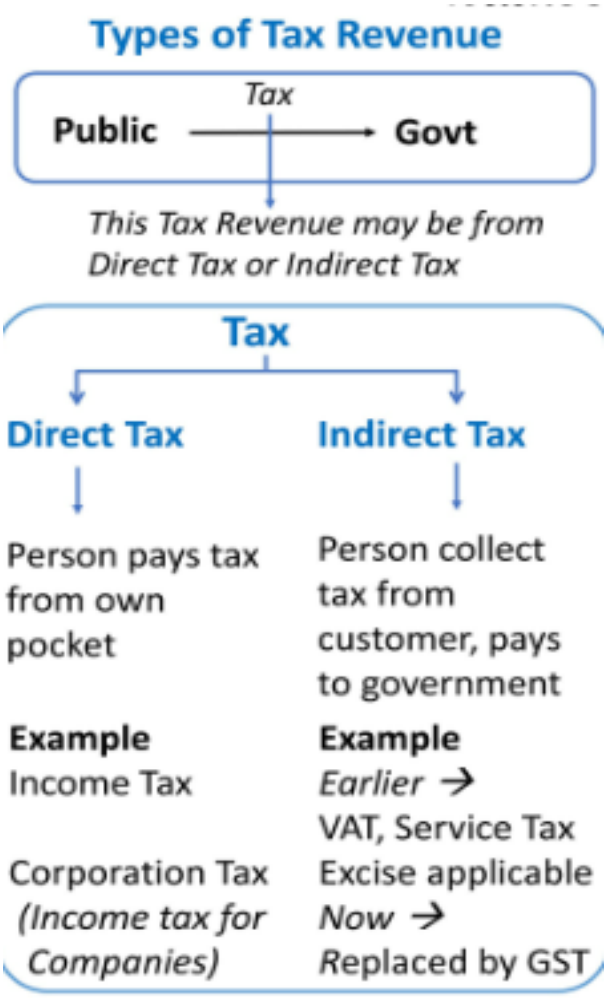

गैर-कर राजस्व

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

नकद अनुदान

- सरकार को विभिन्न देशों और यूएनओ जैसे संगठनों से नकद अनुदान (सहायता) प्राप्त होता है

लाभांश और लाभ

- केंद्र सरकार के पास एसबीआई, ओएनजीसी, बीएचईएल जैसे कई पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के शेयर हैं
- इन पीएसयू का मुनाफा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाता है

प्राप्त ब्याज

- केंद्र सरकार राज्य सरकार आदि को ऋण देती है जिस पर वह ब्याज अर्जित करती है

शुल्क एवं अन्य रसीदें

- सरकार विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क लेती है जैसे कंपनी पंजीकरण के लिए शुल्क आदि।
- यह कर आदि देर से जमा करने पर विलंब शुल्क और जुर्माना भी वसूलता है।

Example 1 -Aid

Aid /Cash Grant Received by Government from Foreign Country

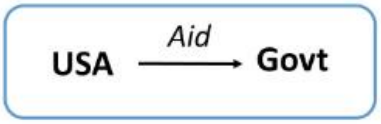

Example 2 -Dividend

Dividend (Profit share) received by Government from PSU

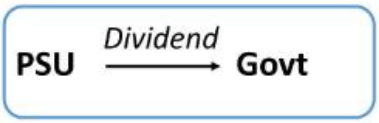

Example 3 –Interest Received

Interest received by Govt on loan given to State govt

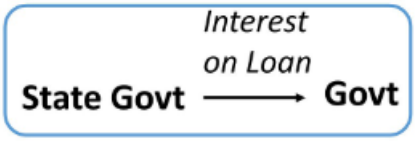

Example 4 –Fees Received

Govt Receives fees from Public for providing different services

Summary-Revenue Receipts

(Receipts of Govt which are Non-Redeemable)

Tax Revenue *(Revenue from Tax)*

Direct Tax

For Individuals
Personal Income Tax

For Companies
Corporation Tax

Indirect Tax

Earlier
Excise, Service Tax ,CST

Now
GST

Non-tax Revenue *(Revenue Other than Tax)*

4 Types

Cash Grant(Aid)→
From Outside Countries

Dividend→
From PSU

Interest Income→
On Loans Given

Fees→
From Public, Business

What are Capital Receipts

Receipts of Govt which
Increase Liability
or
Reduce Financial Assets

Hence,
Capital Receipts are of 2 types

- *Receipts which Create Liability*
  Example-
  Loan taken from public

- *Receipts which Reduce Asset*
  Example-
  Recovery of Loan Given

पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण जो देनदारी को बढ़ाता है

1. जनता से उधार

- सरकारी बांड जारी करके जनता से ऋण जुटाया गया

2. आरबीआई, वित्तीय संस्थानों और बैंकों से उधार

- -यह टी-बिल, सीएमबी, दिनांकित प्रतिभूतियों आदि की बिक्री के माध्यम से किया जाता है।

3. विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से उधार

उदाहरण - बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से ऋण लिया गया

4. बचत योजनाएँ

- -राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर बचत योजनाओं की बिक्री

पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण जो वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करता है

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली

- मान लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण दिया गया है। यह केंद्र सरकार की बैलेंस शीट में संपत्ति है
- मान लीजिए कि राज्य सरकार इस ऋण को चुकाती है। यह केंद्र सरकार की वित्तीय संपत्तियों में कमी है
- तो, यह एक पूंजीगत प्राप्ति है।

Example 1 –Repayment of Loan

Loan given by Central Govt to State govt is asset,
When it is repaid,
it is reduction of financial asset

विनिवेश

- विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों की बिक्री। सरकार के पास एसबीआई, ओएनजीसी, बीएचईएल जैसी विभिन्न कंपनियों के शेयर हैं।
- तो, ये केंद्र सरकार की संपत्ति हैं।
- मान लीजिए कि सरकार इन शेयरों को बेचती है, तो यह वित्तीय संपत्ति में कमी है। अतः, यह एक पूंजीगत प्राप्ति है।

Example 2 –Disinvestment

When Govt invest money in PSU, It is Financial Asset for Govt. When Govt Sells its share in PSU (does disinvestment), It is called Reduction of Financial Asset

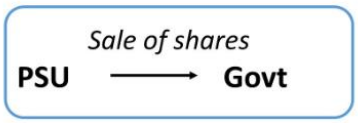

पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर

पूंजीगत व्यय क्या है?

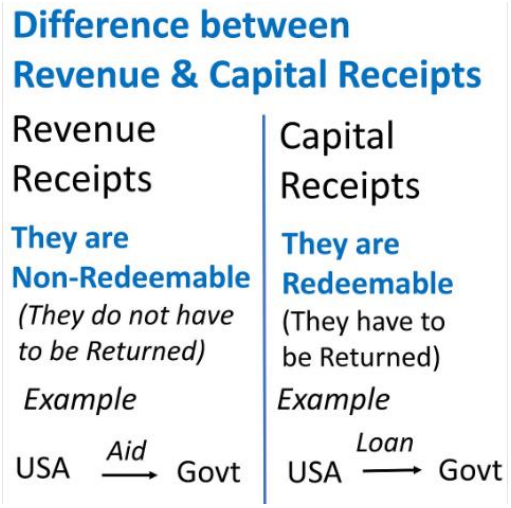

- यह उस व्यय को संदर्भित करता है जिससे संपत्ति का निर्माण होता है या सरकार की देनदारी में कमी आती है।

उदाहरण:

- भौतिक संपत्ति: सरकार द्वारा भवन या फर्नीचर की खरीद।
- वित्तीय संपत्ति: केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण, किसी कंपनी के शेयरों की खरीद
- वित्तीय देनदारियाँ कम करना: केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान।

Different Capital Receipts which Create Liability

Borrowings from Public by Govt

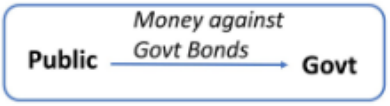

Borrowings from RBI

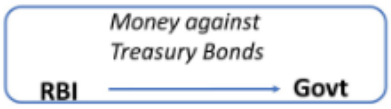

Borrowings from Foreign Govt/Foreign Institution

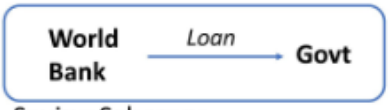

Saving Schemes
(Post Office Savings Scheme, NSC)

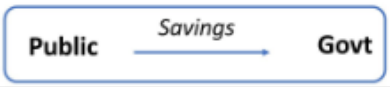

राजस्व व्यय क्या हैं?

- यह उस व्यय को संदर्भित करता है जो संपत्ति नहीं बनाता है या देनदारी को कम नहीं करता है। यह एक आवर्ती व्यय है
- ये सरकार के सामान्य रोजमर्रा के खर्चे हैं।
- उदाहरण: वेतन भुगतान, प्रशासनिक व्यय, राज्यों और अन्य देशों को दिया गया अनुदान, सरकार द्वारा हथियारों की खरीद, ब्याज भुगतान और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी।

They are recurring in nature	They are non recurring
Example	*Example*
Public —*Tax*→ Govt	Public —*Bonds*→ Govt
Tax will be collected again and again	*Public may not invest again in Bonds*

इसमें शामिल है:

1. सरकारी विभाग के सामान्य कामकाज के लिए व्यय

(जैसे कर्मचारियों को वेतन, कार्यालय व्यय)

2. ऋण पर ब्याज भुगतान

(केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण जिस पर उसे ब्याज देना होता है)

3. राज्य सरकार और अन्य को दिया गया अनुदान

(अनुदान वापसी योग्य नहीं है, इसलिए वे संपत्ति नहीं हैं)

4. सब्सिडी

यह वस्तु की कीमत कम रखने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की वित्तीय सहायता है

उदाहरण - रसोई गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 600 है, बाजार में 500 में बेचा जाता है (क्योंकि 100 सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है)

5.रक्षा व्यय

विभिन्न हथियारों की खरीद और सेना, नौसेना, वायु सेना आदि के वेतन का भुगतान करने पर व्यय।

संतुलित, अधिशेष और घाटे वाला बजट

हम जानते हैं कि बजट में प्राप्तियाँ और व्यय होते हैं।

- यदि प्राप्तियां व्यय के बराबर हैं, तो यह संतुलित बजट है
- यदि प्राप्तियाँ व्यय से अधिक हैं, तो यह अधिशेष बजट है
- यदि प्राप्तियाँ व्यय से कम हैं, तो यह घाटे का बजट है

इसलिए, हम कह सकते हैं कि बजट 3 प्रकार का होता है:

1. संतुलित बजट 2. अधिशेष बजट 3. घाटे का बजट

What is Deficit Budget

RECEIPTS	1000
PAYMENTS	1100
SURPLUS	0
DEFICIT	100

If Govt Receipts are **less than** Govt Expenditure it is called **Deficit Budget**

Here, Govt spends more than it collects

It is most common case

What is Surplus Budget

RECEIPTS	1000
PAYMENTS	800
SURPLUS	200

If Govt Receipts are **more than** Govt Expenditure it is called **Surplus Budget**

Here, Govt spends less than Money it collects

It is also Rare Case

What is Balanced Budget

RECEIPTS	1000
PAYMENTS	1000
SURPLUS	0

If Govt Receipts are equal to Govt Expenditure it is called ***Balanced Budget***

In this case., Govt spends exactly equal to Money it collects

It is Rare Case

राजस्व घाटा क्या है?

- यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है
- राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय
- इसमें केवल वे लेनदेन शामिल हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करते हैं।

How to Calculate Revenue Deficit?

Revenue Receipts	3000
Capital Receipts	2000
Total Receipts	**5000**
Revenue Expenditure	3200
Capital Expenditure	2100
Total Expenditure	**5300**

Answer

Revenue Expenditure	3200
Less	
Revenue Receipts	2000
Revenue Deficit	**1200**

Note-
To Calculate Revenue Deficit, we take only Revenue items and not Capital Receipts and Exp.

EFFECT OF REVENUE DEFICIT

Revenue Expenditure	3200
Less	
Revenue Receipts	2000
Revenue Deficit	**1200**

Effect

- Option 1: Govt Dissaves
- Option 2: Govt Borrows
- Option 3: Govt cuts Expenditure

What happens If Govt Dissaves in case of Revenue Deficit

Revenue Deficit

↓

Govt Dissaves (Use savings of Other sectors)

↓

Capital Receipt use to Pay Revenue Exp

Example
Funds received from Sale of PSU Used to pay Salaries To Govt Employees

नोट: डिसेव का अर्थ है वर्तमान खर्चों के लिए बचत का उपयोग करना।

What happens If Govt Borrows in case of Revenue Deficity

Revenue Deficit

↓

Govt Borrows *(Take loans or issue bonds)*

↓

Govt has to pay Interest

↓

Increase in Debt

↓

Increase in Interest Liability

What happens If Govt cuts Expenditure in case of Revenue Deficit

Revenue Deficit

Committed Exp	**Welfare Exp**	**Capital Exp**
↓	↓	↓
Can't be reduced	Causes Adverse effect in long run on welfare	Affects growth

How To Reduce Revenue Deficit?

We can Increase Revenue Receipts (like by -Increasing Taxation)

Example

Suppose my Revenue Deficit is 100 as shown below

Revenue Receipts	1000
Revenue Expenditure	1100
Revenue Surplus	0
Revenue Déficit	100

Answer

Increase Revenue Receipts by 100

Revenue Receipts	~~1000~~ 1100
Revenue Expenditure	1100
Revenue Surplus	0
Revenue Déficit	100

Second Method to Reduce Revenue Deficit?

We can increase Revenue Expenditure

(like by Decrease Govt Expenditure on Welfare Projects)

Example

Suppose my Revenue Deficit is 100 as shown below

Revenue Receipts	1000
Revenue Expenditure	1100
Revenue Surplus	0
Revenue Déficit	100

Answer

Increase Receipts Expenditure by 100

Revenue Receipts	1000
Revenue Expenditure	~~1000~~ 1100
Revenue Surplus	0
Revenue Déficit	0

राजकोषीय घाटा

⟶ यह कुल सरकारी व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है।

⟶ इसलिए, इस मामले में,

⟶ हम कुल व्यय (राजस्व और पूंजी दोनों) लेते हैं

⟶ हम कुल प्राप्तियां (राजस्व और पूंजी दोनों) लेते हैं लेकिन हम उन पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल नहीं करते हैं जो ऋण (ऋण) बनाती हैं।

टिप्पणी-

पूंजीगत प्राप्तियों में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋण की वसूली आदि।
- विनिवेश से बिक्री आय (पीएसयू के शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि)
- केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ऋण (आरबीआई, देश के बाहर, जनता से)
- इस मामले में, पहले 2 को गैर-ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है

(हम उन्हें राजकोषीय घाटे की गणना करते समय लेते हैं)

- और आखिरी को डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहा जाता है

(राजकोषीय घाटे की गणना करते समय हम इसे छोड़ देते हैं)

WHAT IS FISCAL DEFICIT?

It is difference between total Receipts and Total Expenditure Excluding borrowings

	REVENUE EXP
ADD	CAPITAL EXP
	TOTAL EXPENDITURE
Less	REVENUE RECEIPTS
	CAPITAL RECEIPTS (Non Debt)*
	FISCAL DEFICIT

↓

**Here we take all capital receipts But do not include borrowings*

Type of Capital Receipts

Example 1
How to calculate Revenue and Fiscal Deficit

RECEIPTS	
Revenue Receipts	3000
Capital Receipts (Non-debt)	2000
Capital Receipts (Debt)	1000
Total	**6000**
EXPENDITURE	
Revenue Exp	4500
Capital Exp	1500
Total	**6000**

Revenue Deficit
=Revenue Exp-Revenue Receipts
=4500-3000
=1500

Fiscal Deficit
=Total Exp-Revenue Receipt-Capital Receipt (non debt)
=6000-3000-2000
=1000

Example 2

CALCUALTE REVENUE DEFICIT AND FISCAL DEFICIT

REVENUE RECEIPTS	
Tax Revenue	100
Non Tax Revenue	200
Total	**300**
CAPITAL RECEIPTS	
Recovery Of Loans Given	50
From Sale of PSU(disinvestment)	250
From Borrowings	400
Total	**700**
REVENUE EXPENDITURE	**600**
CAPITAL EXPENDITURE	**400**

What is Revenue Deficit and Fiscal Deficit

Calculation of Revenue Deficit

Revenue Expenditure	600
Revenue Receipts	300
Revenue Deficit	300

Calculation of Fiscal Deficit

Revenue Exp	600
Capital Exp	400
Total Expenditure	**1000**
Revenue Receipts	300
Capital Receipts (Non-debt)	300
Total Receipts	**600**
Fiscal Deficit	**400**

NOTE

Borrowings	400
Fiscal deficit	400

hence,
Fiscal Deficit=Borrowings

प्राथमिक घाटा क्या है?

- यह चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और शुद्ध ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है

FORMULA

प्राथमिक घाटा

= राजकोषीय घाटा - शुद्ध ब्याज देयता

= राजकोषीय घाटा - (लिए गए ऋण पर पूर्ण भुगतान - दिए गए ऋण पर प्राप्त अंतर)

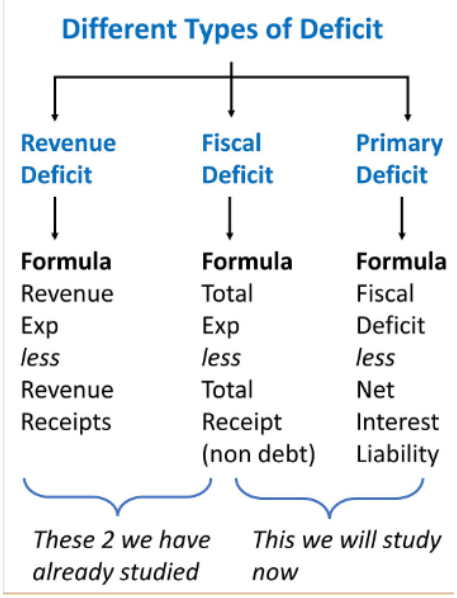

How to Calculate Revenue, Fiscal and Primary Deficit

RECEIPTS	
Revenue Receipts (Int Income 200,Others 2800)	3000
Capital Receipts (non Debt)	2000
Capital Receipts (Debt)	1000
TOTAL	**6000**
EXPENDITURE	
Revenue Exp (Interest Exp 500, Other Exp 4000)	4500
Capital Exp	1500
TOTAL	**6000**

Calculation of Revenue Deficit	
Revenue Expenditure	4500
Revenue Receipts	3000
Revenue Deficit	1500

Calculation of Fiscal Deficit	
Revenue Exp	4500
Capital Exp	1500
Total Expenditure	**6000**
Revenue Receipts	3000
Capital Receipts (non Debt)	2000
TOTAL RECEIPTS	**5000**
FISCAL DEFICIT	**6000**

Calculation of Primary Deficit	
Fiscal Deficit	1000
Less Net Interest Liability	300
Primary Deficit	700

Note-

This Int Income of 200 and int expense of 500 Is of loan given last year

So ,Net Interest liability of 500-200=300 is also of last year

How to Finance Budgetary Deficit

EXPENDITURE	1000
LESS	
RECEIPTS	800
DEFICIT	200

How to Finance this Deficit?
(How to meet the shortfall)

Option 1
Increase Taxation

Option 2
Increase Borrowing

Option 3
Print Currency

बजटीय घाटा क्या हैं?

हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि बजटीय घाटा प्राप्तियों पर व्यय की अधिकता है।

उदाहरण- राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा।

Option 1 -Increase Taxation

	Earlier	Now
Expenditure	1000	1000
Less		
Receipts	800	1000
Deficit	200	0

Govt increase taxes

↓

This Increases Govt Revenue (Receipts)

↓

Deficit Reduced

Note-
This Method is not popular as people don't like to pay more taxes)

Option 2 -Increase Borrowings

Expenditure	1000
Less	
Receipts	800
Deficit	200
Borrowings	200
Deficit After Borrowings	0

Govt takes loan And pay interest

↓

This interest is extra expense

↓

It adds to Deficit of Next year

Option 3 -Print Currency

Expenditure	1000
Less	
Receipts	800
Deficit	200
Less Currency Printed	200
Balance Deficit	0

Govt issues treasury bonds to RBI

↓

RBI prints currency

↓

Increase Money Supply in Economy

↓

Causes Inflation

बजटीय घाटे का वित्तपोषण कैसे किया जाता है?

व्यय और प्राप्तियों के बीच के अंतर को भरने के लिए, सरकार आम तौर पर निम्नलिखित में से एक कार्य करती है-

1. कराधान

- सरकार अपने कर बढ़ाती है (इससे सरकारी प्राप्तियाँ बढ़ती हैं)

2. उधार लेना

- सरकार सार्वजनिक या विदेशी संस्थानों से ऋण लेती है
- इससे उसकी कर्ज और ब्याज देनदारी बढ़ जाती है

3. पैसा छापना

- सरकार ने आरबीआई से पैसे छापने को कहा
- जब सरकार कोई मुद्रा छापना चाहती है, तो वह आरबीआई को प्रतिभूतियाँ देती है (जिसे सरकारी सुरक्षा कहा जाता है) जिसके बदले आरबीआई मुद्रा जारी करती है

उपरोक्त 3 तरीकों में से कौन सा ज्यादातर सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है?

- उधार लेने की विधि मुख्य रूप से सरकार द्वारा उपयोग की जाती है।
- सरकार बांड जारी करके अपना कर्ज बढ़ाती है जिस पर उसे ब्याज देना पड़ता है।
- यदि सरकार हर साल उधार लेना जारी रखती है, तो उसे इस पर अधिक से अधिक ब्याज देना होगा
- इस ब्याज को चुकाने के लिए सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ता है और यह सिलसिला चलता रहता है

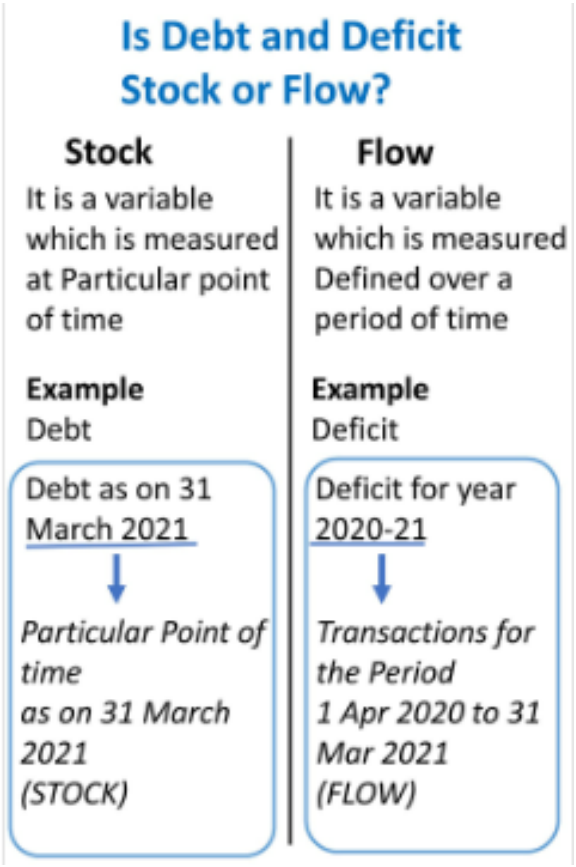

ऋण और घाटा स्टॉक है या प्रवाह?

⟶ हम जानते हैं कि स्टॉक को एक विशेष समय पर मापा जाता है

⟶ ऋण को वार्षिक रूप से 31 मार्च को मापा जाता है, इसलिए यह एक स्टॉक है

उदाहरण- 31 मार्च 2021 तक कर्ज

⟶ प्रवाह को हमेशा समय की अवधि में परिभाषित किया जाता है

⟶ इसलिए, घाटा एक प्रवाह है क्योंकि इसे एक विशेष अवधि के लिए मापा जाता है

उदाहरण- वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय घाटा

⟶ घाटा एक प्रवाह है जो ऋण के स्टॉक में वृद्धि करता है

हम वह जानते हैं,

⟶ ऋण को वार्षिक रूप से 31 मार्च को मापा जाता है, इसलिए यह एक स्टॉक है।

भी,

⟶ घाटा एक प्रवाह है क्योंकि इसे एक विशेष अवधि के लिए मापा जाता है

⟶ जितना अधिक घाटा होगा, उतना अधिक सरकार को घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना होगा। अत: घाटे से ऋण में वृद्धि होती है।

⟶ तो, हम कह सकते हैं कि, घाटा एक प्रवाह है जो ऋण के भंडार में इजाफा करता है

निम्नलिखित कारणों से सरकारी ऋण एक बोझ है

- जब कोई सरकार उधार लेती है, तो वह जनता को बांड जारी करती है। इन बांड्स पर सरकार को भविष्य में ब्याज देना होगा।
- इस ब्याज को चुकाने के लिए सरकार को भविष्य में टैक्स बढ़ाना होगा।
- जब सरकार भविष्य में टैक्स बढ़ाएगी तो भविष्य में लोगों की आय कम हो जाएगी।
- क्योंकि क्रय शक्ति गिर जाएगी, खपत भी गिर जाएगी (क्योंकि भविष्य में खर्च करने के लिए कम राशि उपलब्ध होगी)
- कम खपत का मतलब है भविष्य में कम उत्पादन और इसलिए कम जीडीपी
- क्योंकि जीडीपी गिर जाएगी, लोगों की बचत गिर जाएगी
- तो, कम पूंजी निर्माण और कम वृद्धि होगी। इसलिए, हम कह सकते हैं कि ऋण भावी पीढ़ी पर एक बोझ है

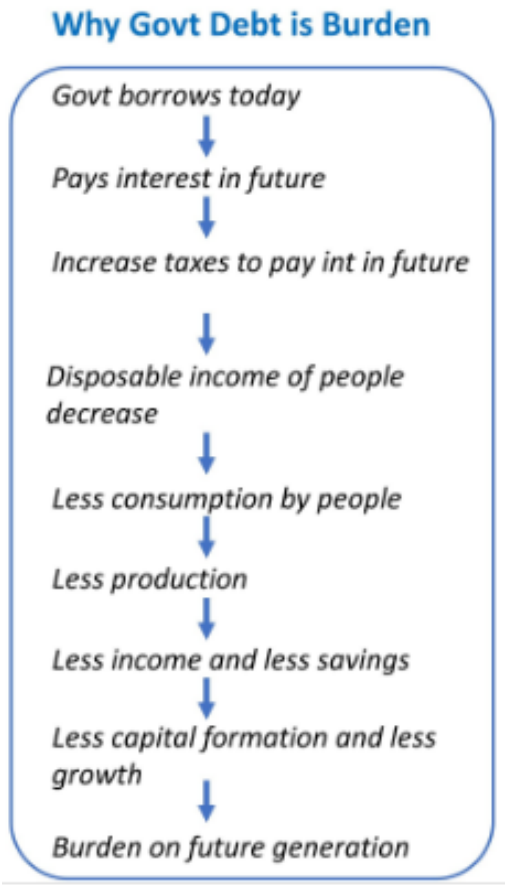

प्रतिवाद - सरकारी ऋण कोई बोझ नहीं है

- कर्ज का कोई महत्व नहीं है क्योंकि हम पर इसका कर्ज है
- यदि सरकार जनता से उधार लेती है, तो उसे जनता को ब्याज देना होगा
- यह ब्याज जनता की आय होगी

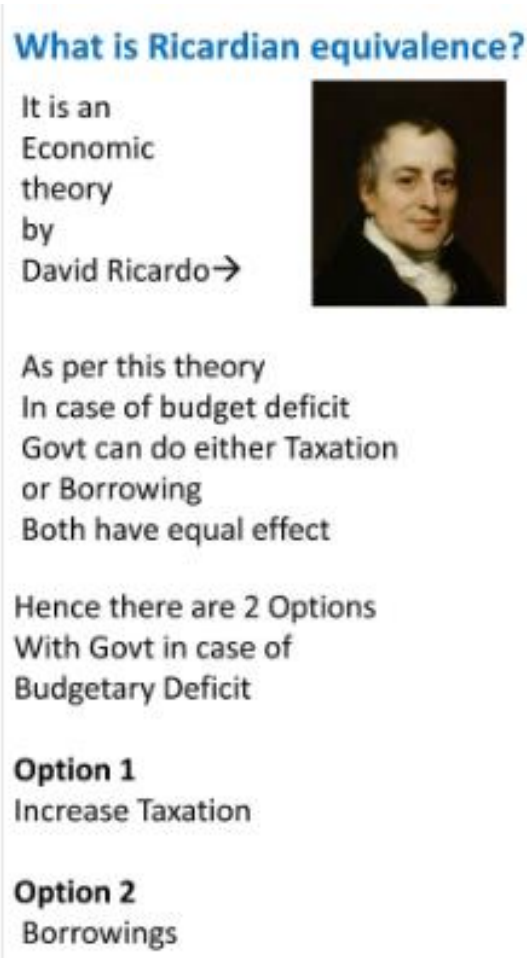

- दोनों मामलों में, कुल बचत समान रहती है।
- अत: जनता की आय में वृद्धि होगी
- क्योंकि लोगों की आय बढ़ेगी, वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक बचत करेंगे
- इसलिए सार्वजनिक बचत में वृद्धि सरकारी बचत में वृद्धि की भरपाई करेगी
- इस प्रति दृष्टिकोण को रिकार्डियन समतुल्यता कहा जाता है

रिकार्डियन तुल्यता क्या है?

- यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया एक आर्थिक सिद्धांत है
- इस सिद्धांत के अनुसार, कराधान और उधार बजट घाटे के वित्तपोषण के समतुल्य साधन हैं
- बजट घाटे की स्थिति में, सरकार या तो उधारी बढ़ा सकती है जिसे भावी पीढ़ी अधिक करों का भुगतान करके चुकाएगी या
- सरकार आज करों में वृद्धि कर सकती है और धन का उपयोग अधिक सरकारी व्यय करने के लिए कर सकती है।
- अगर सरकार आज उधारी बढ़ाती है। इससे सरकार पर ब्याज देनदारी बढ़ जाएगी। इस ब्याज को चुकाने के लिए सरकार भविष्य में टैक्स बढ़ाएगी। लोगों को उम्मीद होगी कि सरकार भविष्य में कर बढ़ाएगी, इसलिए वे आज अपने खर्च में कटौती करके अधिक बचत करेंगे।
- यदि सरकार आज कर बढ़ाती है, तो व्यक्ति की प्रयोज्य आय कम हो जाएगी। इसलिए, वे कम बचत कर पाएंगे. हालाँकि, सरकार अधिक बचत करने में सक्षम होगी।

Ricardian Equivalence Option 1

If Govt increases borrowing today

More borrowing by Govt

↓

More interest to be paid by Govt

↓

To Pay interest Govt will Increase Tax

↓

People know about increased taxes

↓

People cut their spending

↓

People's Income increases

↓

More tax to be paid

Summary

Govt can either increase borrowing which will be repaid by future generation by paying more taxes

Ricardian Equivalence Option 2

If Govt Increases taxes today

More taxes by Govt

↓

Less income left by People to spend

↓

People disposable income Reduced

↓

Less Saving by People But more saving for Govt due to increased taxes

↓

More Govt Expenditure

Summary

Govt can increase taxes today and use the money to make more govt expenditure

Counterview-

Debt is a Burden if taken from Outside Country

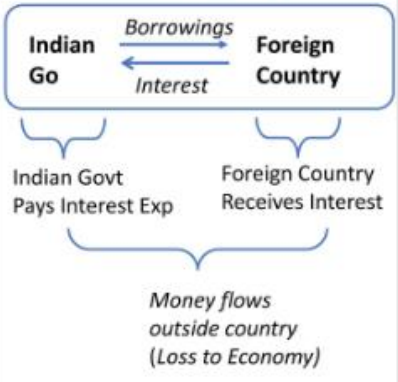

टिप्पणी:

यदि सरकार देश के भीतर (जनता से) कर्ज लेती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्ज बढ़ने से जनता को अधिक आय और बचत होगी।

- यदि सरकार बाहरी देश से कर्ज लेती है, तो यह मायने रखता है क्योंकि हमें बाहरी देश को ब्याज देना पड़ता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खर्च और विदेश के लिए आय होगी।

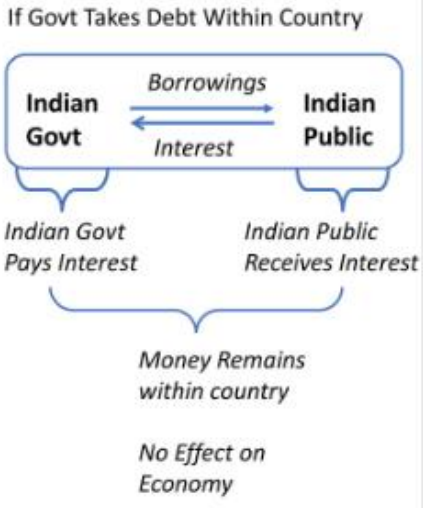

क्या बजट घाटा मुद्रास्फीतिकारी है?

- बजटीय घाटा या तो करों में कमी या सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण होता है।
- यदि सरकार करों को कम करती है, तो डिस्पोजेबल आय बढ़ जाती है। इसलिए, उत्पाद की मांग बढ़ जाती है।
- सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि के मामले में, सरकार अधिक उत्पाद खरीदेगी, इसलिए उत्पाद की मांग बढ़ जाती है जिससे अंततः कीमतों या मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

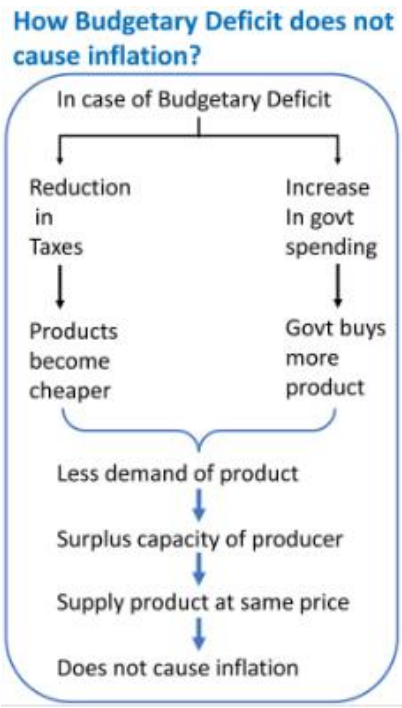

प्रति-दृश्य

बजट से महंगाई नहीं बढ़ती

- बजटीय घाटे से मांग में वृद्धि होती है
- लेकिन उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता है
- इसलिए, वे कीमतें बढ़ाए बिना इस मांग को पूरा करने में सक्षम हैं

बजटीय घाटे के कारण निवेश में कमी आती है

- बजटीय घाटे के कारण निजी क्षेत्र में निवेश में कमी आती है।
- बजटीय घाटे की स्थिति में, सरकार जनता को बांड जारी करके उधार लेती है।
- ये सरकारी बांड निजी कंपनियों के बांड से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए, सरकारी बॉन्ड के कारण निजी बॉन्ड को कम सदस्यता मिलती है।
- इससे निजी क्षेत्र को निवेश के लिए कम धन उपलब्ध होता है

प्रति-दृश्य

- बजटीय घाटे की स्थिति में, सरकार पैसा उधार लेती है और इस पैसे का उपयोग बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए करती है।
- इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि और अधिक आय होती है। अतः निजी क्षेत्रों को भी निवेश के लिए अधिक धन उपलब्ध है।

घाटे में कमी: बजटीय घाटे को कैसे कम करें?

हम जानते हैं कि घाटा = व्यय - प्राप्तियाँ

इसलिए, व्यय को कम करके या प्राप्तियों को बढ़ाकर घाटे को कम किया जा सकता है।

व्यय कम करके घाटा कम करना

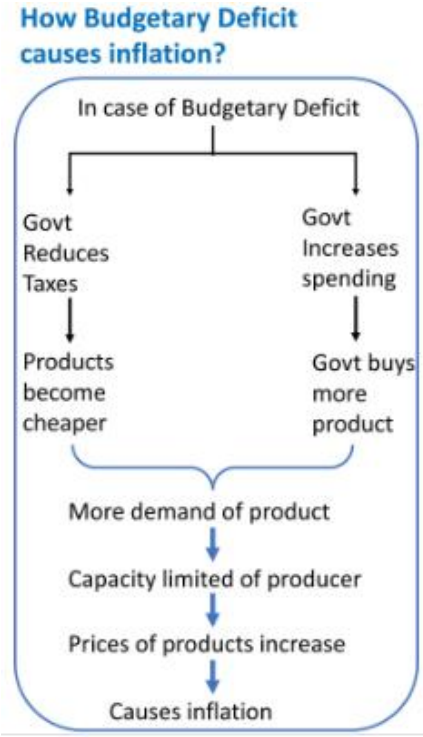

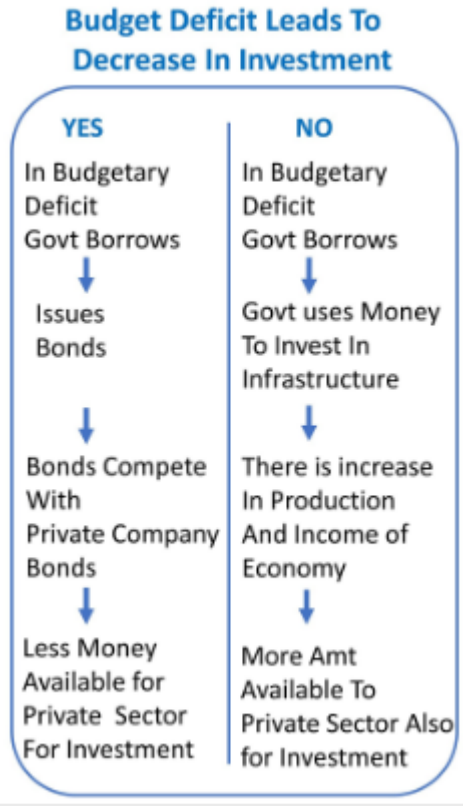

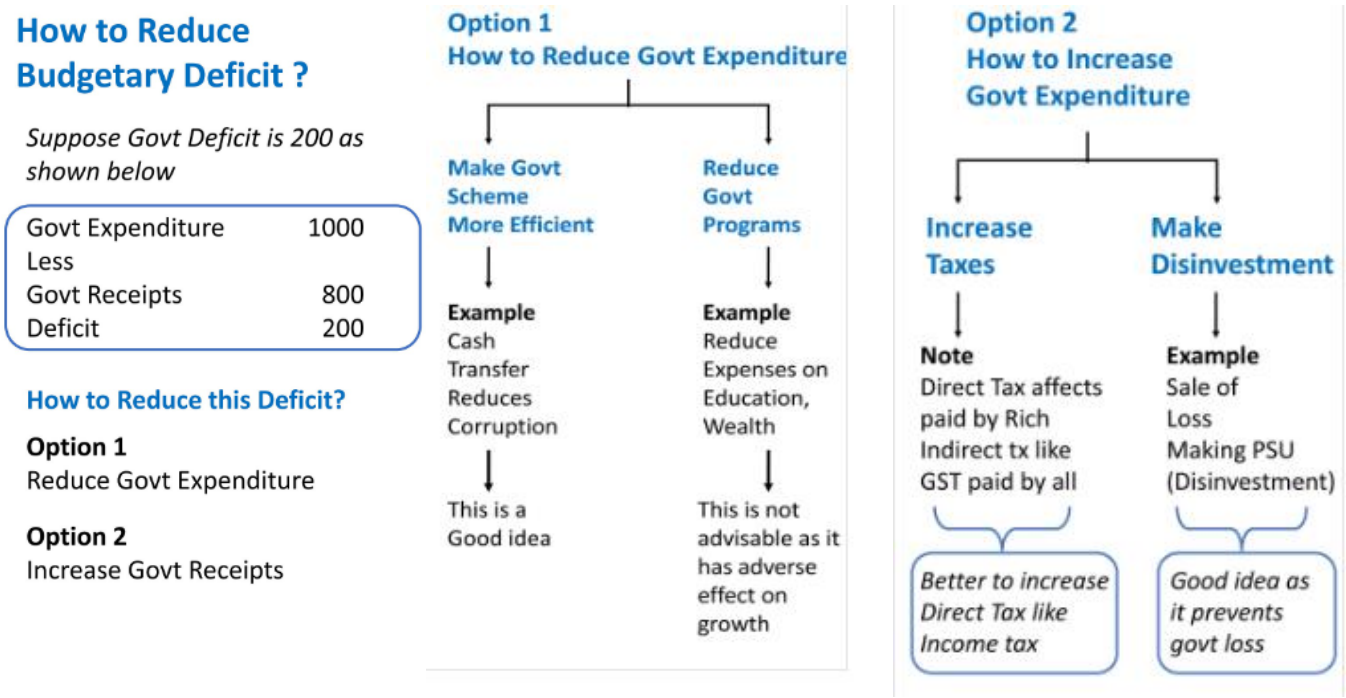

सरकारी योजनाओं को और अधिक कुशल बनाना

- सरकार खाद्य सब्सिडी (गरीब लोगों को मुफ्त राशन) जैसी कई सब्सिडी देती है।
- इस मामले में, बहुत भ्रष्टाचार है और आम आदमी तक वास्तव में बहुत कम सब्सिडी पहुंचती है
- तो इस मामले में, सरकार सब्सिडी देने के बजाय सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में बैंक हस्तांतरण शुरू कर सकती है
- इससे सरकार का पैसा बचेगा और राजस्व घाटे को पूरा करने में मदद मिलेगी

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को कम करना

- स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी खर्च बहुत महत्वपूर्ण है
- इन क्षेत्रों में खर्चों में कटौती करने से लंबे समय में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

प्राप्तियाँ बढ़ने से घाटे में कमी

घाटे को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा सकती है

- टैक्स 2 प्रकार के होते हैं-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
- प्रत्यक्ष करों (जैसे आयकर) को बढ़ाना बेहतर है क्योंकि यह प्रकृति में प्रगतिशील है (अमीरों पर अधिक कर, गरीबों पर कम या कोई कर नहीं)
- यदि जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, तो वे प्रकृति में प्रतिगामी हैं (अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं)
- सरकार विनिवेश कर सकती है
- सरकार धन प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने शेयर बेच सकती है जिसका उपयोग बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है

CLASS 12

CHAPTER 6

यह अध्याय निम्नलिखित अवधारणाओं को उजागर करेगा:

- ✓ खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था
- ✓ खुली अर्थव्यवस्था में संबंध
- ✓ भुगतान संतुलन
- ✓ बीओपी में खातों के प्रकार
- ✓ भुगतान स्थानांतरित करें
- ✓ व्यापार घाटा और अधिशेष
- ✓ निवेश के प्रकार
- ✓ आधिकारिक रिजर्व लेनदेन
- ✓ स्वायत्त लेनदेन
- ✓ समायोजनकारी लेनदेन
- ✓ विदेशी मुद्रा
- ✓ विनिमय दर निर्धारित करने की विधियाँ
- ✓ घरेलू मुद्रा की प्रशंसा और मूल्यह्रास
- ✓ क्रय शक्ति समता सिद्धांत
- ✓ मुद्रा का अवमूल्यन
- ✓ स्थिर बनाम लचीली विनिमय दर
- ✓ प्रबंधित फ़्लोट

खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बीच अंतर

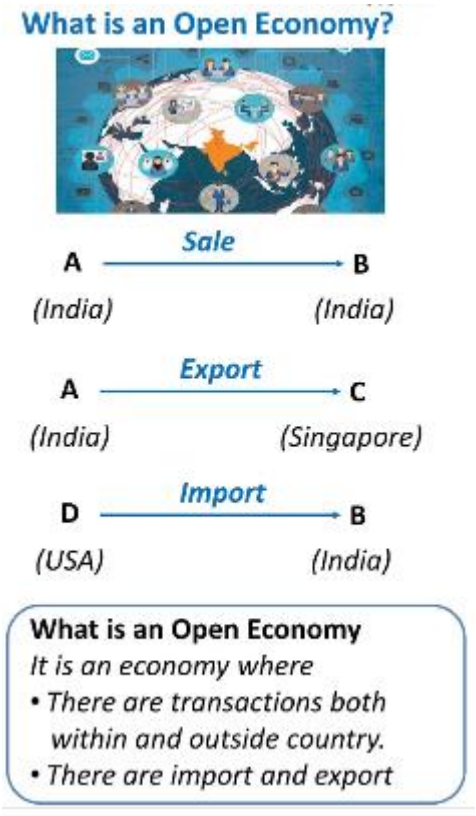

बंद अर्थव्यवस्था

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। बाहरी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है। कोई आयात-निर्यात नहीं है. सभी व्यापार आंतरिक (देश के भीतर) होते हैं।

खुली अर्थव्यवस्था

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका बाहरी दुनिया के साथ संपर्क है।
- विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंध हैं।
- निर्यात और आयात के साथ-साथ आंतरिक व्यापार भी होता है।

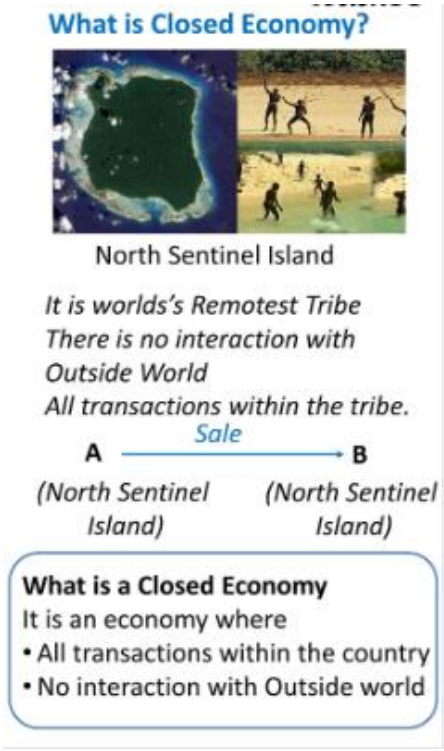

बंद अर्थव्यवस्था	खुली अर्थव्यवस्था
बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं	बाहरी शब्द के साथ अंतःक्रिया होती है
देश के बाहर कोई आर्थिक संबंध नहीं	विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंध हैं
केवल आंतरिक व्यापार किया जाता है	निर्यात और आयात के साथ-साथ आंतरिक व्यापार भी होता है
यह एक अवास्तविक अवधारणा है (आमतौर पर नहीं पाई जाती)।	यह आजकल अधिकतर पाया जाता है और दुनिया के लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्था वाले हैं (कुछ अधिक खुली और कुछ कम)।

खुली अर्थव्यवस्था में संबंध

खुली अर्थव्यवस्था में, बाहरी दुनिया के साथ तीन प्रकार के संबंध होते हैं।

उत्पाद बाज़ार लिंकेज

- उपभोक्ता और फर्म चुन सकते हैं कि घरेलू सामान और विदेशी सामान से सामान और सेवा खरीदनी है या नहीं
- वे स्थानीय उत्पाद या आयातित उत्पाद खरीद सकते हैं

वित्तीय बाज़ार लिंकेज

- निवेशक चुन सकते हैं कि उन्हें घरेलू संपत्ति में निवेश करना है या विदेशी संपत्ति में
- वे भारतीय कंपनियों या विदेशी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं

श्रम बाज़ार लिंकेज

- श्रमिक चुन सकते हैं कि उन्हें कहाँ काम करना है, चाहे भारत में या भारत के बाहर
- फर्म यह भी चुन सकती है कि उसे अपनी फ़ैक्टरियाँ कहाँ स्थापित करनी हैं, भारत के भीतर या भारत के बाहर

Closed Economy & Open Economy

Closed Economy	Open Economy
No Interaction or Economic Relation with Outside world	There is interaction & Economic Relation with Outside world
There is only Internal Trade	There is Internal Trade+ Export Import
It is unrealistic Concept	It is Mostly found
No country is completely closed economy	All countries are Open Economies *Some more Open Example*-USA *Some less open Example*-North Korea
There is no Linkage	*There are 3 types of linkage:* Product Market Financial Market Labor Market Linkage

Characteristics /Properties Of Open Economy

What is Open Economy?

It is an economy which trades with other economies in goods, services and financial assets

It has 3 types of linkages

Output Market Linkage	→	Trade in Goods & Service allowed with Other Economies
Financial Market Linkage	→	Trade in Financial Assets allowed with Other Economies
Labour Market Linkage	→	Trade in Labor Market allowed with Other Economies

भारत की अर्थव्यवस्था खुली है या बंद अर्थव्यवस्था?

- भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है।
- भारत का आयात और निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है

  हालाँकि, हम उन अन्य देशों की तुलना में कम खुले हैं जिनका व्यापार अनुपात अधिक है।

भारत में भी सभी 3 प्रकार के लिंकेज उपलब्ध हैं

- हम भारतीय उत्पादों या आयातित उत्पादों (उत्पाद बाजार लिंकेज) के बीच चयन कर सकते हैं
- हम भारतीय शेयर बाजार या विदेशी शेयर बाजार (फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज) में निवेश कर सकते हैं।
- हम भारत में या भारत के बाहर काम करना चुन सकते हैं (श्रम बाजार लिंकेज)

भारत एक खुली अर्थव्यवस्था क्यों है?

We can choose to buy Indian product or foreign product *(Product Market Linkage)*

We can choose to invest in Indian Companies or Foreign Companies *(Financial Market Linkage)*

We can chose to work in India or Outside India *(Labour Market Linkage)*

Domestic Trade & Circular flow of Income Circular flow of Income

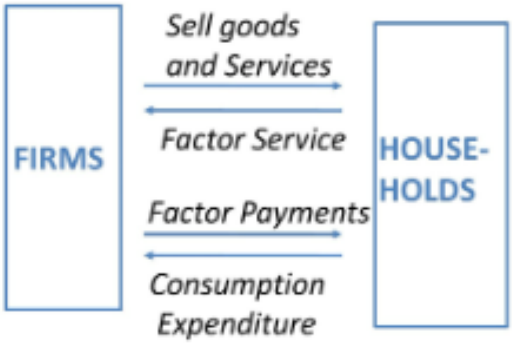

Note:-
Incase of domestic trade
Money Remains within country
As both Firm and household are from within country

How does Foreign Trade Affect Circular Flow of Income?

Import

Here, Money is flowing out of India
Hence we can say,
Import leads to Leakage from Circular flow of Income

Export

Here, money is flowing into India due to exports
Hence we can say,
Export leads to Injection into Circular flow of Income

भुगतान संतुलन क्या है?

- यह एक लेखा वर्ष में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्ति में लेनदेन का एक आर्थिक रिकॉर्ड है।
- विदेशों से प्राप्त राशि जमा की जाती है (सकारात्मक आंकड़े के रूप में दिखाया गया है)
- विदेशी देशों को भुगतान की गई राशि डेबिट की गई है (नकारात्मक में दिखाया गया है)

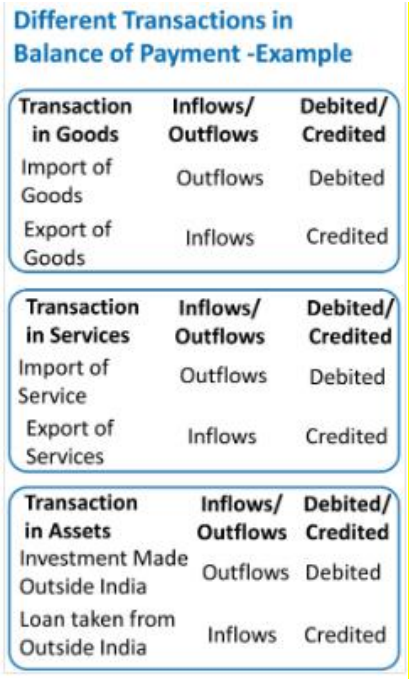

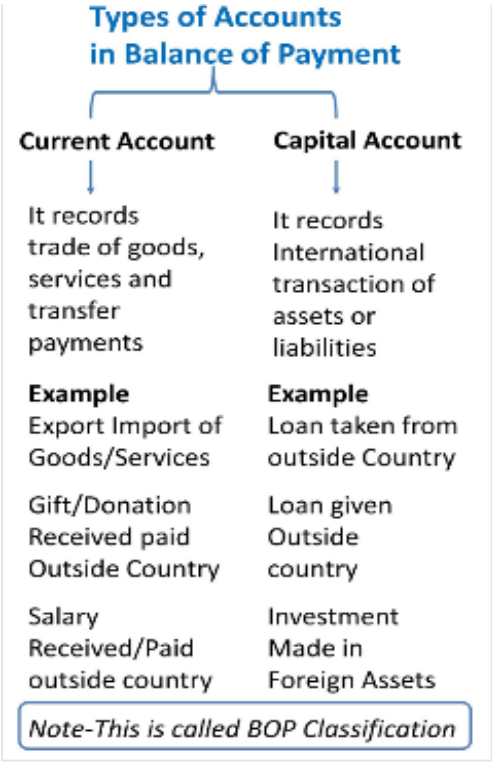

भुगतान संतुलन में खाते के प्रकार

इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं - पूंजी खाता और चालू खाता।

चालू खाता क्या है?

चालू खाता निम्नलिखित का योग है:

- वस्तुओं का निर्यात आयात: इसे व्यापार संतुलन कहा जाता है
- सेवाओं का निर्यात/आयात: इन 2 को अदृश्य कहा जाता है
- स्थानांतरण भुगतान (एकतरफा स्थानांतरण)

वस्तुओं का व्यापार

(निर्यात, माल का आयात)

हम जानते हैं कि निर्यात का अर्थ है देश के बाहर माल बेचना और

आयात का अर्थ है बाहरी देश से सामान खरीदना।

व्यापार संतुलन = वस्तुओं का निर्यात - वस्तुओं का आयात

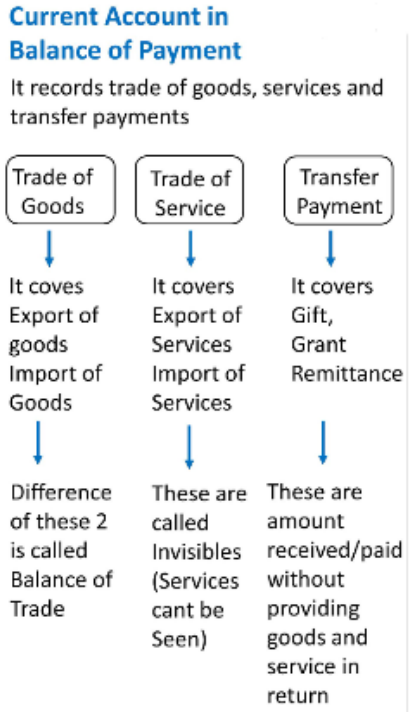

उदाहरण:

मान लीजिए देश ने 500 करोड़ का माल निर्यात किया

इसने 300 करोड़ का माल आयात किया

इस स्थिति में, व्यापार संतुलन = निर्यात - आयात = 500-300 = 200 करोड़

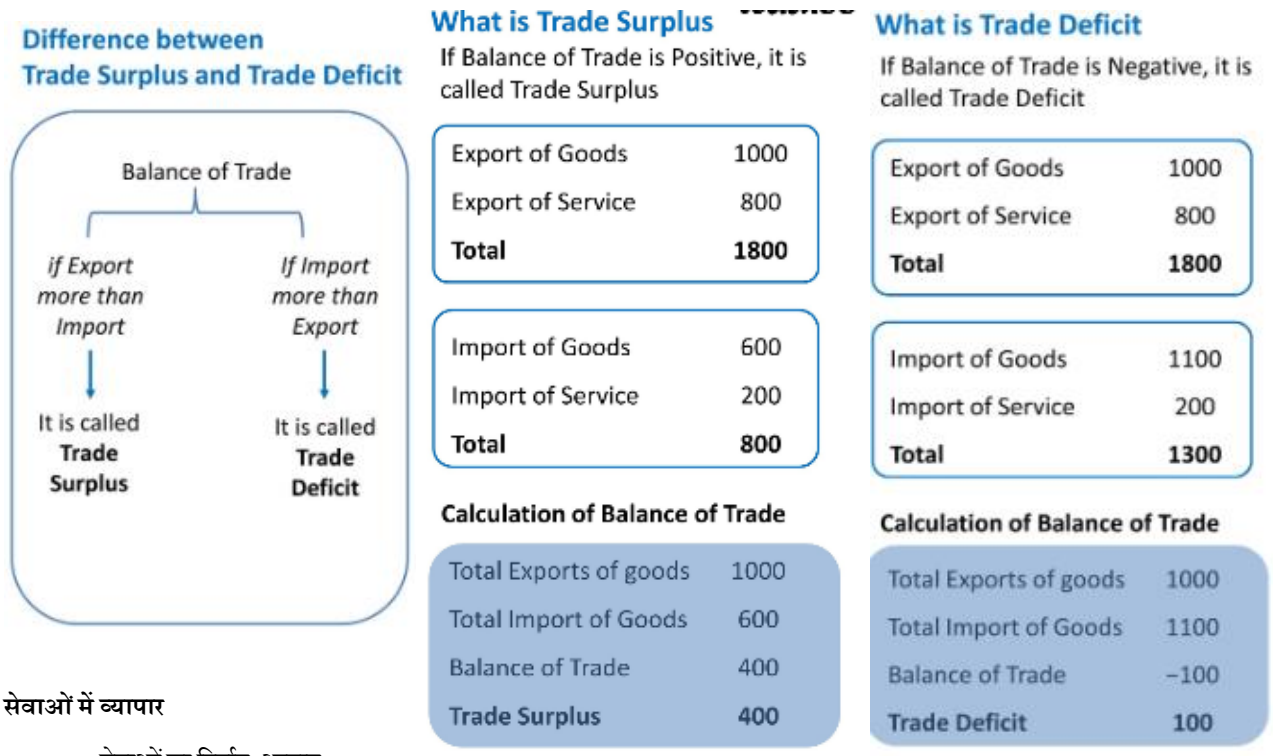

सेवाओं में व्यापार

⟶ सेवाओं का निर्यात, आयात

⟶ वस्तुओं की तरह, सेवाओं का भी निर्यात/आयात किया जा सकता है।

उदाहरण: भारत में सॉफ्टवेयर कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका को तकनीकी सेवा प्रदान करती हैं

⟶ इसी तरह हम बाहरी देश से भी Service ले सकते हैं.

उदाहरण: भारत की एक कंपनी फ्रांस स्थित एक वास्तुकार से परामर्श लेती है

नोट - वस्तुओं के विपरीत, सेवाओं को नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, उन्हें अदृश्य या अदृश्य व्यापार कहा जाता है।

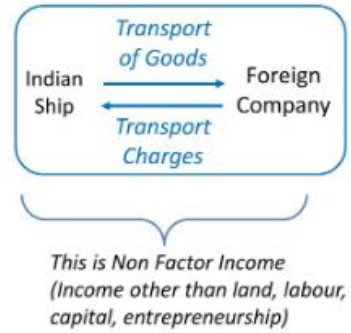

शुद्ध कारक आय

- ये उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय हैं जैसे कर्मचारियों को मुआवजा, शेयरधारक को लाभांश, ऋण पर ब्याज और उद्यमियों को लाभ (उत्पादन के कारक)
- हम शुद्ध आय = अर्जित आय कम भुगतान की गई आय लेते हैं

शुद्ध गैर-कारक आय

इनमें उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय के अलावा अन्य आय भी शामिल है। उदाहरण: शिपिंग, बीमा, बैंकिंग, पर्यटन आदि।

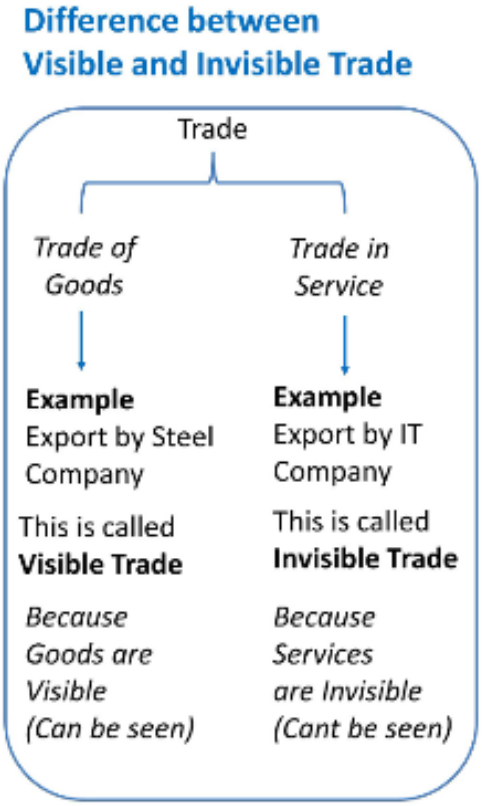

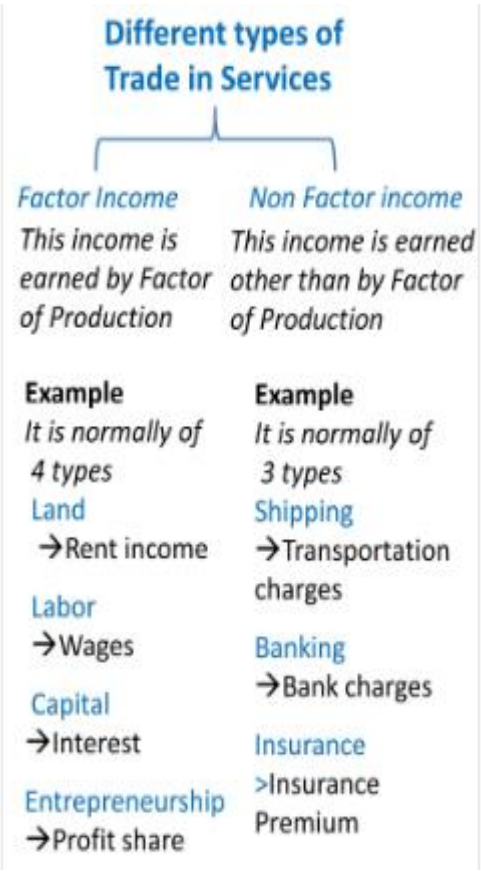

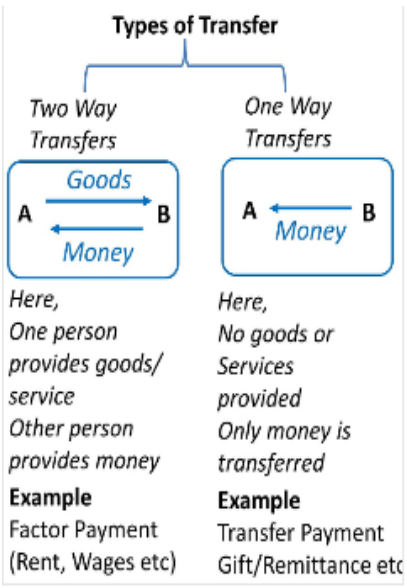

स्थानांतरण भुगतान (एकतरफा स्थानांतरण)

→ इसमें निवासियों द्वारा निःशुल्क प्राप्त की गई राशि (बदले में कोई वर्तमान या भविष्य का भुगतान किए बिना) शामिल है। इन्हें वन-वे ट्रांसफ़र भी कहा जाता है।

उदाहरण: बाहरी देश से प्राप्त उपहार/अनुदान और प्रेषण।

व्यापार अधिशेष और घाटा क्या है?

- यदि देश का निर्यात आयात से अधिक हो तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है।
- यदि किसी देश का आयात निर्यात से अधिक है तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है
- यहां, हम केवल वस्तुओं पर विचार करते हैं, सेवाओं पर नहीं

Example 1

A gift given by Indian citizen to his Canadian Friend

Example 2

USA Govt gave aid for Covid Relief to India.

Note

It is also called Unilateral Transfers

चालू खाता अधिशेष/घाटा क्या है?

चालू खाते में 3 प्रकार की आय होती है

1. माल का शुद्ध निर्यात (माल का निर्यात-आयात)
2. सेवाओं का शुद्ध निर्यात (निर्यात - सेवाओं का आयात)
3. एकतरफ़ा स्थानान्तरण

यदि तीनों का योग सकारात्मक है, तो यह चालू खाता अधिशेष है

यदि तीनों का योग नकारात्मक है, तो यह चालू खाता घाटा है

क्या किसी देश में व्यापार घाटा और चालू खाता अधिशेष हो सकता है?

हाँ।

किसी देश में निर्यात की तुलना में वस्तुओं का आयात अधिक हो सकता है, इसलिए व्यापार घाटा होता है

हालाँकि, यदि चालू खाता अधिशेष होने के लिए सकारात्मक अदृश्य (सेवाओं का शुद्ध निर्यात और स्थानांतरण आय) हो सकता है

उदाहरण:

माल का शुद्ध निर्यात (निर्यात - माल का आयात)	-5000 (व्यापार घाटा)
सेवाओं का शुद्ध निर्यात (निर्यात - सेवाओं का आयात)	6000
एकतरफा स्थानान्तरण	1000
चालू खाता अधिशेष	2000

Can we have Trade Deficit & Current Account Surplus?

Receipt	
Export of Goods	1000
Export of Service	900
Remittance Received	300
Total	**2200**
Payments	
Import of Goods	1600
Import of Service	200
Gift Given	100
Total	**1900**

Trade Deficit
=Import of Goods-Export of Goods
=1600-1000=600

Current Account Surplus

=Trade in Goods	1000-1600=-600
+Trade in Service	900-200=700
+Unilateral Transfers	300-100=-200
Total	**300**

What are Invisibles?

Trade in Services
and
Transfer Payments
are called Invisibles

For Calculation of
Current Account Surplus/Deficit
We consider 3 things

1. Total Exports of goods
2. Total Import of Goods
3. Trade Deficit

These 2 are called invisibles as we cant physically see them

पूंजी खाता

- इसमें शेष विश्व से पूंजी प्रवाह घटाकर शेष विश्व में पूंजी प्रवाह शामिल है
- इनमें निवासियों और शेष विश्व के बीच लेनदेन शामिल हैं जो सरकार या निवासियों की संपत्ति/देयता स्थिति में परिवर्तन का कारण बनते हैं

पूंजी खाता लेनदेन का उदाहरण:
उधार निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं

1. बाहरी सहायता

इसमें विदेशी सरकारों से लिया गया कर्ज भी शामिल है

2. बाह्य वाणिज्यिक उधार

इसमें विदेशी बैंकों या अन्य संस्थानों से लिया गया उधार शामिल है
ये उधार सरकारी या निजी क्षेत्र के हो सकते हैं

Different Types of Capital Account Transactions

Investment	Borrowings	Deposits
Example	**Example**	**Example**
Investment made by Indian investors in foreign assets	Loan taken by Indian business from foreign banks	Indian Deposits Funds in Foreign Banks
Investment made in India by foreign investors	Loan extended by Export Import bank of India to foreign countries	Non Residents depositing funds in Indian Banks

External Commercial Borrowings Calculation

Loan by EXIM Bank India to Foreign Companies	*5000*
Loan to Indian Companies by Foreign Banks	*6000*
Answer	
Loan Received	6000
less	
Loan Given	5000
External Commercial Borrowing	**1000**

Note-
We calculate Net ECM
Loan Received
less
Loan Given

Difference between External Assistance and External Commercial Borrowings

External Assistance	**External Commercial Borrowings**
It includes loan taken from foreign governments	It includes Borrowings from Foreign Banks or other institutions
Note This loan Is not for Commercial purpose (Taken by Govt)	**Note** This loan Is for Commercial purpose (Taken by Govt or Private Sector)

What are External Commercial Borrowing

EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS

Foreign country | *Business purpose* | *Loan*

It refers to commercial loans taken by Residents from Non Residents

Important Points

- This loan is for business purpose (and not foreign aid)
- This loan is normally taken by industries and companies
- These loans may be short term or long term

What is External Assistance

EXTERNAL ASSISTANCE

Foreign country | Help or Aid

It refers to help/aid received by one state to another state

Important Points

- This loan is not for commercial purpose
- It is for helping different countries at time of financial crises or in case of calamity
- It is given by one govt to another (not business)

We calculate Net External Assistance
Aid /Assistance Received
less
Aid/Assistance Given

How to Calculate External Assistance

Loan given by Indian Govt to Afghanistan Govt for Infrastructure Development	*7000*
Loan received by Indian Govt from USA Govt for Covid Relief	*8000*
Answer	
Aid /Assistance Received	8000
less	
Aid/Assistance Given	7000
External Assistance (net)	1000

Note-
We calculate Net EA
Aid Received
less
Aid Given

निवेश निम्न प्रकार का होता है:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में किया गया निवेश जैसे (विदेश में व्यवसाय/फ़ैक्टरी स्थापित करना)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

- विदेशी देशों के शेयरों में निवेश करना या विदेशी देशों के बांड की खरीद।
- इसमें रियल एस्टेट या विदेश की अन्य परिसंपत्तियों में निवेश भी शामिल हो सकता है।

Different Types of Investments (FDI and FII)

Foreign Direct Investment (FDI)	Portfolio Investment (FII)
It means Setting up a New business in Foreign Country (Establishing Factory, Shop, Office)	It means Purchasing Shares of Foreign Companies Investing in Assets (Deposits, Land) etc of Foreign Countries
It is less liquid (Amount invested cannot be withdrawn easily)	It is more liquid (Amount invested can be withdrawn easily)
It is more beneficial to the country where investment made as it generates employment	It is less beneficial to the country where investment made as no new employment generated

शुद्ध पूंजी प्रवाह क्या है?

- इसका मतलब है कि शेष विश्व से पूंजी प्रवाह में से शेष विश्व में पूंजी प्रवाह को घटाकर।
- यदि शुद्ध पूंजी संतुलन सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि पूंजी अधिशेष है
- यदि शुद्ध पूंजी संतुलन नकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि पूंजी घाटा है

How to Calculate Net investments

It is difference between Investment Received and Investment Made

Example	Amount
• Purchase of Shares in US Companies Shares by Indian Investors	1000
• Purchase of land in USA by Indian Citizen	1500
• Adani India purchased coal mines in Australia	200
• Investment in Indian Stock Market by Dubai Investors	3000
• Amt invested in Bullet Train Project by Japan	4000

Particular	Amount
Investment Made	7000
Less	*(3000+4000)*
Investment Received	2700
	(1000+1500+200)
Net Investment	4300

Difference between Balance of Payment Surplus, Deficit & Equilibrium

BOP Surplus	BOP Deficit	BOP Equilibrium
Sum total of Capital & Current Account is **Positive**	Sum total of Capital & current Account is **Negative**	Sum total of Capital & current Account is **0**
it leads to **Increase** in Forex Reserves	it leads to **decrease** in Forex Reserves	There is **no change** in Forex Reserves

What does Central bank do in Case of Balance of Payment Surplus?

Current Account Surplus	1000
Capital Account (Deficit)	-600
Balance of Account Surplus	**400**

Got has extra money of 400
it ask RBI to buy
Foreign Exchange (Dollars)
or Gold upto amount of Surplus

This is called
Official Reserve Transactions

What does Central bank do in Case of Balance of Payment Deficit?

Current Account Surplus	1000
Capital Account (Deficit)	-1100
Balance of Account Surplus	**-100**

Got has shortage of 100
it ask RBI
To sell Foreign Exchange (Dollars)
or
take loan from IMF, World bank

This is also
Official Reserve Transactions

आधिकारिक आरक्षित लेनदेन क्या हैं?

- वे भुगतान संतुलन अधिशेष या घाटे के मामले में विदेशी मुद्रा के आधिकारिक भंडार का प्रबंधन करने के लिए मौद्रिक प्राधिकरण (केंद्रीय बैंक या आरबीआई) द्वारा किए गए लेनदेन हैं।
- घाटे के दौरान विनिमय बाजार में विदेशी मुद्राएं बेचकर भंडार निकाला जाता है, अधिशेष के दौरान विदेशी मुद्राएं खरीदी जाती हैं।

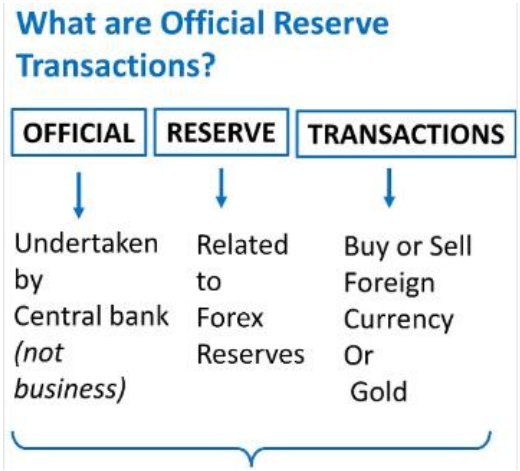

स्वायत्त लेनदेन और समायोजन लेनदेन

- विदेशी लेनदेन को स्वायत्त या समायोजन लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

स्वायत्त लेनदेन

- वे ऐसे लेनदेन हैं जो लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं
- ये आम तौर पर निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं
- ये बीओपी की स्थिति की परवाह किए बिना किए जाते हैं

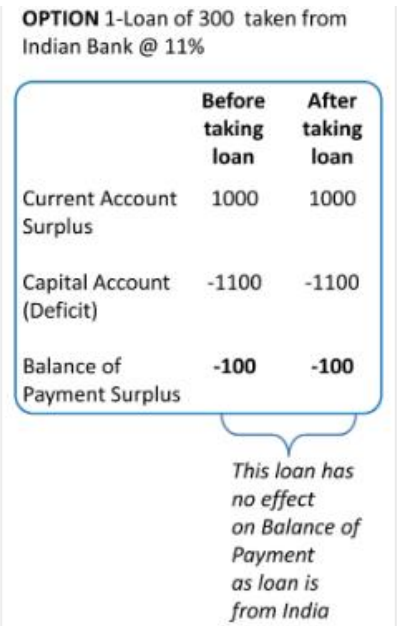

उदाहरण:

- यदि कोई व्यापारी सामान खरीदना चाहता है और आयातित सामान भारतीय सामान की तुलना में सस्ता है, तो वह आगे बढ़कर आयातित सामान खरीदेगा।
- वह इस तथ्य पर विचार नहीं करेगा कि इससे आयात बढ़ेगा और बीओपी नकारात्मक होगी
- ये लेनदेन पूंजी और चालू खाते दोनों में हो सकते हैं।

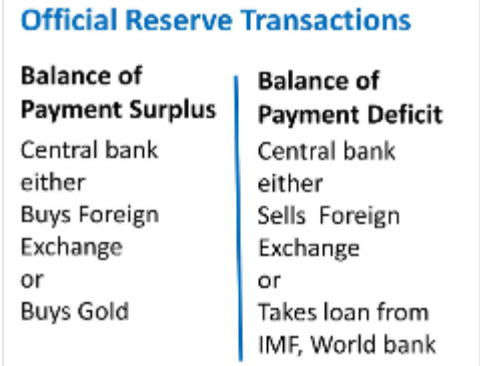

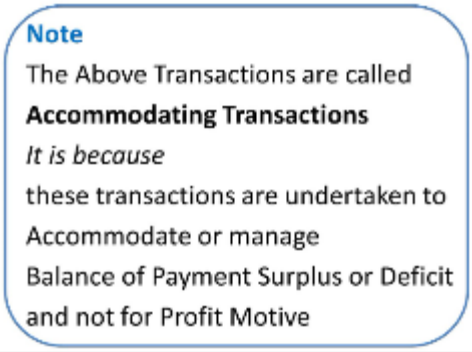

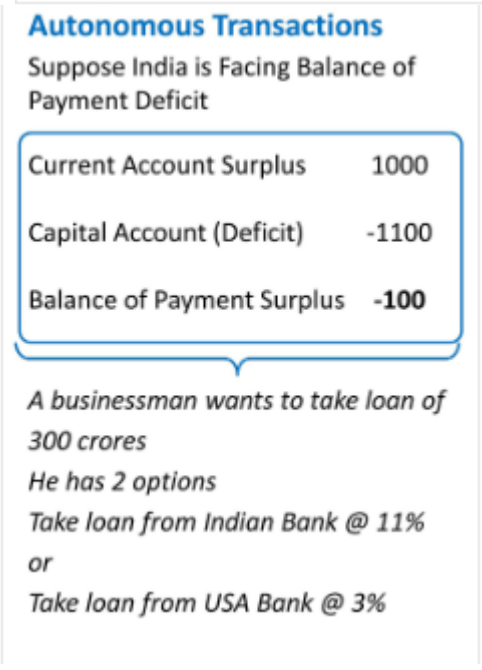

व्यवसायी कौन सा विकल्प चुनेगा?

- व्यवसायी विकल्प 2 को चुनेगा और विदेशी बैंक से ऋण लेगा क्योंकि वह कम ब्याज पर ऋण प्रदान कर रहा है। लेकिन इस कर्ज से बीओपी में घाटा बढ़ेगा.

अनुकूल लेन-देन

- वे ऐसे लेनदेन हैं जो लाभ के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। ये आम तौर पर सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। यदि बीओपी नकारात्मक है तो ये आम तौर पर किए जाते हैं।

उदाहरण:

⟶ चालू खाता घाटा -300 और पूंजी खाता अधिशेष 200 है

⟶ इस मामले में, भुगतान बिल = -300 + 200 = -100

⟶ इसलिए सरकार आधिकारिक आरक्षित लेनदेन में संलग्न होगी (अपने विदेशी मुद्रा लेनदेन को बेचेगी)

⟶ इससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आएगी. ये केवल पूंजी खाते में होते हैं.

Accommodating Transactions

Suppose India is Facing Balance of Payment Deficit

Current Account Surplus	*1000*
Capital Account (Deficit)	*-1100*
Balance of Account Surplus	***-100***

What will RBI do in this case?

OPTION 1
RBI will Sell Foreign Currency of 100 to meet deficit

Option 2
RBI will borrow 100 from IMF/World Bank etc.

Note
Above transactions are not undertaken for Profit Motive. They are undertaken to accommodate or manage Balance of Payment Deficit .So it is called **Accommodating Transactions**

AUTONOMOUS TRANSACTION	ACCOMODATING TRANSACTIONS
They are international transactions which are undertaken for profit motive	They are international transactions which are undertaken to cover BOP Surplus/Deficit
They are undertaken by Private Sector	They are undertaken by Monetary Authority (Central Bank, RBI)
They are undertaken irrespective of effect on Balance of Payment	They are undertaken after seeing status of Balance of Payment Surplus/deficit

मुद्रा क्या है?

- यह वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान का माध्यम है।

उदाहरण- डॉलर, रुपया आदि।

विदेशी एवं घरेलू मुद्रा क्या है?

- जो मुद्रा अपने देश में प्रयोग की जाती है उसे घरेलू मुद्रा कहा जाता है

- घरेलू मुद्रा के अलावा अन्य सभी मुद्राओं को विदेशी मुद्रा कहा जाता है
- इसलिए, भारत में INR (भारतीय राष्ट्रीय रुपया) घरेलू मुद्रा है और पाउंड, डॉलर आदि विदेशी मुद्रा हैं

विदेश व्यापार किस मुद्रा में होता है?

- विदेशी मुद्रा आम तौर पर डॉलर या यूरो जैसी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं में होती है।
- आईएनआर जैसी घरेलू मुद्राएं आमतौर पर विदेशी व्यापार के लिए स्वीकार नहीं की जाती हैं।
- इसलिए विदेशी व्यापार करने के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

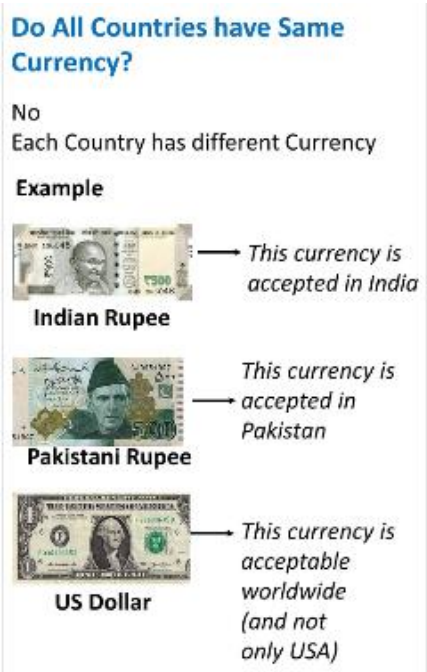

विदेशी मुद्रा दर क्या है?

- यह एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत है।

विदेशी मुद्रा बाज़ार क्या है?

यह वह बाज़ार है जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। इसमें 3 प्रमुख प्रतिभागी हैं:

1. वाणिज्यिक बैंक
2. विदेशी मुद्रा दलाल और अधिकृत व्यापारी
3. मौद्रिक प्राधिकरण (भारत में आरबीआई)

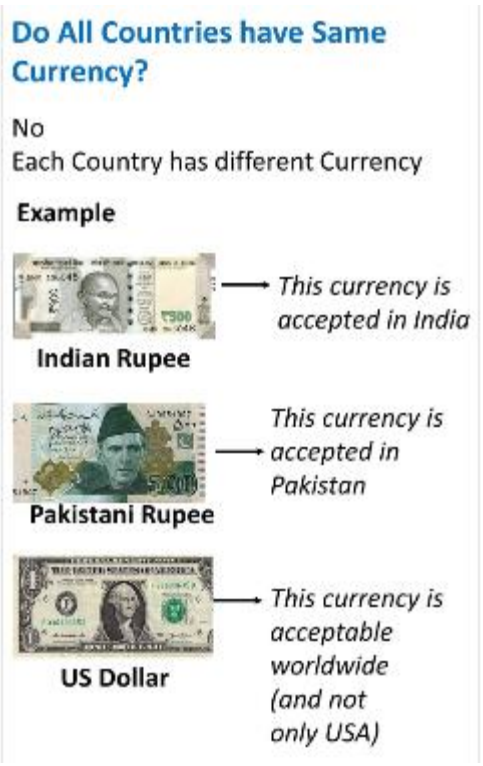

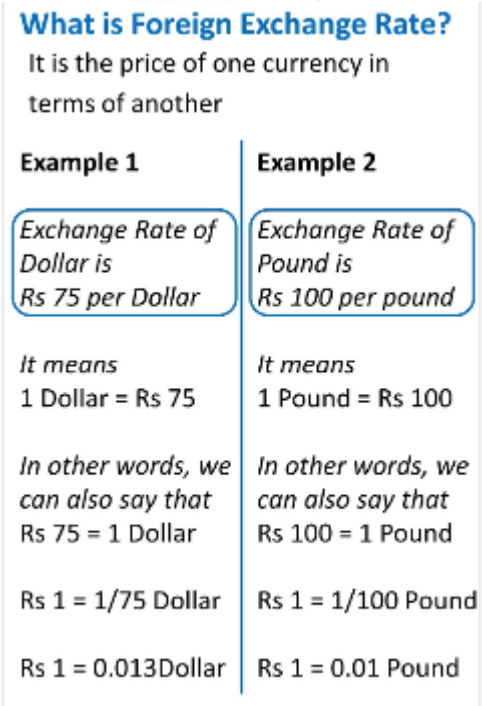

→ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने रुपये को डॉलर से बदलना चाहता है, तो वह अपने बैंक/मनी एक्सचेंज एजेंट से संपर्क करेगा

→ इसी प्रकार, RBI भी विदेशी मुद्रा रखता है और नियमित रूप से इसकी खरीद और बिक्री करता है

विदेशी मुद्रा दर/बाज़ार का उद्देश्य क्या है?

यह विभिन्न देशों की मुद्राओं को जोड़ता है।

(एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में क्या है?)

यह अंतरराष्ट्रीय लागत और कीमत की तुलना करने में सक्षम बनाता है

(मान लीजिए कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 डॉलर का एक बर्गर खरीदते हैं, भारत में इसकी कीमत 70*5 = 350 है)

विदेशी मुद्रा की मांग का क्या कारण है?

What Causes Demand for Foreign Exchange?

(Why do we need Foreign Currency like Dollars)

For Importing Goods

Foreign Country ⟵ *Goods* / *Dollars* ⟶ India

For Purchasing Assets

Land/Shares in USA ⟵ *Purchase* / *Dollars* ⟶ India

For Sending Gifts (Unilateral Transfers)

NRI ⟵ *Dollars* India

Tourism

Foreign Tour ⟵ *Dollars* India

के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है

1. वस्तुओं और सेवाओं का आयात
2. विदेश में उपहार भेजना/एकतरफ़ा स्थानांतरण
3. विदेश में निवेश (विदेश में संपत्ति की खरीद)
4. पर्यटन (विदेश जाने वाले लोगों को विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है)
5. अटकलें (लोग विदेशी मुद्रा खरीदते हैं यदि उन्हें इसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है)

विदेशी मुद्रा दर और विदेशी मुद्रा मांग के बीच संबंध

- विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है
- यदि विदेशी मुद्रा की दर बढ़ती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आती है।
- यदि विदेशी मुद्रा की दर घटती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है।

What is the Purpose of Foreign Exchange?

It facilitates **International Trade** by linking currencies

(We need to convert our currency to import or export or travel)

It enables **Comparison of International Cost and price** (Suppose a Car cost 100,000 Dollar in USA, It will cost Rs75,00,000 in India)

Foreign Exchange Demand For Speculation

Suppose Dollar Rate is 75/$
A speculator expects it to become 80/$ in future

So he will buy foreign exchange today and sell in future
Buying today increases demand for Foreign exchange

Dollar Rate Current	75/$	Speculator purchase $1000 and sells them in future
Expected in future	80/$	

Sales 80000
Purchase 75000
Profit 5000

This Purchase increase Demand for Foreign Exchange

Foreign Exchange Rate and Supply

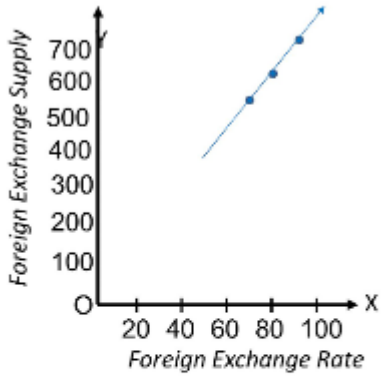

On X Axis,
we show Foreign Exchange Rate

On Y Axis,
we show Foreign Exchange Supply

As the Rate increases,
Supply also Increases
Hence, Supply Curve has Upward Slope

Relation between Foreign Exchange Rate & Demand

Imported Car Cost $ 100,000

Year 2021	**Year 2022**
Suppose Exchange Rate is Rs70 What is Cost of Car in Rupees?	*Suppose Exchange Rate increases to Rs 80. What is Cost of Car in Rupees?*
Cost = 100,000*70 = Rs 70,00,000	**Cost =** 100,000*80 = Rs 80,00,000
Price is less More Cars sold More Demand	Price is more Less Cars will be sold Less Demand

When Exchange Rate increases
Demand of Foreign Exchange Decreases

विदेशी मुद्रा की आपूर्ति का क्या कारण है?

स्वदेश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह निम्न कारणों से होता है:

1. वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात
2. बाहरी देश से उपहार/एकतरफ़ा स्थानांतरण प्राप्त करना
3. विदेशियों द्वारा भारत में किया गया निवेश
4. घरेलू देश में पर्यटन (भारत आने वाले लोगों को अपनी विदेशी मुद्रा बेचनी पड़ती है)
5. अटकलें (लोग विदेशी मुद्रा बेचते हैं यदि उन्हें इसकी कीमत कम होने की उम्मीद होती है)

विदेशी मुद्रा दर और विदेशी मुद्रा आपूर्ति के बीच संबंध:

- विदेशी मुद्रा की आपूर्ति सीधे विदेशी मुद्रा की दर से आनुपातिक होती है
- यदि विदेशी मुद्रा की दर बढ़ती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है
- यदि विदेशी मुद्रा की दर घटती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है

Foreign Exchange Rate & Supply

Tour to India Cost Rs 140000

Year 2021	**Year 2025**
Suppose Exchange Rate is Rs70 What is Cost of Tour in Dollars	*Suppose Exchange Rate increases to Rs 100. What is Cost of Car in Rupees?*
Cost = 140000/70 =$2000	**Cost =** 140000/100 = $1400
Price is more Less Tour sold Less Demand of Foreign Exchange	Price is less More Tour sold More Demand of Foreign Exchange

When Exchange Rate increases
Supply of Foreign Exchange Increases

विनिमय दर निर्धारित करने की विभिन्न विधियाँ क्या हैं?

मुद्रा विनिमय दर निर्धारित करने की 3 विधियाँ हैं:

1. लचीली या अस्थायी विनिमय दर
2. निश्चित विनिमय दर
3. प्रबंधित फ़्लोटिंग विनिमय दर

लचीली या अस्थायी विनिमय दर

- यह एक ऐसी प्रणाली है जहां विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- इस मामले में, सेंट्रल बैंक विनिमय दर निर्धारित करने में हस्तक्षेप (हस्तक्षेप) नहीं करता है।

विदेशी मुद्रा दर कैसे निर्धारित की जाती है?

यह उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां मांग और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं

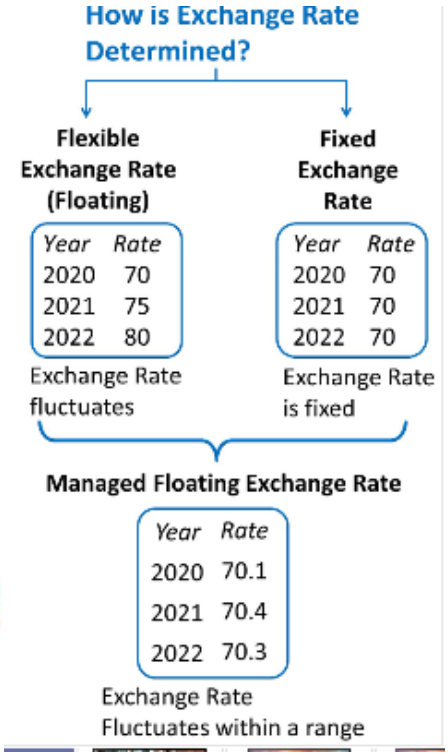

Schedule Representation of Flexible (Floating Exchange Rate)

Foreign Exchange Rate	Foreign Exchange Demand	Foreign Exchange Supply
70	900	500
71	800	600
72	700	700
73	600	800

This Decreases with Increase in Rate

This Increases with Increase in Rate

Here Demand=Supply This is how Foreign Exchange Rate Determined

Graph Representation of Flexible (Floating Exchange Rate)

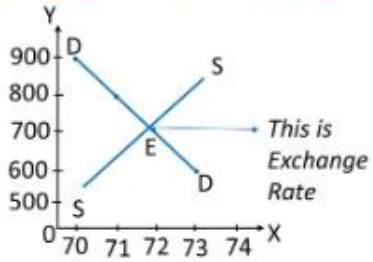

Graph

On X Axis, we show Foreign Exchange Rate

On Y Axis, we show Foreign Exchange Demand/ Supply

Demand Curve has Downward Slope

But Supply Curve has Upward Slope

At Point of Intersection of Supply Curve and Demand Curve Exchange Rate is Determined

What is Flexible or Floating Exchange Rate

Year	Exchange Rate
2020	70
2021	75
2022	80

In this case, Exchange Rate is determined by forces of Demand and Supply

Demand of Foreign Exchange

More the Exchange Rate Less the Foreign Exchange Demand (it is Inversely Proportional)

Supply of Foreign Exchange

More the Exchange Rate More the Foreign Exchange Supply (it is Directly Proportional)

घरेलू मुद्रा की प्रशंसा और मूल्यह्रास

घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास का क्या कारण है?

- इसका अर्थ है भारतीय मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि

उदाहरण

⟶ मान लीजिए विनिमय दर 70 रुपये है

⟶ 1 साल बाद यह बढ़कर 75 रुपये हो जाता है

⟶ इसका मतलब है कि भारतीय रुपये की तुलना में डॉलर का मूल्य बढ़ गया है

⟶ हम यह भी कह सकते हैं कि, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य कम हो गया है

What is Depreciation and Appreciation of Domestic Currency ?

Depreciation of Domestic Currency → Decrease In Price → of Indian Rupees

Appreciation of Domestic Currency → Increase In Price → of Indian Rupees

Example

Exchange Rate of $ increased from 70 to 75 per dollar

Earlier	Now
$1= Rs 70	1 $ =Rs 75
Rs 1 = 1/70	Rs 1= 1/70
= $0.0142	= $0.0133

Value of Indian Rupee decreased
So this is **Depreciation** of Domestic Currency (Rupees)

Depreciation and Appreciation of Domestic Currency ?

Depreciation	Appreciation
It means Increase in price of foreign currency or Decrease in price of domestic currency	It means Decrease in price of foreign currency or Increase in price of domestic currency
Foreign Currency ($) becomes expensive	Foreign Currency ($) becomes cheaper
Example Dollar increased from 70 to 75	**Example** Dollar decreased from 75 to 72
It is caused by Increase in Demand Or Decrease in Supply of Foreign Exchange	It is caused by Decrease in Demand Or Increase in Supply of Foreign Exchange

Both Depreciation and Appreciation possible under Flexible Rate only

घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास का कारण

⟶ यह विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि या विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी के कारण होता है।

What is Depreciation of Domestic Currency

It means
Increase in price of foreign currency
or
Decrease in price of domestic currency

In this case
Foreign Currency ($) becomes expensive

Example
Dollar increased from 70 to 75
It means Rupee depreciated
from 0.0142 to 0.0133

Causes
This is caused by Increase in Demand or Decrease in Supply of Foreign Exchange } *Hence there are 2 Cases of Depreciation*

Depreciation due to Increase in Demand Of Foreign Exchange

How is Exchange Rate Determined under Flexible(Floating) Rate?

It is determined at point where Demand & Supply curve intersect It is at Point E in this case

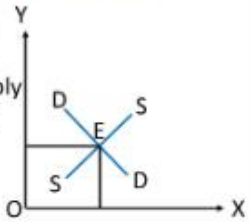

What if there is Increase in Demand of Foreign Currency?

In this case, Demand curve moves Rightwards Now Demand & Supply curve meet at E1. It is new exchange rate

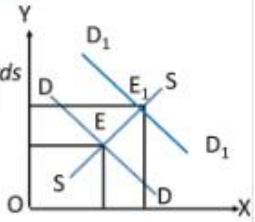

Depreciation due to Decrease in Supply of Foreign Exchange

How is Exchange Rate Determined under Flexible(Floating) Rate?

It is determined at point where Demand & Supply curve intersect It is at Point E in this case

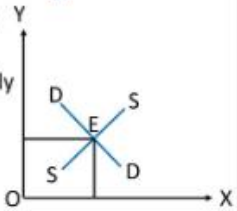

What if there is Decrease in Supply of Foreign Currency?

In this case, Supply curve moves Rightwards Now Demand & Supply curve meet at E1 It is new exchange rate

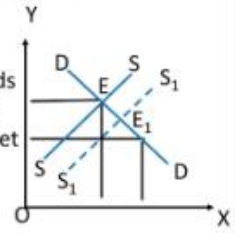

घरेलू मुद्रा की सराहना (वृद्धि) का क्या कारण है?

- इसका अर्थ है भारतीय मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा की कीमत में कमी। यह विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण होता है।
- उदाहरण- मान लीजिए विनिमय दर 70 रुपये है। 1 वर्ष के बाद, यह घटकर 65 रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि भारतीय रुपये की तुलना में डॉलर का मूल्य कम हो गया है।
- हम यह भी कह सकते हैं कि, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ गया है

What is Appreciation of Domestic Currency?

It means
Decrease in price of foreign currency
or
increase in price of domestic currency

In this case
Foreign Currency ($) becomes cheaper

Example
Dollar decreased from 70 to 60
It means Rupee appreciated
from 0.0142 to 0.0166

Causes
This is caused by
Decrease in Demand
or
Increase in Supply
of Foreign Exchange

Hence there are 2 Cases of Appreciation

Case 1
Appreciation due to Decrease in Demand Of Foreign Exchange

How is Exchange Rate Determined under Flexible(Floating) Rate?

It is determined at point where Demand & Supply curve intersect
It is at Point E in this case

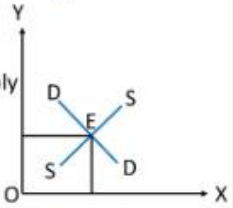

What if there is Decrease in Demand of Foreign Currency?

In this case, Demand curve moves Leftwards Now Demand & Supply curve meet at E1. It is new exchange rate

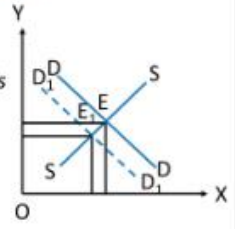

Case 2
Appreciation due to Increase in Supply of Foreign Exchange

How is Exchange Rate Determined under Flexible(Floating) Rate?

It is determined at point where Demand & Supply curve intersect
It is at Point E in this case

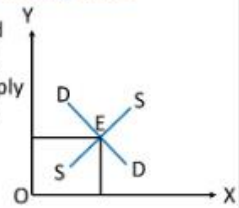

What if there is Increase in Supply of Foreign Currency?

In this case, Supply curve moves Rightwards Now Demand & Supply curve meet at E1 It is new exchange rate

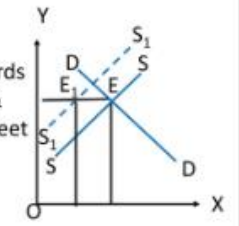

लचीली दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

निम्नलिखित कारक विनिमय दरों को प्रभावित करते हैं

1. विदेशी मुद्रा की मांग
2. विदेशी मुद्रा की आपूर्ति
3. आय
4. अटकलें
5. ब्याज दरें
6. क्रय शक्ति सिद्धांत

विनिमय दरों पर आय का प्रभाव क्या है?

- जब देश की आय बढ़ती है, तो लोग अधिक खर्च करते हैं और अधिक सामान खरीदते हैं।
- इसलिए, वे आयातित सामान भी अधिक खरीदते हैं।
- इससे आयात में वृद्धि होती है। इसके कारण विदेशी मुद्रा की मांग अधिक हो जाती है। इससे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है।

Factors affecting Exchange Rate under Flexible Rate System

Factor		We have already studied
Supply of Foreign Currency	Decrease	*Depreciation*
	Increase	*Appreciation*
Demand of Foreign Currency	Decrease	*Appreciation*
	Increase	*Depreciation*

Income
Speculation
Interest Rates
Purchasing Power Theory

These we will study now

अटकलें विनिमय दरों को कैसे प्रभावित करती हैं?

लोग मुनाफा कमाने के लिए विदेशी मुद्रा में सट्टा लगाते हैं

उदाहरण 1:

मान लीजिए कि डॉलर की विनिमय दर वर्तमान में 70 रुपये प्रति डॉलर है। व्यक्ति को लगता है कि भविष्य में यह बढ़कर 80 रुपये प्रति डॉलर हो जाएगा. इसलिए, वे आज 70 रुपये की दर पर डॉलर खरीदेंगे और बाद में इसे 80 रुपये पर बेचेंगे। इसलिए, विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हुई है

उदाहरण 2:

मान लीजिए कि डॉलर की विनिमय दर वर्तमान में 70 रुपये प्रति डॉलर है। व्यक्ति को लगता है कि भविष्य में यह गिरकर 60 रुपये प्रति डॉलर पर आ जायेगा. इसलिए, वे आज डॉलर को 70 रुपये पर बेचेंगे और बाद में इसे 60 रुपये पर खरीदेंगे। अब बेचने से विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है। अत: विदेशी मुद्रा की मांग में कमी आयी है।

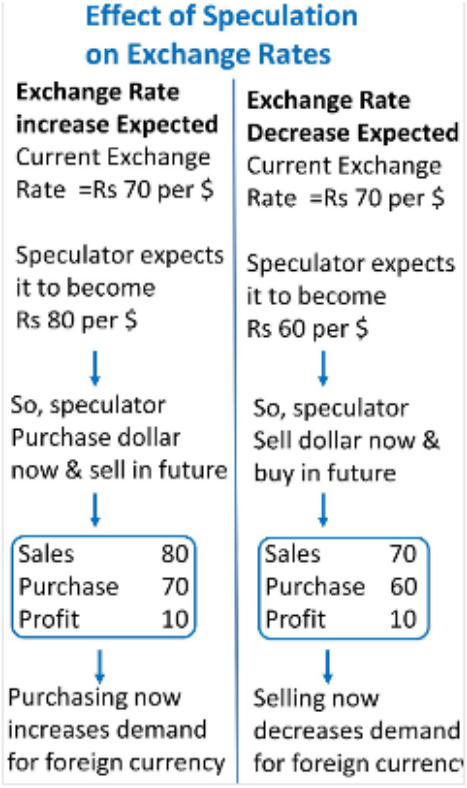

विनिमय दरों पर ब्याज दरों का क्या प्रभाव पड़ता है?

- प्रत्येक देश में ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं। इसलिए, निवेशक कम ब्याज दर वाले देशों से अधिक ब्याज दर वाले देशों की ओर रुख करते हैं।
- इससे उच्च ब्याज दरों वाले देश की मुद्रा की सराहना होती है।

उदाहरण:

मान लीजिए कि दो देश ए और बी हैं। दोनों देश सरकारी बांड जारी करते हैं। सरकारी बांड पर ब्याज दर ए में 8% और बी में 10% है। इसलिए, ब्याज दर में 2% का अंतर है। B देश के निवेशक देश A के बजाय अपने देश में निवेश करना पसंद करेंगे। साथ ही, देश A के निवेशक देश B में निवेश करना पसंद करेंगे। इसलिए, वे B देश की विदेशी मुद्रा खरीदेंगे। इसलिए, बी की मुद्रा की अधिक मांग होगी और इसलिए बी देश की मुद्रा की सराहना होगी।

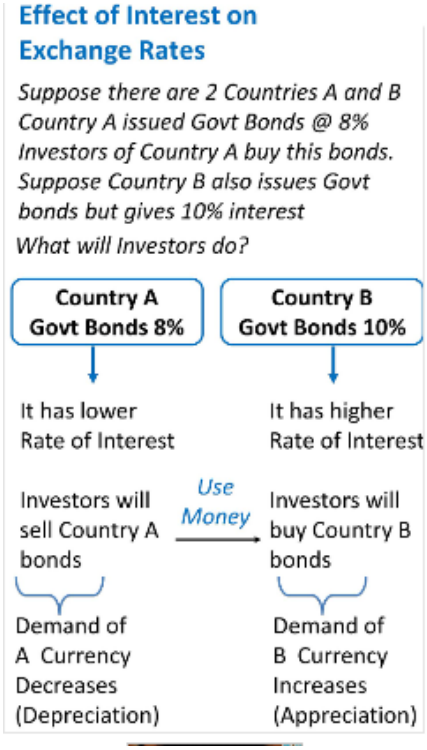

क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या है?

इस सिद्धांत के अनुसार, विनिमय दर लंबी अवधि में इस तरह समायोजित होती है कि समान उत्पादों की लागत समान होती है, चाहे घरेलू मुद्रा (रुपये) में मापी गई हो या विदेशी मुद्रा (डॉलर) में मापी गई हो।

मान लीजिए कि भारत में एक शर्ट खरीदने की लागत 400 रुपये है, और अमेरिका में एक समान शर्ट खरीदने की कीमत 8 डॉलर है। सेब से सेब की तुलना करने के लिए, हमें पहले INR को $ में बदलना होगा।

यदि विनिमय दर 1$= 70 INR है

तो अमेरिका में शर्ट की कीमत $8 है, इसलिए भारत में उसी शर्ट की कीमत 400/70 = $5.7 होगी

इसलिए, पीपीपी 8/5.7 यानी 1.4 होगा

दूसरे शब्दों में, भारत में शर्ट पर खर्च किए गए प्रत्येक 1 डॉलर के लिए, अमेरिका में वही शर्ट प्राप्त करने के लिए 1.4 डॉलर लगते हैं। इसलिए, INR की अधिक मांग होगी और डॉलर की कम मांग होगी।

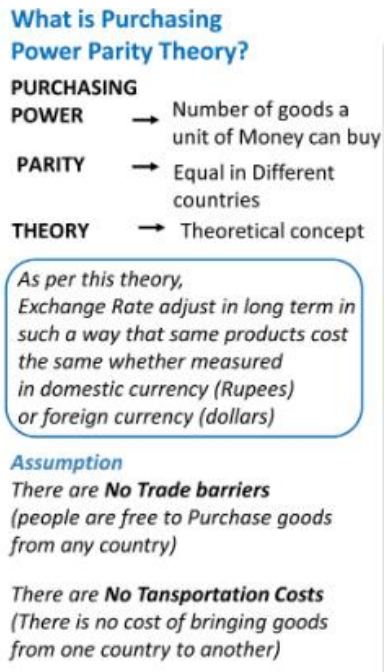

निश्चित विनिमय दर प्रणाली

- इस मामले में, किसी मुद्रा की विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है। विनिमय दर में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव नहीं होता है। उदाहरण- मान लीजिए कि सरकार विनिमय दर 70 रुपये प्रति डॉलर तय करती है, यह तब तक वही रहेगी जब तक सरकार इसमें बदलाव नहीं करती।
- यह विदेशी व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सरकार विनिमय दर को 80/$ तक बढ़ा सकती है जिसे अवमूल्यन कहा जाता है) या विनिमय दर को घटाकर 60 रुपये प्रति $ कर सकती है जिसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है

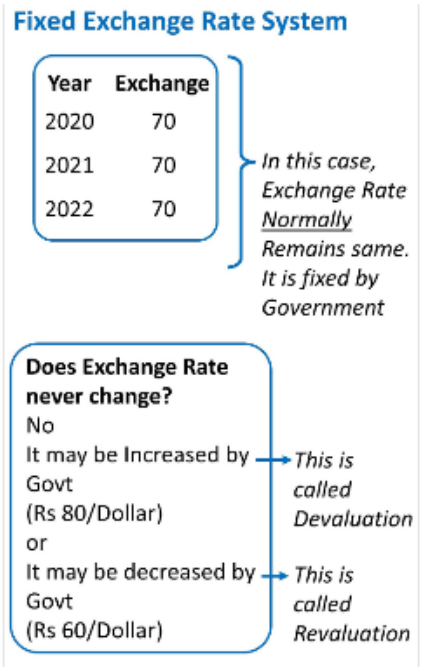

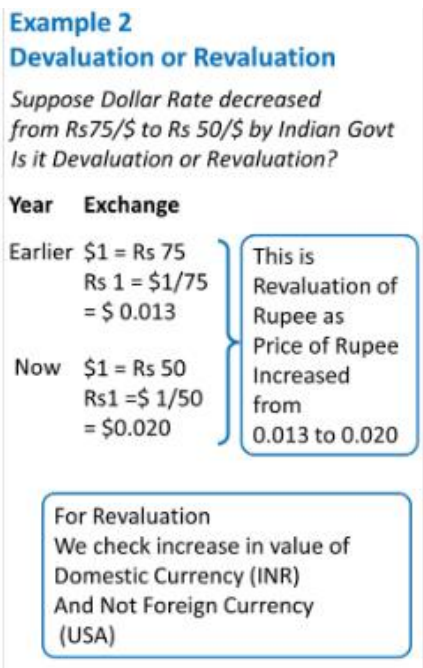

अवमूल्यन कब किया जाता है

- यदि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, तो वह उच्च विनिमय दर तय करेगी।
- उदाहरण - यह डॉलर की विनिमय दर को 70 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 80 रुपये प्रति डॉलर कर देगा
- इसलिए, इससे घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाएगी और बदले में घरेलू सामान सस्ता हो जाएगा
- ऐसा करने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा खरीदेगी।

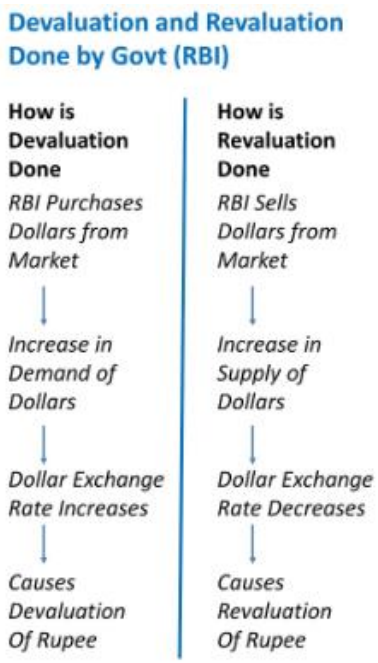

Basis	Devaluation	Revaluation
Meaning	It means Reduction in Price of Domestic Currency in terms of all foreign currency	It means Increase in Price of Domestic Currency in terms of all foreign currency
	In this case, Higher Exchange Rate is fixed by Govt	In this case, Lower Exchange Rate is fixed by the govt
Example	Exchange Rate increased from Rs 70 per $ to Rs80 per $	Exchange Rate decreased from Rs 70 per $ to Rs60 per $
	Hence, Value of Rupee decreases as compared to dollar	Hence, Value of Rupee increases as compared to dollar
Method	When the govt increases exchange rate	When the govt decreases exchange rate
	There is excess supply of foreign currency in market	There is excess demand of foreign currency in market
	So Govt buys foreign Exchange from the market	Govt Sells foreign Exchange in the Market

सारांश

- स्थिर विनिमय पद्धति में सरकार विनिमय दर को स्थिर रखती है।
- विनिमय दर में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव नहीं होता है। ऐसा विदेशी व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
- सरकार विनिमय दर बढ़ा सकती है (जिसे अवमूल्यन कहा जाता है) या सरकार विनिमय दर घटा सकती है (जिसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है)।

निश्चित विनिमय दर और लचीली विनिमय दर के बीच अंतर

निश्चित विनिमय दर	लचीली विनिमय दर
इस मामले में, विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है	इस मामले में, विनिमय दर मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है
विनिमय दर स्थिर रहती है और इसमें उतार-चढ़ाव नहीं होता है	विनिमय दर में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता है
सरकार द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन या पुनर्मूल्यांकन हो सकता है	विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के कारण मुद्रा का मूल्यह्रास या मूल्यह्रास हो सकता है
विदेशी व्यापार में अधिक स्थिरता है	यह कम स्थिर है क्योंकि विनिमय दर बदलती रहती है
इसमें सरकार और केंद्रीय बैंक की भूमिका अधिक होती है क्योंकि उसे विदेशी मुद्रा खरीदनी और बेचनी होती है	इसमें सरकार की भूमिका कम होती है क्योंकि विनिमय दर स्वचालित रूप से निर्धारित होती है
इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है	इस पद्धति का प्रयोग सामान्यतः सभी विकसित देशों द्वारा किया जाता है

मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है?

- यह लचीली या फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली और निश्चित विनिमय दर प्रणाली का मिश्रण है
- इस प्रणाली में, मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के आधार पर विनिमय दर में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता है
- हालाँकि, विनिमय दर की गतिविधियों को सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है
- यदि विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने से विदेशी मुद्रा में अधिक उतार-चढ़ाव होता है तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करते हैं।

नाममात्र विनिमय दर क्या है?

- नाममात्र विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है।

उदाहरण: डॉलर की दर 75/डॉलर है, इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा डॉलर की एक इकाई 75 रुपये के बराबर है।

वास्तविक विनिमय दर क्या है?

- यह घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है
- वास्तविक विनिमय दर =
- सामान्य विनिमय दर * विदेशी मूल्य/घरेलू मूल्य

Definition Nominal and Real Exchange Rate?

Nominal Exchange Rate
It is Normal Exchange Rate
Price of one unit of Foreign Currency in terms of domestic currency
Example -75/$

Real Exchange Rate
It is relative price of foreign goods in terms of domestic goods

Real Exchange Rate =
Normal Exchange Rate*foreign Price/Domestic Price
75*2/100
= 1.5

What is Purchasing Power Parity

If Real exchange rate is equal to 1 it is called Purchasing Power Parity

Example
A Mc Donald's Burger cost Rs 150 in India
Same Burger cost $2 in USA
(Exchange Rate Rs 75 per $)

India

Burger
Cost Rs 150

USA

Burger Cost $2
Cost in Rupees
= 2*75 = 150

Real Exchange Rate =
Normal Exchange Rate*foreign Price/Domestic Price
75*2/150 =150/150 =1
This is called Purchasing Power Parity

Example
A Mc Donald's Burger cost Rs 100 in India. Same Burger cost $2 in USA

India

Burger
Cost Rs 100

USA

Burger Cost $2
(Exchange Rate Rs 75 per $)
Cost in Rupees
= 2*75 = 150

It means a Burger costing 100 in India costs 150 in USA
So real Exchange Rate of USA is 150/100 =1.5

What is Nominal and Real exchange Rate?

Nominal Exchange Rate	Rs 70 per $
Real Exchange Rate	1.5

Example 2 – Purchasing Power Parity

A Mc Donald's Burger cost Rs 100 in India
Same Burger cost $2 in USA
(Exchange Rate Rs 50 per $)

India

Burger
Cost Rs 100

USA

Burger Cost $2
Cost in Rupees
= 2*50 = 100

Real Exchange Rate =
Normal Exchange Rate*foreign Price/Domestic Price
50*2/100
=100/100
=1

This is called Purchasing Power Parity

विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी या बुरी है

निर्यात के लिए

- यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. निर्यात में वृद्धि क्योंकि विदेशियों के लिए हमारा उत्पाद खरीदना सस्ता है।
- इससे हमें विदेशों से आय प्राप्त होगी और हमारी आय में वृद्धि होगी

उदाहरण

⟶ मान लीजिए कि एक विदेशी व्यक्ति 70,000 रुपये का सामान खरीदना चाहता है

⟶ विनिमय दर 70 रुपये प्रति डॉलर है

⟶ तो, विदेशी को खर्च करना होगा = रु 70,000/70 = $1000

⟶ अब, मान लीजिए कि डॉलर की विनिमय दर 80 रुपये हो जाती है।

⟶ मान लीजिए कि एक विदेशी व्यक्ति 70,000 रुपये का सामान खरीदना चाहता है। तो, विदेशी को खर्च करना होगा = 70,000/80 = $875

⟶ इसलिए, विदेशियों के लिए हमारे उत्पाद खरीदना सस्ता है, इसलिए निर्यात बढ़ेगा

आयात के लिए

- यह अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है. जैसे-जैसे आयातित वस्तुएँ महँगी होती जाती हैं, इससे हमारे ख़र्चे बढ़ते हैं और हमारी आय घटती जाती है।

उदाहरण

⟶ मान लीजिए हम 1000 डॉलर का माल आयात करना चाहते हैं

⟶ विनिमय दर 70 रुपये प्रति डॉलर है

⟶ तो, हमें 70*1000 = 70,000 रुपये का भुगतान करना होगा

⟶ मान लीजिए विनिमय दर बढ़कर 80 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है

⟶ अब हमें 80*1000=80,000 देने होंगे

⟶ चूँकि, हमें अधिक खर्च करना पड़ता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है।

WALL OF FAME

UTKARSHA NISHAD
UPSC RANK - 18

SURABHI DWIVEDI
UPSC RANK - 55

SATEESH PATEL
UPSC RANK - 163

SATWIK SRIVASTAVA
SDM RANK-3

DEEPAK SINGH
SDM RANK-20

ALOK MISHRA
DEPUTY JAILOR RANK-11

SHIPRA SAXENA
GIC PRINCIPAL (PCS-2021)

SALTANAT PARWEEN
SDM (PCS-2022)

KM. NEHA
SUB REGISTRAR (PCS-2021)

SUNIL KUMAR
MAGISTRATE (PCS-2021)

ROSHANI SINGH
DIET (PCS-2020)

AVISHANK S. CHAUHAN
ASST. COMMISSIONER
SUGARCANE (PCS-2018)

SANDEEP K. SATYARTHI
CTD (PCS-2018)

MANISH KUMAR
DIET (PCS-2018)

AFTAB ALAM
PCS OFFICER

ASHUTOSH TIWARI
SDM (PCS-2022)

CHANDAN SHARMA
Magistrate
Roll no. 301349

YOU CAN BE THE NEXT....

8009803231 / 8354021661

D 22&23, PURNIYA CHAURAHA, NEAR MAHALAXMI SWEET HOUSE, SECTOR H, SECTOR E, ALIGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH 226024

Saarthi

THE COACH

1 : 1 MENTORSHIP BEYOND THE CLASSES

- **Diagnosis** of candidates based on background, level of preparation and task completed.
- **Customized solution** based on Diagnosis.
- One to One **Mentorship.**
- Personalized schedule **planning.**
- Regular **Progress tracking.**
- **One to One classes** for Needed subjects along with online access of all the subjects.
- Topic wise **Notes Making sessions**.
- One Pager **(1 Topic 1 page)** Notes session.
- **PYQ** (Previous year questions) Drafting session.
- **Thematic charts** Making session.
- **Answer-writing** Guidance Program.
- **MOCK Test** with comprehensive & swift assessment & feedback.

Ashutosh Srivastava
(B.E. , MBA, Gold Medalist)
Mentored 250+ Successful Aspirants over a period of 12+ years for Civil Services & Judicial Services Exams at both the Centre and state levels.

Manish Shukla
Mentored 100+ Successful Aspirants over a period of 9+ years for Civil Services Exams at both the Centre and state levels.